इंदौर से सबक

देश के सबसे स्वच्छ शहरों में वर्षों से शिखर पर रहे इंदौर में दूषित पेयजल की वजह से अनेक लोगों की मौत बहुत दुखद और चिंताजनक है। लगभग 150 लोग दूषित पेयजल की वजह से अस्पतालों में भर्ती हैं। यह एक ऐसी त्रासद घटना है, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने आपातकालीन स्थिति बताया है। न्यायालय ने भी संज्ञान लेकर यथोचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चौतरफा आलोचनाओं के बीच राज्य सरकार ने आपातकालीन उपाय तेज कर दिए हैं, लेकिन यह समस्या ऐसी है कि जिसका स्थायी उपाय करने की जरूरत है। एक आरोपी अधिकारी को बर्खास्त किया गया है, तो दो को उचित ही निलंबित किया गया है। इंदौर के इस हादसे से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इस एक हादसे ने देश के तमाम शहरों में लोगों को चिंता में डाल दिया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में अगर लोगों को जहरीला पानी मिल सकता है, तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा? दूषित जल से नुकसान का सही आकलन करना जरूरी है। करीब 80 प्रतिशत बीमारियों और एक तिहाई मौतों के पीछे दूषित जल ही दोषी है। हालांकि, हमें यह भी देखना होगा कि दूषित जल के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं?

अभी जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार, सीवेज लाइन में रिसाव था और वह जलापूर्ति लाइन से होकर गुजर रही थी। यह अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं है। ऐसा अनेक जगहों पर हुआ है और समय रहते समाधान के उपाय भी किए गए हैं। दरअसल, जहां लोग जागरूक हों और स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाता हो, वहां दूषित आपूर्ति को रोकना आसान है। इंदौर में ऐसा हो सकता है कि दूषित जल पर देर से ध्यान गया हो। खैर, इंदौर में ऐसे अनेक सवाल खड़े हुए हैं, जो देश के दूसरे शहरों पर भी लागू होते हैं। क्या पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है? क्या पेयजल की गुणवत्ता में आ रहे बदलावों पर नजर रखी जाती है? क्या यह देखा जाता है कि जलापूर्ति तंत्र या सीवेज तंत्र कितना पुराना हो गया है? ऐसे तंत्र की आयु कितनी होती है? कितने साल या दशक के बाद इस तंत्र का नवीनीकरण करना चाहिए? इंदौर की दुखद घटना साफ संकेत है कि देश के अच्छे शहरों में भी जलापूर्ति तंत्र को तत्काल ठीक करने की जरूरत है। जहां लाइनें पुरानी पड़ गई हैं, वहां तत्काल प्रभाव से नवीनीकरण होना चाहिए। आज जिस दौर में हम हैं, वहां गांव हो या शहर, हम कभी भी पेयजल गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते। यह देश के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जिसमें निवेश बढ़ाना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है।

करीब 80 प्रतिशत बीमारियों और एक तिहाई मौतों के पीछे दूषित जल ही दोषी है। हालांकि, हमें यह देखना होगा कि दूषित जल के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं?

इंदौर में दूषित जल के सेवन के बाद लोगों को उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण की शिकायत हुई है। अब समय आ गया है, जब शौचालय तंत्र और जलापूर्ति तंत्र को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाए। यह एक सामान्य जागरूकता की बात है कि यदि किसी जल से किसी भी प्रकार की दुर्गंध आए, तो उसके सेवन से हर हाल में बचना चाहिए। यह सावधानी आसान नहीं, लेकिन इसे सुनिश्चित करना होगा। मोटे अनुमान के अनुसार, 70 प्रतिशत से ज्यादा भारत में व्यवस्थित सीवेज तंत्र का अभाव है। अगर देश में 70 एमएलडी दूषित जल पैदा होता है, तो उसमें से महज 30 एमएलडी जल के शोधन की क्षमता है। बगैर-शोधन के जब दूषित जल मिट्टी में मिलता है, तो जाहिर है, जल व मिट्टी, दोनों की हानि होती है। इंदौर जैसे कथित स्वस्थ शहर में खतरे की एक घंटी बजी है और यह पूरे देश के जागने का समय है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 01 जनवरी, 1951

संकट का वर्ष

यह वर्ष न केवल भारत के लिए किन्तु समूचे संसार के लिए एक संकट का वर्ष रहा है। हमारे देश में इस वर्ष जितनी प्राकृतिक आपत्तियां आईं, जितनी गत कई वर्षों से नहीं आई थीं। कहीं अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि और आसाम में भीषण भूकम्प के परिणामस्वरूप देश के प्रायः सभी भागों में अकाल पड़ गया। पूर्वी पाकिस्तान की सरकार की हिन्दू-विरोधी नीति के कारण लाखों हिन्दू वहां से भागकर भारत आने लगे, जिससे विशेषतः पूर्वी भारत की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई। इतना ही नहीं, ईश्वर ने वर्ष के अन्त में हमारे देश के एक महान नेता सरदार वल्लभभाई पटेल को, जिनमें देश की आंतरिक स्थिति को समझने और संकट से बचा लेने की शक्ति थी, हमसे छीन लिया। सन् 1948 में महात्मा गांधी के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात हमारे देश को इतना बड़ा धक्का नहीं लगा था, जितना सरदार पटेल के स्वर्गवास हो जाने से लगा। लोग ऐसा मानते थे कि गांधीजी के चले जाने के पश्चात नेहरूजी और सरदार पटेल दोनों मिलकर गांधीजी जैसे एक व्यक्ति बन जाते थे। गांधीजी के कुछ गुण नेहरूजी और कुछ गुण सरदार पटेल में थे; इस तरह गांधीजी की कमी को कुछ हद तक दोनों नेता मिलकर पूरी करते थे। विशेषतः यह कमी अब नेहरूजी अधिक महसूस करेंगे।

इसके सिवा आज विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आज यह कहना असंभव है कि क्या इस वर्ष के 25 जून को तृतीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया; उसी दिन कोरिया की 38वीं अक्षांश रेखा पर दो विरोधी शक्तियों का भीषण युद्ध प्रारम्भ हुआ था और उसके पश्चात् सुरक्षा परिषद ने कोरिया में अमरीका के हस्तक्षेप की स्वीकृति दे दी। थोड़े दिनों के पश्चात विश्व के 53 राष्ट्रों ने उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी ठहराया और संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से दक्षिण कोरिया को आक्रमण से बचाने के लिए सेना भेजने का अनुरोध किया गया। कई देशों ने, जिनमें आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, तुर्की और स्याम के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, थोड़े समय पश्चात् वहां सेना भेजी और कुछ देशों ने, जिनमें भारत का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, सांकेतिक सहायता भेजी। इस तरह कोरिया में संयुक्त राष्ट्रसंघ के झण्डे के बीच कई देशों की सेना ने उत्तर कोरिया और बाद में चीन की सेना का सामना किया।

भारतीय विदेश नीति पर रहेगी नजर

यहां स्कैन करें

हर्षवर्धन श्रृंगला | पूर्व विदेश सचिव व सांसद

नए साल में हमारा फोकस 'भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे' पर होगा, जो परिवहन, ऊर्जा व डिजिटल नेटवर्क के जरिये इन देशों से हमारे रिश्ते मजबूत करेगा।

हम नए साल में प्रवेश कर गए हैं। इस समय दुनिया में अनिश्चितता, शक्ति संतुलन में बदलाव और बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति बनी हुई है। साल के पहले दिन ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ताइवान संबंधी बयान ने स्पष्ट कर दिया कि यह वर्ष काफी जटिल स्थितियां जनने जा रहा है। जिनपिंग का दो टूक लहजे में यह कहना कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा और ताइवानी राष्ट्रपति का अपनी संप्रभुता से किसी किस्म का समझौता करने से इनकार करना साल 2026 में टकराव की आशंकाओं की एक बानगी भर है। ऐसे माहौल में भारत की विदेश नीति पर सबकी निगाह रहने वाली है।

हालांकि, अपने उद्देश्य की स्पष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय-वैश्विक हितों को साधने वाली साझेदारियों के प्रति हमारी नीति पूरी तरह साफ है। इस साल अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आसियान, अफ्रीकी संघ और खाड़ी के देशों से रिश्ते हमारी विदेश नीति के केंद्र में रहेंगे। भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी, खासकर रक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थिर रहने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ व्यापार और टैरिफ पर जारी मतभेदों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मित्रता और ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए जाने से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की संभावना है। अमेरिका ने अपनी 'राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025' में भारत के साथ वाणिज्यिक संबंधों और हिंद-प्रशांत रणनीतिक संबंधों को एक साथ विकसित करने के प्रति भी रुचि जताई है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों रूस से बाहर कम यात्रा करते हैं। इसके बावजूद बीते दिसंबर में उनकी भारत यात्रा हुई। यह अपवाद था। उस यात्रा ने भारत के साथ रूस के संबंधों की अहमियत को एक बार फिर रेखांकित किया। यूरेशियाई आर्थिक संघ के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत रूस से व्यापारिक रिश्ते को विस्तार देने पर इस साल फोकस रहेगा।

चीन के साथ संबंधों में कुछ विवादों और सीमा-संघर्ष के कारण गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। बढ़ते व्यापार घाटे के अलावा दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में उसके बढ़ते कदमों के कारण भी कई चुनौतियां पैदा हुई हैं, फिर भी उसके साथ रिश्ते सामान्य बनाने की दिशा में इस वर्ष नई कोशिशें हो सकती हैं। ब्रिटेन और ओमान के साथ तरजीही व्यापार समझौतों से भारतीय निर्यात, पूंजी निवेश और भारतीय युवाओं के लिए वैश्विक आवागमन के द्वार खुलने के संकेत हैं। इसी तरह, गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय नेताओं की भारत यात्रा और यूरोपीय संघ के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित आर्थिक समझौते को संपन्न कराने की दिशा में उठाए गए कदमों से यूरोपीय संघ के साथ हमारा जुड़ाव बढ़ेगा।

भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण कारक 'कनेक्टिविटी' रहा है। इससे आर्थिक एकीकरण और रणनीतिक साझेदारियों में घनिष्ठता आती है। इस साल हमारा ध्यान 'भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे' (आईएमईसी) पर केंद्रित होगा, जो एकीकृत परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क के जरिये इन देशों के साथ हमारे संबंधों को काफी मजबूत कर सकता है। इसके लागू होने से व्यापारिक कुशलता बढ़ेगी, आपूर्ति-श्रृंखला मजबूत हो सकेगी और भारत उभरती क्षेत्रीय मुहिम में अहम भूमिका निभा सकता है। पश्चिम एशिया से शुरू होने वाली 'लुक वेस्ट' नीति सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ओमान समेत खाड़ी के अन्य देशों व इजरायल के साथ भारत के संबंधों को और मजबूती देगी।

आसियान के साथ भारत का जुड़ाव उसकी 'एक्ट ईस्ट' नीति का मुख्य स्तंभ बना रहेगा, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक एकीकरण और समुद्री सुरक्षा के साझा हितों पर आधारित है। सहयोग के क्षेत्र में व्यापार व निवेश, आपूर्ति-श्रृंखला की मजबूती, डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षमता-निर्माण भी शामिल हैं। 'भारत-अफ्रीका फोरम' के आयोजन से अफ्रीकी संघ के साथ भारत की साझेदारी को इस साल नई ऊर्जा मिलेगी। यह दशकों के विकास सहयोग और 'दक्षिण-दक्षिण एकता' पर आधारित है। क्षमता निर्माण, विकास, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा और कनेक्टिविटी के मामले में सहयोग के अतिरिक्त शांति व सुरक्षा के साथ बढ़ता व्यापार-निवेश इस साझेदारी का अभिन्न अंग बना रहेगा।

भारत के निकट पड़ोस में घट रही घटनाओं को कम करके नहीं आंका जा सकता, इसलिए भारत 'पड़ोस पहले' की अपनी नीति को इस साल भी प्राथमिकता देना जारी रखेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भूटान में पनबिजली परियोजनाओं से लेकर नेपाल में सड़क व बुनियादी ढांचा निर्माण की पहल के साथ-साथ श्रीलंका व मालदीव से समुद्री व रक्षा सहयोग ने एक क्षेत्रीय भागीदार के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत बनाया है। भारत बांग्लादेश में हो रहे राजनीतिक और संस्थागत बदलाव से तालमेल बिठा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री एस जयशंकर का शरीक होना इसका ठोस प्रमाण है। भारत नेपाल के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और गहरा कर रहा है, तो भूटान के प्रमुख रणनीतिक भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को मजबूती दे रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्रवाई करने के प्रयासों ने भारत की स्थिति एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में मजबूत बनाई है।

जाहिर है, *वसुधैव कुटुंबकम* के सिद्धांत के तहत दुनिया के गरीब देशों में कल्याणकारी कार्यों में योगदान भारतीय विदेश नीति का अहम पहलू है। भारत 'ग्लोबल साउथ' की एक प्रमुख आवाज के रूप में उभरा है। भारत इस क्षेत्र की विकास प्राथमिकताओं, न्यायसंगत विकास और वैश्विक संस्थानों में विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की वकालत करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के नेताओं के साथ सीधे संपर्क में हैं। उन्होंने जी-20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े वैश्विक मंचों पर भी इस संघर्ष को समाप्त कराने में संवाद का समर्थन किया है। इस तरह से वह कूटनीतिक तौर पर सभी पक्षों से जुड़े हैं। ये तमाम कवायदें भारत के इस विश्वास को पुष्ट करती हैं कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही शांति संभव है। साल 2026 में हमारा कदम सतर्क, संतुलित और आशावादी रहेगा। इस तरह, बहुध्रुवीय दुनिया में हमारी विदेश नीति के केंद्र में रणनीतिक स्वायत्तता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास ही रहेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

रोजगार गारंटी को मजबूत बनाए रखने की जरूरत

यहां स्कैन करें

हिमांशु | एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू

सरकार ने दो दशक पुराने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) का नाम और उद्देश्यों को बदलकर उसकी जगह 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' या वीबी-जी राम जी कानून लागू किया है।

सार्वजनिक रोजगार योजनाएं लंबे समय से देश में आजीविका सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए लागू की जाती रही हैं। महाराष्ट्र में 1970 के दशक से ऐसी ही योजना प्रभावी है। हालांकि, मनरेगा में अलग बात यह थी कि इसमें हरेक ग्रामीण परिवार को मांग-आधारित और बिना शर्त रोजगार की गारंटी दी गई थी। बेशक, इसमें रोजगार की पूर्ण गारंटी नहीं थी, क्योंकि इसमें एक परिवार को अधिकतम 100 दिनों का ही रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान था, लेकिन इसने ग्रामीण बुनियादी ढांचों में सुधार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी उपयोगिता तब विशेष रूप से साबित हुई, जब कोरोना महामारी के दौरान गांव लौटे लाखों प्रवासियों के लिए भी यह कानून जीवनदायक बना।

मनरेगा की खासियत यह भी थी कि इसे कानूनी समर्थन हासिल था। इसकी बिना शर्त सबके लिए उपलब्धता ने इसे अनेक परिवारों की जीवन-रेखा बना दिया। जब पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको रोकने की कोशिश की, तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनरेगा को महज तकनीकी कारणों से नहीं रोका जा सकता। मजदूरों के लिए मनरेगा से इतर कहीं और काम करने का मतलब था, मनरेगा में तय मजदूरी से अधिक मिलना। इस तरह इस कानून ने श्रम बाजार को परोक्ष रूप से मजबूत किया। इस बात के पर्याप्त सुबूत हैं कि इसने 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण मजदूरी बढ़ाने और गरीबी कम करने में मदद की। बाद के वर्षों में इसके कई प्रावधानों को केंद्र एवं राज्य सरकारों ने कमजोर किया और इसकी मजदूरी, जो बाजार दर से अधिक थी, वह उसकी दो-तिहाई रह गई। फिर भी, इसमें काम की मांग बनी हुई थी, जिसका फायदा अमूमन औरतें और वंचित समुदायों के लोग उठा रहे थे।

काम की पूरी गारंटी न रहने से ग्रामीण संकट बढ़ सकता है और धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुस्त पड़ सकती है।

नए कानून में मनरेगा वाले अधिकार का अभाव है और अधिकतम सीमा से अधिक काम की मांग नहीं की जा सकती। इसके तहत अब केंद्र सरकार अपने तय 'उद्देश्यों' के तहत फंडिंग करेगी। कृषि सीजन में इस कानून के तहत काम मांगने की गांरटी 60 दिनों के लिए टाल दी गई है। बेशक, इस दौरान अधिकतर मजदूर मनरेगा का काम नहीं ढूंढ़ते थे, पर गारंटी के कारण उन्हें बेहतर मजदूरी के लिए मोलभाव करने में मदद मिलती थी। मनरेगा ने निस्संदेह मजदूरी बढ़ाने में मदद की, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि इसने सूखा या खेती के काम की कमी के दौरान रोजगार उपलब्ध कराकर मजदूरों को सहारा दिया। हालांकि, हाल के दिनों में 22 राज्यों में इसकी मजदूरी दर बाजार दर से कम हो गई थी, जिस कारण इसमें काम की मांग घट गई थी। मगर ऐसे समय में, जब खेती की मजदूरी स्थिर है और गैर-खेती की मजदूरी में करीब एक दशक से कमी आ रही है, तब फसल सीजन के दौरान इसे लागू करने पर रोक लगाने से मजदूरी पर और दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा काम के अधिकतम दिनों को 125 करने का भी कोई खास फायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि पिछले दो दशकों में मनरेगा में काम के दिनों की औसत संख्या प्रति परिवार 50 से कम रही है और मुश्किल से दो से तीन प्रतिशत परिवार ही 100 दिनों तक काम कर पाए हैं।

नए कानून को आर्थिक मोर्चे पर भी जूझना पड़ सकता है। मनरेगा में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब वह बड़े राज्यों को खर्च का सिर्फ 60 प्रतिशत हिस्सा देगी। इस तरह, नया कानून कमजोर अर्थव्यवस्था वाले राज्यों के लिए बोझ बन सकता है। इससे राज्यों के बीच असमानता बढ़ सकती है, जिससे कम उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को नुकसान हो सकता है। मनरेगा ज्यादातर गरीबों के लिए एकमात्र सामाजिक सुरक्षा की गारंटी थी, जिससे लगभग एक-तिहाई ग्रामीण परिवार लाभ उठा रहे थे। जाहिर है, इसके खत्म होने से ग्रामीण संकट बढ़ सकता है और धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुस्त पड़ सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

लाओत्से की अंतिम सीख

मरते समय किसी ने लाओत्से से पूछा, आप अपने जीवन के कुछ रहस्य बता दें। लाओत्से ने कहा, पहला रहस्य तो यही है कि मुझे जिंदगी में कोई कभी हरा नहीं सका। उनके शिष्य बड़े उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, यह तो आपने हमें कभी बताया नहीं। जीतना तो हम भी चाहते हैं। हमें तरकीब बताइए?

लाओत्से ने कहा, तुम सब भूल कर गए। मैंने कुछ और कहा था। मैंने कहा था, मुझे कोई हरा नहीं सका, और तुम लोग पूछते हो कि जीतना तो हमें भी है। ये दोनों बातें उल्टी हैं। ये एक सी लगती हैं। शब्दों की दुनिया में इनका एक ही अर्थ है कि जो नहीं हारा, मतलब जीता। तुम सब मेरी बात न समझ सकोगे।

शिष्यों ने कहा, हमें समझाएं। वह तरकीब तो बता दें कि आप कैसे नहीं हारे? लाओत्से ने कहा, मुझे कोई हरा न सका, क्योंकि मैं सदा हारा हुआ था। मुझे कोई हरा न सका, क्योंकि मैंने कभी जीतना ही नहीं चाहा। असल में, मेरी लड़ाई ही खड़ी न हो सकी। मुझसे कोई लड़ने भी आया, तो मैं हारा ही हुआ था। हराने में तो उसी को मजा आता है, जो जीतना चाहता हो। जो जीतना ही नहीं चाहता, उसको हराने में क्या मजा आएगा? लाओत्से ने आगे कहा, तुम लोग दूसरी बात पूछ रहे हो। तुम पूछ रहे हो कि ऐसी कोई तरकीब बताएं, जिससे कि हम जीत जाएं। अगर तुमने जीतने की सोची, तो तुम हारोगे। जीतने की सोचने वाला हारता ही है।

लाओत्से ने आगे कहा, मेरा कभी कोई अपमान नहीं कर सका। तब एक शिष्य ने कहा, इसका भी राज बताइए, क्योंकि अपमान तो हमें भी बहुत तकलीफ देता है। लाओत्से ने उससे कहा, फिर तुमसे भूल हो रही है। है। मेरा कोई अपमान नहीं कर सका, क्योंकि मैंने मान को कोई आकांक्षा नहीं पाली। तुम्हारा अपमान होता ही रहेगा, क्योंकि तुम मान की आकांक्षा से भरे हो।

लाओत्से कहता है, जीवन का राज घास से पूछो, जिनको बड़ी से बड़ी आंधी भी उखाड़ नहीं पाती। क्या है उनका राज? वे पूरे के पूरे सुरक्षित रह जाते हैं। वे इतने कमजोर हैं कि जरा सा झोंका हवा का उन्हें तोड़ दे, पर भयंकर झंझावात चलता है और उनकी जड़ें भी नहीं हिलतीं। बड़े-बड़े वृक्ष, जिनकी गहरी जड़ें हैं जमीन में, वे धराशायी हो जाते हैं।

मुझे कोई हरा न सका, क्योंकि मैं सदा हारा हुआ था। मुझे कोई हरा न सका, क्योंकि मैंने कभी जीतना ही नहीं चाहा। जो जीतना ही नहीं चाहता, उसको हराने में क्या मजा आएगा?

पूछो, उन बड़े वृक्षों की भूल क्या थी? उन वृक्षों ने लड़ना चाहा, जीतना चाहा। बड़े वृक्षों ने झंझावात से युद्ध मोल लिया। उन्होंने कहा, हम कुछ हैं। वहीं घास के तिनके चुपचाप झुक गए। उन्होंने कोई झगड़ा ही न लिया। उन्होंने झंझावात को दुश्मन ही न माना। उन्होंने उसे प्रेम से अंगीकार कर लिया। उन्होंने उसे खेल समझा, युद्ध नहीं समझा। उन्होंने कहा- ठीक है, बह जाओ और रास्ता दे दिया।

ओशो

राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री

हमारी ओर गौर से देखो, हम वही सभ्यता हैं, जिसे मिटाने के लिए न जाने कितने आक्रांता आए। आज उन आक्रांताओं के कहीं अवशेष नहीं बचे हैं, जबकि हमारे ध्वज समंदर पार भी गगन से बातें कर रहे हैं।

अनुलोम-विलोम

विपक्ष

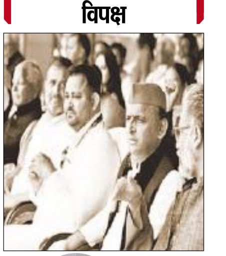

विपक्षी दलों पर लोगों को भरोसा नहीं

लोगों को विपक्षी दलों पर किंचित भी भरोसा नहीं। किसी मनोवैज्ञानिक से दरयाफ्त करें, कहीं यह खुद पर अविश्वास का सूचक तो नहीं! अमूमन लोग दूसरों के बारे में वैसी ही धारणा बनाते हैं, जैसे खुद होते हैं। मनुष्य की अपनी मानसिक सीमा होती है। मामला यहीं तक सीमित होता, तब भी कोई बात थी। बात आगे बढ़ गई है। थोड़ा सच और ढेर सारा झूठ मिलाकर ऐसे गैर-जिम्मेदाराना आरोप गढ़ लेना, जिनकी कल्पना भी सामान्य आदमी के जेहन में कठिन है। हो सकता है, ऐसा करते समय वे अपनी ही (आपराधिक) मानसिकता का परिचय दे रहे हों। उनकी कल्पना में वही आता हो, जो ऐसी स्थिति में वे खुद करते।

सब्र और जिम्मेदारीपूर्ण आलोचना तो भारतीय जनतंत्र की शब्दावली से हटा ही देनी चाहिए। फेसबुक पर भी ऐसे ही गैर-जिम्मेदार और सच-झूठ की मिलावट से निःसृत कुत्सित आरोपों से भरी पोस्ट बहुतायत में दिख जाएंगी। जैसे निखालिस इसी एजेंडे के तहत सोशल मीडिया पर अवतरित हुए हों। मगर सबसे खतरनाक पहलू दूसरा है। मीडिया-वर्चस्व के इस युग में सामान्य जनता राजनीतिक दलों से सीधे प्रभाव ग्रहण करती है। उनके नेताओं का विचलन सामान्य जनता के विचलन को आश्वस्ति प्रदान करता है। पूरे देश की चारित्रिक गिरावट का पूरा सरंजाम मौजूद है। विपक्ष की हताशा देखकर लगता तो यही है कि बेहतर विकल्प देने की सारी संभावनाएं खर्च हो चुकीं। अब तो यही कहा जाएगा कि सत्ता पक्ष जाएगा, तो अपने ही 'कर्मों', अंतर्विरोधों व कदाचारों से जाएगा। विपक्ष के बूते की बात नहीं कि उसे टस से मस कर सके।

हाल में बिहार में उन्मत्त और बेलगाम घोड़ों (मोटर साइकिलों) पर सवार युवा सेनानियों ने ऐसा समां बांधा कि लगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय का बिहार अंगड़ाई ले रहा है और बस जागने ही वाला है, मगर ढाक के वही तीन पात। 'एसआईआर' न हुआ, ब्रह्मास्त्र हो गया।

अब वही दंगल पश्चिम बंगाल में चलने वाला है। वहां एक अजेय वीरांगना का सेनापतित्व है और 'इंडिया' ब्लॉक के नामचीन और अनाम घटकों की सेनाओं का जमावड़ा। तलवारें खिंच गई हैं। उधर सीमा पार के देश में सत्ता-सदनों पर हमले आयोजित हो रहे हैं, जबकि वहां की दो वीरांगनाएं- तस्लीमा नसरीन और शेख हसीना- किसी तरह जान-बचाकर भारत की शरण में हैं। जरूरत पड़े, तो स्वयं की जान देकर शरणागत की रक्षा करना हमारा परंपरागत और परम धर्म है। जो भी हो, बंगाल का चुनाव-परिणाम हमारे विपक्षी दलों के महान गठबंधन की अग्नि-परीक्षा है, और भारत के राजनीतिक भविष्य का पूर्वराग भी।

कमलाकांत त्रिपाठी, टिप्पणीकार

सत्ता पक्ष को विपक्ष ने लगातार घेरा

आज के समय में विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस को लेकर एक निराशावादी माहौल बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया व कुछ राजनीतिक हलकों में कांग्रेस को कोसना और राहुल गांधी का उपहास उड़ाना मानो फैशन बन गया है। कहा जाता है कि कांग्रेस खत्म हो रही है, पर वास्तविकता इससे पूरी तरह अलग है। कांग्रेस को कोसने या राहुल गांधी का मजाक उड़ाने से कोई राजनीतिक सत्य सिद्ध नहीं होता; बल्कि यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की विचारधारा और विपक्ष की भूमिका से कुछ लोग असहज हैं।

सच यह है कि 2014 और 2019 की करारी हार के बाद, जब कांग्रेस संगठनात्मक रूप से टूटने के कगार पर थी, तब राहुल गांधी ने पार्टी को पूरी तरह छोड़ा नहीं। 'भारत जोड़ो यात्रा' जैसे अभियानों के माध्यम से उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आम जनता से संवाद स्थापित किया और कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर 2019 की तुलना में अपनी ताकत दोगुनी की। 'इंडिया' ब्लॉक ने भाजपा को पूर्ण बहुमत से रोका। यह लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने और उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना, सामाजिक असमानता, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरा।

निश्चय ही कांग्रेस के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। 2024 के बाद कुछ राज्यों में चुनावी हार, संगठन के भीतर मतभेद और भाजपा की सशक्त चुनावी मशीनरी के सामने संसाधनों की कमी- ये सभी वास्तविक समस्याएं हैं। पार्टी को युवाओं, महिलाओं और हाशिये पर खड़े वर्गों से और गहरे जुड़ने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर उसे अधिक स्पष्ट और आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। इतिहास गवाह है कि यह पार्टी विभाजन, आपातकाल, 1984 की त्रासदी और 2014 व 2019 की पराजय जैसे अनेक संकटों से उबर चुकी है, और हर बार उसने स्वयं को पुनर्गठित किया है। कांग्रेस को कोसने वाले यह भूल जाते हैं कि एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की रीढ़ होता है। सत्ता से सवाल पूछना, नीतियों की समीक्षा करना और वैकल्पिक दृष्टि पेश करना- यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। कांग्रेस आज भी जीवित है, क्योंकि वह जनता से जुड़ने का प्रयास कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रही है। यह मैं लोकतंत्र समर्थक होने के नाते कह रहा हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी देश में लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब सत्ता के साथ-साथ विपक्ष भी मजबूत हो।

राकेश पाण्डेय, टिप्पणीकार

मन और तन का बना रहे तालमेल

तन की लंबी बीमारियां मन को भी खोखला करने लगती हैं। डॉक्टरों के चक्कर, ढेर सारे टेस्ट, रोज की दवाएं और दूसरों पर निर्भरता मरीज को मेडिकल बर्नआउट की ओर धकेलने लगते हैं। यहां तक कि मामूली खांसी-जुकाम या सूजन का भी लंबे समय तक बने रहना मूड बिगाड़ देता है। तन और मन के संतुलन का ध्यान रखना कितना जरूरी है, बता रही हैं तृप्ति मिश्रा

अक्सर तन और मन की सेहत को अलग मान लिया जाता है। अगर किसी को घबराहट, उदासी या डर है, तो उसे मन का वहम कह दिया जाता है। अगर शरीर में बीमारी है, तो इलाज केवल दवा तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय शोध लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तन और मन की सेहत अलग नहीं एक दूसरे की पूरक है।

मेडिकल बर्नआउट को समझना जरूरी

हार्वर्ड हेल्थ के अध्ययन बताते हैं कि लंबी बीमारी और इसका इलाज चलने से व्यक्ति में मेडिकल बर्नआउट पैदा होता है। बीमारी चाहे लिवर से जुड़ी हो या मामूली समझे जाने वाले खांसी-जुकाम से। अगर ये लंबे समय से हैं, तो मन को जरूर प्रभावित करेंगी। ऐसे रोगियों में मानसिक समस्याओं का खतरा 40 फीसदी अधिक होता है। पीड़ित धीरे-धीरे अपनी पहचान, आत्मविश्वास और सामाजिक भूमिका खोने लगता है। जब बार-बार टेस्ट, दवाएं, परहेज और सावधानियां जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तो मन के भीतर यह सवाल उठने लगता है- 'क्या मैं अब पहले जैसा कभी हो पाऊंगा?' मरीज 'हमेशा बीमार' वाली पहचान से खुद को जोड़ लेता है। जिसके लक्षण कई रूपों में सामने आते हैं, जैसे- मानसिक थकान, ऊर्जा में कमी, उलझन, कमजोर याद्दाश्त, बेचैनी, अनजाना डर, चिड़चिड़ापन, उदासी, एकाग्रता में कमी, अरुचि, हीन भावना व सामाजिक दूरी आदि। विशेषज्ञों के अनुसार तन के रोगों में मन को स्वस्थ बनाए रखना और मन की परेशानियों में शरीर की सेहत का ध्यान रखना समस्या को गंभीर होने से बचाता है।

तन से जुड़ी मन की सेहत

डायबिटीज: अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के शोध के अनुसार डायबिटीज से जूझ रहे मरीजों में डिप्रेशन का खतरा सामान्य से 2 गुना ज्यादा होता है। पीड़ित में हर 4 में से 1 मानसिक थकान से जूझता है। लंबे समय तक बढ़ी हुई शुगर दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे भावनाओं को नियंत्रित करने वाले हिस्से तक ठीक से संकेत प्रेषित नहीं होते। इंसुलिन का असंतुलन डोपामाइन को प्रभावित करता है, जिससे खुशी का अहसास करने की क्षमता घटती है। व्यक्ति में निराशा बढ़ने लगती है।

हृदय रोग: अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, 30-40% हृदय रोगियों में बेचैनी और अवसाद के लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे मरीजों में दिमाग तक पहुंचने वाला खून और ऑक्सीजन असंतुलित होकर मस्तिष्क को अति संवेदनशील बना देते हैं। इसी कारण दिल के मरीजों में डर, बेचैनी और अचानक घबराहट की शिकायतें ज्यादा होती हैं।

> **40**
> फीसदी अवसाद का खतरा बढ़ जाता है लंबी बीमारियों के इलाज की ऊब के कारण, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार

ऑटोइम्यून बीमारियां: ऑटोइम्यून रोगों (गठिया, ल्यूपस, सोरायसिस, ऑटोइम्यून थायरॉइड आदि) में हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र अपने ही अंगों पर हमला करने लगता है। शरीर में लगातार सूजन व दर्द रहता है। नेचर रिव्यू इम्यूनोलॉजी का अध्ययन बताता है सूजनकारी तत्व मूड कंट्रोल सिस्टम को प्रभावित कर डिप्रेशन जैसे व्यवहार को ट्रिगर करते हैं। ऐसे में डिप्रेशन का खतरा 45% ज्यादा बढ़ जाता है।

कैंसर: जर्नल ऑफ क्लीनिकल ऑन्कोलॉजी के अनुसार, हर 3 में से 1 कैंसर रोगी गंभीर मानसिक तनाव में है। इस दौरान शरीर में बनने वाले रसायन दिमाग के तनाव केंद्र को सक्रिय करते हैं। इसके मरीज में बिना स्पष्ट कारण डर, भविष्य को लेकर बेचैनी व भावनात्मक टूटन बढ़ती है।

पाचन संबंधी परेशानियां: गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विशेषज्ञों के अनुसार, पाचन तंत्र रोगों (आईबीएस, आईबीडी, पुरानी कब्ज या दस्त, गैस, उफार, एसिडिटी, सूजन, कमजोर जठराग्नि/मेटाबॉलिज्म) से जूझ रहे 70-80% मरीजों में बेचैनी या डिप्रेशन आम हैं। हमारे शरीर में 90% सेरोटोनिन (खुशी से जुड़ा हार्मोन) आंतों में बनता है। खराब पाचन से सेरोटोनिन और गाबा जैसे रसायन कम हो जाते हैं। अगर पाचन तंत्र गड़बड़ है, तो मन का असंतुलित होना तय है।

हार्मोनल असंतुलन: हार्मोन असंतुलन से दिमाग का एमिग्डाला (डर का केंद्र) हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जिससे छोटी-छोटी बातों में मूड स्विंग्स होते हैं। हार्मोनल समस्याओं में थायरॉइड, पीसीओएस/पीसीओडी, मेनोपॉज, एड्रिनल थकावट जैसी परेशानियां शामिल हैं। महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन ज्यादा होता है, जिससे उनमें डिप्रेशन का जोखिम सामान्य से दोगुना होता है।

क्रॉनिक पेन: लगातार रहने वाला दर्द, चाहे वह पीठ का हो, जोड़ों का हो या सिर दर्द मन पर गहरा असर डालता है। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च में छपी रिपोर्ट के अनुसार क्रॉनिक पेन से पीड़ित हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी मानसिक परेशानी से जूझता है। डिप्रेशन का खतरा बढ़ता है।

क्रॉनिक फटीग: मेयो क्लिनिक के अध्ययनों के अनुसार, लगातार थकान, कमजोरी व ऊर्जा की कमी से दिमाग 'खतरे की अवस्था' में चला जाता है। इससे चिंता, बेचैनी लाचारी का भाव और आत्म-संदेह बढ़ता है।

नींद की कमी: स्लीप मेडिसिन रिव्यू के अनुसार, 2-3 हफ्ते की खराब नींद भी दिमाग की निर्णय क्षमता कमजोर कर देती है। नींद की कमी से दिमाग का इमोशनल फिल्टर टूट जाता है और व्यक्ति नकारात्मक होने लगता है।

खांसी जुकाम: खांसी-जुकाम से नींद पर असर पड़ता है। इससे तनावकारी हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। व्यक्ति चिड़चिड़ा, थका हुआ और मानसिक रूप से सुस्त महसूस करता है। गंभीर बीमारी होने की आशंका में व्यक्ति की बेचैनी बढ़ जाती है। यह बेचैनी खांसी को और बढ़ा देती है। व्यक्ति बोलने और मिलने-जुलने से बचता है। लगातार संक्रमण से लड़ने के कारण शरीर में साइटोकिन्स रसायन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे प्रेरणा की कमी व उदासी बढ़ सकती है।

हमारे विशेषज्ञ:
डॉ. अक्षय चुग (कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन), मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा। **डॉ. अमृता शर्मा,** अमृतम आयुर्वेद क्लिनिक, नोएडा। **वैद्य स्वाति त्यागी,** इम्यूनिटी क्लीनिक, भारतीय धरोहर वैद्यशाला, नोएडा

आयुर्वेदिक उपायों को अपनाएं

आज गंभीर और पुरानी बीमारियों में एलोपैथिक इलाज के साथ आयुर्वेद और नेचुरोपैथी थेरेपी को सहायक उपचार के रूप में अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। शोधों के अनुसार शिरोधारा जैसी थेरेपी मस्तिष्क के तनाव केंद्र को शांत कर नींद और भावनात्मक संतुलन में मदद करती है, वहीं नस्य क्रिया (नाक में घी, तेल डालना) से दिमाग पर सीधा असर डालकर चिंता और बेचैनी कम करने में मदद मिलती है। अश्वगंधा, ब्राह्मी और शंखपुष्पी जैसी जड़ी-बूटियां तनाव हार्मोन नियंत्रित कर शरीर को मजबूती देती हैं। नियमित ध्यान, गहरी सांसें लेना, तेल मालिश, गाय के घी का सेवन जैसे उपाय तन-मन बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं।

मन की बीमारी तन पर भारी

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में लगभग 28 करोड़ लोग अवसाद (डिप्रेशन) जैसे मानसिक रोगों का सामना कर रहे हैं और लगातार तनाव इसका मुख्य कारण है। यह शरीर में न केवल ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ता है, बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) भी कमजोर कर देता है। साथ ही तनाव दिमाग की भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को भी कम करता है, जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। यूके बायो बैंक जैसे अध्ययन बताते हैं कि अवसाद वाले लोगों में मधुमेह, हृदय रोग और गठिया जैसे रोग अधिक देखने को मिलते हैं। लगातार मानसिक तनाव झेलने वाले लोगों में हृदय रोग का खतरा 30-40% तक बढ़ जाता है। क्रोनिक तनाव और चिंता से जूझ रहे लोगों में नींद की समस्याएं 2 से 3 गुना अधिक होती हैं। मन का ठीक न होना रोगों के ठीक होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है।

तन और मन बने रहेंगे मजबूत

- नियमित दिनचर्या रखें। समय पर संतुलित भोजन करें। गुनगुना पानी पिएं।
- अकेले न रहें। मन की बात साझा करें।
- रोज पैदल चलें। व्यायाम करें। धूप और खुली हवा में समय बिताएं।
- अनावश्यक तनाव व डराने वाली सूचनाओं से दूरी रखें। नींद पूरी करें।
- सेहत व नियमित जांच की अनदेखी न करें।

बड़े-बुजुर्गों में टीकाकरण की अहमियत समझना जरूरी

नए साल के सेहत संकल्पों में अक्सर भोजन, व्यायाम और तनाव प्रबंधन की चर्चा होती है। इस कड़ी में बड़ों में टीकाकरण को शामिल करना कितना जरूरी है, बता रहे हैं रुमेटोलॉजिस्ट डॉ. श्यामाशीष बंद्योपाध्याय

बहुत से लोग मानते हैं कि टीके केवल बच्चों के लिए होते हैं। हालांकि, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने लगती है, जिससे हम संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। वयस्कों में टीकाकरण लंबे समय तक स्वस्थ रहने का प्रभावी और सरल उपाय है। इससे सेहत समस्याओं को गंभीर होने से बचा जा सकता है। इसके तीन कारण हैं-

1. मौसमी संक्रमण

इन्फ्लुएंजा, फ्लू जैसे मौसमी संक्रमण सामान्य लग सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये बेहद गंभीर हो सकते हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, मधुमेह, सीओपीडी व हृदय रोग जैसी स्थितियों के साथ जी रहे लोगों में रोगों के गंभीर होने और अस्पताल में भर्ती होने की आशंका अधिक होती है।

फ्लू की एक बार चपेट में आना हफ्तों तक चलने वाली कमजोरी, सांस फूलने और थकान का कारण बन सकता है। इससे लोगों की सक्रियता कम होने लगती है। रोज के काम करना कठिन हो जाते हैं और दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है। फ्लू के वायरस हर साल बदलते हैं, इसलिए टीके की दवा भी बदल जाती है। समय पर टीकाकरण बुजुर्गों को सक्रिय रहने, अस्पताल के चक्करों से बचने में मदद करता है।

2. परिवार का भी बचाव

एक संक्रमण जो परिवार के एक सदस्य में हल्के लक्षण पैदा करता है, वह दूसरे के लिए गंभीर हो सकता है। खासकर शिशुओं, गर्भवती महिलाओं या कमजोर प्रतिरक्षा वाले बुजुर्गों में संक्रमण गंभीर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 'शिंगल्स' स्वयं संक्रामक नहीं है, लेकिन इसका वायरस उन लोगों में चिकनपॉक्स का कारण बन सकता है, जिनकी प्रतिरक्षा कम है। यह बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। बुजुर्गों में टीकाकरण को बढ़ावा देना परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी सुरक्षा कवच बन सकता है।

3. पुरानी बीमारियों पर बना रहे काबू

किसी पुरानी बीमारी के प्रबंधन के लिए निरंतर ध्यान, दवा और जीवनशैली में बदलाव की जरूरत होती है। जब फ्लू या शिंगल्स जैसे संक्रमण होते हैं, तो पुरानी स्थितियां काबू रखने में दिक्कत आती है। जैसे फ्लू से दमा का दौरा बढ़ सकता है या हृदय की स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं, मधुमेह के रोगियों में शिंगल्स के कारण ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है, भले ही वे अपना उपचार सही ढंग से ले रहे हों।

अध्ययन बताते हैं कि संक्रमण से शरीर में सूजन और तनाव बढ़ता है। नियमित टीकाकरण संक्रमण के जोखिम को कम करता है। साथ ही एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत भी कम हो जाती है।

सवाल-जवाब

गठिया का दर्द हो, तो ज्यादा साइकिल न चलाएं

डॉ. साइमन थॉमस
डायरेक्टर, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग

■ **सवाल : मेरी उम्र 35 साल है। मुझे ऑस्टियो-आर्थराइटिस है। साइकिल चलाने के कारण मेरी जांघों की नसों में खिंचाव आ गया है। जांघ की नसें मोटी हो गई हैं। जांघें पतली लगती हैं। इसका उपचार बताएं।**

जवाब : इस उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आपको अपने जोड़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। गठिया का इलाज स्पेशलिस्ट से ही कराएं। नियमित व्यायाम ऑस्टियो-आर्थराइटिस में संजीवनी का काम करता है। आप साइकिल चलाते हैं, यह अच्छी बात है। यह कूल्हे और घुटनों के लिए अच्छा व्यायाम है, लेकिन बहुत अधिक साइकिल चलाना नुकसान कर सकता है। खासकर, अगर आपने अचानक खूब साइकिल चलाना शुरू किया है।

खराब पॉस्चर में साइकिल चलाने से भी खिंचाव आ सकता है। अगर आप कुछ दिन साइक्लिंग करना छोड़ दें, तो यह समस्या ठीक हो जाएगी। उसके बाद दोबारा साइकिल चलाना शुरू करें। धीरे-धीरे समय और गति बढ़ाएं। ऑस्टियो-आर्थराइटिस में मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। ऐसे में ज्यादा जोर पड़ने पर मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। कुछ खिंचाव मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और यह व्यायाम सीखें। जांघ की गर्म सिकाई दिन में दो से तीन बार 10 से 15 मिनट करें। इससे आराम मिलेगा। डॉक्टर की बताई कुछ दर्द निवारक दवाएं लें। इससे 4 से 5 दिनों में अंदरूनी सूजन कम हो जाएगी। खिंचाव कम होगा। इसके लिए अपने चिकित्सक से संपर्क करें।

जांघ का पतला होना मांसपेशियों की कमजोरी की निशानी भी है। कई बार इसकी वजह से भी नसें मोटी नजर आती हैं। आमतौर पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, लेकिन इस वजह से दिक्कत महसूस होती है या नसों में उभार बढ़ता हुआ लगता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अपने डॉक्टर से मिलें, वे जरूरत महसूस होने पर कुछ टेस्ट करा सकते हैं। प्रेशर स्टाकिंस पहनने से भी इसमें आराम मिल सकता है। दवाओं से भी राहत मिलती है।

मांसपेशियों को मजबूत रखना जरूरी है। कैल्शियम और विटामिन डी इसमें खासी भूमिका निभाते हैं। जांच में अगर इनकी कमी आती है, तो इनकी दवाएं आती हैं। साथ ही रोज आधा घंटा शरीर को धूप लगाएं।

जब तक आराम न हो, ज्यादा व्यायाम न करें। भारतीय शौचालय का इस्तेमाल न करें। जमीन पर बैठ कर काम करने से बचें।

■ **सवाल : सर्दियों में मुझे पैर में बहुत दर्द रहता है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द में गर्म सिकाई फायदेमंद है या ठंडी। कृपया बताएं?**

जवाब : अगर दर्द लगातार बढ़ रहा हो, सूजन, लालिमा या जकड़न ज्यादा रहती है और सुबह की अकड़न 1 घंटे से ज्यादा रहे या चलने-फिरने में दिक्कत आने लगे, तो अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें।

गरम पानी की सिकाई दिन में दो से तीन बार 15 से 20 मिनट करें। आधे घंटे धूप का सेवन जोड़ों के दर्द में राहत देता है। सर्दी में अपने शरीर को, जोड़ों को ढक कर रखें, गरम कपड़े पहनें, इससे अकड़न और दर्द कम होगा। विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने से भी फायदा होगा।

सामान्यतः अगर कोई चोट लगी हो या नया दर्द हो और उसके कारण सूजन हो, तो बर्फ की सिकाई बताई जाती है। शेष स्थितियों में लंबे समय से चले आ रहे दर्द, खासतौर पर सर्दी के मौसम में जोड़ों के दर्द में गरम सिकाई राहत देती है। इसे गरम पानी की बोतल से, हीटिंग पैड से, गरम पानी में भीगे तौलिये आदि तरीकों से किया जा सकता है।

भेजें अपने सवाल

सेहत से जुड़े सवाल **tanmanhindustan@gmail.com** पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं-
तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आय में वृद्धि भी होगी।

वृष : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। आय में वृद्धि होगी।

मिथुन : दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। मीठे खानपान में रुचि बढ़ेगी।

कर्क : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भवन के रख-रखाव तथा साज-सज्जा पर खर्च बढ़ सकते हैं।

सिंह : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु संयत भी रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। क्रोध से बचें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं।

कन्या : आत्मविश्वास बहुत रहेगा। शैक्षिक व शोधादि कार्यों में सफल रहेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। भागदौड़ बढ़ेगी।

तुला : मन परेशान रहेगा। नौकरी में बदलाव की संभावना बन रही है। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें।

वृश्चिक : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

धनु : आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। कारोबार में लाभ के मौके मिलेंगे।

मकर : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। आय में कमी व खर्च अधिक की स्थिति हो सकती है। कारोबार में कठिनाई आ सकती है।

कुंभ : संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन : आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। आत्मसंयत रहें। शांति बनाए रखने के प्रयास करें। नौकरी में बदलाव हो सकता है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

02 जनवरी, शुक्रवार **शक संवत्:** 12 पौष (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग:** 19 पौष मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम:** 12 रज्जब, 1447, **विक्रमी संवत्:** पौष शुक्ल चतुर्दशी तिथि सायं 06.54 बजे तक पश्चात पूर्णिमा तिथि, मृगशीर्ष नक्षत्र रात्रि 08.04 बजे तक, चंद्रमा वृष राशि में प्रातः 09.26 बजे तक उपरांत मिथुन राशि में। **सूर्य दक्षिणायन।** सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सायं 06.54 बजे से सूर्योदय पूर्व 05.14 बजे तक। ईशान व्रत। श्री सत्यनारायण व्रत।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया कुछ ऐसे उपाय बताएं, जो कि हमारी समस्याओं को कुछ कम करें।
-सुकीर्ति झा, देवघर

- यदि मानसिक तनाव है, तो सोमवार को दीपक में थोड़े से चावल डालें।
- यदि किसी संकट की आशंका है, तो मंगलवार को दीपक में लौंग डालें।
- यदि व्यापार में समस्या आ रही है, तो बुधवार को दीपक में हरी इलायची डालें।
- यदि धन की समस्या आ रही है, तो गुरुवार को दीपक में हल्दी और चावल डालें।
- यदि एश्वर्य की प्राप्ति करनी हो, तो शुक्रवार को दीपक में चावल और लौंग डालें।
- यदि रुकावटें ज्यादा आ रही हैं, तो दीपक में काले तिल एवं लौंग डालें।

वर्ग पहेली : 8197

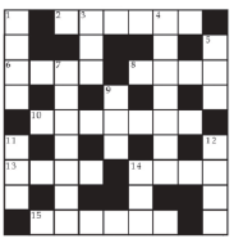

बाएं से दाएं
2. गुप्त रूप से; चोरी-चोरी; छिपकर; बिना बताए (3,3)
6. कारागृह; कैदखाना; बंदीगृह (4)
8. पीछा करते हुए दूर तक भगाना; हटाना (4)
10. बहाना; धारा में छोड़ना; चिंता करना; ध्यान रखना (4,3)
13. वर्षा; बारिश (4)
14. कुरीति; कदाचार; दुराचार (4)
15. जांचना; पहचान करना (3,3)

ऊपर से नीचे
1. विश्राम काल; छुट्टी; अवसर; समय (4)
3. कठोर पदार्थ; कठोर पिंड; प्रस्तर (3)
4. गुप्त रखना; परदा कराना; स्त्रियों को घर से बाहर न निकलने देना (3,1,3)
5. अज्ञात; अप्रसिद्ध; अविख्यात; नामहीन; बिना नाम का (3)
7. थोड़े शब्दों में कही गई महत्वपूर्ण बात; कम शब्दों में की गई भावाभिव्यक्ति (3,1,3)
9. नगरवासी; शहर का; शहर से संबंधित (3)
11. जिसके साथ सेना हो; बलशाली; शक्तिशाली (3)
12. पत्रवाहक; डाकिया (4)
14. अत्यधिक; असीम; जिसका कोई पार न हो (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8196

सुडोकू : 8179

*आसान

8		2				7		4
	5			2			9	
9			8		5			3
		7	1	8	2	9		
		5	9	6	4	3		
6			5		3			2
	3			1			6	
5		9				1		8

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8178

2	6	8	7	3	1	9	5	4
7	5	4	2	9	8	3	1	6
9	3	1	4	6	5	8	7	2
5	9	6	1	4	3	2	8	7
3	4	7	5	8	2	1	6	9
8	1	2	9	7	6	5	4	3
4	2	9	8	5	7	6	3	1
6	7	5	3	1	9	4	2	8
1	8	3	6	2	4	7	9	5

संपादकीय

हमसे जुड़ने के लिए QR Code स्कैन करें

दैनिक नवज्योति
आपके लिए, आपके साथ
dainiknavajyoti.com
जोधपुर, शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026

90 विश्वसनीयता के dainiknavajyoti.com

इंदौर में दूषित जल से मौतें

देश में स्वच्छ शहर के मामले में कई वर्षों से लगातार सबसे अव्वल स्थान पर रहने वाले मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी के सेवन से ग्यारह लोगों की मौत हो गई। एक हजार से अधिक लोग बीमार हो गए। जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। त्रासदी ऐसे अवसर पर हुई जब पूरी दुनिया नए वर्ष के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई थी। हादसे के बाद शहर में भय और आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर भारी रोष भी जाहिर किया। शहर के भागीरथपुरा इलाके की यह घटना जल-प्रदूषण के खतरों की ओर इशारा करती है। जो शहरों में जलापूर्ति व्यवस्था की नियमित और पर्याप्त निगरानी के अभाव का अहसास कराती है। अधिकांश शहरों में पानी की पुरानी पाइप लाइनें होने, इनकी टूट-फूट की समय पर मरम्मत नहीं होने की शिकायतें भी आम हैं। ऐसी क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों में प्रदूषित पदार्थों के प्रवेश से लोगों में हैजा, दस्त, टीबी, उल्टी-दस्त, टाइफाइड एवं अन्य पेट के विकार फैल जाते हैं। विभिन्न शहरों, गांवों और देहातों से ऐसी खबरें आए दिन सुनने और पढ़ने को मिल जाती हैं। विश्व बैंक के अनुसार देश को हर साल जल-प्रदूषण से अपनी जीडीपी का लगभग 3 फीसदी हिस्सा गंवाना पड़ता है। हरों में प्रदूषित होने वाला जल, सतह से गुजरकर भू-जल में भी जहर घोल रहा है। नदी-नालों में गिरकर उन्हें भी प्रदूषित कर रहा है। हर साल गर्मियों और बारिश के मौसम में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दूषित पानी के सेवन से मरने और बीमार होने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। लेकिन इंदौर में इस त्रासदी के पीछे संबंधित विभागों की घोर लापरवाही सामने आई है। हालांकि राज्य सरकार ने इस हादसे के तुरंत बाद पूरे मामले की प्रशासनिक जांच करने के आदेश दे दिए हैं। बीमारों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। नगर निगम ने पानी की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की जिसने जांच शुरू कर दी है। लापरवाही के आरोप में तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रभावित इलाकों में टैंकरों के जरिए स्वच्छ पानी वितरित किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस घटना पर गंभीरता दिखाई है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस त्रासदी पर स्वतः प्रसंज्ञान लेकर इस हादसे की वास्तविक रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि भागीरथपुरा क्षेत्र की पुलिस चौकी के पास बने शौचालय के नीचे स्थित नर्मदा मुख्य पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने पर गंदा पानी सीधे स्वच्छ पीने के पानी की लाइन में चला गया जिससे घर-घर दूषित पानी पहुंचा। पानी का स्वाद कड़वा होने की शिकायतें आने पर जलप्रदाय विभाग की ओर से अतिरिक्त जलशोधक रसायनों का प्रयोग किया गया। पूरा ध्यान भौतिक प्रदूषण और क्लोरीन की कमी पर केंद्रित रहा न कि रोग के फैलने के कारणों पर।

भारत की परिवार परम्परा दुनिया के लिए अनुकरणीय

पारिवारिक परंपरा को बोझ नहीं, समाधान समझें

दृष्टिकोण

"भारत ने तो वसुधैव कुटुम्बकम् का उद्घोष करते हुए समूची दुनिया को एक परिवार ही माना है। वैसे भारत की परिवार परम्परा दुनिया के लिये अनुकरणीय है। हम सभी एक परिवार हैं, चाहे हमारी नागरिकता, धर्म, जाति, सीमाएं या नस्ल कुछ भी हो। समग्र मानव जाति को एक साथ आना चाहिए और प्रेम और शान्ति में विश्वास करना चाहिए।

समग्र विश्व एक वैश्विक ग्राम है और हम सभी इस बृहतपरिवार का हिस्सा हैं। भारत ने तो वसुधैव कुटुम्बकम् का उद्घोष करते हुए समूची दुनिया को एक परिवार ही माना है। वैसे भारत की परिवार परम्परा दुनिया के लिये अनुकरणीय है। हम सभी एक परिवार हैं, चाहे हमारी नागरिकता, धर्म, जाति, सीमाएं या नस्ल कुछ भी हो। समग्र मानव जाति को एक साथ आना चाहिए और प्रेम और शान्ति में विश्वास करना चाहिए और विश्व में सुख और आशा लाने हेतु इसका अभ्यास करना चाहिए। संसार संघर्षों, युद्धों, उपद्रवों, कष्ट और पीड़ा से भरा पड़ा है। यदि हम सभी एक साथ आएं और दुनिया को प्रेम और धैर्य से ठीक करें, तो हम सभी खुशी से और अपने हृदयों में आशा के साथ रह सकते हैं। वैश्विक परिवार दिवस विविधता एवं एकता और विश्व शान्ति और अहिंसा महत्व के बारे में जागरूकता लाता है।

परिवार की भूमिका

परिवार की भूमिका, उसकी बदलती संरचना और सामाजिक प्रासंगिकता आधुनिक समाज की सबसे गहरी विडंबनाओं और चुनौतियों को उजागर करने वाला एक चिंतन बन गया है। परिवार मानव जीवन की वह मूल इकाई है, जहां व्यक्ति का भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक निर्माण होता है। भारतीय संदर्भ में परिवार केवल रक्त-संबंधों का समूह नहीं रहा, बल्कि वह संस्कारों की पाठशाला, शांति, सहयोग एवं सौहार्द की प्रयोगभूमि और जीवन-मूल्यों का आधार रहा है। इसी परिवार-परंपरा ने भारत को सदियों तक सामाजिक स्थिरता, अहिंसा, सहिष्णुता और मानवीय करुणा का देश बनाए रखा। आज विडंबना यह है कि जिस भारतीय परिवार व्यवस्था को दुनिया एक आदर्श मॉडल के रूप में देख रही है।

उपभोक्तावादी जीवनशैली

वैश्वीकरण, शहरीकरण, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावादी जीवनशैली ने परिवार को सुविधा केंद्रित इकाई में बदल दिया है। संयुक्त परिवारों का विघटन, एकल परिवारों का बढ़ना और रिश्तों में औपचारिकता का प्रवेश इस परिवर्तन की स्पष्ट पहचान है। माता-पिता दोनों के कार्यरत होने की स्थिति में बच्चों के साथ समय बिताना एक चुनौती बन गया है। परिणामस्वरूप बचपन, जो कभी परिवार के स्नेह, संवाद और अनुभवों से संवरता था, आज स्क्रीन, अकेलेपन और भावनात्मक रिक्तता के बीच पनप रहा है। बच्चों के जीवन में माता-पिता की अनुपस्थिति केवल समय की कमी नहीं है, बल्कि वह सुरक्षा, संवाद और मार्गदर्शन की कमी भी है। परिवार का वह सहज वातावरण, जहां प्रश्न पूछे जा सकते थे, गलतियां स्वीकार की जा सकती थीं और भावनाएं साझा की जा सकती थीं, आज धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है। बुजुर्ग, जो कभी परिवार की धुरी हुआ करते थे, अनुभव और संस्कार के संवाहक थे, आज कई घरों में हाशिये पर खड़े दिखाई देते हैं।

वैश्विक स्तर पर

उनके पास समय नहीं, धैर्य नहीं और कभी-कभी सम्मान भी नहीं बचा। यह स्थिति केवल पीढ़ियों के बीच दूरी नहीं बढ़ा रही, बल्कि समाज को उसके नैतिक आधार से भी वंचित कर रही है। दूसरी ओर, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वैश्विक स्तर पर आज परिवार की भूमिका को नए सिरे से समझा जा रहा है। पश्चिमी देशों में, जहां अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने सामाजिक अकेलेपन को जन्म दिया, अब परिवार, साझेदारी और सामूहिक जीवन की पुनर्स्थापना पर गंभीर विमर्श हो रहा है। परिवार केवल निजी जीवन की इकाई नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और सामाजिक संतुलन की आधारशिला भी है। दुनिया भर में संस्कृतियां और धर्म अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी मानव जाति एक बड़ा परिवार है, जो एकजुट होकर ही जीवित रह सकती है। परिवार के साथ शिक्षा और कल्याण ही भविष्य की ओर संकेत करता है कि परिवार की भूमिका केवल बच्चों को पालने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह शिक्षा का पहला केंद्र और कल्याण का स्थायी आधार है।

जीने की संस्कृति

परिवार की प्रासंगिकता इसी बिंदु पर सबसे अधिक उभरकर सामने आती है कि परिवार केवल रहने की व्यवस्था नहीं, बल्कि जीने की संस्कृति है। परिवार में बिताया गया समय निवेश है, व्यय नहीं। बच्चों के साथ संवाद, बुजुर्गों के साथ सहभागिता और रिश्तों के बीच संवेदनशीलता समाज के दीर्घकालिक स्वास्थ्य की गारंटी है। यदि आज परिवार टूट रहे हैं, तो उसका प्रभाव केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह सामाजिक असंतुलन, मानसिक तनाव और मूल्यहीनता के रूप में व्यापक रूप से सामने आएगा। इस संदर्भ में आवश्यक है कि हम परिवार को नए दृष्टिकोण से देखें। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित किया जाए।

शांत और सहयोगी

बुजुर्गों को केवल सहारा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक के रूप में पुनः स्वीकार किया जाए। परिवार ही हमें यह सिखाता है कि परिवार जितना सशक्त होगा, समाज उतना ही शांत और सहयोगी बनेगा। परिवारों में संवाद होगा तो समाज में टकराव कम होंगे। परिवारों में साझेदारी होगी, तो सहयोग की भावना मजबूत होगी। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपनी पारिवारिक परंपरा को बोझ नहीं, बल्कि वैश्विक समाधान के रूप में देखे। अंततः परिवार हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। यदि परिवार सशक्त हुए तो शांति, साझेदारी और मानवीय मूल्यों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।

-ललित गर्ग

यह लेखक के अपने विचार हैं।

जीवन बोध

मनुष्य को जीवन

मनुष्य चलेगा, तो गिरेगा भी और गिरेगा, तो उठेगा भी। यह तो जीवन में चलता ही रहता है। यही जीवन है। पर मनुष्य को जीवन की प्रत्येक घटना को साक्षीभाव से देखते हुए चलना चाहिए, उस घटना से सबक लेना चाहिए और वह घटना फिर से न हो, यह ध्यान रखना चाहिए। अपने भूतकाल के जख्मों को कुरेदते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुरेदते रहे, तो फिर अपने जख्मों को कुरेदना ही स्वभाव बन जाएगा और जख्म कभी भी भर नहीं पाएंगे। कई लोग उन जख्मों को कुरेदते-कुरेदते इतने आदी हो गए हैं कि बिना जख्मों के जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यानि चित्त मनुष्यजीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें अच्छा हो या बुरा, वह उस चित्त में स्थान को घेरता है। वर्तमान में सफल जीवन व्यतीत करने के लिए चित्त का खाली होना अत्यंत आवश्यक है। चित्त खाली होगा, तो शुद्ध होगा, उसमें अच्छे या बुरे, कोई व्यक्ति नहीं होंगे। और खाली होगा, तो ही पवित्र होगा और पवित्र होगा, तो ही सशक्त होगा और सशक्त होगा, तो ही वह परमात्मा की शक्तियों से जुड़ सकता है। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में छोटे-छोटे प्राणकणों के रूप में फैला हुआ है। और इसी प्राणशक्ति के कणों की सामूहिकता के साथ जुड़ जाते हैं।

-शिवकृपानंद स्वामी

जल तरंग

दो नहीं तीन या चार

असमंजस रहता है, पता नहीं चल पाता कि रत्न मिलेगा या लक्ष्मी आएगी। सुना है जिम्मेदारी से भरा खर्चीला काम है, लेकिन संजीदा कोशिश करो तो कौन सा काम है, जो नहीं हो सकता। जोखिम तो है। महत्वपूर्ण, जरूरी, बड़े और जोखिम भरे कामों में सफलता हासिल करने के लिए कई चीजें निवेश करनी पड़ती हैं। एक लक्ष्मी और एक रत्न सहजता से मिल जाए, तो आम व्यक्ति, सामान्य तौर पर पंगा नहीं लेता। मान लिया जाता है कि परिवार पूरा हो गया। देश की जनसंख्या घटाने में कुछ सहयोग भी हो जाता है। परिवार में लक्ष्मी और दुर्गा पधार चुकी हों, तो भी संपन्न व्यक्ति एक प्रयास और जरूर करता है। सामान्य कमजोर आर्थिकी वाला बंदा ऐसा करे तो पंगा कहा जाता है, लेकिन स्थिति और सोच अपनी अपनी होती है। कई दम्पत्ति एक ही शिशु पैदा करते हैं, चाहे लक्ष्मी मिले या रत्न। सारा खेल पैसे का है। समझदारी भी काफी काम करती है। कभी समझदारी भी न पिघलने वाली बर्फ की तरह जम जाती है। कुछ परिवारों के दो बच्चों में से जो बच्चा किसी भी तरह विदेश जा पा रहा है, जा रहा है। बच्चों में से अगर एक पुत्र है और वह विदेश चला जाता है, तो माता पिता को एक दूसरे के सहारे रहना, खाना, पीना और जीना पड़ता है। दूसरा बच्चा बेटी हो तो वह अपना परिवार, घरबार और ससुराल देखती है। वैसे भी अगर एक बच्चा विदेश में न होकर, देश में भी दूर नौकरी करता है, तो जरूरी नहीं कि माता पिता उसके परिवार के साथ रह पाते हैं। उन्हें तब भी एक दूसरे के साथ और सहारे रहना होता है। तीसरा बच्चा और हो तो सुविधा रहती है। लड़ाई झगड़ा करना हो, किसी को पीटना हो तो तीन या चार बच्चे ठीक रहते हैं। आजकल कोई बाहरी व्यक्ति, किसी की लड़ाई में अपनी टांग नहीं फंसाना चाहता इसलिए दो नहीं तीन या चार बच्चे हों तो बेहतर रहता है। किसी भी कीमत पर दो बच्चे अपने पास रखना व्यावहारिक है, ताकि संस्कृति, परम्परा अनुसार बुढ़ापे का सहारा बने। अगर बुरे समय के कारण कुछ अप्रत्याशित हो जाए, तो एक बच्चा तो सलामत रहे। पहला बच्चा अभिभावकों की बात नहीं मानेगा तो तीसरा या चौथा तो मान सकता है। मातापिता के ही ख्वाब पूरे करने के लिए तीन या चार में से एक बच्चा तो कोशिश कर ही सकता है। यह काम अब सामाजिक स्तर पर आसान हो गया है। कहा जा रहा है कि बच्चे तो तीन या चार ही पैदा करने चाहिए। आग्रह करने वाले समझदार हैं। दूर की सोच पोषित कर सकने में सक्षम हैं तभी तो ऐसा कह रहे हैं। उनके अनुसार कम बच्चे वालों के परिवार से जुड़े समाज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उन्होंने समझाया कि जनसंख्या देश के लिए बोझ और अवसर दोनों हैं। बोझ तो उन परिवारों के लिए है, जहां भारत का रोटी, कपड़ा और मकान सीरियल चल रहा है। वैसे इस मामले में मुफ्त प्रायोजक मिलते रहे हैं।

-संतोष उत्सुक

यह लेखक के अपने विचार हैं।

आज का विचार

वक्त अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता है पर बातें, घटनाएं और लोग हमेशा याद रहते हैं। अच्छे वचन, व्यवहार, संकल्प के साथ नव उत्कर्ष, नव हर्ष हमेशा बना रहे।

-श्री चंद्रप्रभ जी

विंडो टू द वर्ल्ड

गुजरात का खिजड़िया पक्षी अभयारण्य

जामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खिजड़िया पक्षी अभयारण्यहै । इस अभ्यारण्य में 300 से अधिक प्रकार के प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। यह अभयारण्य 605 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य को वर्ष 1982 में सभी प्रकार के पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल घोषित किया गया था।

हेल्थ इज वेल्थ

- ताजे फल खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं।
- इसलिए अपनी डाइट में फलों को शामिल किरें।
- फलों में कई तरह के विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं।
- इनकी वजह से हमारा शरीर मजबूत बनता है।
- फलों की वजह से ही शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है।
- हमारी कोशिकाओं को मरम्मत करने का मौका मिलता है।
- इनमें प्राकृतिक शुगर होता है,जो नुकसान नहीं करता।
- फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है।
- इसमें मौजूद कैलोरी कम होती है,फैट की मात्रा भी इसमें कम पाई जाती है।
- इनसे आपको वजन काबू में रखने में मदद मिलती है।

अपनों से अपनी सी बात

छोटे बच्चे की बड़ी सीख

एक बार एक राजा नगर भृमण को गया तो रास्ते में क्या देखता है कि एक छोटा बच्चा माटी के खिलौनों के कान में कुछ कहता फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है। राजा को बड़ा अचरज हुआ, तो उसने बच्चे से पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो,तो बच्चे ने कहा कि मैं इनसे पूछता हूं कि कभी राम नाम जपा है, और माटी को माटी में मिला रहा हूं।तो राजा ने सोचा इतना छोटा सा बच्चा और इतनी ज्ञान की बात ! राजा ने बच्चे से पूछा,कि तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे,तो बच्चे ने कहा कि जरूर रहूंगा,पर मेरी कुछ शर्तें है। जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा। मैं भोजन करूंगा और तुम्हे भूखा रहना पड़ेगा। जब कभी मैं मुसीबत में पड़ जाऊं, तो तुम्हें सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हों, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। राजा ने कहा ये तो असम्भव है। ये तो तुम्हारा कोई खास से खास आदमी भी होगा तो वह भी नहीं कर पाएगा, भला मेरी क्या बिसात बच्चे ने कहा तो रहने दो राजन मुझे माफ करो,मैं आपके साथ नहीं चल सकता। राजा ने उस बच्चे को तरह तरह के प्रलोभन दिए पर बच्चा टस से मस नही हुआ। बच्चे ने कहा,राजन मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आसरे क्यों रहूं, वो खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है,खुद जागता है और मैं निश्चिंत सोता हूं,जब मैं किसी मुसीबत में होता हूं, तो वो बिना बुलाए, मेरे लिए अपने सारे काम छोडकर दौड़ा आता है।भाव केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विषय विकारों में उलझकर परमात्मा को भुलाए बैठे हैं,जो हमारी पल पल सम्भाल कर रहा है,उसके नाम को भुलाए बैठे है।

-ललित अकिंचन

Feedback@dainiknavajyoti.com

चिंतन

यह चेतावनी है, अब भी नहीं संभले तो देर हो जाएगी

अरावली में खनन भविष्य के लिए खतरनाक

"अगर अरावली ढाई तो सिर्फ पहाड़ ही नहीं ढहेंगे, पानी, खेती, हवा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में पड़ जायेगा। यह विकास नहीं,चेतावनी है कि अब भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जायेगी।

ज्ञानेन्द्र रावत

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा और सहायक मुद्दों के संबंध में बीते दिवस स्वत संज्ञान लेते हुए अभी फिलहाल अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की नयी परिभाषा स्वीकार करने वाले अपने 20 नवम्बर के आदेश पर रोक लगा दी है और अपने आदेश में कहा है कि पिछले फैसले में निर्धारित निष्कर्षों और निर्देशों को स्थगित रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनपर स्पष्टीकरण की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे की व्यापक और समग्र समीक्षा के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल कर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि क्या अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की परिभाषा,जो विशेषकर दो या दो से अधिक पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के क्षेत्र तक सीमित है, एक संरचनात्मक विरोधाभास पैदा करती है,इससे संरक्षित क्षेत्र का भौगौलिक दायरा संकुचित हो जाता है।

अनियमित खनन

इस सीमांकन में गैर अरावली क्षेत्रों के दायरे को विस्तृत कर दिया है, जिसके चलते अनियमित खनन और अन्य विघटनकारी गतिविधियों को जारी रखने में सुविधा हो रही है,क्या 100 मीटर और उससे ऊंची पहाड़ियां निर्धारित 500 मीटर की सीमा से अधिक की दूरी होने पर भी एक सन्निहित पारिस्थितिकीय संरचना का गठन करती हैं। व्यापक रूप से प्रचारित आलोचना कि राजस्थान की 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1048 पहाड़ियां ही 100 मीटर की ऊंचाई की सीमा को पूरा करती हैं, जिससे शेष निचली पहाड़ियों को पर्यावरण संरक्षण से वंचित कर दिया जा रहा है, क्या यह तथ्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से सही है। शीर्ष अदालत का यह भी मानना है कि पर्यावरणविदों ने नयी परिभाषा और कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या और अनुचित कार्यान्वयन की आशंका जताते हुए चिंता प्रकट की है।

निर्देशों में स्पष्टता

यह आशंका, आलोचना या असहमति कोर्ट के निर्देशों में स्पष्टता की कमी से उत्पन्न हुयी है। इसलिए अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिकीय अखंडता को कमजोर करने वाली किसी भी नियामकीय खामी को रोकने के लिए जांच और स्पष्टीकरण की बेहद जरूरत है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है। आगे क्या होगा लेकिन इतना तय है कि इसने 20 नवम्बर के आदेश से उपजे असंतोष और विरोधियों के स्वरों को राहत पहुंचाने का काम किया है। असलियत में देश के पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस नयी परिभाषा का कड़ा विरोध करते हुए आशंका जताई थी कि इससे पहाड़ियों में खनन, रियल स्टेट ओर अन्य परियोजनाओं के लिए रास्ता खोलकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित साजिश की जा रही है। यह भी कि अरावली क्षेत्र में खनन बढ़ाने की सोच भविष्य के लिए खतरनाक है।

विरोध प्रदर्शन हुए

सुप्रीम कोर्ट के 20 नवम्बर के फैसले के विरोध में देश में खासकर अरावली क्षेत्र के राज्यों में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए, जगह-जगह रैलियां हुयीं। यहां तक कि इसके विरोध में हुये प्रदर्शनों में आमजन के अलावा राजनैतिक दलों, स्कूल-कालेज के छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया है और वे बड़ी संख्या में आज भी सेव अरावली नामक अभियान बड़े जोर-शोर से चला रहे हैं। उनका मानना है कि उत्तर से पश्चिम तक फैली अरावली को तोड़ना भारत की विरासत को तोड़ने जैसा है। अगर अरावली ढाई तो सिर्फ पहाड़ ही नहीं ढहेंगे, पानी, खेती, हवा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में पड़ जायेगा। यह विकास नहीं,चेतावनी है कि अब भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जायेगी। असलियत में अरावली को लेकर जो बावेला मचा हुआ है, वह उसके अस्तित्व को लेकर है जिसपर खतरा मंडरा रहा है।

प्राकृतिक ढाल है

इसका एकमात्र कारण यह है कि अरावली मात्र हमारे लिए भूगोल का एक अध्याय नहीं है, वह पत्थरों का एक ढेर नहीं, चट्टानों की एक कतार नहीं, एक पहाड़ नहीं है, उस पर मरुधरा का पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। वह रेगिस्तान से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है ।वह 670 किलोमीटर क्षेत्र में फैला उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है, जो हजारों सालों से थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर विस्तार को रोकता है ताकि पूर्वके लोग खुली हवा में सांस ले सकें। वह भूजल को संचित करती है, धूल भरी आंधियों और प्रदूषण से शहरों को बचाती है। इस क्षेत्र में 300 से भी ज्यादा पक्षी प्रजातियों के अलावा तेंदुए जैसे जंगली जानवरों का वास है। सुप्रीम कोर्ट ने भले 20 नवम्बर के फैसले को बदल कर एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की है जो इससे जुड़े मुद्दों पर गहन मंथन करेगी। इसमें दो राय नहीं कि पेड़ों की जड़ मिट्टी को बांधकर रखती हैं। उनके कटते ही मिट्टी बहने लगती है,उसकी उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है और जमीन बंजर होने लगती है। असलियत यह है कि पेड़ों के कटते ही कार्बन सोखने की प्राकृतिक क्षमता काफी घट जाती है,नतीजा वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा काफी बढ़ जाती है और तापमान बढ़ने लगता है। जलवायु परिवर्तन में तेजी इंसानों और जीव-जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है।

यह लेखक के अपने विचार हैं।

जागरूक संपादकीय

जागरूक टाइम्स। मुंबई | शुक्रवार, 2 जनवरी 2026

श्रीरामचरितमानस

अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ॥
कहौं कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई॥

भावार्थ : नीच अजामिल, गज और गणिका (वेश्या) भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते॥

संभावनाओं का साल

नए साल 2026 की आर्थिक संभावनाओं पर प्रकाशित विभिन्न वैश्विक आर्थिक संगठनों की रिपोर्टों के अनुसार नव वर्ष भारत के लिए बेहतर आर्थिक संभावनाओं वाला होगा। केयर एज रेटिंग्स के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। ऐक्सिस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आगामी वर्ष में भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंचती दिख सकती है। जहां भारत वर्ष 2025 में 4.18 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी बन गया है। नए साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर आगे बढ़ेगा। वैश्विक निवेश फर्म इन्वेसको का कहना है कि इस साल भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति कायम रखेगा। हालांकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चिताओं के बीच भारत

को आर्थिक और वित्तीय सुधारों को गति भी देनी होगी। नए वर्ष में घरेलू बाजार की मजबूती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार बनी रहेगी। इस दौरान भारत का घरेलू बाजार 10 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ेगा और इस तेज गति से वर्ष 2030 तक भारत का घरेलू बाजार लगभग 237 अरब डालर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। 2026 में महंगाई घटने, टैक्स सुधार और ब्याज दर में कमी से घरेलू बाजार को रफ्तार से बढ़ने के आधार मिलेंगे। रिजर्व बैंक का कहना है कि 2026 में महंगाई में नरमी बनी रहेगी। गत वर्ष जीएसटी की दरों में सुधारों की जो पहल शुरू हुई है, उसके फल इस साल और व्यापक रूप से मिलने शुरू होंगे। नए वर्ष में मनेरगा की जगह लागू वीबी-जी राम जी से भी ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक अप्रैल से लागू किया जाने वाला नया इनकम टैक्स कानून महज कुछ धाराओं के बदलाव ही नहीं, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था के कायापलट के साथ आर्थिकी को आगे बढ़ाया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे मांग बढ़ेगी और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का जो सिलसिला शुरू किया, उसके इस साल भी जारी रहने के ही आसार हैं। इससे भी मांग और खपत में तेजी आएगी। वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म ग्लोबल वेल्थ मैनेजर की नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 खपत के स्तर में सुधार के मामले में भारत दुनिया का सबसे आकर्षक बाजार होगा। बढ़ते उद्योग-कारोबार, सर्विस सेक्टर, बुनियादी ढांचा, शेयर बाजार और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति के कारण देश में जीएसटी और इनकम टैक्स संग्रहण में तेज वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच जीएसटी संग्रह गत वर्ष की इसी अवधि से बढ़कर 14.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

कश्मीर से निकला, अब देश को बना खतरा

पत्थरबाजी का खौफनाक आतंक

मनोज वार्ष्णेय

सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ़ गलवान' का अभी सिर्फ 1.12 मिनट का टीज़र ही खबरों में आया है, यानी फिल्म थिएटरों में रिलीज़ होना शेष है और प्रोडक्शन हाउस व सेंसर बोर्ड के सदस्यों के अतिरिक्त आधिकारिक तौरपर उसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन चीन उस पर बौखला गया है और उसने फिल्म पर कड़ी आपत्ति की है। चीन के सरकारी अख़बार 'ग्लोबल टाइम्स' ने लिखा है कि फिल्म में बात का बतंगड़ बनाया गया है और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि सिनेमा रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है और भारत उस पर पाबंदी नहीं लगाता है। बहरहाल, इस पूरे विवाद को समझने के लिए संक्षेप में गलवान की झड़प और फिल्म की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है।

इमेज

21वीं सदी को पूरा होने में जब महज 74 साल बचे हों और केंद्र सरकार का ड्रीम, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलवाना है, तब यह सोचकर ही रूह कांप जाती है कि देश में पत्थरबाजों का आतंक धीरे-धीरे हर राज्य में फैल रहा है। कश्मीर पत्थरबाजी का पैटर्न कहें या फिर यह कहें कि कश्मीर से चला पत्थरबाजों का आतंक पूरे देश में फैल चुका है तो कोई खास बात नहीं मानी जानी चाहिए। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, हरियाणा आदि सभी राज्य धीरे-धीरे इसकी चपेट में आ चुके हैं। पहले सेना के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से पत्थर फैंके जाते थे, वही तरीका अब हर कहीं अख्तियार किया जा रहा है। जब नया वर्ष आरंभ हो चुका हो, तो अब इस पत्थरबाजी पर रोक लगे और विरोध का हैवानियत तरीका है उसे खत्म करना होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के नजदीक चौमूं में एक मस्जिद के आगे रेलिंग लगाने के लिए एकत्र किए गए पत्थरों को जब हटाने के लिए स्थानीय पुलिस बल, निकाय के कर्मचारियों के सहयोग के लिए गयी, तो उस पर पत्थरों की बरसात कर दी गई। इस पत्थरबाजी में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए, पूरा क्षेत्र छावनी में बदल दिया गया और चालीस साल पुराने विवाद में इंटरनेट तो बंद करना ही पड़ा साथ ही उपद्रवियों में से करीब पचास से अधिक पत्थरबाजों को पकड़ा गया। इसके बाद उत्तराखंड के ऋषिकेश से भी ऐसी ही खबर आई। यहां पर वन भूमि के सर्वे में गुस्साई भीड़ ने हरिद्वार-ऋषिकेश रेलमार्ग को ठप्प करने का प्रयास किया और समझाइश पर पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की। यहां के बारे में तो यहां तक कहा जा रहा है कि पुलिस, जीआरपी तथा आरपीएफ के जवानों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस मामले में आधा दर्जन पुलिसकर्मियों का घायल होना और 600 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना बताता है कि यहां पर पत्थरबाजी कितनी संगीन रही होगी। पुलिस या सेना पर जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वे पत्थरबाज मासूम नहीं हैं और न ही यह सिर्फ खुद को बचाने के लिए पत्थरबाजी करते हैं। याद कीजिए जब कोरोना था और डॉक्टर्स, समुदाय विशेष के इलाके में जाते थे, तो उन पर पत्थरबाजों ने कोरोना के खिलाफ युद्ध में भी व्यवधान डाला था। इससे समझिए, कितनी खतरनाक स्थिति है। एक तरफ जनता को समझाते कानून के रखवाले और दूसरी तरफ छतों से उन पर फैंके जाते पत्थर, सामने से चुन-चुनकर निशाना लगाकर आते पत्थर? एक तरफ आपकी जान बचाने के लिए आते चिकित्सक, दूसरी ओर उन्हें खदेड़ने के लिए घरों की छतों-गलियों के अंधे मोड़ से निशाना ताक कर आते पत्थर। जिनके हाथ में पत्थर हों वह भला किसी की समझाइश से समझ सकेंगे? इसमें कोई दुराव या छिपाव नहीं है कि यह पत्थरबाज प्रयोजित होते हैं, इन्हें कहीं से फंडिग होती है। कम से कम कश्मीर में तो यही बात सामने आई थी। दरअसल आज पत्थरबाजी एकाएक आरंभ नहीं हुई है, हां, यह जरूर है कि इसकी पुनरावृति में तेजी आई है। चाहे कोई धार्मिक यात्रा हो, सर्वे टीम हो, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस हो, आतंकवादियों को तलाशने के लिए तलाशी अभियान हो हर जगह, विरोध करने-खुद को सुरक्षित करने के लिए पत्थरबाजी सबसे आसान तरीका है। यदि पुलिस या कोई तलाशी के दौरान पत्थरों को सामान्य स्थिति में देखता है तो यह कहकर बचा जा सकता है कि यह किसी निर्माण कार्य से बचे हुए हैं। कानूनी तौरपर इनको उन धाराओं में नहीं गिना जा सकता, जिनमें पेट्रोल बम, अवैध असलहा या दूसरे विस्फोटक पदार्थ गिने जाते हैं, लेकिन ये मारक उन सभी से अधिक, लगते ही सीधा असर। जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं वह नासमझ नहीं हैं। उन्हें सब कुछ पता है बल्कि छतों पर पत्थर, कांच की बोतलें आदि एकत्र करने का उद्देश्य ही है पत्थरआतंक फैलाकर सामने वाले को भगाना या घायल करना। कश्मीर में तो किशोरों को भी अर्थात 12वर्ष से कम के बच्चों को भी पत्थर फेंकते हुए पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के संभल के विषय में तो कुछ भी कहना बेकार है। यहां पर सरकार ने कितनी बार इन पत्थर आताताईयों को खदेड़ा है, पकड़ा है। यह क्या कम है कि उनके पोस्टर चिपकाए गए। कश्मीर में तो सेना के मेजर ने सेना को सुरक्षित करने के लिए एक पत्थरबाज को अपनी जीप के आगे बांधकर ढाल के रूप में रखा था। पत्थरबाजों के खिलाफ कितनी भी कड़ी कार्रवाई की गई हो लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। पत्थरबाज देश के विकास में बाधक भी हैं। नहीं तो क्यों, वंदे भारत पर अब तक एक दर्जन से अधिक बार पत्थर फेंकने की घटनाएं हो चुकी हैं। सामान्य रेलों पर तो इनकी संख्या कितनी है, यह कहना मुश्किल है। नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के खिलाफ सिर्फ असम में पत्थरबाजी की हिंसा हुई हो ऐसा भी नहीं था। दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश से भी पुनरावृति के समाचार थे। यह पत्थरबाज युवाओं को तो इस कार्य में उपयोग करते ही हैं, साथ ही बच्चों को भी आगे कर देते हैं। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों का पत्थरबाजी में उपयोग करने पर दंडात्मक आदेश दिए थे। इसमें सात साल की कैद के साथ ही पांच लाख का जुर्माना तक लगाने की बात थी। सुरक्षा विशेषज्ञों की मानें तो पत्थर अश्रु गैस, रबर की गोलियां, लाठीचार्ज आदि के सामने हथियारों की तरह प्रयोग किए जाते हैं।

गीता सार

श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्।
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् कीर्तिकरमर्जुन॥२-२॥

भावार्थ : श्रीभगवान बोले- हे अर्जुन! तुम्हें इस असमय में यह शोक किस प्रकार हो रहा है? क्योंकि न यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न यश देने वाला ही है॥

मानुषी/लाइफस्टाइल

अगर ओवरवेट हो तो भी आप दिख सकतीं फैशनेबल

मधु सिंह

वजन जब ज्यादा हो और अपने लिए कपड़े चुनने की बात हो तो लड़के हों या लड़कियां, उनके लिए चुनाव करना थोड़ा कठिन हो जाता है। 'यह आपको फिट नहीं आयेगा', 'यह आपके लिए नहीं है', 'इस डिजाइन में आपके लिए नहीं मिलेगा', 'आपका साइज ज्यादा है, इसमें लिमिटेड ऑप्शंस हैं' जैसे तीखे कमेंट सुनने के बाद लड़कियों को विशेष तौरपर जब ऑप्शन की कमी महसूस होती है तो वे अकसर ढीले-ढाले और मन मारकर जो भी मिलता है, बेढंगा, आउट ऑफ फैशन पहनने को मजबूर हो जाती हैं। लेकिन वजन ज्यादा होने के बावजूद सही फिटिंग के कपड़े न पहनना, इससे शरीर का आकार बिगड़ता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जो मोटापा होने के बावजूद आपके शरीर की प्राकृतिक बनावट को तो छुपाते ही हैं, आपकी खूबसूरती को भी उभारते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। अगर आपके पूरे शरीर पर चर्बी जमा है और हाइट भी कम है, तो सिंपल और क्लासी रहने का मंत्र अपनाएं। अपनी वार्डरोब के बेसिक कपड़ों को सिंपल और क्लासिक रखकर आप साइज या फिटिंग की चिंता किए बिना ऐसे कपड़े चुनें, जो मोटापे से ग्रस्त लड़कियों के लिए आरामदायक और आकर्षक हों। शोल्डर से राउंड स्लीव्स का चयन करें। इससे शरीर कम चौड़ा दिखता है। स्लीव्लेस और छोटी स्लीव पहनने से बचें। इससे शरीर ज्यादा चौड़ा दिखता है। पार्टीवेयर में लंबे गाउन, अनारकली और हाई हील्स से मोटापा छिप जाता है। लेयर्ड ड्रेसेज, शॉर्ट ड्रेसेज, हॉरिजेंटल स्ट्राइप्स और फ्लैट फुटवेयर से बचें। ड्रेसेज के लिए सही रंगों को चुनें। अपने मनपसंद रंग भी बेहिचक पहने जा सकते हैं। बस सही शेड्स और कॉम्बीनेशन ढूंढ़ें। एक ही रंग के कपड़े सुडौल लुक देते हैं।

यदि आपकी गर्दन पर फैट ज्यादा है तो कॉलर्स और हाईनेक जैसे नेक पहनने से बचें। थोड़ी डिप नेकलाइन पहनें ताकि गर्दन दबी हुई न दिखाई दे। गर्दन मोटी होने पर वह छोटी दिखती है, अपनी बैठने की मुद्रा ऐसी रखें कि गर्दन लंबी दिखे। वी नेक टॉप या कुर्ते पहनें, गले में शॉर्ट ज्वैलरी पहनें, बड़े और मोटे बीड्स की बजाय पतली चेन का चयन करें। अगर आपकी कमर पर चर्बी ज्यादा जमा है तो अपनी टॉप पर बेल्ट लगाएं, उससे कमर कम चौड़ी दिखाई देती है। मिड वेस्ट जींस का चयन करें ताकि बॉडी का मिडल पार्ट ज्यादा लंबा दिखे। स्ट्रेट कट टॉप, कप्तान स्टाइल लंबे टॉप, मोटी महिलाओं के लिए परफेक्ट हैं।

तिथि विशेष

गोपाल कृष्ण गोखले

गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन महान नेताओं में से थे, जिन्होंने राजनीति को नैतिकता, शिक्षा और सामाजिक सुधार से जोड़ा। उनका जन्म 2 जनवरी 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे गोखले ने अपने

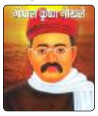

परिश्रम, विद्वत्ता और विचारशीलता से राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाई। गोखले प्रारंभ से ही शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने एलफिंस्टन कॉलेज, मुंबई से उच्च शिक्षा प्राप्त की और बाद में शिक्षक बने। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। वे मानते थे कि शिक्षित समाज ही स्वतंत्र और सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1905 में 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' की स्थापना की, जिसका लक्ष्य राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित, चरित्रवान और प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करना था। राजनीतिक जीवन में गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में गिने जाते हैं। वे संवैधानिक सुधारों, संवाद और शांतिपूर्ण संघर्ष के पक्षधर थे। गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश शासन से अधिकार तर्क, नीति और जनमत के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने विधान परिषद में रहते हुए भारतीयों की आर्थिक दुर्दशा, शिक्षा, कर व्यवस्था और प्रशासनिक अन्याय के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया। गोपाल कृष्ण गोखले का महात्मा गांधी के जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। गांधीजी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधीजी ने गोखले के मार्गदर्शन में देश की सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को समझा। गोखले ने गांधी को संयम, सहिष्णुता और जनसेवा का मार्ग दिखाया। गोखले केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील समाज सुधारक भी थे।

संभावना-2026/विज्ञान और तकनीक

साल 2030 के लक्ष्य की नींव

संजय श्रीवास्तव

नया साल भारत के विज्ञान, तकनीक, रक्षा, पर्यावरण और कृषि में रणनीतिक निर्णायकता के उस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां अवसरों और चुनौतियों का संगम है। 2026 में नीति-समन्वय और निवेश-निरंतरता नहीं बनी, तो उपलब्धियां टुकड़ों में बंट सकती हैं और यदि ये बनीं, तो देश का 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुपरपावर बनने का सपना पूरा होगा।, नया वर्ष 2026 भारत के लिए विज्ञान, तकनीक, रक्षा, पर्यावरण और कृषि क्षेत्रों में प्रगति और चुनौतियों के साथ परिवर्तनकारी संभावनाओं के साल के बतौर भी दर्ज होगा। यह साल कई मामलों में तकनीकी उपभोक्ता से स्वायत्तता और वैश्विक स्तर के निर्माता बनने की ओर प्रस्थान बिंदु बनेगा।

इमेज

साल 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य प्राप्ति हेतु यह अनिवार्य भी है। बेशक, चुनौतियां कठिन हैं पर हम 2026 से सस्ते हरित ऊर्जा, तेज इंटरनेट, सुरक्षित साइबर स्पेस, रक्षा आत्मनिर्भरता से मजबूत होती सुरक्षा, पर्यावरण सुधार से साफ होती हवा, शुद्ध पेयजल के साथ समृद्ध कृषि की आशा रख सकते हैं। सरकार, उद्योग और नागरिकों का त्रिकोणीय प्रयास इस लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। सबसे महत्वपूर्ण है विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट आवंटन। 2026 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को 20,000 करोड़ रुपए और जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 3,446 करोड़ रुपए आवंटन की आवश्यकता बताई तो जाती है पर यह खुशफहमी साबित होगी। भले राष्ट्रीय एआई मिशन जैसे कार्यक्रम इसे समर्थन देंगे, लेकिन तकनीकी स्वायत्तता, हरित नवाचार, स्वदेशी अनुसंधान और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर रणनीतिक जोर देने के लिए यह नाकाफी साबित हो सकता है। इसके बावजूद सेमीकंडक्टर, क्वांटम, बायोटेक, उन्नत सामग्री और एआई, डिजिटल भुगतान, ओपन नेटवर्क, विज्ञान और तकनीक में स्टार्टअप की संख्या में बढ़ोत्तरी जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति के संकेत स्पष्ट हैं। इस साल डीपटेक सबसे बड़ी संभावना वाला क्षेत्र रहेगा। यह एक लाख स्टार्टअप्स में से 20 प्रतिशत डीपटेक, खासकर क्वांटम, बायोटेक पर केंद्रित होंगे। इस क्षेत्र में निवेश 2025 के 50 बिलियन डॉलर से बढ़कर 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग व डिजाइन में प्रोत्साहन योजनाओं, एआई मिशन और विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग के विस्तार से रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक मजबूती मिलेगी। सेमीकंडक्टर डिजाइन में भारत की प्रतिभा वैश्विक कंपनियों को भा रही है, सो इस साल इस क्षेत्र में घरेलू स्टार्टअप्स के उभरने की पूरी संभावना है। साल 2026 में सेमीकंडक्टर मिशन से दस लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना है। व्यावसायिक उपयोग सीमित है पर क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान और पायलट एप्लिकेशन की वृद्धि होगी। इसरो हर साल की तरह खबरों में छाया रहेगा। स्वदेशी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणाली के प्रदर्शन, इंडो-मॉरीशस संयुक्त उपग्रह और ध्रुव स्पेस का लीप-2 उपग्रह भेजने के साथ गगनयान परियोजना का पहले मानवरहित मिशन समेत तकरीबन दर्जन भर महत्वपूर्ण प्रक्षेपण उसकी कार्य सूची में है। इसकी कम-लागत नवाचार, उपग्रह संचार और पृथ्वी-अवलोकन सेवाएं कृषि, आपदा प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स में गुणात्मक बदलाव लाएंगी। रडार सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैपिंग तकनीक की दुनियाभर में मांग बढ़ती जा रही है। इन सेक्टर में छोटे-छोटे स्मॉलकैप कंपनियों की बढ़ती भूमिका के तहत 2026 तक स्पेस टेक्नोलॉजी से कमाई की तस्वीर बदलेगी। डीआरडीओ और निजी उद्योग की भागीदारी रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की गति को बढ़ाएगी तो स्वदेशी हथियार प्रणालियों, ड्रोन, एआई-डिफेंस और साइबर क्षमताओं में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। हाइपरसोनिक हथियार, उन्नत लड़ाकू विमान, अग्नि-6 मिसाइल परीक्षण, सुखोई 30 को तेजस एमके-2 से बदलना और डीआरडीओ के एआई-संचालित ड्रोन सेल्फ अरमाडा परियोजना चर्चा में होंगे, तो आईडेक्स की फंडिंग से तकनीकी स्टार्टअप्स फलेंगे-फूलेंगे। इस बरस डीप ओशन मिशन के तहत विकसित मत्स्य 6000 पनडुब्बी जो 6000 मीटर की गहराई तक तीन वैज्ञानिकों को ले जाएगी। यह समुद्री संसाधन, खनिज खोज और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा निगरानी के लिए अहम साबित होगी। भारत फोरकास्ट सिस्टम इस साल पूरी तरह सक्रिय होगा, जो संसार में सबसे बेहतर 6 किलोमीटर के रिज़ोल्यूशन वाला है। मतलब अब मौसम की भविष्यवाणी ज्यादा सटीक और स्थानीयकृत होगी।

वायरल

तीन लाख पचास हजार रुपए का चीज वाला देश का सबसे महंगा पिज्जा

आपने आज तक ढेर सारे पिज्जा खाए होंगे। इसमें मार्गरीटा, पेपरोनी, चीज़ बर्स्ट, पनीर ओवरलोड जैसे वेराइटी शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी ट्राई किया है वो पिज्जा जिसका सिर्फ चीज ही 3.5 लाख रुपए का हो? जी हां, यहां बात हो रही है देश के सबसे महंगे पिज्जा की। सुपरचार्ज्ड शिकागो डीप डिश पिज्जा, जो आम से बहुत अलग है। ये कोई साधारण पिज्जा नहीं है बल्कि एक 10 किलो के करीब का विशाल पिज्जा है जिसमें लाखों का पार्मेसन, एडम चीज, स्मोकी ट्विस्ट और ढेर सारा प्रीमियम चीज लोडेड होता है। इसके मुंह में जाते ही वो चीज पिघलकर घुल जाता है और क्रिस्पी क्रस्ट, मेल्टिंग चीज पुल और वो लग्जरी फील आता है, जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये शिकागो स्टाइल डीप डिश है, जिसमें चीज की लेयर इतनी मोटी होती है कि पिज्जा जैसे एक चीज का पहाड़ बन जाता है। हर स्लाइस में चीज का पुल इतना लंबा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है।

पंचांग

2 जनवरी 2026

- विक्रम संवत् - 2082
- शक संवत् - 1947
- रवि - उत्तरायण
- ऋतु - शिशिर
- मास - पौष
- पक्ष - शुक्ल
- तिथि चतुर्दशी - 18.55 तक
- वार - शुक्रवार
- नक्षत्र मृगशिरा - 20.06 तक
- योग शुक्ल - 13.08 तक
- करण गर - 08.39 तक
- सूर्योदय - 07.13 प्रातः (मुंबई)
- सूर्यास्त - 06.11 शाम (मुंबई)
- सूर्योदय - 07.26 प्रातः (भीनमाल)
- सूर्यास्त - 06.02 शाम (भीनमाल)
- चंद्र राशि - वृषभ 09.27 तक
- अभिजीत - 12.20 से 13.04
- राहु काल - 11.19 से 12.42
- दिषा शूल - पश्चिम
- व्रत त्यौहार - व्रत की पूनम, बुधास्त पूर्व, भद्रा 18.55 से 29.12, रवियोग 20.06 तक, मरुधर केसरी मिश्रीमल पुण्य स्था. जैन

• शास्त्री प्रवीण त्रिवेदी, भीनमाल

X का एक्सरे

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलाई जाएगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की रात की यात्राओं के लिए डिजाइन की गई है। यह ट्रेन यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा और एक आधुनिक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। इसे भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।

अश्विनी वैष्णव

तृणमूल कांग्रेस जनता के लिए संघर्ष करता रहेगा और किसी भी 'बुरी ताकतों' के सामने समर्पण नहीं करेगा। आज भी हमारा हर कार्यकर्ता इस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। जनता के आशीर्वाद से हम देश के हर व्यक्ति के लिए अपनी लड़ाई में मजबूती से डटे रहेंगे। हम किसी भी बुरी शक्ति के सामने नहीं झुकेंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

ममता बनर्जी

तीन आपराधिक कानूनों को लागू करने में असम देश में पहले स्थान पर है। 2021 में 1.33 लाख मामले दर्ज किए गए थे, जो 2025 में घटकर 43748 रह गए हैं। अदालतों में आरोप पत्र दाखिल करने में 81 फीसदी की वृद्धि हुई है। दोषसिद्धि दर बढ़कर 26.38 प्रतिशत हो गई है। 2025 में 2919 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई।

हिमंत बिस्वा सरमा

अगर अंतिम मतदाता सूची में गड़बड़ियां पाई जाती हैं, तो तृणमूल कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं करेगी और कानूनी लड़ाई लड़ेगी। चुनाव में वोट चोरी ईवीएम से नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट के जरिए हो रही है। घुसपैठ का मुद्दा उठाकर पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला।

अभिषेक बनर्जी

नारायण पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक-प्रकाशक-हेमल पुरोहित द्वारा एआईएस प्रिंटिंग सोल्यूशंस, प्लॉट नं. ए-544, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, ठाणे-बेलापुर रोड, महापे, नवी मुंबई 400709 से मुद्रित एवं प्रिमाइसेस नं. 1303/चेंबर्स, 13वां माला, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 099 से प्रकाशित, पोस्टल रजि. MCN/325/2023-24, (चकाला MIDC पी.ओ.) रजि. नं. MAHHIN/2004/13755, संपादक-हेमल पुरोहित, स्थानीय संपादक-नीरज दवे, फोन : 022-46024646, ईमेल : jagruktimes@gmail.com

राष्ट्रीय सहारा
पटना। शुक्रवार ● 2 जनवरी ● 2026
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जीवन की विडम्बना यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बल्कि यह है कि पहुंचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था।
-बेंजामिन मेस

नये वर्ष की दस्तक नई जिम्मेदारी

वर्ष 2025 भी अब स्मृतियों का हिस्सा बन चुका है और वर्ष 2026 का आगमन हो चुका है। बीता हुआ वर्ष ऐसे फिसल गया मानो मुट्ठी से रेत निकल जाती है। समय की यह गति केवल कैलेंडर के पन्ने नहीं पलटती, बल्कि देश और दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों, अवसरों और जिम्मेदारियों की याद भी दिलाती है। वर्ष 2025 अपने साथ कई सबक छोड़ गया है। कुछ पीड़ादायक, कुछ प्रेरक और कुछ चेतावनी देने वाले। पिछले वर्ष पर नजर डालें तो दुनिया ने अशांति और अनिश्चितता के कई दौर देखे। अलग-अलग हिस्सों में युद्ध, संघर्ष और तनाव ने वैश्विक शांति को चुनौती दी। आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई बहसें छेड़ीं। युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहे, उनका प्रभाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, महंगाई और आम जनजीवन तक महसूस किया गया। यह स्पष्ट हो गया कि आज की दुनिया परस्पर निर्भर है और किसी एक क्षेत्र की अस्थिरता पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए भी बीता वर्ष चुनौतियों और उपलब्धियों का मिला-जुला रहा। एक ओर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के प्रयास हुए, बुनियादी ढांचे, डिजिटल विस्तार और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़े, वहीं दूसरी ओर रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर निरंतर सजग रहने की आवश्यकता महसूस हुई। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हुई है। दुनिया भारत को केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि स्थिरता और संतुलन देने वाले राष्ट्र के रूप में देख रही है। वर्ष 2026 का आगमन केवल उत्सव और संकल्पों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह आत्ममंथन का भी समय है। देश के सामने चुनौतियां कम नहीं है। सामाजिक समरसता, आर्थिक समावेशन, तकनीकी परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रश्न निरंतर हमारे सामने खड़े है। इनका समाधान केवल सरकार या किसी एक संस्था के प्रयास से संभव नहीं है। इसके लिए समाज, नागरिक, नीति-निर्माता और युवा सभी को साझा जिम्मेदारी निभानी होगी।

एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण केवल सैन्य शक्ति या आर्थिक आंकड़ों से नहीं होता। यह मजबूत संस्थाओं, जागरूक नागरिकों, पारदर्शी शासन और सामाजिक एकता से बनता है। जब शिक्षा सशक्त होगी, युवाओं को अवसर मिलेंगे, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और गांव-शहर के बीच की खाई कम होगी, तभी राष्ट्र की नींव मजबूत होगी। साथ ही, वैश्विक चुनौतियों के दौर में आत्मनिर्भरता और नवाचार पर जोर देना समय की मांग है। नए वर्ष में हमें संकल्प लेना होगा कि हम केवल समस्याओं की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि समाधान की दिशा में ठोस कदम भी बढ़ाएंगे। मतभेद लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन विभाजन राष्ट्र को कमजोर करता है। संवाद, सहयोग और संवेदनशीलता ही आगे बढ़ने का मार्ग है। दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, उसमें भारत को संतुलन, शांति और विकास का मॉडल बनकर उभरना होगा। वर्ष 2026 उम्मीदों का वर्ष बन सकता है, बशर्ते हम बीते अनुभवों से सीख लें और भविष्य के प्रति जिम्मेदार बनें। यह समय है व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने का। चुनौतियां चाहे जितनी बड़ी हों, एकजुट प्रयास और सकारात्मक सोच से उनका सामना किया जा सकता है। नए वर्ष की यह दस्तक हमें यही संदेश देती है। समय रुकता नहीं, लेकिन दिशा हम तय कर सकते हैं।

अयोध्या : आस्था-राष्ट्र गौरव का प्रतीक बना

अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 31 दिसम्बर को रामनगरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में 90 के दशक के राम मंदिर आंदोलन और उसके व्यापक प्रभावों पर प्रकाश डाला। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तीव्रता और जन-जागरण के साथ यह आंदोलन पूरे राष्ट्र के सामने आया, उसने

समाज को पूरी तरह से आंदोलित कर दिया था। राजनाथ सिंह की यह बात सराहनीय योग्य कि लोगों ने न केवल इस आंदोलन को देखा, बल्कि इसे जिया भी था। पांच सौ वर्षो के संघर्षो और संकल्पों को अंततः अयोध्या को सिद्धि प्राप्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयोपरांत साढ़े चार वर्ष पूर्व रामजन्मभूमि पर प्रारंभ हुआ भव्य-दिव्य मंदिर का निर्माण अब पूर्णता को प्राप्त हो गया है। जैसे-जैसे रामलला के धाम को उसका आकार मिला, वैसे-वैसे करोड़ों सनातनियों की आकांक्षाओं को भी पंख मिलते गए। निर्माण की पूर्णता के पश्चात राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धर्म ध्वजा का आरोहण किया तो शिखर दर्शन के लिए पूरी दुनिया रामनगरी के प्रति आकर्षित हो गई। इस वर्ष अब तक अयोध्या आए लगभग 23 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं व पर्यटकों का आगमन इसी की परिणति है। अब रामजन्मभूमि परिसर के सातों पूरक मंदिरों में भी दर्शन हो चुके है। रामनगरी का धार्मिक पर्यटन अब नए आयाम को प्रस्तुत करेगा।

नौ नवंबर 2019 को जब उच्चतम न्यायालय ने मंदिर के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया और पांच अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया तो सनातन धर्मियों का उत्साह चरम पर था। साढ़े चार वर्षो की लंबी यात्रा और देशभर के विलक्षण प्रतिभाओं वाले कारीगरों के परिश्रम से जन्मभूमि पर न केवल दिव्य राम मंदिर खड़ा हो गया, अपितु इसके पूरक रूप में सात देवी-देवताओं के मंदिरों को भी भव्य स्वरूप मिला। निर्माण की पूर्णता पर राम विवाह के दिन 25 नवंबर को आयोजित ध्वजारोहण उत्सव ने रामभक्तों के मन में श्रद्धा का ज्वार पैदा कर दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की भांति यह उत्सव भी अपने वृहद स्वरूप व अकल्पनीयता के लिए अविस्मरणीय बन गया। 'संकल्प की सिद्धि' के परिचायक रहे ध्वजारोहण समारोह के बाद यहां के पर्यटन व्यवसाय को भी नई रफ्तार मिल गई। राम मंदिर की सनातन पताका का दर्शन करने के लिए देश-विदेश के भक्त इस कदर उमड़े कि बंद हो चुके होटल-रेस्टोरेंट व होमस्टे आदि फिर आबाद हो गए।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम और बजरंगबली की कृपा से आज अयोध्या सुरक्षित है। उन्होंने रामचरितमानस की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे तो फिर कोई आतंकी यहां घुस ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षो में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचे है, जबकि पहले यहां केवल कुछ लाख लोग ही आते थे। यह अयोध्या के बदले स्वरूप, सुरक्षा और विकास का प्रमाण है। मुख्यमंत्री की यह बात सत्य है कि राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या में उमड़ा श्रद्धा और उत्साह यह दर्शाता है कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और राष्ट्रगौरव का प्रतीक बन चुका है।

मधुर मोहन तिवारी

समाज, करियर व अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर

साल 2026

आचार्य पवन तिवारी

साल 2026 में समाज, करियर और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह समय मन, व्यवस्था और जेब पर मौन दबाव लाने वाला होगा। नौकरियों पर असर पड़ेगा, खासकर आईटी क्षेत्र में रिश्तों में तनाव आ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं की भी आशंका है। सोने-चांदी के दाम बढ़ सकते है। भारत की युवा शक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

वर्ष 2026 समाज, करियर, अर्थव्यवस्था और विश्वास की जड़ों को धीरे-धीरे परखेगा। और देह पर नहीं, मन, व्यवस्था और जेब पर असर डालेगा। किसी प्रत्यक्ष आपदा की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मौन दबाव की तरह महसूस होगा, और धीरे-धीरे सामाजिक मूल्यों, करियर और जीवन की आर्थिक रीढ़ के स्तर पर मनुष्य को परखेगा। यह संकट दिखाई नहीं देगा, पर बहुत गहरे पैठ कर, भीतर रूह तक असर कर सकता है। यह महामारी जैसा होगा, पर देह पर नहीं, मन, व्यवस्था, जेब और भरोसे पर हो सकता है। ढेरों नौकरियां जाने की आशंका है।

साल 2026 के राजा गरु और मंत्री होंगे मंगल: वैदिक ज्योतिष की सूक्ष्म दृष्टि से विक्रम संवत् 2082 (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 18 मार्च 2026 तक) का राजा सूर्य और मंत्री चंद्र है , जो प्रारंभिक वर्ष में नेतृत्व परिवर्तन, जल-संबंधी प्लावन, सैलाब, अग्निकांड, भावनात्मक अस्थिरता व जनता में असंतोष के योग रच रहे है। वर्षारंभिक उथल-पुथल, जल और अग्नि से हानि की आशंका बलवती हो रही है। तत्पश्चात 19 मार्च 2026 से संवत 2083 (रौद्र संवत्सर) का प्रारंभ होगा, जहां बृहस्पति राजा और मंगल मंत्री अनूठे वैश्विक चित्र रचेंगे। शनि वर्ष पर्यन्त मीन में नए चित्र गढ़ेंगे, राहु कुंभ में, केतु सिंह में संचार करेंगे। जून तक शनि-राहु-केतु योग प्रलयकारी प्रभाव डालेगा। बृहस्पति 2 जून तक मिथुन, फिर कर्क में अक्टूबर अंत तक, तत्पश्चात सिंह में विचित्र गति से रक्षा सुरक्षा को प्रभावित करेगा।

शनि रहेंगे निष्पक्ष, होंगे कई बड़े बदलाव: यह वह समय है जब धन रहेगा, पर स्थिर नहीं। साधन होंगे, पर संतोष नहीं। निवेश में उतावलापन, योजनाओं में असंतुलन और भविष्य को लेकर एक अदृश्य बेचैनी समाज में व्याप्त होने की संभावना है। इसी कालखंड में शनि अपना न्यायासन संभाले हुए है। शनि न क्रूर है, न दयालु, वे केवल निष्पक्ष है। जिन व्यवस्थाओं ने वर्षो तक सतही वृद्धि, उधार की समृद्धि और दिखावटी स्थिरता पर भरोसा किया, शनि अब उनसे हिसाब लेगा। बैंकिंग, कॉर्पोरेट और शासन, ये सारे सेक्टर दबाव महसूस करेंगे। टालमटोल की आदतें, लापरवाह नीतियां और नैतिक शिथिलता सामने आ सकती है। आकाश मण्डल में राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे है। यह स्थिति अचानक बदलाव, तकनीकी उथल-पुथल और अप्रत्याशित घटनाओं की सूचक है। यही कारण है कि 2026 को डिजास्टर का वर्ष कहा जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक कम, आर्थिक और संरचनात्मक अधिक ढेरों नौकरियां जाएंगी, विशेषकर आईटी और उससे जुड़े क्षेत्रों में। जहां मशीनें मनुष्य की जगह लेने को तैयार है। यातायात को लेकर कोहराम मचेगा।

साल 2026 रिश्तों पर भी डालेगा असर: वर्ष 2026 नई सोच, नई तकनीक, परिवर्तन की लहर, नव ज्ञान, नया अनुभव और सृजन का वाहक और संवाहक बनेगा। पुराने ढर्रे के अनुयायी उखड़ जाएंगे, नव बीज महमहाएंगे। नवीन विचार अपनाने वाले दीपक से जगमगाएंगे, अकड़ने वाले सिकुड़ जाएंगे। ज्योतिष, विज्ञान, और तकनीक में गहन शोध प्रस्फुटित होंगे, रहस्यों के चकित करने वाले पट खुलेंगे। इस बरस रिश्ते में तनाव, दरारें पड़ सकती है। रिश्तों की कसौटी भी कड़ी होगी, कुछ बंधन टूटेंगे, कुछ और प्रामाणिक बनेंगे। हुक्मरान संपन्न होंगे, जनता विपन्न होगी। अग्निकांड भयभीत करेंगे। विश्व पटल और देश में बड़े संघर्ष, आंदोलनों के संग कई प्रकार के संघर्ष या दंगे संभव है। कुछ क्षेत्रों में जातीय या धार्मिक उन्माद के द्वारा शांति भंग करने करने का प्रयास होने की आशंका है। विद्रोह के स्वर गूंजेंगे। भूस्खलन , भूकंप, या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं व्याकुल करेंगी। बिजली गिरेगी। भारत में आतंक की छाया मंडराने की संभावना है।

वर्ष 2026 समाज, करियर, अर्थव्यवस्था और विश्वास की जड़ों को धीरे-धीरे परखेगा। मन, व्यवस्था और जेब पर असर डालेगा। किसी प्रत्यक्ष आपदा की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मौन दबाव की तरह महसूस होगा, और धीरे-धीरे सामाजिक मूल्यों, करियर और जीवन की आर्थिक रीढ़ के स्तर पर मनुष्य को परखेगा। यह संकट दिखाई नहीं देगा, पर बहुत गहरे पैठ कर, भीतर रूह तक असर कर सकता है। यह महामारी जैसा होगा, पर देह पर नहीं, मन, व्यवस्था, जेब और भरोसे पर हो सकता है।

एआई का वास्तविक युग होगा आरंभ: ज्ञात-अज्ञात ज्वर या विकार लोगों को पीड़ित करेंगे। नेक लोगों का मनोबल मंद और चोरों, अपराधियों और माफियाओं का हौसला बुलंद होने की आशंका है। कुछ सत्यनिष्ठ अधिकारी नायक बन कर उभरेंगे। मौसम तपेगा। प्रवासी भारतीयों में पुनः भय का संचार होगा। इस बरस भी कुछ भारतीयों को जबरन देश भेजा जाएगा। पशुओं को किसी बीमारी या महामारी से कष्ट होने की आशंका है। राष्ट्रों में परस्पर संघर्ष दृष्टिगोचर होगा।

भूकंप, सनामी जैसी आपदा आने की आशंका: प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी घटनाएं परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य संकट गहराएगा। कुछ राष्ट्रों में परस्पर वैमनस्य छाएगा। मंगल जनवरी से मकर-कुंभ-मीन, मई में मेष, नवंबर तक सिंह में गोचर कर ऊर्जा-संघर्ष भड़काएगा। बुध वक्री फरवरी, जून-जुलाई, अक्टूबर में संचार-व्यापार को डगमगाएगा। शुक्र अक्टूबर तुला वक्री रिश्तों में दरार डालेगा। भारत की विदेश नीति अपना दशक पुरानी चोला बदलेगी। इस्लामिक देशों में नया धुवीकरण नज़र आयेगा। विश्व में एक बड़ा देश किसी दूसरे बड़े देश की स्थिर सत्ता को अस्थिर करने का प्रयास करेगा।

आसमान छू सकते है सोना-चांदी के रेट: यह आर्थिक संकुचन का विचित्र बरस है। बचत अनिवार्य महसूस होगी। संचित धन ही काम आएंगे। वर्षारंभ में दुग्ध संकट, सरसों-जौ-चना-गन्ना अधिक, कीटों से फसल हानि होने की आशंका। पूर्वार्ध में अन्न-फल में कमी, उत्तरार्ध में फलोत्पत्ति उत्तम रहेगी। शेयर बाजार में नया उछाल दरअसल भविष्य में बड़ी गिरावट की पटकथा लिख सकता है, मई-जुलाई में ट्रेडर्स को हानि का सामना करना पड़ सकता है, अक्टूबर के बाद शेयर बाजार की स्थिति विचित्र नज़र आएगी। तकनीक क्षेत्र उन्नति करेगा। धातुओं में उछाल आएगा। सोना-चांदी में प्रारंभिक गिरावट के पश्चात महातेजी दृष्टिगोचर होगी, तब आज की कीमतें सस्ती लगेंगी। मानसून के बाद धातुओं के भाव में उछाल आएगा। आने वाले बरसों में तांबा उत्कर्ष की नई कहानी लिखेगा।

बड़ी चनौतियां आएंगी सामने: ट्रैवल्स-फूड-कैब ऐप्स धनाभाव से जूझ सकतें है। आपात निधि को संजो कर रखें, वह सबसे बड़ा साथी सिद्ध होगा। एक करियर से काम नहीं चलेगा। बहु-कार्य संस्कृति उभरेगी, नौकरियों में समस्याएं बढ़ सकती है। निफ्टी में आरंभिक उछाल, मई-जून गिरावट, डिफेंस-एनर्जी-मेटल्स-फिनटेक तेज, रियल एस्टेट पुनर्गठन, हरित ऊर्जा शुभ। सोना, चांदी गिरावट के बाद तेज हो जाएंगे। कृषि को वर्षा से हानि होने की संभावना है। स्टॉक मार्केट में गिरावट, रियल एस्टेट में ठहराव और नकद प्रवाह में संकोच, ये सब आगामी वर्ष के श्रृंखला की कड़ियां है। ऐसे समय में मनुष्य स्वाभाविक रूप से सोना, चांदी और धातुओं की ओर लौटता है, मानो सभ्यता अपने पुराने विश्वासों की शरण में चली जाती हो। विश्व राजनीति अशांत होने से बाजार भी अशांत हो सकता है। न्यूक्लियर शक्ति, वैश्विक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता इस काल की पृष्ठभूमि बन सकती है। इस बीच भारत की दिशा अपेक्षाकृत स्पष्ट दिखाई देगी। चुनौतियां होंगी, पर संभावनाएं भी। भारत की युवा शक्ति, तकनीकी समझ का बौद्धिक बल और संतुलन साधने की क्षमता उसका अस्त्र बनेगी।

इस साल डिजिटल कंटेंट्स का बूम देखने को मिलेगा। नए इन्फ्लुएंसर्स चमकेंगे। उनका क्रेज बढ़ेगा। बॉलीवुड के सब्जेक्ट और आईडिया में बदलाव दिखेगा। खेल क्षेत्र में भारत उन्नति करेगा। अगले ओलंपिक के परफॉरमेंस में कुछ सुधार आएगा।, क्रिकेट-एथलेटिक्स में नए सितारे उभरेंगे। कई खिलाड़ी चोटिल होने की आशंका है। आने वाले साल और सालों में कई काबिल खिलाड़ियों के करियर में बदलाव आ सकता है।

बालों को काला और घना बनाता है 'भृंगराज'

■ 'भृंगराज' बालों को काला करने के साथ ही बुद्धि भी तेज करता है। आयुर्वेद में 'केशराज' नाम से जाने जाने वाले 'भृंगराज' के पत्ते, फूल, तने, जड़, सभी औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इसका वैज्ञानिक नाम 'एक्लिप्टा अल्बा' है

■ यह एस्टेरेसी परिवार से संबंधित है, और इसे अंग्रेजी में 'फाल्स डेजी' और बोलचाल की भाषा में 'घमरा', 'भांगड़ा' जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह भारत, चीन, थाईलैंड, ब्राजील आदि देशों में आम तौर पर दलदली स्थानों में पाया जाता है। यह घरों के आसपास के मैदानों में आसानी से उग जाता है। हालांकि, इसके प्रयोग से पहले चिकित्सकों से सलाह जरूर लेनी चाहिए

(मीडिया इनपुट्स)

संसद में तीखी चर्चा के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के 193 देशों में से केवल तीन ने ही पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया। लेकिन कितने देश भारत की सैन्य कार्रवाई के पक्ष में आए। इसका मूल कारण जानने पर ही पता लग सकेगा कि भारत को सीमा-पार आतंकवाद से किस कदर अकेले दम जूझना पड़ रहा है।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

2025 नक्सल मुक्त भारत के लिए एक निर्णायक वर्ष

वर्ष 2025 भारत के आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में एक दुर्लभ क्षण के रूप में दर्ज होग। भारत ने हिंसा का मुकाबला सिर्फ सीमाओं पर नहीं किया, बल्कि उसकी जड़ों तक जाकर निर्णायक लड़ाई लड़ी। कई दशकों में पहली बार भारत ने अपने सबसे बड़े आंतरिक खतरे से प्रभावी ढंग से निपटते हुए वामपंथी उग्रवाद की सशस्त्र गतिविधियों पर निर्णायक चोट की। दशकों तक वामपंथी उग्रवाद ने राज्य की क्षमता को कमजोर किया, जन-जीवन को संकट में डाला और संवेदनशील क्षेत्रों में विकास को बाधित किया। इसके बावजूद भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि स्थायी राजनीतिक संकल्प और संस्थागत समन्वय के माध्यम से चिरस्थायी परिणाम हासिल किए जा सकते है।

वर्ष 2025 में भारत ने छिट-पुट कार्रवाइयों से आगे बढ़कर समग्र आंतरिक सुरक्षा रणनीति अपनाई सशस्त्र माओवादी तत्वों के विरुद्ध सटीक अभियान और साथ ही लंबे समय से उपेक्षित क्षेत्रों में शासन, अवसंरचना और पुनर्वास का विस्तार। इसके परिणाम स्पष्ट रहे, विद्रोही गतिविधियों का भौगोलिक दायरा संकुचित हुआ, उग्रवादी नेतृत्व संरचनाएं ध्वस्त हुई और बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण हुए।

नक्सलवाद की रीढ़ पर वार 2025 के अंत के साथ ही मोदी सरकार का यह ऐलान केंद्र में बना हुआ है कि 31 मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलमुक्त कर दिया जाएगा। अब जब लक्ष्य तक पहुँचने में थोड़ा ही अधिक समय बचा है और CPI (माओवादी) का संगठनात्मक ढांचा काफी हद तक टूट चुका है, तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकने वाला दिखाई देता है। वर्ष 2013 में 182 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, जबकि अब 2025 में प्रभावित जिलों की संख्या केवल 11 रह गई है। नक्सल मुक्त भारत बनाने के मोदी सरकार के विज़न की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटाकर 3 पर ला दी गई है।

नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रमुख मुठभेड़ अकेले साल 2025 में ही, सुरक्षा बलों ने 335 नक्सलों को निष्क्रिय किया, 2167 से अधिक आत्मसमर्पण कराए और 942 गिरफ्तारियां कीं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत 27 कट्टर नक्सलों को निष्क्रिय किया गया। 24 मई 2025 को बीजापुर में 24 कट्टर नक्सलों ने आत्मसमर्पण किया।

नवंबर 2025 में, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू ज़िले के मारेडुमिल्ली वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। मृतकों में वरिष्ठ माओवादी नेता और केंद्रीय समिति के सदस्य मड़वी हिड़मा, उनकी पत्नी राजे तथा उनके कई करीबी अनुयायी शामिल थे। वह साल 2010 के दांतेवाड़ा हमले, साल 2013 के झीरम घाटी नरसंहार और साल 2021 के सुकमा बीजापुर मुठभेड़ में शामिल था। सितंबर 2025 में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा से सटे अबूझमाड़ क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई, जहाँ सुरक्षा बलों ने केंद्रीय समिति के वरिष्ठ नेताओं कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कादरी सत्यानारायण रेड्डी को मार गिराया। मई 2025 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में किए गए एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 27 कुख्यात माओवादियों को निष्क्रिय किया, जिनमें सीपीआई माओवादी का महासचिव, शीर्षतम नेता तथा नक्सल आंदोलन की रीढ़ माना जाने वाले नंबाला केशव राव उर्फ़ बासवराजू भी शामिल था।

बड़े-बड़े माओवादी नेताओं का आत्मसमर्पण एवं नेतृत्व संरचना का पतन हाल ही में दिसंबर 2025 में मिली एक बड़ी सफलता के तहत, कान्हा भोरमदेव (केबी) डिवीजन के 10 माओवादियों ने बालाघाट में सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिनमें 77 लाख रुपये का इनामी, मोस्ट-वांटेड कमांडर सुरेंद्र उर्फ़ कबीर भी शामिल था। वरिष्ठ माओवादी नेता विकास नागपुरे उर्फ़ नवज्योत उर्फ़ अनंत ने पिछले माह नवंबर में आत्मसमर्पण किया था और हथियार छोड़ने की सार्वजनिक अपील की थी। साथ ही, नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के 15 सक्रिय कैडरों ने, जिन पर कुल मिलाकर लगभग 50 लाख रुपये का इनाम था, हथियार डाल दिए। इनमें कुख्यात पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन संख्या 1 के चार कट्टर सदस्य भी शामिल थे पीपीसीएम मड़वी सन्ना, सोड़ी हिडमे, सूर्य उर्फ़ रव्वा सोमा तथा मीना उर्फ़ मड़वी भीमे जिनमें से प्रत्येक पर आठ लाख रुपये का इनाम घोषित था। 14 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ उत्तर बस्तर क्षेत्र के 170 तथा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के 61 शामिल थे। इनमें कई वरिष्ठ कैडर और क्षेत्र कमांडर भी थे, जिनके ऊपर बड़े-बड़े इनाम थे। आत्मसमर्पण सूची में 10 वरिष्ठ माओवादी ऑपरेटिव शामिल है, सतीश उर्फ़ टी. वासुदेव राव (केंद्रीय समिति का सदस्य) उल्लेखनीय रूप से, टी. वासुदेव राव पर 1 करोड़ रुपये का इनाम था, जो इस आत्मसमर्पण की लहर के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। रानिता (दक्षिणी ज़ोनल समिति की सदस्य एवं सचिव, माड़ डीवीसी),। भास्कर (डीवीसी सदस्य, पीएल 32), नीला उर्फ़ नांडे (डीवीसी सदस्य, प्रभारी एवं सचिव, नेलनार क्षेत्र समिति) । दीपक पालो (डीवीसी सदस्य, प्रभारी एवं सचिव, इंद्रावती क्षेत्र समिति) सितंबर 2025 में वरिष्ठ माओवादी नेता सुजाता ने 43 वर्षो तक अंडरग्राउंड रहने के बाद आत्मसमर्पण किया। अप्रैल 2025 में सुकमा ज़िले का बड़ेसट्टी गाँव बस्तर संभाग की पहली ऐसी ग्राम पंचायत घोषित किया गया, जो पूर्णतः नक्सल-मुक्त है।

साल 2025 में नक्सलवाद के खिलाफ हासिल की गई उपलब्धियाँ केवल सुरक्षा या कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में हासिल की गई सफलताओं से कहीं अधिक है। सशस्त्र कैडरों का निष्क्रिय होना, नेतृत्व नेटवर्क का उखड़ना और बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण केवल आंकड़े नहीं है; ये उस विद्रोही पारिस्थितिकी तंत्र का क्रमिक और सुव्यवस्थित क्षरण दर्शाते है, जिसने दशकों तक हिंसा को जीवित रखा। 2025 वह वर्ष माना जाएगा जब भारत ने अपनी सबसे लंबे समय तक चली आंतरिक सुरक्षा चुनौती पर निर्णायक विराम लगाया, और नक्सल-मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर ठोस और प्रगति की।

परिवार

डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

परिवार बसा लेना आसान है, लोग आये दिन बसाते ही रहते हैं, उसका पालन भी कोई विशेष कठिन नहीं है। सभी उसका पालन करते ही हैं,

किन्तु परिवार को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए उसका निर्माण करना एक श्रम साध्य कर्त्तव्य है। कहना न होगा कि परिवार की परिवरिस किसी तपस्या से कम नहीं है। और अधिकतर लोग परिजनों के लिए अधिकाधिक सुख-सुविधाएं देने, उनके लिए अच्छा भोजन, वस्त्र तथा आराम की चीजें जुटाना ही पारिवारिक जीवन का उद्देश्य मान बैठे हैं। वे यह कभी नहीं सोच पाते कि भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ परिवार की एक सर्वोपरि आवश्यकता भी है, और वह है उसे सुणी बनाना। आपके पास एक ऐसी प्रेम की रस्सी होनी चाहिए, आपके पास ऐसी मिठास की रस्सी होनी चाहिए, आपके पास अपने व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण पेश करने की ऐसी रस्सी होनी चाहिए जिससे प्रभावित करके आप आदमी के हाथ जकड़ सकें, पैर जकड़ सकें और काम जकड़ सकें। सारे के सारे को जकड़ कर जिंदगी भर अपने साथ बनाए रख सकें। अपने उद्धार के लिए नारी को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने आपको आत्मा, वह आत्मा जो पुरुषों में भी है, समझना होगा। मातृत्व के महान पद की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित रखने के लिए उसे सीता, गौरी, मदालसा, देवी, दुर्गा, काली की सी शक्ति, क्षमता और कर्त्तव्य का उत्तरदायित्व ग्रहण करना होगा। कामिनी, विलास की सामग्री न बन कर अपने आपको आदर्श, पूजनीय गुणों का आधार बनाना होगा, तभी वह गिरी हुई अवस्था से उठ सकती है। नारी का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। पुरुष से भी अधिक कह दिया जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वह गृहिणी है, नियत्री है, अन्नपूर्णा है। नारी में ममतामयी मां का अस्तित्व निहित है, तो नारी पुरुष की प्रगति, विकास की प्रेरणा सोत जाह्नवी है। नारी अनेकों परिवारों का संगम स्थल है। नारी मनुष्य की आदि गुरु है, निर्मात्री है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मानव समाज में नारी का बहुत बड़ा स्थान रहा है, और रहेगा। कह सकते हैं कि नारी की उन्नत अथवा पतित स्थिति पर ही समाज का भी उत्थान-पतन निर्भर करता है।

रीडर्स मेल

नववर्ष 2026 सबको मंगलमय हो

इन्द्रदेव त्रिवेदी

नव आगत की तैयारी कर
कुछ - कुछ भूलें, कुछ याद करें,
अब आगत की तैयारी कर।।
जो बीता मत तू सोच उसे, बस
आगत की तैयारी कर।।
जो आज अतीत बना भू पर, जो
सीख सकें उससे सीखें।
हम उस अतीत से ज्योतित हो,
उस ज्योति से खुद भी दीखें।।
अब नई रोशनी आती है, नव आगत की तैयारी कर।।
जो बीता मत तू सोच उसे...
जो साल अभी बीता मित्रों, उसको दर्पण सा मान यहां।
इतिहास बनाता है सबकी, तेरी - मेरी पहचान यहां।।
जीवंत करेगा आगत अब, इस आगत की तैयारी कर।।
जो बीता मत तू सोच उसे...
सबका जीवन गतिमान रहे, ये ही हम सबका ध्येय बने।
हर सृजन एक उद्देश्यपूर्ण, हर मानव का पाथेय बने।।
हम सबको सुख - उल्लास मिले, उस आगत की तैयारी कर।।
जो बीता मत तू सोच उसे...

चेतना के कवि तुलसीदास

तुलसीदास जयंती केवल एक कवि की स्मृति नहीं है, अपितु यह भारतीय भक्ति परंपरा, लोक संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का भी पर्व है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। उन्होंने जिस प्रकार रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु श्रीराम की कथा को जन-जन तक पहुंचाया, वह भारतीय साहित्य के इतिहास में अद्वितीय है। नई पीढ़ी को तुलसी की रचनाओं से जोड़ कर हम उनमें नैतिकता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक गौरव का भाव जगा सकते हैं। तुलसीदास केवल एक कवि नहीं हैं, बल्कि कालजयी विचारधारा के वाहक भी हैं, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि भक्ति केवल पूजा नहीं है, बल्कि सेवा, संवेदना और आत्मविवेक का मार्ग भी है। उनका जीवन और लेखनी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। आवश्यक है कि उनके लिखे को आत्मसात करके जीवन जिया जाए।

महेन्द्र तिवारी, ई मेल से

एसआईआर की प्रासंगिकता

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के अंतर्गत चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान एक ओर जहां मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर यह कई आलोचनाओं का भी केंद्र बन गया है-विशेषकर दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर खड़े समुदायों के संदर्भ में। विपक्ष की पार्टियों ने तो इसके खिलाफ बाकायदा एक अभियान ही छेड़ दिया है। कहना न होगा कि एक राष्ट्र तभी सशक्त होता है, जब उसका सबसे कमजोर नागरिक भी अपने मताधिकार को बिना डर, बाधा या भेदभाव के प्रयोग कर सके। और जब तक एसआईआर जैसे अभियान में यह सुनिश्चित नहीं होता, तब तक यह प्रश्न प्रासंगिक बना ही रहेगा कि-क्या दलित, महिलाएं और अल्पसंख्यक सचमुच बाहर हो रहे हैं?

आदित्य वर्मा, लखनऊ
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
● राष्ट्रीयता ● कर्त्तव्य ● समर्पण
वर्ष - 20, अंक 6878
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । **स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी ***।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, **फैक्स :** 2535935,2520760 **विज्ञापन**-3911455/434, **प्रसार**- 3911451/428
आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 02-01-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH06 User: cci Time: 01-01-2026 21:05 Color:

दुर्घटनाएं अपने आप नहीं होतीं, वे कारणों से होती हैं।

– एच. डब्ल्यू. हेनरिक, अमेरिकी औद्योगिक सुरक्षा एक्सपर्ट

मानकों की अनदेखी

नए साल का जश्न आमतौर पर उम्मीद, उल्लास और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। लेकिन, स्विट्जरलैंड के क्रांस मोंटाना के एक प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में हुए हादसे ने जश्न को त्रासदी में बदल दिया है। भीषण आग ने सैकड़ों परिवारों को वर्ष के पहले दिन ही ऐसी पीड़ा दी, जिसे वे कभी भुला नहीं पाएंगे।

अधूरी जानकारी । ये लाइनें लिखे जाने तक इस हादसे को लेकर बहुत कुछ संशय में था। नहीं पता कि आग कैसे लगी, कितने लोग मारे गए, मौके पर कितने मौजूद थे और मरने वालों की पहचान क्या है। जांच अधिकारियों के बयानों से लगता है कि इसमें अभी लंबा समय लगेगा। शुरुआत में इसे आतंकी वारदात भी माना जा रहा था, लेकिन अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। फिर भी इतना बड़ा हादसा कई सवाल छोड़ जाता है।

स्विट्जरलैंड में हादसा

सख्त मानक । यह घटना बताती है कि भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन की कितनी सख्त जरूरत है। पिछले महीने गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग में कई लोगों की मौत हो गई थी। वहां लोगों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला और ऐसा ही कुछ क्रांस मोंटाना में भी सामने आ रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि बचाव का मौका नहीं मिल पाया।

गलती की गुंजाइश नहीं । जांच आगे बढ़ने पर कई और बातें पता चलेंगी, लेकिन यह घटना बताती है कि पर्यटन स्थलों पर छोटी-सी चूक भी कितनी भारी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि बार की क्षमता 300 थी और हादसे के समय वह फुल था। मौके पर अगर पर्याप्त सुरक्षा उपाय होते, भीड़ को नियंत्रित किया जाता और क्षमता के अनुसार लोगों की ही एंट्री होती, तो शायद इतना नुकसान होने से रोका जा सकता था।

सुरक्षा सबसे ऊपर । क्रांस मोंटाना हो या दुनिया का कोई और शहर - ये हादसे सभी के लिए सबक हैं। पर्यटन उद्योग में अक्सर मौकों को भुनाने की होड़ लगी रहती है। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक - कमाई का एक बढ़िया सीजन है। लेकिन, इसके साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी निवेश किए जाने की जरूरत है।

जागरूकता जरूरी । जांच और उसके बाद एक्शन, यह तो होना ही है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है कमियों का उजागर होना और उनसे सीखना। सही सीख लेकर ही उम्मीद कर सकते हैं कि फिर ऐसी दर्दनाक खबर से वास्ता नहीं पड़ेगा।

तिराहा

कोसिए, ख़ुश रहिए!

प्रेम शंकर मिश्र

'ये मुए विदेशी भी! कह रहे हैं कि गाली देने से मन को शांति मिलती है,' सुधर्मा गालियों के असर पर रिसर्च की खबर पढ़ भुनभुना रही थीं। सुखनंदन ने धीरे से कहा, 'कोसने, गाली देने से सुख की परंपरा तो शाश्वत है। लोकतंत्र का यह अनिवार्य गहना है!'

'इसका लोकतंत्र से क्या लेना-देना?', सुधर्मा ने आंखें तरेरी। 'तुमने नारद मोह नहीं सुना? विश्वमोहिनी के लिए वर की तलाश शुरू हुई। पिता ने महर्षि नारद से अनुरोध किया। विश्वमोहिनी को देख नारद स्वयं ही मोह गए। भगवान के पास पहुंचे, गुहार लगाई कि मुझे इतना आकर्षक बना दें कि मोहिनी मुझे ही चुने। भगवान ने उन्हें शरीर सौष्ठव तो दिया, लेकिन मुंह बंदर का बना दिया। नाराज नारद ने उन्हें श्राप दे दिया।'

'अब देखो! जनता के लिए साफ पानी, हवा जैसी बुनियादी चीजें भी विश्वमोहिनी जैसी असंभव हो गई हैं। रेल, सड़क, प्लेन से भी गंतव्य तक पहुंचना मंगल यात्रा-सा दुष्कर है। ऐसे में जनता कभी व्यवस्था को तो कभी एक-दूसरे को कोस, गाली देकर आक्रोश शांत कर लेती है। विष्णु जी क्षमाशील थे। उन्होंने नारद की इच्छा का भी मान रखा, उन्हें क्षमा भी कर दिया। आज तो नारदजी को पैरवी के लिए वकील तक नहीं मिलता, नरक में अलग धकेले जाते', सुखनंदन ने हंसते हुए कहा।

'गालियां केवल मन को ही शांत नहीं करती, कानून-व्यवस्था को भी बनाए रखती हैं। रक्त का उबाल इनसे ही शांत हो जाता है, शारीरिक हिंसा की आवश्यकता न्यून ही पड़ती है, जबकि इससे उपजने वाला दर्द, अपमान लाठी की चोट सरीखा ही होता है। चूंकि 'मौखिकी हिंसा हिंसा न भवति', इसलिए अब इसके लिए प्लैटफॉर्म भी बना दिए गए हैं। तब रोम का एरीना था, जिसमें एक्चुअल ग्लैडिएटर लड़ खून बहाते थे, अब 'क्रोम' का एरीना है जिसमें वर्चुअल ग्लैडिएटर गाली दे खून जलाते हैं।'

'पर व्यवस्था पर गालियां कैसे बेअसर हैं?' सुधर्मा ने बात काट दी। 'व्यवस्था भगवान बुद्ध के दर्शन की अनुगामी है, जब अपेक्षा, भड़ास, शिकायतें, गालियां स्वीकार ही नहीं करनी तो असर कैसे करेंगी?' जवाब आया।

एकदा

संकलन : **ललित गर्ग**

ईश्वर की अनुभूति

Subrata Dhar

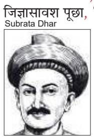

संत नामदेव ने एक बार अपने शिष्यों को ईश्वर की अनुभूति का अत्यंत सरल, लेकिन गहन पाठ पढ़ाया। एक शिष्य ने जिज्ञासावश पूछा, 'यदि ईश्वर सभी जगह हैं, तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देते और उन्हें अनुभव करने का उपाय क्या है?' संत नामदेव ने इसका उत्तर शब्दों में देने के बजाय एक छोटे-से प्रयोग से समझाना उचित समझा। उन्होंने एक लोटा पानी मंगवाया और उसमें थोड़ा-सा नमक घुलवाया। नमक पूरी तरह घुल गया, लेकिन दिखाई नहीं दिया। संत ने शिष्यों से पूछा, 'क्या अब नमक दिख रहा है?' सभी ने कहा, 'नहीं, पर स्वाद से स्पष्ट है कि नमक मौजूद है।' इसके बाद उन्होंने उस पानी को उबालने को कहा। जब पानी वाष्प बनकर उड़ गया, तो लोटे के तल में नमक स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब संत नामदेव ने समझाया कि जैसे नमक पानी में घुलकर अदृश्य रहता है, वैसे ही ईश्वर होते हुए भी नहीं दिखते हैं। जैसे नमक को प्रकट करने के लिए पानी को तपाना पड़ा, वैसे ही ईश्वर को महसूस करने के लिए संयम, तप, साधना और सत्कर्म से गुजरना होता है। इससे संत नामदेव ने शिष्यों को यह बोध कराया कि ईश्वर बाहर खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि भीतर अनुभव करने की चीज है।

रक्षा क्षेत्र को लेकर प्राइवेट सेक्टर ने जो वादा किया है, उसके प्रति वह जवाबदेह बने

जो वादा किया है, निभाना पड़ेगा

मनु पब्बी

Adobestock

डिफेंस में आए बदलाव
- भारतीय रक्षा कंपनियों ने रियल टाइम में सहयोग किया
- देश को स्वदेशी हथियारों के तेजी-से उत्पादन की जरूरत
- इंडस्ट्री से जवाबदेही चाहती है सरकार, देसी पर जोर

आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को पिछले पांच दशकों में सबसे करारा जवाब इस बार ऑपरेशन सिंदूर से मिला। इसके साथ ही भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उसकी जमीन पर कोई आतंकी हमला होता है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों की दिशा तय करने वाले हैं।

सोची-समझी साजिश । 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरी दुनिया सन्न रह गई। इस नरसंहार के पीछे की मंशा लगभग तुरंत ही साफ हो गई थी। पीड़ित परिवारों से बातचीत के दौरान आतंकियों ने जो कहा, वह सीधे सरकार के लिए संदेश था। इससे यही संकेत मिला कि पहलगाम हमला एक सोची-समझी साजिश थी, ताकि भारत को सैन्य प्रतिक्रिया के लिए उकसाया जा सके।

मुनीर को फायदा । हालांकि इस हमले के पीछे जो बड़ा खेल था, उससे पर्दा उठने में थोड़ा वक्त लगा। आज की परिस्थितियां देखें तो पता चलता है कि पहलगाम आतंकी हमले और उस पर भारत के जवाब, इन दोनों से ही सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तानी सेना को मिला। उसके प्रमुख असीम मुनीर ने सरकार पर दबाव डालकर प्रमोशन ले लिया और फील्ड मार्शल बन गए। अब वही पाकिस्तान के वास्तविक शासक हैं। यह स्थिति दो साल पहले की तस्वीर से बिल्कुल उलट है, जब जनता की नजरों में पाकिस्तानी सेना की साख बिल्कुल निचले स्तर पर थी। तब इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में लोग सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे।

स्ट्राइक की ताकत । इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि पाकिस्तानी सेना को जब लगता है कि वह देश के भीतर कमजोर पड़ रही है, तो अहमियत बढ़ाने के लिए वह दांव पर कुछ भी लगा सकती है - यहां तक कि युद्ध भी कर सकती है। इससे भी बड़ा सबक है कि पाकिस्तान की परमाणु हमले की गीदड़भभकी का जवाब देते हुए भारत सीधे वहां के सैन्य शक्ति केंद्रों को निशाना बना सकता है। भारी नुकसान के बाद भी पाकिस्तानी सेना जीत का ही दावा करेगी। उसका पूरा ध्यान होगा देश के भीतर नैरेटिव बनाने पर।

नए साल की आशा

पाकिस्तान की गलतफहमी । भारत के पास अब ऐसी क्षमता है कि पाकिस्तान की जमीन पर कहीं भी मौजूद आतंकी ढांचे पर प्रभावी और बार-बार स्ट्राइक कर सके। 1998 में परमाणु क्षमता हासिल करने के बाद पड़ोसी देश को लगता था कि वह सुरक्षित हो चुका है, लेकिन उसकी यह गलतफहमी दूर हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई आतंकी ढांचे ध्वस्त हुए, पर इससे भी बड़ा हासिल वे सबक हैं, जिनके आधार पर भविष्य के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत की पारंपरिक सैन्य क्षमता इतनी है कि वह पड़ोसी को कुछ ही दिनों में दबाव में ला सके।

इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर । इस अभियान ने ब्रह्मोस, स्कैल्प और S-400 की अहमियत साबित की। आने वाले समय में ऐसे और हथियार देखने को मिलेंगे। स्वदेशी पर जोर है। वहीं, तमाम ड्रोन जैमिंग और स्पूफिंग की वजह से लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। इस मामले में पाकिस्तान की हालत और खराब रही। इससे साफ हुआ कि मौजूदा ड्रोन तकनीक कमजोर है और देश की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता तेजी से मजबूत हो रही है। इस ऑपरेशन की एक खास बात यह रही कि भारतीय रक्षा कंपनियां भी अभियान से जुड़ी थीं। कई स्वदेसी कंपनियों ने रियल टाइम में मोर्चे से ही सेना की मदद की। यह बदलाव रक्षा मंत्रालय के चार साल के प्रयासों का नतीजा है, जिसमें साथ मिलकर हथियारों के विकास और साथ मिलकर लड़ाई के मॉडल को अपनाया गया है।

नतीजों पर नजर । उद्योग जगत के स्तर पर सीख यह रही कि देश को स्वदेशी हथियारों के तेजी-से उत्पादन की जरूरत है। पहलगाम हमले के एक हफ्ते बाद नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी, जिसमें भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता को आंका गया। यहां जो निष्कर्ष निकला, उसे रणनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है। 2025 में नीतियों में बदलाव, सुधार, सेना-उद्योग के बीच तालमेल हुआ, तो 2026 में नतीजों पर नजर होगी। देखना होगा कि उद्योग जगत अपने वादों पर कितना खरा उतरता है।

समय की पाबंदी । सरकार चाहती है कि इंडस्ट्री जो वादा कर रही है, उसके प्रति जवाबदेह बने। देरी या गलती को कामकाज का हिस्सा मानकर छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाले कुछ महीनों में सरकार कठोर उदाहरण पेश कर यह संदेश दे सकती है कि भारत के रक्षा उद्योग को अब ठीक से और समय पर काम करना होगा। नाकाम रहने वालों को साइडलाइन किया जा सकता है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

संकल्प ऐसा हो, जो मन को नई ऊंचाई की उड़ान दे सके

आनन्दमूर्ति गुरुमां

नए साल पर लोग संकल्प लेते हैं कि अमुक-अमुक काम करेंगे। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि जो संकल्प साल के शुरू में लोग लेते हैं, उसे जनवरी महीना खत्म होने से पहले ही तोड़ भी देते हैं। मन एक बिगड़े हुए घोड़े की तरह है। जब तक हम इसको लगाम नहीं लगाते, तब तक यह पता नहीं क्या उलटे-सीधे काम करता रहता है। असल में संकल्प इसीलिए करना चाहिए।

नए साल की शुरुआत में लोग बहुत प्रकार के संकल्प करते हैं, जैसे- वजन कम करेंगे, मीठा नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे संकल्प करना भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे भी आपके मन की शक्ति बढ़ जाती है। बहुत लोग संकल्प तो करते हैं, पर उसे पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि मन बेईमान हो जाता है। जैसे पानी के लिए नीचे गिरना आसान और सहज होता है, वैसा ही होता है मन के साथ। पानी को ऊपर उठाना हो तो मोटरपंप की जरूरत पड़ती है। वैसे ही मन को ऊंचा उठाने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है।

AI Image

मैं आपको कुछ संकल्प करने को कहूंगी तो उसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप खुद संकल्प करेंगे तो उसे खुशी से कर लेंगे। इसलिए यह विचार अवश्य करना चाहिए कि हम अपने जीवन की नैया को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उपनिषद में कहा है कि वास्तव में समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। 2025 नहीं बीता, हम बीत गए हैं।

इस नए वर्ष में कुछ नए गुण, नई सोच, नई विधा, नया चिंतन और कुछ अच्छे कर्म अपने जीवन में ले आएं। विचार ऐसे उत्तम होने चाहिए कि हमारे हाथ से कभी कुछ गलत हो ही नहीं। हमारी जीभ कुछ गलत बोले ही नहीं, हमारी आंखें कुछ गलत देखें ही नहीं, कान कुछ गलत सुनें ही नहीं।

याद रखना जो कुछ आप अपने अंदर डालोगे, वही आपसे बाहर आएगा। वही देखें और सुनें, जिससे मन में प्रेम, करुणा, दया इत्यादि भावनाएं निर्मित हों। वही सुनें जिससे साधना, ज्ञान, भक्ति बढ़े। क्रोध, लोभ, कामना, दुविधा बढ़े - ऐसी चीजों से अपनी इंद्रियों को बचाएं।

मां बनने से क्यों हिचक रही हैं आजकल महिलाएं

रश्मि बंसल

टेक्नॉलजी कंपनी Zoho के फाउंडर श्रीधर वेंबू ने कुछ समय पहले महिलाओं को सही समय पर मां बनने की सलाह दी थी। उनका मानना है कि युवाओं को 20 साल में शादी करके 22 साल तक पैरंट बन जाना चाहिए। उनका ये सुझाव इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि आजकल महिलाओं की फर्टिलिटी को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। हाल यह है कि कोई भी इस पर ज्ञान देता रहता है। लेकिन, यह भी जानना जरूरी है कि महिलाएं मां बनने से परहेज क्यों कर रही हैं।

परफेक्ट पैरंट की चाह । महिलाओं के मां नहीं बनने के कई कारण गिनाए जाते हैं। कोई कहता है कि वे अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं। किसी को लगता है कि यंग कपल बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मगर, असल समस्या परफेक्ट पैरंट बनने की है। आज के मां-बाप सिर्फ दफ्तर में ही नहीं, बच्चों की परवरिश में भी परफेक्ट बनना चाहते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूं, जो मेहमानों को डोर-बेल बजाने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि इससे उनका बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा।

सबकुछ मां पर । हमारी दादी-नानी ने बगैर शिकायत क्रिकेट टीम जितने बच्चे पाले। लेकिन तब बच्चों की देखभाल के लिए घर में कई लोग होते थे। अब पैरंट्स में खासकर मां पर बच्चों की परवरिश का ज्यादा ही दबाव रहता है। अगर वह कामकाजी है तो दफ्तर के साथ उसे घर भी देखना पड़ता है। भले ही उसका एक ही बच्चा हो और घर में मदद करने वाले लोग भी हों, फिर भी वह अपनी मां के मुकाबले दस गुना ज्यादा तनाव में रहती है।

कॉमन रूम

AI Image

मां बनने की सही उम्र । महिलाओं को अधिकतम 30 साल की उम्र तक बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। इससे थोड़े समय परेशानी हो सकती है, लेकिन आगे की जिंदगी के लिए यह सही होगा। 30 के बाद अगर आप मां बनती हैं तो आपके पास संसाधन तो अधिक होंगे, मगर 50 साल की उम्र में भी आपको पैरंट-टीचर मीटिंग में जाना पड़ेगा।

परवरिश की परेशानियां । पहले बच्चे आस-पड़ोस में खेलने के लिए चले जाते थे। आज अच्छे पड़ोसियों की भी कमी है। शायद अच्छे पड़ोसी हों भी, पर हमारे पास उन्हें जानने की फुर्सत नहीं है। IIM से पढ़े एक कपल का तो साफ कहना है कि वे बच्चे नहीं पाल पाएंगे। उनका सीधा मतलब था कि शहर के महंगे स्कूल और सबसे महंगे कॉलेज में एडमिशन कराना उनके वश का नहीं है। भाई, बच्चे को ये सब नहीं बस प्यार चाहिए। उन्हें बस ऐसी परवरिश मिले, जिससे बड़े होकर वे कूल, कॉन्फिडेंट और जागरूक बन सकें।

(लेखिका उद्यमिता और समाज से जुड़े विषयों पर लिखती हैं)

कांटे की बात

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 1400 से 1500 लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से 198 अस्पताल में भर्ती हैं। सरकारी आंकड़ा चार लोगों की मौत का है, लेकिन यहां घूमने के दौरान 8-9 लोगों की मौत की जानकारी मिली।

कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री

सप्ताह की शख्सियत

अर्जुन का कुछ अलग ही है स्टाइल

दोहा में हुई वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में अर्जुन एरिगैसी ने कांस्य पदक जीतकर विश्वनाथन आनंद की बराबरी कर ली। वारंगल में 2003 में जन्मे अर्जुन ने 14 साल में ही ग्रैंडमास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया था।

12 में इंटरनैशनल मास्टर

शतरंज की चालों से अर्जुन 4 साल की उम्र में परिचित हो गए थे। शुरू में उनके लिए भी यह खेल ही था। लेकिन, उनके मां-पापा को लगा कि उनकी याददाश्त और सोचने की क्षमता असाधारण है। वारंगल में ज्यादा सुविधाएं नही थीं। बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए विदेश जाना भी आसान नही था। कम उम्र में ही हार, दबाव से जूझने वाले अर्जुन ने 8 साल की उम्र से घरेलू चैंपियनशिप में छाप छोड़नी शुरू की। 12 साल में वह इंटरनैशनल मास्टर बन गए।

हार से मिली सीख

आत्मविश्वास से लबरेज और आक्रामक खेलने के लिए प्रसिद्ध अर्जुन ने जब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से मुकाबला किया, तो उन्हें लगातार हार मिली। उनकी शैली पर सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे कि वह ज्यादा आगे नही जा पाएंगे। लगने लगा कि टैलंट के बाद भी टिक पाना मुश्किल है। इससे हताश हुए बगैर उन्होंने कमजोरियों पर काम किया। शैली बदलने के बजाय उसे और निखारा। फिर दिग्गज खिलाड़ियों को हराने लगे।

जनता जंक्शन

इरफ़ान

BJP की नाक का सवाल होगा पश्चिम बंगाल

पूनम पाण्डे

इस साल BJP ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता जो इसलिए भी अहम रहा क्योंकि यह जीत 27 साल बाद मिली थी। इस साल बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बन गई और इस बार पहले से भी ज्यादा सीटों के साथ। BJP सबसे ज्यादा सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी भी बनी। चुनावी जीत के लिहाज से साल 2025 BJP के लिए काफी अच्छा रहा। अब नया साल सामने है। सवाल है कि BJP और NDA के सामने इस साल में क्या है और क्या ये साल अलग तरह की चुनौतियां लेकर आएगा।

विशुद्ध राजनीति कसौटी

मिशन साउथ कैसा रहेगा

इस साल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। ये चुनावी साल BJP के लिए ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि वह तमिलनाडु और केरल में अपनी जड़ें जमाने की काफी वक्त से कोशिश कर रही है। उत्तर भारत में तो पार्टी अपने पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत क्रैक करना उसके लिए चुनौती है। हालांकि BJP ने केरल में अपनी मौजूदगी दर्ज करना शुरू कर दिया है, पर अब भी मिशन साउथ की सफलता के लिए उसे लंबी राह तय करनी है।

पश्चिम बंगाल से उसे पिछले चुनाव में भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। इस बार उसके लिए यह नाक का भी सवाल है और साख का भी। यहां खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। बांग्लादेश की उथलपुथल और घुसपैठियों के मुद्दे के बीच देखना होगा कि BJP पश्चिम बंगाल में कितना असर दिखाती है। असम में BJP की सरकार है और यहां उसके सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल की तरह ही यहां भी बांग्लादेश के हालात और घुसपैठिए ये दोनों ही बड़ा मुद्दा हैं। इस साल BJP को एक और फ्रंट पर काम करना होगा। वह है सहयोगियों को एकजुट रखना।

केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार है और BJP के पास इस बार अपना बहुमत नहीं है। जाहिर है, ऐसे में उसकी आगे की राह उतनी आसान नहीं रहेगी। इन मुश्किलों के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। मिसाल के तौर पर NDA में शामिल बिहार के ही कुछ छोटे दल राज्यसभा सीट की मांग को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं। हालांकि ये प्रेशर टैक्टिस ज्यादा है लेकिन फिर भी गठबंधन के साथियों को छिटकने न देना और NDA की एकजुटता बरकरार रखना BJP के लिए एक ऐसी चुनौती है जो बनी रहेगी।

BJP ने इस साल के आखिर में 45 साल के नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर जनरेशनल शिफ्ट के संकेत तो दे ही दिए। अब नए साल में एक बड़ी चुनौती नई टीम बनाने की होगी। देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुराने और बुजुर्ग नेता नितिन की टीम का हिस्सा बनेंगे या संगठन में नए और युवाओं को ज्यादा जगह दी जाएगी।

नए मुद्दों की तलाश

BJP विपक्ष से कहती रही कि मोदी नहीं तो कौन? इस सवाल का जवाब BJP को भी तलाशना है। भले ही अभी नहीं लेकिन आने वाले वक्त के लिए उसे इसका जवाब ढूंढकर रखना होगा। इस मसले पर पार्टी में कोई मनमुटाव या गुटबाजी ना हो यह सुनिश्चित करना भी आसान नहीं होगा। BJP ने विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों पर लोगों को एकजुट करने और समर्थन जुटाने का काम किया उनमें ज्यादा मुद्दे अब रहे नहीं। उसे ऐसे नए मुद्दे तलाशने होंगे जिन पर वह लोगों को अपनी ओर गोलबंद कर सके। खासकर ऐसे मुद्दे जो Gen Z को भी टच करें।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

ट्रंप से उम्मीद नहीं

1 जनवरी को प्रकाशित लेख 'नए साल में खत्म हो जाएगा ट्रंपवाद' 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की दूसरी पारी के पहले वर्ष का संतुलित आकलन करता है। ऊंचे टैरिफ लगाने और वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बावजूद अमेरिका और भारत में तेज आर्थिक वृद्धि दर्ज हुई, क्योंकि वास्तविक टैरिफ अपेक्षा से कम रहे और AI निवेश ने विकास को गति दी। हालांकि AI बूम रोजगार सृजन में कमजोर साबित हुआ, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। 2026 में स्लोडाउन, महंगाई और चुनावी दबाव से ट्रंपवाद को झटका लग सकता है। भारत पर असर पड़ेगा, पर मजबूत मैक्रो स्थिति और STEM प्रतिभा उम्मीद जगाती है।

ब्रजेश मिश्र, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु.; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

विकास के नाम पर जंगलों की सुनियोजित हत्या!

सोनम लववंशी

भारत जैसे देश में यह अपराध और अधिक गंभीर है, जहाँ जंगल केवल पर्यावरणीय इकाई नहीं, सांस्कृतिक स्मृति, जीवन पद्धति और सामाजिक संतुलन का आधार रहे हैं। इसके बाद भी बीते चार वर्षों में देशभर में 78,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को गैर-वनीय उपयोग के लिए स्वीकृति दी गई। यह आँकड़ा अपने आप में एक आरोप-पत्र है।

अखबारों की सुर्खिय़ाँ जब किसी शहर पर बंदरों के 'आतंक' की बात करती हैं या किसी गाँव को हाथियों और भालुओं की दहशत में दिखाती हैं, तब समाज सहज रूप से एक निष्कर्ष पर पहुँच जाता है, कि वन्यजीव समस्या हैं। यह निष्कर्ष सुविधाजनक है, भावनात्मक भी और सत्ता-तंत्र के लिए उपयोगी भी। इसी सुविधा के बीच कहीं अधिक भयावह सच अदृश्य बना रहता है और वह है जंगलों पर संगठित, सुनियोजित और वैध ठहराया गया वह आतंक, जो उद्योग, परियोजना और निवेश के नाम पर फैलाया जा रहा है। यह आतंक शोर नहीं करता, खून नहीं दिखाता, फिर भी इसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। दरअसल ग्लोबल वॉर्मिंग आज केवल वैज्ञानिक शब्द नहीं रह गया है। यह हर सूखते जलस्त्रोत, हर बढ़ती लू, हर अनियमित बारिश और हर जहरीली हवा में दर्ज हो चुका है। पृथ्वी का तापमान लगातार ऊपर जा रहा है और इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण वही है, जिसे हम विकास का उत्सव कहकर नजरअंदाज करते आए हैं। जंगलों का विनाश इस पूरी प्रक्रिया की धुरी है। जब वृक्ष कटते हैं, तब केवल लकड़ी नहीं हटती, बल्कि कार्बन को रोकने वाली प्राकृतिक ढाल भी खत्म होती है। धरती की त्वचा नंगी होती जाती है और सूरज की तपिश सीधे उसके भीतर उतरने लगती है।

भारत जैसे देश में यह अपराध और अधिक गंभीर है, जहाँ जंगल केवल पर्यावरणीय इकाई नहीं, सांस्कृतिक स्मृति, जीवन पद्धति और सामाजिक संतुलन का आधार रहे हैं। इसके बाद भी बीते चार वर्षों में देशभर में 78,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को गैर-वनीय उपयोग के लिए स्वीकृति दी गई। यह आँकड़ा अपने आप में एक आरोप-पत्र है। मध्य प्रदेश में 17,393 हेक्टेयर, ओडिशा में 11,033 हेक्टेयर, अरुणाचल प्रदेश में 6,561 हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 5,480 हेक्टेयर और छत्तीसगढ़ में 4,092 हेक्टेयर वन क्षेत्र विकास परियोजनाओं के हवाले किया गया। इन संख्याओं के पीछे उजड़े जंगल, विस्थापित आदिवासी, सूखती नदियाँ और टूटता जैव-विविधता का ताना-बाना छिपा है और इसी बीच अरावली पहाड़ी को लेकर गढ़ी गई नई परिभाषा इस पूरे श्रृंखला के अधिकतर हिस्से के विनाश का प्रतीक बन सकती है। गौर करने वाली बात है कि यह पहाड़ियाँ उत्तर भारत के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच रही हैं। रेगिस्तान के फैलाव को रोकना, भूजल को संजोना, प्रदूषण को थामना, ये सभी जिम्मेदारियाँ अरावली सदियों से निभाती आई हैं। खनन, रियल एस्टेट और तथाकथित विकास के नाम पर इन्हें खोखला किया जा रहा है। अरावली को नुकसान पहुँचाने का अर्थ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भविष्य को दाँव पर लगाना है। यह केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि नीति-निर्माण की संवेदनहीनता का प्रमाण है। इसके अलावा वनों को अक्सर पेड़ों की गिनती में समेट दिया जाता है। यह दृष्टि खतरनाक है। जंगल एक जीवित व्यवस्था हैं, जहाँ मि ी, पानी, हवा, कीट, पक्षी, जानवर और मनुष्य एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं।

एक पेड़ कटता है तो उसके साथ सैकड़ों जीवन-श्रृंखलाएँ टूटती हैं। पक्षियों के घोंसले उजड़ते हैं, मि ी की पकड़ कमजोर होती है, वर्षा का चक्र असंतुलित होता है। यही असंतुलन धीरे-धीरे बाढ़, सूखा और हीटवेव का रूप ले लेता है। वृक्षारोपण के अभियानों को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कैमरों के सामने पौधे लगाए जाते हैं, आँकड़े जारी होते हैं, तस्वीरें वायरल होती हैं। एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान भावनाओं को छूते हैं, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक कठोर है। जब एक ओर प्रतीकात्मक पौधारोपण होता है, दूसरी ओर लाखों पेड़ परियोजनाओं की भेंट चढ़ते हैं। यह संतुलन नहीं, एक छल है। पौधा लगाना तब सार्थक होता है, जब वह जीवित रहकर जंगल बने। संरक्षण के बिना रोपण केवल आत्मसंतोष की कवायद बनकर रह जाता है। विकास की मौजूदा परिभाषा सबसे बड़ा संकट है। सड़क, फैक्ट्री और मॉल को प्रगति का पैमाना मान लिया गया है। हवा, पानी और हरियाली को विकास की राह में बाधा समझा जाने लगा है। दिल्ली इसका सबसे भयावह उदाहरण है, जहाँ सांस लेना स्वास्थ्य जोखिम बन चुका है। तापमान हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ता है, जल संकट स्थायी सच्चाई बन चुका है। यह स्थिति किसी प्राकृतिक दुर्घटना का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों की नीतिगत लापरवाही का नतीजा है।

ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि जंगलों का विनाश केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, यह सामाजिक और नैतिक प्रश्न भी है। जंगल कटते हैं तो सबसे पहले हाशिए पर खड़े समुदाय उजड़ते हैं। आदिवासी अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान से वंचित होते हैं। विकास का लाभ कुछ गिने-चुने हाथों में सिमटता है और उसकी कीमत समाज का बड़ा हिस्सा चुकाता है। यह असमानता भविष्य के सामाजिक संघर्षों की जमीन तैयार करती है। समाधान की दिशा स्पष्ट है। विकास परियोजनाओं की स्वीकृति में वास्तविक पर्यावरणीय मूल्यांकन होना चाहिए। स्थानीय समुदायों की सहमति केवल कागजी औपचारिकता न बने। हर कटे पेड़ के बदले केवल पौधा नहीं, पूरा पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापित किया जाए। उद्योगों की जवाबदेही तय हो और पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। विकास और प्रकृति के बीच टकराव का विचार ही गलत है। दीर्घकालिक सोच के साथ दोनों का सहअस्तित्व संभव है। आज आवश्यकता है सजग नागरिक चेतना की। उस समाज की, जो अखबार की सुर्खिय़ों से आगे देखकर असली खतरे को पहचान सके। बंदरों, हाथियों और भालुओं से डरना आसान है। उस आतंक का सामना करना कठिन है, जो फाइलों में छिपा रहता है और विकास का मुखौटा पहनकर जंगलों को निगलता है। जंगलों की खामोशी दरअसल एक चेतावनी है। यह खामोशी चीख बनकर उभरने से पहले सुनी जानी चाहिए। यदि आज दिशा नहीं बदली गई, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें उस समय के रूप में याद रखेंगी, जब मनुष्य ने अपने ही घर की नींव काट दी। ऐसे में उपर्युक्त तथ्य और बातें केवल सूचना नहीं, एक आग्रह है सजग होने का, सचेत होने का और उस विकास को रोकने का, जो जीवन के विरुद्ध खड़ा दिखाई देता है। (स्वतंत्र लेखिका एवं शोधार्थी) (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

गिग वर्कर्स की हड़ताल

नए साल की पूर्व संध्या पर देश में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसकी कल्पना सुविधाभोगी संपन्न तबके ने नहीं की थी। 31 दिसंबर को देश भर के डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स हड़ताल पर उतर आए। इसका मतलब यह हुआ कि स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से जुड़े हजारों डिलीवरी पार्टनर्स ने बुधवार को ऐप बंद करके काम रोका, जबकि यह दिन उनके लिए काम के लिहाज से सबसे व्यस्ततम दिनों में से एक होता है। कुछ साल पहले तक पड़ोस के परचून की दुकान वाला घर पहुंच सेवा दिया करता था। हालांकि उसमें कोई समयसीमा नहीं होती थी, फिर भी बुजुर्गों, अकेले रहने वालों या अन्य तरह से जरूरतमंदों के लिए यह बड़ी सुविधा होती थी। इसी चलन को मोबाइल ऐप्स पर आधारित कर एक नए किस्म का व्यवसाय खड़ा कर दिया गया। घर बैठे 10 मिनट में सारी चीजें मिलने लगीं, मानो कोई चिराग का जिन्न हो, जो आदेश देते ही उसे पूरा कर दे। पलक झपकते ही इच्छा पूरी होने वाली बात मुहावरे तक सीमित नहीं रही, उसे गिग वर्कर्स ने सच कर दिखाया। हालांकि इसमें उनके लिए जो खतरे बढ़े, उसे पहचानते हुए भी दूर करने की पहल नहीं की गई। इसलिए अब उन्हें हड़ताल पर उतरना पड़ा है।

यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन यानी टीजीपीडब्ल्यूयू और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यानी आईएफएटी के बैनर तले की गई। आईएफएटी ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को लिखे एक खत में 10 मिनट की असुरक्षित डिलीवरी व्यवस्था पर रोक लगाने, सही मजदूरी देने, हाल ही में लागू नए श्रम कानूनों के तहत कंपनियों को नियमों में लाने और यूनियन बनाने तथा मोल-भाव करने के अधिकार को मान्यता देने की मांग की है। टीजीपीडब्ल्यूयू के नेता शेख सलाउद्दीन का कहना है कि प्लेटफॉर्म कंपनियां '10 मिनट डिलीवरी' का विकल्प पूरी तरह हटा दें, क्योंकि इससे कर्मचारियों पर बहुत दबाव पड़ता है और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। इसके साथ ही, पुरानी भुगतान व्यवस्था बहाल की जाए, जिसमें त्योहारों जैसे दशहरा, दीवाली और बकरीद पर अच्छा वेतन और भत्ता मिलता था।

गौरतलब है कि इस साल की शुरूआत में सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड को लागू किया, जिससे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार एक औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में लाया गया। इससे इन कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस पर रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और वे स्वास्थ्य, विकलांगता, दुर्घटना बीमा और बुढ़ापे की सहायता जैसी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे। इसका मकसद लाखों कर्मचारियों को उनकी गैर-परंपरागत नौकरी के बावजूद बुनियादी सुरक्षा देना है। सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत, पहली बार 'गिग वर्कर्स', 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' और 'एग्रीगेटर्स' कंपनियों की परिभाषा दी गई है। इस कोड में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने की योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें, कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी की राशि, जुमार्ने आदि से पैसा आएगा।

चिंतन-मनन

मृत्यु की चिंता और चिंतन का महत्व

एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे और उन्हें योगाभ्यास सिखाते थे। वह सत्संग भी करते थे। एक शिष्य चंचल बुद्धि का था। बार-बार गुरु से कहता, आप कहां जंगल में पड़े हैं, चलिए एक बार नगर की सैर करके आते हैं। महात्मा ने कहा, मुझे तो अपनी साधना से अवकाश नहीं है। तुम चले जाओ। शिष्य अकेला ही नगर चला गया। नगर में बाजार की शोभा देखी। मन अति प्रसन्न हुआ। इतने में एक भवन की छत पर निगाह पड़ी। देखा कि एक परम सुंदरी छत पर कपड़े सुखा रही है। बस वह कामदेव के बाण से आहत हो गया। जब शिष्य आश्रम लौटा तो चेले का चेहरा देखकर महात्मा जान गए कि यह बच्चा काम वासना शिकार हो गया है। पूछने पर चेले ने उत्तर दिया - गुरुदेव! हृदय में असहनीय पीड़ा हो रही है। महात्मा बोले, क्या नजर का कांटा हृदय में गड़ गया? चेले ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। चेले से गुरुजी ने उस स्त्री का पता पूछा तो पता चला कि वह नगर के एक सेठ की पत्नी है। महात्मा ने एक पत्र के जरिए सेठ को अपनी पत्नी को लेकर आश्रम में एक रात के लिए आने के लिए कहा। सेठ आया तो उसे अलग बैठाकर महात्मा स्त्री को लेकर शिष्य के पास गए और कहा, यह स्त्री रात भर तेरे पास रहेगी, पर ध्यान रखना कि सूर्य निकलते ही तेरा देहांत हो जाएगा। उस स्त्री को सारी बात बता कर आश्वासन दिया कि तुम्हारे धर्म पर कोई आंच नहीं आएगी। इधर चेला रात भर कांपता रहा। सारी वासना काफूर हो गई। सुबह गुरुजी ने पूछा, तेरी इच्छा पूरी हुई? शिष्य ने आपबीती सुना दी। स्त्री को सम्मानपूर्वक सेठ के साथ रवाना कर महाराजजी ने शिष्य से कहा, मृत्यु की चिंता और चिंतन सदा करते रहना चाहिए। यही तुझे बचाएगी।

इजराइल और अमेरिका की दादागिरी को दुनिया के देशों की चुनौती

सनत जैन

वैश्विक व्यापार में स्वदेशी करंसी का महत्व बढ़ा...

वर्ष 2026 वैश्विक व्यापार को लेकर एक नई आधार शिला रखने की ओर आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के सैकड़ों मुल्क वैश्विक लेन-देन में डॉलर की एक ध्रुवीय व्यवस्था से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से सैन्य ताकत, आर्थिक प्रतिबंधों और राजनीतिक दबाव के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अपने हितों के अनुसार संचालित कर एक अलग तरीके का दबाव बनाकर आतंक पैदा कर रहे थे। अमेरिका के साथ नाटो के देश भी इसमें शामिल हो जाते थे। अब यही रणनीति उनके लिए चुनौती बनती जा रही है। कई देश इस दादागिरी के खिलाफ खुलकर खड़े होकर वैकल्पिक लेन-देन की व्यवस्था करने लगे हैं। जिसका असर अमेरिका के ऊपर स्पष्ट रूप से पड़ता हुआ दिख रहा है। डॉलर एवं यूरो मुद्रा का लेन-देन दिन-प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। मुद्रा का उपयोग अमेरिका और यूरोपीय समुदाय ने प्रतिबंध के लिए करना शुरू कर दिया था। यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष ने अमेरिका और इजराइल की दोहरी नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। एक ओर लोकतंत्र, मानवाधिकार और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बातें की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिबंध, एसेट फ्रीज और सैन्य हस्तक्षेप कर कई देशों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। रूस के सेंट्रल बैंक के अरबों डॉलर के एसेट्स को फ्रीज करना इसी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका और यूरोप के देशों की इस कार्रवाई से न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर सवाल खड़े हुए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी दिखा दिया गया, कि पि मी वित्तीय व्यवस्था पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता किसी भी देश के लिए खतरे में डाल सकती है। इसी दादागिरी के कारण वैश्विक व्यापार में लोकल करंसी के उपयोग का महत्व तेजी से बढ़ा है। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार अब डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं में बढ़ता चला जा रहा है। रूस-चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा रूबल और युआन में हो रहा है। वहीं पि म एशिया में ऊर्जा व्यापार के लिए भी डॉलर के विकल्प की तलाश हो रही हैं। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। इससे अमेरिकी और यूरोपीय देशों के प्रतिबंध के असर और जोखिम को सीमित करने की कोशिश लगभग 40 देशों में शुरू हो गई है। विभिन्न देश अपनी करंसी में व्यापार को महत्व देने लगे हैं। इसका एक बड़ा लाभ यह है, विकासशील देशों पर डॉलर का दबाव कम होता जा रहा है। मुद्रा की अस्थिरता का जोखिम भी कम हो रहा है। इस नई व्यवस्था से विभिन्न देशों को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने और सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों पर भरोसा बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैकल्पिक भुगतान प्रणालियो में चीन का सीआईपीएस रूस का, एसपीएफएस और भारत का यूपीआई का प्रभाव तेजी के साथ वैश्विक व्यापार में बढ़ रहा है। जो अर्थव्यवस्था के बड़े बदलाव का संकेत है।

इजराइल-हमास युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र में बार-बार वीटो का इस्तेमाल करने से वैश्विक असंतोष और विभिन्न देशों के बीच में असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। जिसके कारण डॉलर के स्थान पर मिश्रित मुद्राओं में वैश्विक व्यापार की नई शुरूआत हो गई है। ग्लोबल साउथ के देशों में यह धारणा बन चुकी है, कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निष्पक्ष तरीके से अपना काम नहीं कर रहीं हैं। यही कारण है कि अब कई देश पि मी दबदबे को चुनौती देने के लिए आर्थिक सहयोग और वैश्विक लेन-देन में मिश्रित मुद्राओं के जरिए लेन-देन करने की ओर बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका, यूरोपीय देश और इजराइल की आक्रामक नीतियों ने अनजाने में ही सही एक नई वैश्विक सोच को जन्म दे दिया है। लोकल करंसी में व्यापार का बढ़ता चलन यह दशार्ता है। दुनिया धीरे-धीरे एक अधिक संतुलित और बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। यह बदलाव कितना प्रभावी होगा, यह आने वाला समय तय करेगा। इस परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। वैश्विक व्यापार में डॉलर की पुरानी व्यवस्था अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। दिन प्रतिदिन डॉलर को विभिन्न देशों से चुनौती मिल रही है। अमेरिका की साहूकारी में यह सबसे बड़ा झटका है। डॉलर मुद्रा के रूप में वैश्विक व्यापार होने से अमेरिका को बड़ी कमाई होती थी। अमेरिका की दादागिरी दुनिया के सभी देशों में देखने को मिलती थी, लेकिन जब से रूस और चीन जैसे देशो से चुनौती मिलना शुरू हुई है। विशेष रूप से जब रूस जैसी महाशक्ति की मुद्रा को अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रूस की संपत्ति और मुद्रा को सीज कर प्रतिबंध लगाया, तो उसका भय सारी दुनिया के देशों में फैला। रही सही कसर इजराइल और फिलिस्तीन में गाजा युद्ध के दौरान जो दादागिरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अमेरिका और इजराइल की रही उसने एक नई सोच को जन्म दे दिया है। आज विभिन्न देश आपस में यह तय करने में लगे हैं कि भुगतान किस-किस मुद्रा में कितने प्रतिशत में किया जाएगा। यूपीआई आ जाने के कारण अब वैश्विक व्यापार में लेन-देन यूपीआई के जरिए तुरंत होने लगा है जिसके कारण डॉलर मुद्रा को सारे विश्व से चुनौती मिलना शुरू हो गई है। सभी दुनिया के देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का भंडारण कम करके उसके स्थान पर सोने का भंडारण करना शुरू कर दिया है। जिन देशों के साथ उनके कारोबारी रिश्ते हैं। वह अपनी जरूरत के अनुसार विभिन्न मुद्राओं में भुगतान करके डॉलर से बच रहे हैं। इससे अमेरिका को दोहरा नुकसान हो रहा है। डॉलर में भुगतान होने के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ हो रहा था। वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक में विदेशी मुद्रा में डॉलर को प्राथमिकता मिलने से डॉलर मजबूत होता था। अब डॉलर के स्थान पर सभी देशों के सेंट्रल बैंक सोने को मुद्रा के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण अमेरिका को सारी दुनिया के देशों से एक अलग आर्थिक चुनौती मिलना शुरू हो गई है। अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है। यदि यही स्थिति आगे भी देखने को मिलती रही, तो अमेरिका की दादागिरी जल्द ही खत्म होने वाली है। जिस तरह से सोवियत रूस के हाल हुए थे, वही स्थितियां अब अमेरिका में बनने लगी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तेजना में जिस तरह के निर्णय कर रहे हैं, उसके कारण वैश्विक स्तर पर अमेरिका की साख दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। वहीं अमेरिका के लिए आर्थिक चुनौतियां भी बढ़ती चली जा रही हैं।

देश को कहाँ ले जायेंगे ये नफरती संस्कार?

निर्मल रानी

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गत 9 दिसंबर को कुछ स्थानीय युवकों द्वारा अगरतला (त्रिपुरा) के निवासी 24 वर्षीय अंजेल चकमा नामक एक छात्र पर जानलेवा हमला किया गया। हमले के बाद 17 दिनों तक अस्पताल में इलाजरत रहने के बाद गत 26 दिसंबर को आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। चकमा, देहरादून स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में एमबीए अंतिम वर्ष के छात्र थे। खबरों के अनुसार देहरादून में अंजेल चकमा की मौत एक कथित नस्लीय हमले के कारण हुई। बताया जाता है कि 9 दिसंबर को जब अंजेल और उनके 21 वर्षीय छोटे भाई माइकल चकमा पास के सेलाकुई इलाके में किराने का सामान खरीदने गए थे उसी समय उनके चेहरों को देखकर हमलावरों ने उन्हें नस्ली गालियां दीं। बताया जाता है कि घटनास्थल पर करीब छह लोगों का एक समूह, जो पास में ही पहले से किसी के जन्मदिन का जश्न मना रहा था, ने उन्हें रोक लिया। हमलावरों ने उनपर नस्ली टिप्पणियां करते हुये उनपर चिंकी, चीनी और मोमो जैसी टिप्पणी की। जबकि एक आरोपी ने कहा कि ओये चीनी, क्या सूअर का मांस खरीदने आए हो? माइकल ने इसका विरोध किया, तो एक आरोपी ने उन्हें ब्रेसलेट से सिर पर मारा। अंजेल ने अपने भाई की रक्षा करने की कोशिश की और शांतिपूर्वक कहा, हम चीनी नहीं हैं... हम भारतीय हैं। क्या प्रमाण-पत्र दिखाएं कि हम भारतीय हैं? लेकिन नफरती संस्कारों में डूबे गुंडों के इस समूह ने हिंसक रूप से उनपर हमला कर दिया। यज्ञ अवस्थी नामक मुख्य आरोपी ने अंजेल की गर्दन और पीठ पर तेज हथियार से वार किया, जिससे वे गिर पड़े। माइकल भी घायल हुए, लेकिन उन्होंने अंजेल को पास के अस्पताल पहुंचाया। अंजेल की हालत गंभीर थी उनकी गर्दन और स्पाइन में गहरी चोटें थीं आखिरकार वे कभी पूर्ण चेतना में वापस नहीं आए और नफरत के सौदागरों ने एक होनहार भारतीय छात्र की हत्या कर उसके परिवार को अंधकार में धकेल दिया। नि त रूप से इस घटना ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के छात्रों के खिलाफ उपजी नस्लवाद की समस्या को फिर से उजागर कर दिया है। इस घटना को लेकर त्रिपुरा सहित देश के विभिन्न राज्यों व शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

हालाँकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास को लेकर तरह तरह की बातें करते रहते हैं, परन्तु हक ीकत यही है कि गत कुछ वर्षों में इसी दे० भूमि में सत्ता संरक्षित धर्म जाति आधारित नफरती घटनाओं में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के पुरोला कस्बे में एक 14 वर्षीय लड़की के अपहरण के बाद लव जिहाद का आरोप लगाकर हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़काये गये। मुस्लिम मकानों व दुकानों पर लक्षित हमले किये गये, कई परिवार शहर छोड़कर भागने को मजबूर हुये। इसी तरह हल्द्वानी में 2024 की बनभूलपुरा में अवैध मदरसे और मस्जिद के विध्वंस पर पथराव, आगजनी और पेट्रोल बम फेंके जाने की घटना सबसे प्रमुख रही, जहां 6 लोगों की मौतें हुईं। 2025 में भी कश्मीरपुर और हल्द्वानी में साम्प्रदायिक तनाव देखा गया। राज्य में दलितों के विरुद्ध भी अनेक घटनायें होती रहती हैं। परन्तु समाज में धर्म जाति व क्षेत्र के नाम पर बढ़ती नफरतों के बीच इस राज्य को दे० भूमि के रूप में भी प्रचारित किया जाता है।

सवाल यह है कि उत्तराखंड जैसे शांतिप्रिय राज्य सहित देश के अन्य विभिन्न राज्यों में इस तरह के नफरत व हिंसा पैदा करने वाले हालात क्या अचानक पैदा हुए हैं या सत्ता के संरक्षण में इन नफरती संस्कारों को पोषित किया जा रहा है? उत्तराखंड की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा दिये गये बयान से यह काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुये कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ ऐसी घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं और समाज को भेदभाव रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए। हम लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें मिलकर भेदभाव को रोकना होगा। भारत के किसी भी हिस्से के लोगों को हर जगह सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उनकी मृत्यु बेहद दुखद है। किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि देहरादून में एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ, वह एक भयावह घृणा अपराध है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ऐसी नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। वर्षों से इसे रोजाना, खासकर हमारे युवाओं को, जहरीली सामग्री और गैर - जिम्मेदाराना खबरों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। कोई भी घटना देश के लिए दुखद घटना होती है। अगर देश में ऐसी कोई भी घटना होती है तो पूरे समाज को मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। वहीं, राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी में कहा कि हम प्रेम और विविधता का देश हैं। हमें ऐसा समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीयों को निशाना बनाए जाने पर अनदेखी करे। हमें यह सोचने और सामना करने की जरूरत है कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं?

अफसोस की बात तो यह कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा उत्तराखंड की घटना के बाद व्यक्त किये गये विचार उस समय सामने आये जब उनके अपने पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की नस्लवादी नफरती लोगों द्वारा हत्या कर दी गयी ? जबकि लगभग एक दशक से देश में जगह जगह अल्पसंख्यकों,दलितों व पिछड़े वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है। लिंचिंग की घटनायें घटित हो रही हैं। जगह जगह उन्मादी भीड़ पुलिस की शह पर वर्ग विशेष के लोगों को निशाना बनाती रही है। जगह जगह उकसाऊ भाषण हो रहे हैं। कहीं हथियार बांटे जा रहे हैं। तो कहीं संवैधानिक पदों पर बैठे लोग स्वयं अपने जहरीले बोलों से समाज में हिंसा व नफरत बढ़ा रहे हैं। निःसंदेह गोदी मीडिया भी इस नफरती वातावरण को और भी जहरीला बना रहा है। ऐसे में रिजिजू की चिंताओं के अनुसार भारत के किसी भी हिस्से के लोगों का स्वयं को हर जगह सुरक्षित महसूस करना कहां संभव हो पा रहा है? इस समय देश के समक्ष सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि आखिर देश को कहाँ ले जायेंगे ये नफरती संस्कार?

संपादकीय

सेहत का नया साल

आज हम एक नये साल में प्रवेश कर रहे हैं। नववर्ष पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। मंगलकामनाएं अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन नये वर्ष के आगमन के उत्साह में हम इकतीस दिसंबर को देर रात तक नये साल के जश्न में जुटे रहते हैं। इधर देश में प्रयोगधर्मी खानपान व नशीली पार्टियों का फैशन जैसा बन गया है। देर रात तक चलने वाली पार्टियों के बाद नये साल के पहले दिन ही हमारी नींद देर से खुलती है। फिर नये साल का पहला दिन ही सुस्ती और आलस्य के साथ शुरू होता है। कायदे से नये साल की शुरूआत एक ताजगीभरी सुबह के साथ होनी चाहिए। नये संकल्पों के लिए ऊर्जावान सुबह के साथ शुरू हो पहला दिन। निश्चित रूप से हमारा सामान्य जीवन व्यवहार बंधनों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन स्वस्थ जीवन के लिए कुछ नियम जरूरी भी हैं। दरअसल, नये दौर में हम, खासकर नई पीढ़ी एक अराजक जीवन जीने को अपनी शान समझती है। अमेरिका में हुए कुछ शोधों के बाद पता चला है कि सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना हमारी सेहत की गारंटी होती है। यह पुरानी भारतीय अवधारणा ही है। भारतीय समाज में ब्रह्ममुहूर्त में उठने की प्रतिष्ठित परंपरा रही है। इस समय प्रकृति एकाग्रता-ध्यान हेतु शांत होती है। शरीर के मल स्वतरू बाहर निकलने की प्रक्रिया में होते हैं। यह तथ्यपरक है कि हम जितनी जल्दी नित्यकर्म से निवृत्त होते हैं, उतने जल्दी स्वस्थ होते हैं। नया साल न तो कोई जादू है और न ही चमत्कार करने वाला होता है। महज एक नये दिन मानक होता है। नया दिन बदलाव के संकल्प का और उससे जीवन को सुखमय बनाने का। यूं भी जब जनवरी के पहले दिन का आगमन होता है तो शीत का प्रकोप होता है, जिसके चलते जीवन की गति मंथर हो जाती है। संभवतः शीतजनित इस नीरसता व एकरसता को तोड़ने के लिए दुनिया में नववर्ष के उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने की परंपरा शुरू की गई होगी। सही मायनों में उत्सव का उल्लास हमारे तन-मन को स्वस्थ और मंगलमय बनाने के लिए होता है। लेकिन इस दौरान हम खानपान को लेकर अराजक व्यवहार करने लगते हैं। दरअसल, हमारा शरीर बेहद संवेदनशील व हमारी सेहत के प्रति सचेत होता है। शरीर का अपना उन्नत सुरक्षा-तंत्र लगातार हमारे स्वास्थ्य की फिक्र करता है। वह शरीर को सर्दी-गर्मी के अनुरूप अपना ताप नियंत्रित कर हमारे जीवन की रक्षा करता है। वह बार-बार संकेतों से हमें सचेत करता है। हम उसकी आवाज अनसुनी कर देते हैं। एक सीमा तक वह इसे बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर असहाय होने की स्थिति में बीमार पड़ जाता है। अक्सर देखते हैं कि नये साल के जश्न, शादी-विवाह व मुफ्त की पार्टियों में हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन खाने-पीने की अराजकता पेट को लगातार परेशान करती है। उत्सव व पार्टी में हम सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा खा लेते हैं। योग दर्शन बताता है कि पेट को चार भागों में मानकर दो भाग खाने के लिये, एक पानी और एक आकाश तत्व के लिये रखें। आकाश तत्व यानी खाली रखने के लिए, जिससे पाचन की क्रिया सुगम होती है। हम किसी मशीन में भी कोई पदार्थ ठूंस-ठूंस कर भर दें, तो उसकी गति बाधित होती है। फिर पेट तो कोमलअंगी होता है। जापान के एक द्वीप में सौ से अधिक उम्र के सैकड़ों लोग मौजूद है, जिसने पश्चिमी शोधकताओं को चकित किया। शोध में पता चला कि श्रमशील व प्रसन्न रहने वाले इस द्वीप के लोगों की एक खास आदत है, जब उन्हें लगता है कि खान पर्याप्त हो गया है, तो वे थाली का खाना उसी वक्त छोड़ देते हैं। यही उनकी लंबी उम्र का राज भी है। दरअसल, भूख हमारी शारीरिक जरूरत से अधिक मानसिक होती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे खाने की मात्रा में कमी होनी चाहिए। हम जीने के लिये खाएं, न कि खाने के लिए जीएं। अब चाहे नये साल की पार्टी हो या कोई पर्व-त्योहार, हमें संयमित भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। हल्का, सुपाच्य व कम भोजन जहां दवा है, वहीं गरिष्ठ व अधिक भोजन हानिकारक हो सकता है।

मोदी व नेता प्रतिपक्ष के बीच टकराव का साल

क्रांति से शांति तक नामक फोटो प्रदर्शनी नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय, सानेपा, ललितपुर में आयोजित किया गया था, जहां वर्तमान प्रधानमंत्री प्रचंड आये, और इसके प्रकारांतर पीएम इन वेटिंग, केपी शर्मा ओली भी पधारे। उस अवसर पर प्रचंड का नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा से क्या संवाद हुआ, वह सार्वजनिक नहीं हुआ है। मगर, बुधवार सुबह प्रचंड ने घोषणा की, कि पहले संसद में विश्वास मत करा लेते हैं, फिर मैं कुर्सी छोड़ूंगा। एक साल 180 दिनों से प्रचंड सत्ता में हैं। तीसरे टर्म प्रधानमंत्री पद पर बने रहना कितना कठिन होता है, उसे यों समझा जाये कि अब तक उन्हें चार बार विश्वास मत हासिल करना पड़ा है। आखिरी बार 20 मई, 2024 को प्रचंड को विश्वास मत हासिल करना पड़ा था, तब उपेन्द्र यादव के नेतृत्व वाली जनता समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। बुधवार शाम एमाले ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी।

भले ही कोई जीते लेकिन 2026 टकराव का साल रहने वाला है। यह टक्कर प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष के बीच देखने को मिलेगी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के साथ ही टकराव का जो दौर शुरू हुआ था, वह अब भारतीय राजनीति में एक सिलसिला बनता जा रहा है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मोर्चे पर मोदी सरकार की अग्निपरीक्षा होनी है, तो राहुल गांधी के लिए अपनी कांग्रेस पार्टी को संभालना चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। 2026 में राहुल गांधी जन आंदोलन की सियासत करते दिख सकते हैं। इसमें जेन जी की भूमिका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। मोदी इसका तोड़ निकालने के लिए सालाना बजट में आथ्र्थक सुधार को गति प्रदान कर सकते हैं। अमरीका से व्यापारिक समझौते पर सबकी नजरें होंगी। असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा के नजरिए से देखा जाए तो उसे असम में फिर से जीतना है। केरल और तमिलनाडु में वह न तीन में है और न तेरह में। बंगाल में भाजपा अगर जीती तो चमत्कार होगा और विपक्ष की राजनीति को सदमा लगेगा। लेकिन अगर भाजपा 100 सीट पार करती है तो भी पीठ थपथपाने की अधिकारी होगी। उधर कांग्रेस को हर कीमत पर केरल में तो जीत हासिल करनी ही होगी। केरल के वायनाड से ही प्रियंका गांधी सांसद हैं और केरल की जीत प्रियंका गांधी के खाते में ही जाएगी। असम में कांग्रेस दुविधा में है कि उसे बदरुद्दीन अजमल के साथ जाना चाहिए या नहीं। पिछली बार कांग्रेस को भाजपा से सिर्फ 5 लाख वोट कम मिले थे। वैसे कांग्रेस एक चुनाव हाथ मिलाकर हार चुकी है और एक चुनाव अकेले लड़ कर भी हार चुकी है। कुल मिलाकर देखा

जाए तो विधानसभा चुनावों में बहुत भारी उलटफेर होता दिख नहीं रहा है।

राहुल गांधी लेकिन गांव-गांव, पांव-पांव कार्यक्रम में भारत जोड़ो यात्रा का अक्स देख रहे हैं। मनरेगा का नाम बदल कर जी राम जी करने के खिलाफ 5 जनवरी से गांवों में धरने-प्रदर्शन का सिलसिला कांग्रेस शुरू करने जा रही है। राहुल गांधी को लगता है कि ग्रामीण जनता के सहयोग से इसे जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है और दिल्ली के किसान आंदोलन को दोहराया जा सकता है। अगर किसान वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ गया और विपक्ष ने भी अपना पूरा जोर लगाया तो सियासी खेल में नया रोमांच पैदा हो सकता है। शहरों का युवा और मध्यम वर्ग वैसे ही घटती बचत, बेरोजगारी आदि से परेशान है। यह वर्ग 2024 के लोकसभा चुनावों में अपना गुस्सा सामने ला भी चुका है। राजनीतिक मोर्चे को तो मोदी-अमित शाह की जोड़ी संभाल लेगी, पर आथ्र्थक मोर्चा आंकड़ों के आधार पर फतह नहीं किया जा सकता। जिस देश में विकास दर 8.2 फीसदी हो, उस देश में डालर के मुकाबले रुपया इतना कमजोर क्यों है? उस देश में विदेशी पूंजी निवेश ठहर सा क्यों गया है? उस देश में जी.एस.टी. कलैक्शन स्थिर क्यों होता जा रहा है। उस देश में नौकरियों के मौके बढ़ क्यों नहीं रहे? उस देश में पूंजीपति बैंक में 5 से 6 लाख करोड़ रुपए क्यों रखे हुए हैं, नया उद्योग क्यों नहीं खोल रहे? इन सवालों के जवाब देश चाहता है लेकिन चुप्पी है। क्या यह बताया जाएगा कि ट्रम्प के साथ व्यापार की डील कहां अटकी हुई है और कब तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है?

इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो कार्पोरेट जगत भी तय कर पाएगा कि उसे कितना पैसा लगाना है, कहां लगाना है। चीन से आयात खतरनाक स्तर तक बढ़ता जा रहा है। भारतीय उद्योगपति पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सा उद्योग खोलें जो चीन में नहीं हो। श्रम कानून, बीमा को पूरी तरह से खोलना, परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की अनुमति आथ्र्थक सुधारों की तरफ गंभीर इशारा कर रहे हैं लेकिन भारतीय उद्योग जगत का आत्मविश्वास अभी डगमगाया हुआ है। आर्थिक मोर्चा कहीं न कहीं देश के सामाजिक धार्मिक ताने-बाने से, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इस बार क्रिसमस के मौके पर देश के आधा दर्जन राज्यों में करीब 2 दर्जन घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थीं। दुनिया के 200 देशों में से करीब 120 देश ईसाई धर्म को मानते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में अमीर लोकतांत्रिक देश हैं। अगर माहौल ऐसा विषैला रहेगा तो कौन पूंजी लगाने आएगा? कौन कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के साथ खड़ा नजर आएगा? मुस्लिम बहुल दुनिया में 50 देश हैं जिनकी नाराजगी भारी पड़ सकती है। अगर हर नीति-रणनीति चुनाव को मद्देनजर रख कर बनेगी तो बुनियादी मुद्दों का क्या होगा? कांग्रेस कमजोर है, विपक्ष बिखरा है, संघ बैकफुट पर है, एन.डी.ए. के साथी दल अपने-अपने राज्यों में उलझे हुए हैं, संगठन और सरकार में कोई चुनौती देने वाला नहीं है, लोकप्रियता बरकरार है। यानी सब कुछ मोदी के पक्ष में है। इस मजबूत नींव पर भविष्य की इमारत खड़ी करने का सुनहरा मौका है। हुड़दंगियों पर काबू करना बाएं हाथ का खेल है। संगठन में बदलाव और सरकार में फेरबदल क्या पहला कदम होगा? उसके बाद नए सिरे से मोदी सरकार जनता के बीच दिखेगी, जिसमें नौजवान चेहरे होंगे, नई योजनाएं होंगी और नया कोई नारा होगा। प्रियंका गांधी और मोदी साथ-साथ चाय पी चुके हैं। नए साल में चाय की चुस्कियों का दौर चलता है या चाय के प्याले में तूफान उठता है, देखना दिलचस्प रहेगा।-विजय विद्रोही

2026 शायद हमें भूत और भविष्य, दोनों की सैर कराएगा

स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें स्वीकृत 500 रुपये की सरकारी पेंशन लेने से भी उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि उन्होंने आजादी की लड़ाई पेंशन के लिए थोड़े ही लड़ी थी। खुद्दार तो वे इतने थे कि उन्हें अपनी संतानों, परिजनों व शुभचिंतकों से किसी भी रूप में आर्थिक सहायता लेना गवारा नहीं था। सरकार द्वारा घर देने के प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। उनके पास अपना घर तक नहीं था तो कार या कोई और वाहन होने का सवाल ही नहीं था। इसलिए राजधानी दिल्ली में वे प्रायः बसों से आते-जाते दिखाई देते थे। बाद में उनकी अहमदाबाद वासी बेटी से उनकी दुर्दशा नहीं देखी गई तो वह उन्हें किसी तरह समझा-बुझाकर अपने साथ ले गईं। वर्ष 1998 में 15 जनवरी को अपने सौवें जन्मदिन से कुछ महीनों पहले उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। निधन से कोई साल भर पहले 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया, जबकि पद्मविभूषण से पहले से विभूषित किया जा चुका था। अपने मंत्रिकाल में वे भ्रष्टाचार को लेकर इतने असहिष्णु थे कि भ्रष्टाचारी कितना भी प्रभावशाली या अपना क्यों न हो, उसे बख्शते नहीं थे। एक बार इसी के चलते उन्हें अपना मंत्री पद भी गंवा देना पड़ा था। यह जानना भी दिलचस्प है कि वे जितने बड़े राजनेता, उतने ही अच्छे अर्थशास्त्र के जानकार व लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें तो लिखी ही हैं, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

एन. रघुरामन

हममें से किसी ने भी बॉलीवुड या हॉलीवुड की किसी फिल्म में शायद ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी कैदी को ड्रोन के जरिए सेल से उठाकर बाहर निकाल लिया गया हो। हां, कुछ एक्शन मूवीज में जरूर ड्रोन्स को भाग निकलने या रेस्क्यू ऑपरेशन का अहम हिस्सा बताया गया है।

2026 में यह हकीकत बन सकता है। यूके के प्रिजन गवर्नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष टॉम व्हीटली ने इसी हफ्ते चेतावनी दी है कि सच में जल्द ही ऐसा हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि 100 किलोग्राम तक वजन उठा सकने वाले कृषि कार्यों के लिए बने ड्रोन्स किसी इंसान का वजन उठा सकते हैं। इनके जरिए कैदी जेल से भाग सकते हैं।डीजेआई का एग्रास टी100 ड्रोन ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसानी से तोड़ा जा सकता है, फिर दोबारा जोड़कर जल्दी चार्ज भी किया जा सकता है। व्हीटली के मुताबिक चूंकि बड़े गिरोहों के पास काफी पैसा होता है, इसलिए संगठित गिरोह 20 हजार पाउंड खर्च कर ऐसे ड्रोन ले सकते हैं।उन्होंने चेताया कि लॉजिस्टिक तौर पर यह खतरा अब सामने है। वजह है कि जेलों में ड्रोन डिलीवरी तकनीकी तौर पर इतनी एडवांस हो गई है कि अब यह लगभग उबर ईट्सश जैसी ही है। जेल अधिकारी भी मानते हैं कि कैदी केन्द्रीकृत स्रोत पर ऑर्डर देता है और लोकल ड्रोन ऑपरेटर डिलीवरी कर देता है।

2024 और 2025 के आंकड़े बताते हैं कि दुनियाभर में जेलों के आसपास ड्रोन दिखने और प्रतिबंधित सामान गिराने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ अब ड्रोन को जेलों की सुरक्षा के लिए प्राथमिक खतरा मान रहे हैं। मार्च 2025 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में इंग्लैंड और वेल्स की जेलों में ड्रोन से जुड़ी 1,712 घटनाएं दर्ज हुईं। यह पिछले साल के मुकाबले 43ः ज्यादा और 2021 से करीब 1000ः की भारी बढ़ोतरी है। अमेरिका में भी 479 ड्रोन घटनाएं दर्ज की गईं। जेल अधिकारियों का कहना है कि जेलों में ड्रोन डिलीवरी का पूरा इकोसिस्टम बेहद एडवांस्ड है, जो यूके में कमर्शियल ड्रोन गतिविधियों से कहीं आगे निकल चुका है। जब तकनीक हमें आगे ले जाने और ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है, जो आज मौजूद ही नहीं है- उसी वक्त फूड इन्फ्लुएंसर्स हमें जानबूझकर 150 साल पीछे ले जाकर दिखा रहे हैं कि उस दौर के प्रभावशाली लोग क्या खाते थे। उन्हें क्या पसंद था, वो डिशेज कैसे बनती थीं और आज हम कैसे उनका स्वाद ले सकते हैं। वे इन डिशेज को सिर्फ हेल्दी ही नहीं, बल्कि संजोने लायक इतिहास बता रहे हैं। डॉनी डॉडसन ऐसे ही लोगों में से एक हैं, जिन्होंने करीब 18 महीने पहले 1776 की डिश होकेक्स बनाना शुरू किया। यह शहद और मक्खन में लिपटा कॉर्नमील पैनकेक होता है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन को यह काफी पसंद था। डॉडसन के वीडियो को 1.6 मिलियन व्यूज मिले और आज डॉडसन के पास उस दौर के करीब 200 वीडियो हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर अपनी सीरीज पूरी की और फिर प्राचीन मिस्त्र से लेकर विक्टोरियन इंग्लैंड तक की ऐतिहासिक रेसिपीज बनाने लगे। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फास्ट फूड प्रेम पर उन्होंने कहा कि यह हमारे सांस्कृतिक पतन का संकेत है। वे रेस्टोरेंट्स और किचन में काम करने वाले उस छोटे समूह का हिस्सा हैं, जो भूली-बिसरी रेसिपीज को दोबारा जिंदा कर रहा है। क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो पीढ़ियों तक नहीं बदलतीं। उनमें से एक है खाना। इसीलिए यह आपके और मेरे जैसे लोगों को आकर्षित करता है। मेरे पास मीनाक्षी अम्मल की कुक एंड सी शीर्षक वाली किताबों के कुछ वॉल्यूम हैं। 1951 में जब ये किताबें प्रकाशित हुईं तो उनकी उम्र 45 साल थी। इसमें उन्होंने 1900 से पहले हमारे दादा-पड़दादा के जमाने में बनाई जाने वाली रेसिपीज लिखी थीं। अचंभे की बात नहीं कि उनकी किताब न सिर्फ 2000 के बाद लोकप्रिय हुई, बल्कि आज भी अमेरिकी विश्वविद्यालयों में गाइड के तौर पर इस्तेमाल की जाती है।

गिग वर्कर्स की हड़ताल

स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें स्वीकृत 500 रुपये की सरकारी पेंशन लेने से भी उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि उन्होंने आजादी की लड़ाई पेंशन के लिए थोड़े ही लड़ी थी। खुद्दार तो वे इतने थे कि उन्हें अपनी संतानों, परिजनों व शुभचिंतकों से किसी भी रूप में आर्थिक सहायता लेना गवारा नहीं था। सरकार द्वारा घर देने के प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। उनके पास अपना घर तक नहीं था तो कार या कोई और वाहन होने का सवाल ही नहीं था। इसलिए राजधानी दिल्ली में वे प्रायः बसों से आते-जाते दिखाई देते थे। बाद में उनकी अहमदाबाद वासी बेटी से उनकी दुर्दशा नहीं देखी गई तो वह उन्हें किसी तरह समझा-बुझाकर अपने साथ ले गईं। वर्ष 1998 में 15 जनवरी को अपने सौवें जन्मदिन से कुछ महीनों पहले उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। निधन से कोई साल भर पहले 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया, जबकि पद्मविभूषण से पहले से विभूषित किया जा चुका था। अपने मंत्रिकाल में वे भ्रष्टाचार को लेकर इतने असहिष्णु थे कि भ्रष्टाचारी कितना भी प्रभावशाली या अपना क्यों न हो, उसे बख्शते नहीं थे। एक बार इसी के चलते उन्हें अपना मंत्री पद भी गंवा देना पड़ा था। यह जानना भी दिलचस्प है कि वे जितने बड़े राजनेता, उतने ही अच्छे अर्थशास्त्र के जानकार व लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें तो लिखी ही हैं, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

नए साल की पूर्व संध्या पर देश में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसकी कल्पना सुविधाभोगी संपन्न तबके ने नहीं की थी। 31 दिसंबर को देश भर के डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स हड़ताल पर उतर आए। इसका मतलब यह हुआ कि स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से जुड़े हजारों डिलीवरी पार्टनर्स ने बुधवार को ऐप बंद करके काम रोका, जबकि यह दिन उनके लिए काम के लिहाज से सबसे व्यस्ततम दिनों में से एक होता है। कुछ साल पहले तक पड़ोस के परचून की दुकान वाला घर पहुंच सेवा दिया करता था। हालांकि उसमें कोई समयसीमा नहीं होती थी, फिर भी बुजुर्गों, अकेले रहने वालों या अन्य तरह से जरूरतमंदों के लिए यह बड़ी सुविधा होती थी। इसी चलन को मोबाइल ऐप्स पर आधारित कर एक नए किस्म का व्यवसाय खड़ा कर दिया गया। घर बैठे 10 मिनट में सारी चीजें मिलने लगीं, मानो कोई चिराग का जिन्न हो, जो आदेश देते ही उसे पूरा कर दे। पलक झपकते ही इच्छा पूरी होने वाली बात मुहावरे तक सीमित नहीं रही, उसे गिग वर्कर्स ने सच कर दिखाया। हालांकि इसमें उनके लिए जो खतरे बढ़े, उसे पहचानते हुए भी दूर करने की पहल नहीं की गई। इसलिए अब उन्हें हड़ताल पर उतरना पड़ा है।यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन यानी टीजीपीडब्ल्यूयू और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यानी आईएफएटी के बैनर तले की गई। आईएफएटी ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को लिखे एक खत में 10 मिनट की असुरक्षित डिलीवरी व्यवस्था पर रोक लगाने, सही मजदूरी देने, हाल ही में लागू नए श्रम कानूनों के तहत कंपनियों को नियमों में लाने और यूनियन बनाने तथा मोल-भाव करने के अधिकार को मान्यता देने की मांग की है। टीजीपीडब्ल्यूयू के नेता शेख सलाउद्दीन का कहना है कि प्लेटफॉर्म कंपनियां श10 मिनट डिलीवरीश का विकल्प पूरी तरह हटा दें, क्योंकि इससे कर्मचारियों पर बहुत दबाव पड़ता है और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। इसके साथ ही, पुरानी भुगतान व्यवस्था बहाल की जाए, जिसमें त्योहारों जैसे दशहरा, दीवाली और बकरीद पर अच्छा वेतन और भत्ता मिलता था।गौरतलब है कि इस साल की शुरूआत में सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड को लागू किया, जिससे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार एक औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में लाया गया। इससे इन कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस पर रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और वे स्वास्थ्य, विकलांगता, दुर्घटना बीमा और बुढ़ापे की सहायता जैसी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे। इसका मकसद लाखों कर्मचारियों को उनकी गैर-परंपरागत नौकरी के बावजूद बुनियादी सुरक्षा देना है। सोशल सिक्योरिटी

कोड, 2020 के तहत, पहली बार शिगग वर्कर्सश, श्प्लेटफॉर्म वर्कर्सश और शएग्रीगेटर्सश कंपनियों की परिभाषा दी गई है। इस कोड में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने की योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें, कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी की राशि, जुर्माने आदि से पैसा आएगा।ये सारे प्रावधान सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीन पर ये कितने उतरे हैं, इसकी हकीकत साल के आखिरी दिन हुई हड़ताल ने जाहिर कर दी। प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं कि वे श्रम का सम्मान करते हैं, लेकिन ये हड़ताल कुछ और ही कहानी बयां करती है। असल में ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और सबूत है। सरकार युवाओं को रोजगार के नाम पर पकौड़ा तलने और रील बनाने की सलाह देती है। जो लोग ये नहीं कर पा रहे, वो अब गिग वर्कर बनने पर मजबूर हैं। नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2020 में भारत में लगभग 77 लाख गिग वर्कर्स थे, जिनकी संख्या 2030 तक बढ़कर 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। गिग अर्थव्यवस्था में युवाओं (16 से 23 वर्ष आयु वर्ग) की भागीदारी 2019 से 2022 के बीच आठ गुना बढ़ी है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि स्थायी रोजगार न मिलने की वजह से युवा वर्ग डिलीवरी का काम करने पर मजबूर है। उसकी मजबूरी का फायदा कंपनियां उठा रही हैं।शेख सलाउद्दीन कहते हैं, डिलीवरी करने वाले वर्कर्स की फीस को दिन ब दिन कम किया जा रहा है। प्रति ऑर्डर पहले 80 रुपये फिर 60 रुपये और अब 10 रुपये 20 रुपये, 15 रुपये तक दे रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कंपनियां हमें धमकी दे रही हैं। वेयरहाउस के पास बाउंसर तैनात किए जा रहे हैं और कर्मचारियों के आईडी ब्लॉक किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन कंपनियों को सरकार का बिलकुल खौफ नहीं है, जो वो डिलीवरी करने वाले कर्मियों के वेतन मनमाने तरीके से कम कर रही है, और उन्हें मजबूर कर रही है कि वो काम करें। क्या श्रम मंत्रालय भी इस इंतजार में था कि गिग वर्कर्स अपनी मांगों को सामने रखने के लिए हड़ताल करें, तब उन्हें सुना जाएगा। इस काम में जुड़े 70-80 लाख लोग अगर अपनी आजीविका और अपनी जिंदगी की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, तो सरकार को इस बारे में पता क्यों नहीं चला। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हड़ताल हुई है। पिछले हफ्ते यानी 25 दिसंबर को भी ऐसी ही हड़ताल हुई थी, जिसमें पूरे देश से करीब 40 हजार कर्मचारी शामिल हुए थे, और 31 तारीख की हड़ताल में 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उनकी मांगे थीं कि एल्गोरिदम से कंट्रोल होने वाली सिस्टम में पारदर्शिता लाई जाए। सही इंसेंटिव दिए जाएं। शिकायत निवारण की अच्छी व्यवस्था हो। हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर और पेंशन जैसी सोशल सिक्योरिटी मिले। महिलाओं के लिए सुरक्षित कामकाज, मेटर्निटी लीव और इमरजेंसी लीव हो। प्रति किलोमीटर कम से कम 20 रुपये की न्यूनतम दर हो और मनमाने तरीके से आईडी ब्लॉक करना बंद हो।कर्मचारियों ने अपील की है कि, इस मामले श्सरकार को तुरंत दखल देना चाहिए।

कहानी

रंगा सियार

एक बार की बात है कि एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता-घिसटता अपनी मांद तक पहुंचा। कई दिन बाद वह मांद से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी। शरीर कमजोर हो गया था तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झपटा। सियार कुछ दूर भाग कर हांफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहां रह गई थी? फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की। यहां भी वह असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी न हुई। वह खड़ा सोचने लगा। शिकार वह कर नहीं पा रहा था। भूखों मरने की नौबत आई ही समझो। क्या किया जाए? वह इधर-उधर घूमने लगा पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता-घूमता वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए। सो, वह इधर-उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं-भौं करते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा पर कुत्ते तो कस्बे की गली-गली से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता चला गया। सियार सांस रोक कर रंग में डूबा रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है तो वह बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग हरा हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने हरा रंग घोल रखा था। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता, वह भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कांपते देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज दी, 'भाईयों, भागो मत मेरी बात सुनो।' उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर ठिठके। उनके ठिठकने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, 'देखो-देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है? नहीं ना। मतलब समझो। भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं।' उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, 'वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हार नाम सम्राट ककुदुम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर रहो।' सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते की भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लोटने लगे और एक स्वर में बोले, 'हे बह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ ककुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी।' एक बूढ़े हाथी ने कहा, 'हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है?' रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, 'तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने-पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए।' शेर ने सिर झुकाकर कहा, 'महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।' बस, सम्राट ककुदुम बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वह राजसी शान से रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहतीं, भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, उसकी बलि दी जाती।

भविष्य के भारत को बनाने का समय

बीता वर्ष भारत के लिए चुनौतियों भरा रहा। अमेरिकी नीति ने भारत के निर्यात, रुपये की हैसियत, निवेश तथा भुगतान संतुलन आदि को लेकर मुश्किलें खड़ी कर दीं। राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिकी हितों को आक्रामक ढंग से आगे धकेलने की नीति ने हमारा अहित किया। इसे देखते हुए स्थिति को संभालने के लिए भारत ने कई कदम उठाए गए। जीएसटी की दरें कम की गईं और श्रम कानूनों में बदलाव लाया गया। यह बड़ी उपलब्धि है कि अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितिता की विकट परिस्थितियों में भी भारत की जीडीपी की दर विश्व में अव्वल दर्जे की बनी रही। खुदरा महंगाई दर भी आठ साल में सबसे कम रही। अच्छी पैदावार, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, कच्चे तेल की कम कीमतों ने इन परिस्थितियों में मदद की। शेयर बाजार में घरेलू निवेशक हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत बने। आयकर रिटर्न के दाखिलों और कर-संग्रह में भी सुधार हुआ। बिजली, शहरी विकास, खनन, और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में नई पहलें की गईं। भारत एक बड़ी वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है और अनुमान है कि 2030 तक 7.3 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर जीडीपी के साथ वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सामाजिक संरचना की दृष्टि से देश में मध्यम वर्ग का आकार बढ़ रहा है, जिससे खपत और शहरीकरण में वृद्धि और गरीबी में कमी के आसार बन रहे हैं।

पिछले एक दशक में भारत की छवि निश्चित रूप से एक सशक्त देश के रूप में निखरी है। नए वर्ष में इस बदलते भारत के भविष्य के बारे में सोचते हुए हमें देश की समृद्ध प्राचीन सभ्यता और आधुनिक राष्ट्र-राज्य की संकल्पना, दोनों को ध्यान में रखना होगा। लोक की स्मृति में अभी भी नैतिक और न्यायपूर्ण शासन के लिए रामराज्य की अमिट छवि कायम है। इसलिए जहां वैश्वीकरण के अनुकूल आकांक्षाओं को ध्यान में रखना होगा, वहीं नैतिकता, सत्य तथा अहिंसा जैसे मानदंडों की भी चिंता करनी है। देश की प्रगति की कथा को देखें तो उसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व मिलते हैं।

इस नए वर्ष में हमें संयत होकर यह विचार करना होगा कि विकसित भारत कैसा होगा, क्योंकि भारतीय समाज में अनेक प्रकार की बहुलताएं हैं, जिसे लेकर कुछ विचारक देश की मौलिक एकता को प्रश्नांकित करते हैं। वे भूल जाते हैं कि भारतीय दृष्टि में बहुलता अंतर्निहित मौलिक एकता का ही प्रकटन होती है- एकम् सद् विप्रा बहुधा वदंति। इसी एकता को खोजना पहचानने का उद्देश्य होना चाहिए। पूरे प्राणी जगत में निकटता को आधार बना कर विविधताओं का सह-अस्तित्व और पारस्परिक संवाद इस भारत का मौलिक सोच रहा है। यह अकारण नहीं है कि परिवार या कुटुंब का रूपक हमारे सोच में केंद्रीय है। देश की एकता, देश को अपनाने के भाव और देशप्रेम के लिए भी यह दृष्टि जरूरी है।

बीता वर्ष भारत के लिए चुनौतियों भरा रहा। अमेरिकी नीति ने भारत के निर्यात, रुपये की हैसियत, निवेश तथा भुगतान संतुलन आदि को लेकर मुश्किलें खड़ी कर दीं। राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिकी हितों को आक्रामक ढंग से आगे धकेलने की नीति ने हमारा अहित किया। इसे देखते हुए स्थिति को संभालने के लिए भारत ने कई कदम उठाए गए। जीएसटी की दरें कम की गईं और श्रम कानूनों में बदलाव लाया गया। यह बड़ी उपलब्धि है कि अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितिता की विकट परिस्थितियों में भी भारत की जीडीपी की दर विश्व में अव्वल दर्जे की बनी रही।

खुदरा महंगाई दर भी आठ साल में सबसे कम रही। अच्छी पैदावार, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, कच्चे तेल की कम कीमतों ने इन परिस्थितियों में मदद की। शेयर बाजार में घरेलू निवेशक हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत बने। आयकर रिटर्न के दाखिलों और कर-संग्रह में भी सुधार हुआ। बिजली, शहरी विकास, खनन, और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में नई पहलें की गईं। भारत एक बड़ी वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है और अनुमान है कि 2030 तक 7.3 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर जीडीपी के साथ वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

सामाजिक संरचना की दृष्टि से देश में मध्यम वर्ग का आकार बढ़ रहा है, जिससे खपत और शहरीकरण में वृद्धि और गरीबी में कमी के आसार बन रहे हैं। देश में बुनियादी ढांचा विस्तृत हो रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा (एआइ), अंतरिक्ष विज्ञान, मेट्रो और बुलेट ट्रेन आदि को लेकर भी प्रगति दर्ज हो रही है। मेड इन इंडिया के तहत मैन्यूफैक्चरिंग, आइटी, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप्स में भारी वृद्धि से रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं। उत्पादन क्षेत्र में प्रगति की संभावना दिख रही है और स्वदेशी विकास की नीति अपनाई जा रही है। अनुमान है कि 5-जी और रोबोटिक्स के उपयोग का दायरा विस्तृत होता जाएगा। अब आनलाइन खरीदारी और ओटीटी प्लेटफार्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। भविष्य में एआइ का प्रभुत्व और भी बढ़ेगा। उसी के साथ साइबर अपराध भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा बड़ा महत्वपूर्ण सरोकार बन रहा है। यह भी याद रखना जरूरी है कि देश का भविष्य सिर्फ आर्थिक उन्नति के सूचकों तक सीमित नहीं किया जा सकता। आर्थिक विकास को केवल वृद्धि दर के अर्थ में ही नहीं, बल्कि रोजगार के अधिक अवसर, सामाजिक गतिशीलता और आम जनों के जीवन-स्तर में उन्नति के संदर्भ में भी देखना होगा। सबके लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए आर्थिकी को ज्ञान-केंद्रित और सामाजिक रूप से ज्यादा उत्तरदायी भी बनाना होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए अवसर है, पर हम अपनी सीमाओं को भी अनदेखा नहीं कर सकते। युवा भारत को अक्सर एक पूंजी के रूप में घोषित किया जाता है, पर इसके लिए कौशल, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करना होगा। कौशल विकास की कमी और युवाओं में बेरोजगारी के चलते समाज में असंतोष पैदा हो रहा है। नई शिक्षा नीति की विसंगतियों को दूर कर उसके कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। शिक्षा की पहुंच, उसकी गुणवत्ता और प्रासंगिकता को लेकर संशय बना हुआ है। इसी तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। अभी भी महिला श्रम-भागीदारी निम्न दर पर है। आय और संपत्ति की असमानता भी बढ़ी है और अनौपचारिक क्षेत्र की असुरक्षा बनी हुई है।

सम्पादकीय

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, दो हफ्तों में तीन हत्याएं

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की हिंसक घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले दो सप्ताह में वहां तीन हिंदू नागरिकों की हत्या कर दी गई। इससे हिंदू समुदाय के भीतर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं, जब बांग्लादेश में आए दिन विरोध प्रदर्शनों से अराजक स्थिति पैदा हो रही है। सवाल है कि ऐसे हमले अचानक हो रहे हैं या फिर किसी गहरी साजिश के तहत इस तरह की हिंसा का जाल बुना जा रहा है! ऐसे में वहां की अंतरिम सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। हालांकि, सरकार का दावा है कि इन घटनाओं को सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। अगर यह सही है, तो फिर क्या वजह है कि अल्पसंख्यकों को ही लक्षित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है? कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जाहिर है कि जिस तरह की अराजक स्थिति पैदा हो रही है, उसके लिए शासन एवं प्रशासन ही जवाबदेह हैं। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ था। अंतरिम सरकार बनने के बाद वहां माहौल थोड़ा शांत और स्थिर हुआ था, लेकिन हाल के दिनों में हिंसा फिर से जोर पकड़ने लगी है। खासकर अब हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दो सप्ताह के भीतर तीन हिंदू नागरिकों की हत्या कर दी गई। पहले भालुका इलाके में भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इसके कुछ दिन बाद मैमनसिंह जिले में एक हिंदू नागरिक की हत्या कर दी गई। हाल ही में कपड़े के कारखाने में एक हिंदू कर्मी को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में स्थानीय पुलिस का दावा है कि आरोपी ने मजाक में हिंदू व्यक्ति की तरफ बंदूक तानी थी और इस दौरान अचानक गोली चल गई। जबकि घटना के चश्मदीद का कहना है कि आरोपी ने जान-बूझकर गोली चलाई। बयानों के इस विरोधाभास से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह बात छिपी नहीं है कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और उनके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। अत्याचार, प्रताड़ना, जबरन धर्मांतरण और हिंसा की वजह से वहां हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद से हिंदू समुदाय के लोगों पर लक्षित हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं। वहां जिस उद्देश्य से अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, वह पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की विफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न तो विरोध प्रदर्शन थम रहे हैं और न ही हिंसक गतिविधियों पर अंकुश लग पाया है। इसका असर भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ा है। मगर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां की अंतरिम सरकार भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर गंभीर नहीं है।

दिनचर्या से पहचानी जा सकती है बच्चों में बढ़ती एकाग्रता की कमी

एडीएचडी के पीछे कई शारीरिक और मानसिक कारण होते हैं। फास्ट फूड और जंक फूड का बढ़ता चलन, कम उम्र में मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग, थायराइड ग्रंथि से जुड़े विकार, कोई पुराना शारीरिक दर्द, वायु प्रदूषण, पर्याप्त नींद का अभाव, मानसिक तनाव, स्ट्रेस और अवसाद–ये सभी इसके प्रमुख ट्रिगर माने जाते हैं। यदि एडीएचडी के लक्षणों पर ध्यान दिया जाए, तो इसकी पहचान रोजमर्रा की दिनचर्या से आसानी से की जा सकती है। ऐसा बच्चा या व्यक्ति किसी एक काम, पढ़ाई या बातचीत पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता, विशेषकर जब काम उबाऊ या लंबा हो। विद्यालय या किसी कार्यक्रम में लंबे समय तक बैठने पर बेचैनी महसूस होती है। जरूरी बातें जैसे परीक्षा की तारीख, होमवर्क या अपॉइंटमेंट भूल जाना आम बात हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति कोई काम शुरू तो करता है

वर्तमान समय में बच्चों और युवाओं में एकाग्रता की कमी एक गंभीर और चिंताजनक समस्या के रूप में सामने आ रही है। बदलती जीवनशैली, असंतुलित खानपान, मोबाइल व स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता, नैतिक एवं संस्कारिक शिक्षा का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण तथा बढ़ता मानसिक दबाव–ये सभी कारक बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। परिणामस्वरूप मानसिक विकृतियाँ बढ़ रही हैं और इसी संदर्भ में एक शब्द तेजी से प्रचलन में आया है–एडीएचडी।

-लीलाधर शर्मा
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी गुंसाईसर, रतनगढ़, चूरू

एडीएचडी यानी अटेंशन डिफिसिएट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। सामान्य भाषा में कहें तो यह वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति किसी भी कार्य में लंबे समय तक सही ढंग से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। यह समस्या केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज बड़ी संख्या में वयस्क भी इससे प्रभावित हैं।

एडीएचडी के पीछे कई शारीरिक और मानसिक कारण होते हैं। फास्ट फूड और जंक फूड का बढ़ता चलन, कम उम्र में मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग, थायराइड ग्रंथि से जुड़े विकार, कोई पुराना शारीरिक दर्द, वायु प्रदूषण, पर्याप्त नींद का अभाव, मानसिक तनाव, स्ट्रेस और अवसाद–ये सभी इसके प्रमुख ट्रिगर माने जाते हैं।

यदि एडीएचडी के लक्षणों पर ध्यान दिया जाए, तो इसकी पहचान रोजमर्रा की दिनचर्या से आसानी से की जा सकती है। ऐसा बच्चा या व्यक्ति किसी एक काम, पढ़ाई या बातचीत पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता, विशेषकर जब काम उबाऊ या लंबा हो। विद्यालय या किसी कार्यक्रम में लंबे समय तक बैठने पर बेचैनी महसूस होती है। जरूरी बातें जैसे परीक्षा की तारीख, होमवर्क या अपॉइंटमेंट भूल जाना आम बात हो जाती है।

अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति कोई काम शुरू तो करता है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता। समय प्रबंधन और व्यवस्थापन में कठिनाई रहती है। एक साथ कई काम शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। बिना अधिक श्रम किए ही मानसिक थकान महसूस होना, 'ब्रेन फॉग' यानी मानसिक धुंधलापन, साधारण प्रश्नों का उत्तर न सूझ पाना और हाजिरजवाबी की कमी भी इसके प्रमुख लक्षण हैं।

ध्यान की कमी के कारण रोजमर्रा के कार्यों में लापरवाही भरी गलतियाँ होती हैं। दैनिक जीवन के छोटे-छोटे उदाहरण–जैसे सुबह उठकर बिस्तर ठीक न करना, कपड़े और जूते इधर-उधर छोड़ देना, स्नानघर में कपड़े वहीं पड़े रहना, पढ़ने की मेज और स्कूल बैग का अस्त-व्यस्त होना–ये सभी व्यवस्थापन और सजगता की कमी के संकेत हैं। अक्सर लोग इसे आदत या लापरवाही समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह मस्तिष्क की कार्यशैली से जुड़ा विषय है।

कई बार ऐसा व्यक्ति दूसरों की बात गंभीरता से नहीं सुन पाता, जिससे सामने वाले को लगता है कि वह परवाह नहीं करता, जबकि वास्तविक कारण एकाग्रता की कमी होती है। कार्यों को जल्दबाजी में करना, गुणवत्ता की चिंता न करना और फिर भी काम पूरा न हो पाना–यह स्थिति आगे चलकर जीवन की उपलब्धियों को प्रभावित करती है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जो व्यक्ति छोटे-छोटे दैनिक कार्यों को भी एकाग्रता के साथ पूर्ण करता है, वही आगे चलकर अध्ययन, व्यवसाय या नौकरी के क्षेत्र में अपनी क्षमता का सही प्रदर्शन कर पाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति दिनचर्या के काम भी अव्यवस्थित छोड़ देता है, उसका असर भविष्य में करियर और जीवन की सफलता पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह केवल वास्तु या बाहरी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की एकाग्रता और कार्य क्षमता से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक तथ्य है।

एडीएचडी केवल बच्चों की समस्या नहीं है। वयस्कों में भी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं–जैसे एक जगह देर तक न बैठ पाना, बार-बार बैठने की मुद्रा बदलना, बेचैनी और बार-बार घड़ी देखना।

हालांकि राहत की बात यह है कि एडीएचडी कोई लाइलाज समस्या नहीं है। सही दिशा, अनुशासन और जागरूकता से इसमें काफी हद तक सुधार संभव है। बच्चों को संतुलित और संस्कारयुक्त शिक्षा देना, स्वास्थ्य और करियर के प्रति जागरूक करना, अनुशासित जीवनशैली अपनाना, फास्ट फूड के स्थान पर फल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और संतुलित शाकाहारी भोजन लेना, नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान, पर्याप्त नींद तथा सकारात्मक काउंसलिंग–ये सभी उपाय एडीएचडी की समस्या को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

समय रहते यदि दिनचर्या सुधारी जाए और एकाग्रता को जीवन का मूल आधार बनाया जाए, तो न केवल मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि जीवन भी अधिक व्यवस्थित, संतुलित और सफल बनता है।

नया कालखंड, नए साल से नई उम्मीदें

नव वर्ष का आगमन अनेक अपेक्षाओं के साथ होता है। इस अवसर पर सभी शुभ की कामना करते हैं। हम भारत के लोग तो उस संस्कृति के वारिस हैं, जो प्राणिमात्र के कल्याण की बात करती है और समस्त वसुधा को एक कुटुंब की तरह देखती है, लेकिन सर्वत्र शुभ का संचार होने की चाह के बीच यह भी एक यथार्थ है कि व्यक्ति की तरह समाज और राष्ट्र के जीवन में चुनौतियां आती ही रहती हैं। वे इस वर्ष भी आएंगी। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि इस नए वर्ष में हम उनका सही तरह सामना करने में समर्थ हों और तेजी के साथ प्रगति के उस पथ पर आगे बढ़ें, जिसमें सुख, समृद्धि के साथ समरसता भी बढ़े। यह तब संभव होगा, जब एक राष्ट्र के रूप में हमारी कार्यसंस्कृति बदलेगी और उन बुनियादी समस्याओं का समाधान होगा, जो प्रगति की राह में रोड़ा हैं। वैसे

तो किसी भी देश की कार्यसंस्कृति बदलने का दायित्व मुख्यतः शासन और प्रशासन में बैठे लोगों का होता है, लेकिन इस काम में जनता का सहयोग भी आवश्यक होता है। विश्व के कई देशों का इतिहास इसकी ही गवाही देता है कि उनका भाग्योदय तब हुआ, जब वहां के शासकों के साथ आम लोगों ने भी अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समर्पण भाव से काम किया। अब भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। विशाल आबादी और भिन्न पंथ, भाषा वाले देश की प्रगति के लिए शासन-प्रशासन के साथ आम जनता का रुख-रवैया बदले बगैर बात बनने वाली नहीं है। यह समझा जाए कि जैसे शासक का धर्म होता है, वैसे ही नागरिक का भी। विभिन्न समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन के लोगों को उचित ही कठघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन यह प्रश्न प्रायः अनुत्तरित रहता है कि क्या हम भारत के लोग अपने नागरिक धर्म का निर्वाह सही तरह करते हैं? हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना ही चाहिए, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों को लेकर भी सचेत रहते हैं? यदि हमारी अनेक समस्याओं का समाधान शासन-प्रशासन की ढिलाई के चलते नहीं हो पाता तो कई समस्याएं इसलिए जटिल बनी रहती हैं कि लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। यदि जन सहयोग का यह अभाव दूर हो सके तो इस नए वर्ष में आत्मनिर्भर भारत की राह और आसान हो सकती है और यह किसी से छिपा नहीं कि आत्मनिर्भरता विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पाने की कुंजी है। 2025 की विदाई के साथ ही देश उस नए कालखंड में प्रवेश कर रहा है, जब विकसित भारत का लक्ष्य और निकट आ गया है। यह लक्ष्य वास्तव में प्राप्त हो सके, इसके लिए मानसिकता में बदलाव लाना भी आवश्यक है।

अगर आपका मन साफ और पवित्र है, तो वही सबसे बड़ा तीर्थ है।
-संत रविदास

सफलता भरी शुरुआत

भारत के रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र ने नव वर्ष का आरंभ उपलब्धियां हासिल करके की हैं, ये मात्र तकनीकी सफलताएं नहीं, बल्कि देश की बदलती सामरिक सोच और आत्मनिर्भरता का स्पष्ट संकेत हैं। एक ओर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक ही लॉन्चर से दो प्रलय मिसाइलें दागकर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण के तीसरे चरण का सफल जमीनी परीक्षण कर अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई। रक्षा और अंतरिक्ष—दोनों मोर्चों पर यह साल का समापन भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रलय मिसाइल को एक ही लॉन्च में दो अलग-अलग लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने की क्षमता के कारण बेहद कारगर हथियार माना जा रहा है। इसकी अनुमानित रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच है और यह उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना सकती है। युद्ध की स्थिति में 'डबल अटैक' क्षमता दुश्मन के एयरबेस, बंकरों, कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक हब को एक साथ पंगु बनाने में निर्णायक साबित हो सकती है।

जब एक जगह पर हमला होता है और उसी समय दूसरे स्थान पर भी हो, तो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। यह तकनीक उसके प्रतिक्रिया समय को घटाती है और उसे रणनीति बनाने का अवसर नहीं देती। इस मिसाइल की यह खूबी इसे युद्ध की स्थिति में 'गेम चेंजर' बनाती है। प्रलय जो एक क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी यह उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है और दुश्मन के रडार व एयर-डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। चीन के पास डीएफ-सीरीज़ और पाकिस्तान के पास अब्दाली-नस्र जैसे हथियार हैं, लेकिन भारत की प्रलय आधुनिक युद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित स्वदेशी प्रणाली है। लिक्विड या तरल नोदक भरने में समय लगता है। इसमें ठोस ईंधन यानी सॉलिड प्रोपेलेंट का उपयोग इसे 'रेडी-टू-फायर' बनाता है, जिससे बहुत कम समय में लॉन्च संभव होता है। लांचिंग की यह तीव्रता और विशेष तकनीकी इंटरसेप्ट करना कठिन बनाती है और इसे विश्व की प्रभावशाली मिसाइल प्रणालियों की कतार में खड़ा करती है। हालिया परीक्षण संकेत देता है कि यह प्रणाली सेना के बेड़े में शामिल होने के लिये तैयार है, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों की सामरिक ताकत बढ़ जाएगी।

यह उपलब्धि भारत की रक्षा नीति में एक सूक्ष्म, लेकिन स्पष्ट बदलाव का संकेत भी देती है। अब केवल रक्षात्मक क्षमता नहीं, बल्कि सटीक और सीमित आक्रामक प्रतिरोध पर जोर है। इसी कड़ी में इसरो द्वारा एसएसएलवी के तीसरे चरण का जमीनी परीक्षण भविष्य के लिए अत्यंत अहम है। एसएसएलवी भारत को छोटे उपग्रहों के त्वरित और किफायती प्रक्षेपण में वैश्विक बाजार का बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। रक्षा, संचार और आपदा प्रबंधन के लिए छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह सफलता रणनीतिक भी है। नए वर्ष में डीआरडीओ से हाइपरसोनिक, ड्रोन-रोधी और उन्नत वायु-रक्षा प्रणालियों पर प्रगति की उम्मीद है, वहीं इसरो गगनयान, नए लॉन्च वाहनों और व्यावसायिक मिशनों में आगे बढ़ सकता है।

प्रसंगवश

हिंदी के दो लाख नए शब्द गढ़ने वाले आचार्य रघुवीर

वर्तमान समय में हिंदी की गणना विश्व की समृद्ध भाषाओं में की जाती है। हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने बाली तीसरी भाषा बन गई है। आज हिंदी पूरे विश्व में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा को इस महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचाने के लिए हिंदी के अनेक भाषाविदों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आचार्य रघुवीर की गणना हिंदी के इन्ही अग्रणी विद्वानों और भाषाविदों में की जाती है। वे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे।

संस्कृत भारत की ही नहीं, विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है। इसे सप्रमाण सिद्ध करने वाले आचार्य रघुवीर की गणना संस्कृत और हिंदी के अग्रणी विद्वानों में की जाती है। उनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था। वर्तमान समय में रावलपिंडी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। इनके पिता मुंशी राम जी एक विद्यालय में प्राचार्य थे। उनकी माता जयावती एक धर्मपरायण महिला थीं। घर का वातावरण धार्मिक और सादगीपूर्ण था।

सुरेश बाबू मिश्रा
साहित्यकार

अपने छात्र जीवन से ही रघुवीर संस्कृत एवं अंग्रेजी में कविता लिखने लगे। सभी भाषाओं के बारे में अधिक से अधिक जानने की उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी और वे हर भाषा के व्याकरण को गहराई से समझने का प्रयत्न करते थे। संस्कृत भाषा के विद्वान एवं व्याकरण के आचार्य पाणिनी का जन्म रावलपिंडी के निकट शालापुर ग्राम में हुआ था। रघुवीर जी का व्याकरण के प्रति अतिशय प्रेम देखकर इनके गुरुजन समझ गए कि यह बालक पाणिनी के कार्यों को ही आगे बढ़ाएगा। अगर आचार्य रघुवीर को आधुनिक पाणिनी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

प्राथमिक शिक्षा के बाद रघुवीर जी ने लाहौर के डीएवी विद्यालय से संस्कृत में एमए किया। अब तक वे अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, रूसी तथा जापानी भाषा में अत्यंत निपुण हो चुके थे। अब अजमेर आकर उन्होंने महर्षि दयानंद की अष्टाध्यायी का संपादन किया। 1925 में आचार्य रघुवीर का विवाह हुआ। 1928 में लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी कर वे लाहौर में ही संस्कृत के प्राध्यापक हो गये। अध्यापन के साथ ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय हुए और 'हिंदू रक्षक संघ' की स्थापना की। 1942 में वे सीपी एंड बरार से संविधान सभा के सदस्य बने तथा 1949-50 तक इस पद पर रहे। उनकी योग्यता देखकर कांग्रेस ने 1952 से 62 तक उन्हें राज्यसभा में सांसद बनाया।

उन्होंने विश्व भर से अनेक भाषाओं में उपलब्ध महाभारत तथा रामायण ग्रंथों की पांडुलिपियों को एकत्र कर वृहत् शोध किया। उन्होंने इंडोनेशिया के जावा द्वीप में जोग्या नगर के पास स्थित मंदिरों पर उत्कीर्ण रामकथा के चित्रों को भी संकलित किया। विलुप्त हो चुके संस्कृत एवं भारतीय साहित्य को एकत्र करने के लिए उन्होंने 1934, 46 और 56 में क्रमशः लाहौर, नागपुर और दिल्ली में 'सरस्वती विहार' की स्थापना की।आचार्य जी ने हिंदी भाषा में दो लाख नये शब्द गढ़े। उनकी योजना 20 लाख नये शब्द बनाने की थी; पर उनके असमय निधन से यह काम रुक गया। उन्होंने जो शब्दकोश बनाया, वह आज भी हिंदी में मानक कोश माना जाता है।

1962 में चीन के आक्रमण के समय शासन की नीति से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद वे भारतीय जनसंघ से जुड़े और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1963 में उपचुनाव के समय जब वे डॉ. राममनोहर लोहिया के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर लौट रहे थे, तो 14 मई को कानपुर के पास हुई वाहन दुर्घटना में उनका देहांत हो गया।

जब बेअसर हो जाए ग्रेप पाबंदी भी

पंकज चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

इसे स्वास्थ्य का आपातकाल कहा जा सकता है, 13 दिसंबर को ग्रेप-4 लागू हो गया, अर्थात अभी तक सांसों में जहर भरने के जो संभावित कारण कहे जाते थे, सभी पर सख्ती से पाबंदी, उसके बावजूद 31 दिसंबर की सुबह दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से पार था। जाहिर है कि या तो हम वायु प्रदूषण के असली कारणों का आकलन नहीं कर पा रहे या फिर ऐसे कड़े कदम उठाने से बच रहे हैं, जिससे हालात सुधारे जा सकें। बारीकी से देखें तो साफ होता है कि हमारा सारा ध्यान बढ़ गए प्रदूषण को काम करने में अधिक है, जबकि सारे तंत्र को प्रदूषण कम हो, इसके लिए काम करना होगा। दुर्भाग्य है कि सरकारी प्रक्रिया, ऊपर से नल खोल कर नीचे पोंछा लगा कर फर्श सुखाने की कवायद से अधिक नहीं है।

लगता है सब रस्म अदायगी है, दीवाली के साथ ही अदालत डांटने लगती है। सरकार विज्ञापन देने लगती है और अस्पतालों में बीमारों की भीड़ बढ़ जाती है। आंकड़ों कि बौछार होती है कि जहरीली हवा किस तरह सांस, दिल, हड्डी से ले कर मानसिक रोग तक का कारण बन रही है। हालांकि दिल्ली समग्र राजधानी क्षेत्र में बरसात के कुछ दिनों को छोड़ कर पूरे साल ही हवा में इतना जहर होता है कि न केवल इंसान की आयु रेखा छोटी होती है, बल्कि ढेर सारी बीमारियों के फेर में उसकी जेब में भी छेद होता है।

> 31 दिसंबर की सुबह दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार था। जाहिर है कि या तो हम वायु प्रदूषण के असली कारणों का आकलन नहीं कर पा रहे या फिर ऐसे कड़े कदम उठाने से बच रहे हैं, जिससे हालात सुधारे जा सकें।

दिल्ली वायु प्रदूषण से निबटने के असफल प्रयोगों का स्मारक बन कर रह गई है। जैसे-जैसे इलाज तलाशते हैं मर्ज गहराता जाता है। समझ लें जब कोई कंटक 'सुरसा मुख' सा विशाल बन कर रास्ता रोके तो हनुमान को लघु रूप में ही उसका संहार करना होता है। सरकार बड़ी-बड़ी रिपोर्ट, वैज्ञानिक और मशीनों में हवा साफ करने का निदान तलाश रही है, जबकि असल में इससे पार पाने के लिए महज सशक्त इच्छा शक्ति ही चाहिए।

जिस दिन यह बात समझ आ जाएगी कि दिल्ली-एनसीआर को गैस चेंबर में तब्दील होने का सबसे बड़ा कारण सड़कों पर राज करते वाहन हैं और इसके पीछे यहां बढ़ती आबादी या दूरस्थ अंचलों से दिल्ली की तरफ हो रहे तेजी से पलायन है, समस्या के निदान का रास्ता खुल जाएगा। हम एक तरफ दिल्ली-एनसीआर का विस्तार करते जा रहे हैं, दूसरा, यहां नए-नए दफ्तर, उद्योग के लिए रास्ते खोल रहे हैं, तीसरा, बगैर मूलभूत सुविधा के सस्ते श्रम और मजबूरी के परिवहन की बस्तियां बढ़ा रहे है। फिर सड़कों पर वाहनों की बेतहाशा संख्या से जाम लगता है, तो उत्सर्जित जहर और गहरा होता जाता है।

कोई दो दशक पहले दिल्ली को काले धुएं से निजात दिलवाने के लिए जिस सीएनजी को राम-बाण के रूप में स्थापित किया गया था, अब वही ईंधन से उपजी नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे अधिक प्रदूषण का कारक है। दिल्ली में कुल नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का लगभग 81% हिस्सा अकेले परिवहन क्षेत्र (वाहनों) से आता है। फिर सड़कों पर सम-विषम वाहन का प्रयोग हुआ। समर्थ लोगों ने दो-तीन गाड़ियां खरीद कर घर के बाहर जमा कर लीं। फिर वैज्ञानिकों ने भी बता दिया कि इसका कोई लाभ नहीं हुआ।

अगला साल था स्माग टॉवर के नाम। करोड़ों खर्च हुए। उसके 57 करोड़ के विज्ञापन छप गए, लेकिन कुछ ही महीनों में वे बेअसर कबाड़ बन गए। लाख मना करने के बावजूद दिल्ली पर नकली बरसात के प्रयोग पर खर्च किया गया। इस साल चुनिंदा सड़कों पर बिजली के खंभों पर पानी के फव्वारे लगा दिए गए। उनके संचालन की लागत का कोई हिसाब नहीं, लेकिन आंकड़े बानगी हैं कि जहर होती हवा पर इसका कोई खास असर नहीं है। अब वैज्ञानिकों की कमेटियां बन रही हैं, लेकिन समझना होगा कि वैज्ञानिक बढ़ रहे जहर से निजात के सुझाव दे सकते हैं, जबकि वास्तविक समस्या जहर बनने से रोकना या काम करना है।

आखिर इतने प्रयोग असफल क्यों होते हैं? इसे समझना कोई जटिल विज्ञान नहीं हैं। दिल्ली के सर्वाधिक जहरीले इलाके में से एक आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सामने देखें। दिलशाद गार्डन की तरफ से कोई दो किलोमीटर लंबे फ्लाई ओवर से जब तेजी से आता ट्रैफिक, चार लेन की इस सड़क पर आता है, तो उनके लिए महज एक लेन बकाया रहती है। पटरी बाजार, तिपहिया, बैटरी रिक्शा और फिर बसें, सड़क पर ही डेरा डाले रहती हैं। फिर वहां एक वाहन पानी छिड़ता रहता है और वह यदि इस बची एक लेन में आ गया तो सारा यातायात ठप्प। समझ लें यह सब हर दिन के हजारों-लाखों की अवैध वसूली का परिणाम हैं कि यहां उपज रहे जहर के कारकों पर कोई हाथ नहीं डालता। दिल्ली के लगभग सभी मेट्रो स्टेशन के बाहर लगभग यही स्थिति रहती है।

दिल्ली में तो फिर भी कुछ कड़ाई है, लेकिन दिल्ली की सीमा से शून्य किलोमीटर दूर ज्ञानी बॉर्डर कहलाने वाली जीटी रोड पर सारे दिन कोई दस हजार ट्रक चलते रहते हैं। यहां सड़कें ही नहीं, पूरा आसमान धूल के गुबार से ढका रहता है। एम्स के आगे अरविंदो मार्ग पर गौतम नगर से ग्रीन पार्क तक सड़क पर ही अधिकृत पार्किंग की फीस वसूली जाती है। भले ही वाहनों के चलने के लिए सड़क बचे नहीं। रिंग रोड पर भीकाजी कामा पैलेस से सफदरजंग अस्पताल तक फ्लाई ओवर खत्म होते ही बस स्टैंड और हर बस का स्टैंड से कम से कम दस फुट दूर खड़ा होना पूरे दिन जाम उपजाता है।

बसंत कुंज में दो किलोमीटर के दायरे में कोई 45 स्कूल हैं, जहां बच्चे 300 से अधिक बसों और उससे दुगनी और तिगुनी निजी गाड़ियों से आते हैं। इन सभी स्कूल्स के खुलने और बंद होने का समय लगभग एक है। सो सुबह और दिन में कई-कई घंटे यहां यातायात की आपा-धापी आम बात है। यह थोड़े से उदाहरण हैं। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद या गुरुग्राम में तो और बदतर हाल हैं। इस बार दिल्ली सरकार ने कार्यालयों के खुलने-बंद होने के समय में बदलाव का प्रयोग तो किया, लेकिन उसका वांछित प्रभाव दिखा नहीं।

आमने सामने

1996 में भारत के संसद से जनजाति क्षेत्र में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से पेसा एक्ट बनाया गया था। वर्तमान राज्य सरकार ने पेसा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी तो दी है, मगर इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया जाना उचित नहीं है।

–दीपक प्रकाश
बीजेपी सांसद

मैं पहले तो गठबंधन की पूरी सरकार को इस कानून के लिए बधाई देता हूं। कैबिनेट में जो चीजें पास हो जाती हैं, वह सार्वजनिक होता ही है। आखिर भाजपा को इतनी बेचैनी क्यों है? भाजपा इस मुद्दे पर लोगों में भ्रम और अफवाह फैला रही है।

–प्रदीप यादव
कांग्रेस के नेता

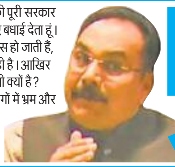

चिप मैन्युफैक्चरिंग और साइबर शक्ति में भारत

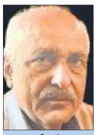

रनबीर सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

चीन की क्विड प्रो क्वो पॉलिसी, अर्थात इस हाथ ले और उस हाथ दे, जिसके तहत विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों को चीन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट वेंचर बनाने का आदेश दिया गया है, लंबे समय से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका (यूएस)-चीन आर्थिक दुश्मनी के केंद्र में रही है। जॉइंट वेंचर की ऑनरशिप लोकल चीनी फर्मों और विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के बीच बंटी हुई है, इसलिए चीनी पार्टनर मैनेजमेंट और फैसले लेने में शामिल होते हैं, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दूसरे तरीकों की तुलना में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज़्यादा असरदार तरीके से हो सकता है।

2001 में वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन में शामिल होने के बाद से चीन ने जॉइंट वेंचर को साफ तौर पर ज़रूरी नहीं बनाया है, फिर भी मल्टीनेशनल कंपनियों पर अंदर ही अंदर दबाव बना रहा। जैसा कि अमरीका के उच्च स्तर के कुछ अधिकारियों ने कहा, वॉलंटरी ही नई ज़रूरी चीज़ है। अमरीका के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित ऑफिस एवं नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा कांग्रेस की समितियों के सामने सुनवाई की दो रिपोर्ट्स इस मामले में अमरीकी नजरिये को सही से पेश करती हैं।

स्ट्रेटेजिक उद्योगों के मामले में हरेक देश अपने तौर से एक एसेसमेंट करता है। भारत ने भी किया है। इनकी रिपोर्ट्स घोषणाओं के बाद से स्लो प्रोग्रेस दिखाने वाली अधिक प्रतीत हुई हैं। बढ़ती आर्थिक दुश्मनी के बीच, यूएस ने हाई-टेक इंडस्ट्रीज़ में चीन में बाहर जाने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी है। अमरीका 2022 का चिप्स और साइंस एक्ट इसका एक उदाहरण है, हालांकि यूएस फर्मों ने टेक्नोलॉजी लीक होने के खतरों के बावजूद, चीन के बड़े मार्केट और कम सैलरी तक पहुंचने के लिए अपनी मर्ज़ी से जॉइंट वेंचर किए। क्या जॉइंट वेंचर पर रोक लगाने का अभी भी कोई आर्थिक कारण है? अगर ऐसा है, तो क्या यूएस फर्मों ने सच में जॉइंट वेंचर के ज़रिए चीन को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की?

इस बाबत की गई नई रिसर्च में मुख्य बात यह है कि यूएस मल्टीनेशनल कंपनियां अपने जॉइंट वेंचर फैसलों के दूसरी यूएस फर्मों पर पड़ने वाले बुरे असर की परवाह नहीं करतीं या उसे अपनाती नहीं हैं। अलग-अलग फर्मों के नज़रिए से, जॉइंट वेंचर बनाना फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन्हें चीनी मार्केट तक पहुंच मिलती है और सैलरी कम होती है, हालांकि जॉइंट वेंचर के ज़रिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके, वे अपने चीनी पार्टनर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं और फैलने से दूसरी चीनी फर्मों को इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाते हैं। समय के साथ, ग्लोबल कॉम्पिटिशन बढ़ता है, जिससे दूसरी यूएस फर्मों को नुकसान होता है।

हाई टेक और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में अमरीकी फर्मों ने 1970 आदि दशक के बाद से जिस तरह से ताइवान में अपना कारोबार स्थापित किया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, उससे ताइवान को जबरदस्त बढ़त अगले 20 सालों में मिली। इसकी बुनियाद पर ताईवानी फर्में अब सेमीकंडक्टर बिजनेस में अपना दबदबा पूरी दुनिया में कायम कर चुकी हैं। ये फर्में हज़ारों किस्म की चिप अरबों की संख्या में हर साल दुनिया भर में बेचती हैं।

इस परिदृश्य में भारत को अभी तक अमरीका ने उपेक्षित रखा और भारत ने भी इस उभरते स्ट्रेटेजिक उद्योग के प्रति ध्यान नहीं दिया। हम मुसीबत में नहीं हैं, परंतु बहुत पिछड़े हुए नज़र आते हैं। इस उद्योग में तीन से पांच साल से ही कुछ ध्यान गया है और नितांत स्वदेशी प्रयासों से हम अगले 10 वर्षों में शायद वर्ल्ड क्लास तो न हो पाएं, लेकिन कुछ मामलों में आत्मनिर्भर जरूर हो जाएंगे। फिर भी अति उन्नत चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के स्तर पर इस टेक्नोलॉजी में हम उस समय तक पिछड़े रहेंगे, जब तक इस क्षेत्र में कम से कम 100 अरब रुपये का निवेश नहीं किया जाता।

ज्ञातव्य है कि चीन ने एक दशक पहले इसके लिए 19 खरब यूएस डॉलर का निवेश किया था। आज अमरीका की सिलिकॉन वैली, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और अमेरिकन माइक्रोडिवाइसेस जैसी कंपनियां चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से डरने लगी हैं। इस उद्योग में खरबों रुपये का बिजनेस अब ताइवान, चीन, जापान और अमरीका के हाथ में है।

> हमारे यहां सेमीकंडक्टर रिसर्च का स्तर अभी सौ में से बीसवें स्तर पर ही है। सिर्फ पॉलिसी बनाकर ऊंची घोषणाएं करने से काम नहीं चलता।

भारत इसमें शायद सौवें स्थान पर होगा। हमारे यहां सेमीकंडक्टर रिसर्च का स्तर अभी सौ में से बीसवें स्तर पर ही है। सिर्फ पॉलिसी बना कर ऊंची घोषणाएं करने और इस बाबत रिपोर्ट्स बनाने से काम नहीं चलता। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक स्वस्थ ईको-सिस्टम बनाने से पहले डींग मारने के लिए अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, जिसका नोटिस विश्व की बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या इन देशों के कॉमर्स विभाग ले पाएं। हम पहले से ही हाई टेक के ट्रांसफर के मामले में अमरीका की ट्रेड-वार्स से पीड़ित रहे हैं। सबसे बड़ी कमी है, रेयर अर्थ मैटेरियल्स को भारत में ढूंढना। इसे प्रॉसेस करना और हाई टेक प्लांट्स लगाना।

सोशल फोरम

बच्चों को चीजों की कीमत समझाने की जरूरत

बचपन में चित्रहार का इंतजार रहता था। पूरे सप्ताह दिन गिना करते थे। आज के ज़माने में, जब सब चीज़ें आपके मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध हैं, तो किसी चीज़ का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं रही, लेकिन उस इंतजार का एक अलग ही मज़ा था, उससे सीख भी मिलती थी और सहनशीलता (रेसिलिएंस) भी विकसित होती थी। पहले सब कुछ बहुत नेचुरल था। चीज़ें कम थीं, विकल्प बहुत ही सीमित थे, इसलिए ज़िंदगी बहुत ही सरल थी।

नीलेश गुप्ता
ब्लॉगर

डिप्रेशन, एंग्जायटी और मोटापा जैसी समस्याएं बच्चों में कभी देखने को नहीं मिलती थीं। आजकल हर चीज़ फिंगरटिप्स पर मौजूद है। यहां तक कि 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स ने तो प्लानिंग की जरूरत भी खत्म कर दी है। जब चाहो, जहां चाहो, कुछ भी मंगवा सकते हो।

मोबाइल का असर सिर्फ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि बच्चों की सामाजिक दक्षताओं (सोशल स्किल्स) पर भी पड़ रहा है। पहले शादी-पार्टियों में बच्चे आपस में बातें करते या छोटे-मोटे काम में मदद करते दिखते थे, लेकिन अब वे सिर्फ मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। कई जगहों पर तो टेबल पर पिता मोबाइल पकड़े होते हैं और मां बच्चे के मुंह में खाना ठूंस रही होती हैं, जबकि बच्चा बिना ध्यान दिए बस मोबाइल स्क्रीन देखे जा रहा होता है। उसे तो यह भी नहीं पता कि वह क्या खा रहा है!

कुछ दिन पहले एक परिचित का फ़ोन आया। उनकी पोस्टिंग बाहर थी और उनकी पत्नी बच्चे की पढ़ाई की वजह से कोटा में रुकी हुई थीं। वे पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपनी पोस्टिंग वाली जगह बुलाना चाहते थे, लेकिन एक महीने के लिए बच्चे की पढ़ाई नहीं छुड़वा सकते थे। निर्णय लिया गया कि बच्चा एक महीने के लिए एक सेंटर में रहेगा। उस सेंटर ने लाइव CCTV एक्सेस माता-पिता को उपलब्ध करा रखा था। वे रोज़ अपने बच्चे को खाना खाते हुए देखते थे और बहुत खुश होते थे कि वह बिना मोबाइल देखे खाना खा रहा था। उनका कहना था कि उन्होंने अपने बच्चे को कभी बिना मोबाइल के खाते हुए नहीं देखा था! हमें तो इसका अंदाज़ा भी नहीं हुआ और न ही बच्चे ने कोई नखरे दिखाए।

जब सब चीज़ें बिना मांगे और बिना किसी प्रयास के मिलने लगती हैं, तो उनकी कद्र ही खत्म हो जाती है। तभी तो कहा जाता है- चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, बच्चों को थोड़ा अभाव में पालिए।

सामयिकी

2026 रहेगा भारत का एआई इंपैक्ट वर्ष

भारत में एआई 2025 में तेज़ी से फैला। अब तक देश में एआई मार्केट लगभग 13 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और 2030 तक 130 बिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। 2025 एआई का 'एक्सपेरिमेंटेशन' का साल था, जहां जनरेटिव एआई और चैटबॉट्स ने दुनिया को चौंकाया, लेकिन 2026 भारत में एआई का प्रोडक्शन, जवाबदेही और गवर्नेंस का साल होगा। एआई अब प्रयोगशाला से निकलकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो बिजली, पानी या इंटरनेट जैसी ज़रूरी चीजों से जुड़ जाएगा। साथ ही कंपनियों और संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि इसे सही ढंग से अपनाएं। सुरक्षित और नैतिक रूप से इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें।

सरकार की इंडिया एआई मिशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित India एआई इंपैक्ट समिट इस बदलाव का केंद्रबिंदु है। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में होने वाला यह समिट का थीम 'प्यूपल, प्लैनेट और प्रगति' (लोग, ग्रह, प्रगति) के साथ होगा, जिसे हिंदी में 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के रूप में व्यक्त किया गया है। यह वैश्विक स्तर पर एआई को समावेशी, सुरक्षित और विकास-केंद्रित बनाने का मंच बनेगा, जहां G-20 देश, स्टार्टअप्स, नीति-निर्माता और शोधकर्ता मिलकर एआई की दिशा तय करेंगे। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में वर्ष 2026 का दौर बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया एआई मिशन और आगामी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से सरकार ने एआई को समावेशी, सुरक्षित और विकास-केंद्रित बनाने का मजबूत लक्ष्य रखा है।

अंबिका अंबी
लेखिका

इंडिया एआई मिशन, भारत को वैश्विक एआई लीडर बनाने का मुख्य आधार है। इसका फोकस एआई को 'सभी के लिए' (एआई फॉर आल) बनाना है, खासकर स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और शासन जैसे क्षेत्रों में। मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैंः उच्च-स्तरीय कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। जिसमें 34,000+ GPUs (और बढ़ते हुए) के साथ शक्तिशाली एआई कंप्यूट संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और MSMEs सस्ती दर पर एआई मॉडल ट्रेन कर सकें।

स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल्स का विकास कर भारत-केंद्रित Large Multimodal Models (LMMs) और इंडियन भाषाओं/संदर्भों पर आधारित एआई मॉडल बनाना। डेटा उपलब्धता बढ़ाना, ताकि इंडिया आई डेटा सेट्स प्लैटफार्म (एआई Kosh) के जरिए उच्च-गुणवत्ता वाले नॉन-पर्सनल डेटासेट्स आसानी से उपलब्ध हो सके। टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट करना, जिससे एआई फ्यूचर स्किल्स और फ्यूचर स्किल्स प्राइम जैसे कार्यक्रमों से लाखों युवाओं को एआई ट्रेनिंग दी जाए। NASSCOM के अनुसार, एआई टैलेंट 2027 तक दोगुना (12.5 लाख+) होने की उम्मीद है।

सामाजिक प्रभाव वाले एआई एप्लिकेशन्स को 30 से अधिक एआई प्रोजेक्ट्स स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और क्लाइमेट में लागू करना। नैतिक और जिम्मेदार एआई हो, जो India AI Governance Guidelines-2025 के तहत सात सिद्धांतों पर केंद्रित है, जिसमें AI Safety Institute भी शामिल है। भारत वैश्विक नेतृत्व प्रदान करेगा। 19-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाला इंडिया एआई इंपैक्ट समिट G20 देशों, स्टार्टअप्स और नीति-निर्माताओं को एक मंच देगा। यह एआई को समावेशी और इंपैक्ट-फोकस्ड बनाने का वैश्विक केंद्र बनेगा। इन लक्ष्यों से एआई अब डिजिटल प्रयोग से आगे बढ़कर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर (बिजली, पानी, इंटरनेट जैसा) बन रहा है।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक हरि ओम गुप्ता द्वारा अमृत विचार प्रकाशन, नवादा जोगियान, चक रोड, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने, बरेली (उ.प्र.), पिन कोड-243006 से मुद्रित एवं 932 कटरा चांद खां, भारत पेट्रोल पंप के सामने पीलीभीत बाईपास रोड बरेली (उ.प्र.) पिन कोड-243005 से प्रकाशित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, स्थानीय संपादक- नवीन गुप्ता*** 0581-4000222 (कार्यालय), ईमेल- editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-UPHIN/2019/78502, *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्यायक्षेत्र बरेली होगा)।

सम्पादकीय

नया कालखंड, नए साल से नई उम्मीदें

नव वर्ष का आगमन अनेक अपेक्षाओं के साथ होता है। इस अवसर पर सभी शुभ की कामना करते हैं। हम भारत के लोग तो उस संस्कृति के वारिस हैं, जो प्राणिमात्र के कल्याण की बात करती है और समस्त वसुधा को एक कुटुंब की तरह देखती है, लेकिन सर्वत्र शुभ का संचार होने की चाह के बीच यह भी एक यथार्थ है कि व्यक्ति की तरह समाज और राष्ट्र के जीवन में चुनौतियां आती ही रहती हैं। वे इस वर्ष भी आएंगी। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि इस नए वर्ष में हम उनका सही तरह सामना करने में समर्थ हों और तेजी के साथ प्रगति के उस पथ पर आगे बढ़ें, जिसमें सुख, समृद्धि के साथ समरसता भी बढ़े। यह तब संभव होगा, जब एक राष्ट्र के रूप में हमारी कार्यसंस्कृति बदलेगी और उन बुनियादी समस्याओं का समाधान होगा, जो प्रगति की राह में रोड़ा हैं।

वैसे तो किसी भी देश की कार्यसंस्कृति बदलने का दायित्व मुख्यतः शासन और प्रशासन में बैठे लोगों का होता है, लेकिन इस काम में जनता का सहयोग भी आवश्यक होता है। विश्व के कई देशों का इतिहास इसकी ही गवाही देता है कि उनका भाग्योदय तब हुआ, जब वहां के शासकों के साथ आम लोगों ने भी अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समर्पण भाव से काम किया।

अब भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। विशाल आबादी और भिन्न पंथ, भाषा वाले देश की प्रगति के लिए शासन-प्रशासन के साथ आम जनता का रुख-रवैया बदले बगैर बात बनने वाली नहीं है। यह समझा जाए कि जैसे शासक का धर्म होता है, वैसे ही नागरिक का भी। विभिन्न समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन के लोगों को उचित ही कठघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन यह प्रश्न प्रायः अनुत्तरित रहता है कि क्या हम भारत के लोग अपने नागरिक धर्म का निर्वाह सही तरह करते हैं?

हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना ही चाहिए, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों को लेकर भी सचेत रहते हैं? यदि हमारी अनेक समस्याओं का समाधान शासन-प्रशासन की ढिलाई के चलते नहीं हो पाता तो कई समस्याएं इसलिए जटिल बनी रहती हैं कि लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। यदि जन सहयोग का यह अभाव दूर हो सके तो इस नए वर्ष में आत्मनिर्भर भारत की राह और आसान हो सकती है और यह किसी से छिपा नहीं कि आत्मनिर्भरता विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पाने की कुंजी है।

2025 की विदाई के साथ ही देश उस नए कालखंड में प्रवेश कर रहा है, जब विकसित भारत का लक्ष्य और निकट आ गया है। यह लक्ष्य वास्तव में प्राप्त हो सके, इसके लिए मानसिकता में बदलाव लाना भी आवश्यक है। ऐसा करके ही हम अपनी कार्यसंस्कृति बदल सकेंगे और आने वाले कल की चुनौतियों से पार पा पाएंगे। हम सब मिलकर ऐसा कर सकें, इस आशा के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं।

क्या अयातुल्लाह खुमैनी सरकार ईरान में सुलग रही जेन जेड क्रांति से कुछ सबक लेगी या शहादत देगी ?

> समझा जाता है कि जब कोई राजनेता देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और मानवीय संसाधनों का दुरुपयोग अपने धार्मिक महत्वाकांक्षाओं, उसके भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक अवसरवादिता के दृष्टिगत करने लगता है तो वह भीतर ही भीतर खोखला होता जाता है।

शिया मुस्लिम बहुल देश ईरान में 'तानाशाह तेरी कब्र खुदेगी' और 'मुल्लाओं को देश छोड़ना होगा' जैसे नारे लगना हैरत की बात है, क्योंकि कोई सच्चा मुसलमान अयातुल्लाह खुमैनी जैसे मुल्ला शासकों और उनके वतन परस्त हमकदम मुल्लाओं का विरोध क्यों करेगा? खासकर उस अयातुल्लाह खुमैनी का जो पूरी दुनिया में इस्लामिक बादशाहत स्थापित करने का स्वप्नद्रष्टा समझे जाते हैं।

बावजूद इसके हाल के ईरान मुल्ला विरोधी आंदोलन में ये नारे आम हो चुके हैं। इसलिए सवाल है कि क्या अयातुल्लाह खुमैनी सरकार ईरान में सुलग रही जेन जेड क्रांति से कुछ सबक लेगी या अपनी शहादत देगी?

बताया जाता है कि यह सरकार विरोधी जन-आंदोलन मुख्य रूप से वहां के आर्थिक संकट से उपजे हैं जहां रियाल की कीमत में भारी गिरावट के बाद लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। वहां से मिली खबरों से पता चलता है कि ईरान में चढ़ी 42% से अधिक की महंगाई ने आम जनता को सड़कों पर उतार दिया है। जानकारों का कहना है कि ये जन-प्रदर्शन तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू होकर मशहद, इस्फहान जैसे शहरों में फैल गए हैं, और लोग 'मुल्लाओं को देश छोड़ना होगा' और 'तानाशाह तेरी कब्र खुदेगी' जैसे आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। यह वहां की अयातुल्लाह खुमैनी सरकार के लिए चिंता की बात है।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि ईरान की मौजूदा आर्थिक बदहाली के पीछे उस पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध मुख्य वजहें हैं, जो उसके मुख्य उत्पाद तेल निर्यात को प्रभावित कर रहे हैं। यही वजह है कि साल 2022-23 के महसा अमीनी आंदोलन के बाद शुरू हुआ हालिया आंदोलन विगत तीन सालों के बाद प्रारम्भ हुआ सबसे बड़े प्रदर्शन हैं जहां भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरता और सालों की नाकामियों से तंग जनता पुनः सड़क पर चुकी है।

वहीं, वैश्विक कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी' ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को और सख्त किया है जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने इसे शासन की आंतरिक कमजोरियों को उजागर करने वाला बताया है, हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेप का कोई स्पष्ट प्रमाण अब तक नहीं मिला है। उधर, इजरायल और अमेरिका के परमाणु ठिकानों पर हमलों ने भी ईरान पर नैतिक दबाव बढ़ाया है। इजरायल जिस तरह से ईरान के सैन्य रणनीतिकारों को ढेर कर देता है, उससे भी सरकार की प्रतिरक्षात्मक कमजोरी जगजाहिर है।

फिर भी ईरान के हालिया मुल्ला विरोधी प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें आर्थिक संकट से निजात और सत्ता परिवर्तन से जुड़ी हैं। आंदोलनकारियों ये मांगें तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुए आंदोलन में स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं- पहला, प्रदर्शनकारी ₹मुल्लाओं को देश छोड़ना होगा₹ और ₹तानाशाह की कब्र खुदेगी₹ जैसे नारों से सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और धार्मिक शासन के खिलाफ खुला विद्रोह जता रहे हैं। दूसरा, वे रियाल की गिरावट, 42% महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त होकर आर्थिक सुधार तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मांग कर रहे हैं। तीसरा, उनकी अतिरिक्त अपेक्षाएं हैं कि जनता इजरायल-अमेरिका के दबाव के बीच परमाणु नीति पर पुनर्विचार करे और महिलाओं पर हिजाब जैसे धार्मिक प्रतिबंधों को समाप्त करने का कार्य करे। यह उनकी सामूहिक अपील है।

हालांकि, अनुभव बताता है जिस तरह से धर्म के आधार पर राष्ट्रपति खुमैनी लोगों को नियंत्रित करने की भूल कर रहे हैं, उसके मद्देनजर यह होना स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए कि कोई भी धर्म पारलौकिक समस्याओं का समाधान तो देता है लेकिन इहलौकिक समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को शिक्षा और विकास जैसे सुशासन की जरूरत होती है।

ऐसा इसलिए कि विरोधी बढ़ जाते हैं जिन्हें काबू में करने के लिए युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी करनी पड़ती है। इसमें खर्च बढ़ने से जनता की सहूलियत में कटौती करनी पड़ती है। इससे महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने से लोगों को भी त्याग करने में कष्ट पहुंचता है। इससे सत्ता विरोधी आक्रोश पनपता है, जिसे विदेशी शक्तियां तूल देती हैं। फिलहाल ईरान, अमेरिका-इजरायल और इनके समर्थक मुस्लिम देशों के षड्यंत्र का सहज शिकार होने के कगार पर पहुंच चुका है। दिलचस्प तो यह है कि जेन जेड पीढ़ी के नेतृत्व में शुरू हुए ये जन-प्रदर्शन 2022 के महसा अमीनी आंदोलन की याद दिलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल के बाद अब ईरान का नेतृत्व भी तथाकथित जेन जेड क्रांति का सहज शिकार होने वाला है। इससे साफ है कि इक्कीसवीं सदी में वैश्विक पटल पर अमेरिकी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए डीप स्टेट प्रोत्साहित जो कथित 'जेन जेड क्रांति' हो रही है, वह विभिन्न एशियाई देशों को अमेरिकी रणनीति के समक्ष घुटने टेकने या अंजाम भुगतने की स्पष्ट नसीहत है।

बता दें कि जेन जेड यानी साल 1997-2012 के बीच जन्मे बच्चे अब सोशल मीडिया के जरिए जलवायु परिवर्तन, तानाशाही और अन्याय के खिलाफ सक्रिय हैं, जैसा कि मिस्र की जैस्मीन क्रांति या ईरान के पुराने हिजाब आंदोलनों में दिखा। अब तक कम से कम 8 देशों में ऐसे युवा आंदोलन दर्ज हैं। खासकर साल 2025 में नेपाल, इंडोनेशिया, पेरू और हाल ही में ईरान में भी जेन जेड के बड़े प्रदर्शन देखे गए हैं। इससे पहले अगस्त 2024 में बंगलादेश में भी इनके सफल प्रदर्शन हो चुके हैं और वहां भी शेख हसीना सरकार की बलि चढ़ाई जा चुकी है। घटनाक्रम बताते हैं कि साल 2025 में इनका आंदोलन इंडोनेशिया से शुरुआत होकर पेरू की राजधानी लीमा में राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते के खिलाफ 27 सितंबर को प्रदर्शन हुए। ईरान में दिसंबर 2025 तक तेहरान समेत कई शहरों में जेन जेड ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ विद्रोह किया। वहीं, नेपाल में 8 सितंबर 2025 को शुरू हुए प्रदर्शनों ने संसद और सरकारी भवनों पर हमले किए, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई। यहां भी युवाओं ने सोशल मीडिया बैन हटवाया और नया संविधान की मांग की। नेपाल में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुई जेन जेड क्रांति के बाद ही वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया।

कमलेश पांडेय

हम एक महाशक्ति तो बन गए हैं पर वास्तव में

भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को पछाड़कर तीसरी रैंक हासिल कर लेगा और 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह जानकारी सोमवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई। चीन, जो दूसरे से पहले स्थान पर जाना चाहता है, और अद्वितीय संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दशकों से नंबर एक पर स्थापित है। एक बार आगे निकलने के बाद ये तीन देश क्यों होते हैं? अनुमान है कि भारत 2030 तक जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा. मजबूत घरेलू खपत और कड़े संरचनात्मक सुधारों के दम पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है.वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2 प्रतिशत बढ़ी, जो पहली तिमाही के 7.8 प्रतिशत और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के 7.4 प्रतिशत से अधिक है. यह छह तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि है, जो वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बावजूद दर्ज की गई.सरकार ने भरोसा जताया है कि मजबूत आर्थिक नींव के साथ, भारत की जीडीपी 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी. वर्तमान में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है. वहीं तीसरे पर जर्मनी है. हम एक महाशक्ति तो बन गए हैं पर वास्तव में, जर्मनी हमारे महाराष्ट्र के बराबर भी नहीं है। अकेले महाराष्ट्र को जनसंख्या और आकार दोनों मोर्चों पर इसे पार करना चाहिए।

अशोक भाटिया

गंगा, यमुना, हिंडन, काली...

डा.वेदप्रकाश

पर्यावरणीय घटकों को बचाने का संकल्प लें

वर्ष 2026 नव संकल्पों से आरंभ होना चाहिए। वैसे तो जब भी व्यक्ति कुछ सकारात्मक और नया करने की ओर बढ़ जाए, वहीं से नया वर्ष या नए का आरंभ हो जाता है। यदि हमारा जीवन ही खतरे में है तो फिर कैसा उल्लास? कैसा नववर्ष? अंग्रेजी नववर्ष के आरंभ में क्या आज से ही हम पर्यावरणीय घटकों को बचाने का संकल्प ले सकते हैं? क्या आज ही एक पौधा लगाकर हम इस दिशा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं? हमारा यह छोटा सा संकल्प बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। प्रकृति-पर्यावरण भयंकर प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। सांस लेना कठिन है, फिर ऐसे में उल्लास के साथ चिंतन करते हुए संकल्प की ओर बढ़ना ही उचित है।

जल, वायु , नदियां, समुद्र, धरती, पहाड़, जंगल, ग्लेशियर, विभिन्न जीव जंतु और वनस्पतियां आदि पर्यावरणीय घटक हैं। ये विभिन्न घटक आज गंभीर प्रदूषण की गिरफ्त में है अथवा अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। परिणामस्वरूप इन घटकों का विकृत होना अथवा असंतुलित होना मानव सहित समूची जीव सृष्टि के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब यह खतरा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। विगत लंबे समय से दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर और बेहद गंभीर श्रेणी में चल रही है। घरों से निकलना मुश्किल है। इससे शारीरिक- मानसिक स्वास्थ्य,

शिक्षा और आर्थिकी पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। यूके स्थित भारतवंशी डाक्टरों ने वायु प्रदूषण को कोरोना महामारी के बाद सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बताया है। दिल्ली एनसीआर में सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आयु वर्ग के लोग सिर दर्द,थकान, हृदय रोग, खांसी, बुखार, गले में जलन, आंखों में जलन और सूखापन, त्वचा के रोग व बार-बार संक्रमण जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। प्रदूषण की अधिकता ने हवा को जहरीला बना दिया है। वाहनों, उद्योगों और विद्युत संयंत्रों की धुल, धुआं व घातक रसायन जीवन पर भारी पड़ रहे हैं। सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश के करीब 78 प्रतिशत ताप बिजली संयंत्रों में सल्फर डाइआक्साइड को नियंत्रित करने की प्रणाली नहीं है और प्रदूषण फैलाने में ताप बिजली संयंत्रों की बड़ी जिम्मेदारी है। क्या इन्हें मानकों के अनुरूप संचालित करना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है?

गंगा, यमुना, हिंडन, काली आदि सैकड़ों नदियां भयंकर प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। महानगरों का अशोधित सीवेज और औद्योगिक कचरा सीधे नदियों में गिर रहा है। विडंबना यह भी है कि विभिन्न प्रदेशों में सीवेज शोधन हेतु एसटीपी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। जितने हैं वे भी समुचित रूप में काम नहीं कर रहे हैं। शासन- प्रशासन की सुस्ती से यह स्थिति और भी चिंताजनक बनती जा रही है। दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि अकेले उत्तर प्रदेश में गंगा व सहायक नदियों में 225 नाले सीधे मिल रहे हैं और लगभग 1100 मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन सीधे नदियों में गिर रहा है। बंगाल के 27 शहरों में कुल 41 एसटीपी हैं जिनमें से अधिकांश मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। पूरे बिहार में केवल 20 एसटीपी के सहारे ही काम चल रहा है। दिल्ली में भी 37 एसटीपी हैं जिनमें से लगभग 16 ही क्षमता के अनुरूप काम कर रहे हैं। दिल्ली सहित देश के विभिन्न महानगरों में छोटे बड़े सैकड़ों नाले सीधे नदियों में गिर रहे हैं। पूरे देश में औद्योगिक अपशिष्ट शोधन प्रणालियों की हालत तो और भी गंभीर है। ध्यान रहे ये सभी नदियां भिन्न-भिन्न रूपों में जीवनदायिनी हैं। क्या पूरे देश में नदियों की बदहाली गंभीर चिंतन का विषय नहीं हैं? वन क्षेत्र धरती के फेफड़े कहे जाते हैं। लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं। प्रत्येक वर्ष करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन उनके संरक्षण- संवर्धन की समुचित योजनाएं नहीं हैं। हाल ही में राज्यों द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी गई एक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि देश के 25 राज्यों में 13 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण है। 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वन क्षेत्र पर अतिक्रमण के बारे में जानकारी नहीं दी है। क्या यह स्थिति गंभीर नहीं है?

ताजा अध्ययनों से यह भी सामने आ रहा है कि जल के महत्वपूर्ण स्रोत ग्लेशियर भी प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों में विभिन्न ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर झीलें संवेदनशील बनी हुई हैं। जिससे बड़ी आपदा आ रही हैं। केदार आपदा और हाल ही में धराली-भराली की आपदाएं इसके प्रमाण हैं।

गंभीर ...

कस्तूरी दिनेश

ठंड है भई ठंड है !

ठंड का मौसम आंदोलनों के लिए बड़ा मुफीद है । संसद विधान सभा में बैठे रहो,कक्ष कितना भी गर्म रहे ठंड तो लगती ही है । सत्ता-पक्ष के भाषण के दौरान कितनी देर तक हंगामा कर लो, उछल-कूद मचाते हुए चीख-चीखकर विरोध में नारा लगा लो, ठंड की कंपकपी है कि जाती नहीं ! ऐसे समय में अपनी पार्टी के सदस्यों का कष्ट देख,विपक्ष के सयाने सदस्य की बुद्धि में शातिर लोमड़ी घुस जाती है और वे चालाकी से सत्ता-पक्ष के भाषण का विरोध करते हुए सदन से सामूहिक बहिर्गमन की घोषणा कर देते हैं ।

बाहर खुली प्रकृति के बीच बढ़िया हाथ-पाँव को सेंकती गर्म-गर्म गुनगुनी धूप है । नीचे जमीन में नर्म-नर्म घास है और सामने है आनन्द भाव से धूप का आनन्द लेती बापू की प्रतिमा ! सब एक राय होते हैं और गांधी जी के चरणों के निकट पहुंचकर सता-पक्ष के पास हुए बिल का हाथ उठा-उठकर विरोध करते हुए नारे का बम फोड़ने लगते हैं ।"तानाशाही नही चलेगी...नहीं चलेगी !" "फलां बिल वापस लो,वापस लो...!" "ढेकां बिल,हाय ...हाय,हाय,हाय... !" घंटे आधे घंटे के हो-हल्ला और उछल-कूद के बाद ठंड एकदम गायब हो जाती है । च्यवनप्राशीय स्फूर्ति महसूस होती है ! पार्टी के गठिया पीड़ित वयोवृद्ध आत्मिक राहत महसूस करने लगते हैं ! सब गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ जाते हैं । विचार-विमर्श शुरू होता है । आज के लोकतंत्र की तो रस्म निभाई हो गई । संसद की हाजिरी का भत्ता भी पक गया ! अब कल किस बात पर सत्ता-पक्ष का विरोध करना है, तय हो जाए ! संसद कक्ष में रोज वोट चोर,वोट-चोर की वही रटी-रटाई रेंक लगाते इस कड़कड़ाती ठंड में बोरियत हो जाती है ! माईंड-फ्रेश करने और ठंड को मारने के लिए आगे विरोध और हंगामे का क्या मुद्दा होगा ? सत्ता-पक्ष के किस बात का विरोध करते हुए मुखिया प्रतिपक्ष इशारा करेगा और हम सब प्रतिपक्षी फिर बहिर्गमन करके बाहर खिली-खिली,गर्म-गर्म तन सेकती,गुदगुदाती धूप में बाहर गांधी जी से आशीर्वाद लेंगे ?

गंभीर बहस चलती है और सबकी राय अलग-अलग है लेकिन नेता प्रतिपक्ष यानी हाईकमान का निर्णय अंतिम रूप से मान्य हो जाता है । प्रजातंत्र में हाईकमान की वाणी ईश्वर की वाणी की तरह अमोघ और अकाट्य है ! अगले दिन सत्ता-पक्ष के जवाब के समय संसद में फिर वही रावण-अंगद संवाद,हो-हल्ला,हंगामा ! सभापति के आसन के पास जाकर पास हुए बिल की प्रति फाड़कर लहराने तथा फेंकने का परम वीरता भरा कृत्य ! वही बहिर्गमन...! चश्मे के अंदर से आँखों ही आँखों में मुस्कुराती गांधी प्रतिमा के चरणों में आकर तन को सेकती, गुनगुनी धूप का वही आनन्द और संसद के अंदर अगले दिन की योजना पर फिर विचार–विमर्श !

बस ऐसे ही, हर बार की तरह प्रजातंत्र-देवता की शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन पूजा-अर्चना; सभापति-पुरोहित के शंखनाद के साथ समाप्त...! मिमियाती-रिरियाती प्रजा चुप रहे...!

जरा हटके

1980 के दशक...

रामस्वरूप रावतसरे

क्या बांग्लादेश में 'बैटल ऑफ बेगम्स' का दौर खत्म हो गया है?

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का 30 दिसंबर 2025 सुबह निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थीं। लंबी बीमारी से जूझ रही खालिदा जिया ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती थीं, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। खालिदा जिया की मौत से बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत हो गया है। वे दशकों तक देश की सियासत की धुरी रहीं और अपनी कट्टर प्रतिद्वंद्वी शेख हसीना के साथ उनकी दुश्मनी ने पूरे देश को प्रभावित किया।

खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के जलपाईगुड़ी जिले में हुआ था, जो आज पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। उनका बचपन का नाम खालिदा खानम 'पुतुल' था। उनका परिवार एक साधारण व्यापारी परिवार से था। 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार पूर्वी बंगाल (आज का बांग्लादेश) के दिनाजपुर जिले में आकर बस गया। खालिदा जिया ने दिनाजपुर की मिशनरी स्कूल और गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। वे खुद को 'सेल्फ-एजुकेटेड' बताती थीं और हाई स्कूल की डिग्री के कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं हैं।

साल 1960 में मात्र 15 साल की उम्र में खालिदा की शादी पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन जियाउर रहमान से हो गई। जियाउर रहमान बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के प्रमुख नायक थे। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में बांग्लादेश के

राष्ट्रपति बने। शादी के बाद खालिदा जिया एक साधारण गृहिणी बनकर रह गईं। वे दो बेटों तारेक रहमान और आरफ रहमान की परवरिश में व्यस्त रहीं। उस समय उन्हें एक शर्मीली और घरेलू महिला के रूप में जाना जाता था जो राजनीति से दूर रहती थीं। जियाउर रहमान ने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की स्थापना की। वे 1977 से राष्ट्रपति थे और देश को सैन्य शासन से लोकतंत्र की ओर ले जा रहे थे। लेकिन 30 मई 1981 को चटगाँव में एक असफल सैन्य तख्तापलट में जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। इस घटना ने खालिदा जिया की जिंदगी बदल दी। शौहर की मौत के बाद बीएनपी संकट में पड़ गई। कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे में खालिदा जिया ने 1982 में पार्टी की सदस्यता ली और 1984 में बीएनपी की चेयरपर्सन बन गईं। एक गृहिणी से राजनीतिक नेता बनने की उनकी यात्रा प्रेरणादायक थी। 1980 के दशक में बांग्लादेश पर जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद का सैन्य शासन था। खालिदा जिया ने इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र बहाली की लड़ाई का नेतृत्व किया। वे सात दलों के गठबंधन की प्रमुख बनीं और हड़तालों, प्रदर्शनों के जरिए सैन्य तानाशाही का विरोध किया। इस दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और घर में नजरबंद रखा गया लेकिन वे डटी रहीं। 1990 में जन आंदोलन के दबाव से इरशाद को सत्ता छोड़नी पड़ी। लोकतंत्र की बहाली के लिए हुई लंबी लड़ाई में शेख हसीना ने भी मोर्चा थामे रखा। ये वही समय था, जब बांग्लादेश के लिए दोनों बेगमों ने एक पक्ष की तरफ से लड़ाई लड़ी, हालाँकि राजनीतिक वजहों से दोनों हमेशा अलग-अलग खेमों की अगुवाई करती रही। साल 1991 में बांग्लादेश में पहली बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए। बीएनपी ने भारी जीत हासिल की और खालिदा जिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। उनके पहले कार्यकाल (1991-1996) में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। उन्होंने संसदीय व्यवस्था बहाल की, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। अर्थव्यवस्था में सुधार आए और बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत हुआ।

साल 1996 में वे चुनाव हार गईं और शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में आई लेकिन 2001 में बीएनपी की वापसी हुई और खालिदा जिया दूसरी बार प्रधानमंत्री बनीं। इस कार्यकाल में भी कई उपलब्धियाँ रहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप और इस्लामी कट्टरपंथी और आतंकवादियों के उभार ने उनकी सरकार को विवादास्पद बना दिया।

नव वर्ष

नव वर्ष में सदैव हमारा जीवन हो सबसे न्यारा ।(अ)
नव वर्ष में हमारा जीवन बने कर्मों से हल्का ।
महावीर प्रभु को नित शीश नमा हों जायें हल्का ।
प्रज्ञा के दीप जला मन का आँगन हम महकाएं ।
फैले क्षण - क्षण में मोहक तान को हम पाएं ।
नव वर्ष में सदैव हमारा जीवन हो सबसे न्यारा । (अ)
जीवन के मधुर क्षणों में, मन का संकल्प हम सजाएं ।
कर्मों को क्षय करने का सही क्रम हम अपनाए ।
पल - पल समय की गति को हम पहचाने ।
जीवन के संग्राम में कभी न हम हार माने ।
नव वर्ष में सदैव हमारा जीवन हो सबसे न्यारा । (अ)
नव वर्ष में हम अपने पुरुषार्थ से तोड़े कर्मों की कारा ।
अपने पुरुषार्थ के सामर्थ्य से मोड़े जीवन की धारा ।
आत्मा की ज्योति जला मन में बहाए अमृत की धारा ।
मन का सौन्दर्य बढ़ाकर मोक्ष का हो लक्ष्य सारा ।
नव वर्ष में सदैव हमारा जीवन हो सबसे न्यारा । (अ)
शुभ संकल्पों को जगाकर डर भय सब दूर भगायें ।
आत्मा का अनुभव कर वितरागता को हम पायें ।
आत्मा का है रंग निराला चहुँ और ऊर्जा हम पायें ।
धर्म ध्यान के द्वारा छलकें अमृत प्यालें को हम पायें ।
नव वर्ष में सदैव हमारा जीवन हो सबसे न्यारा । (अ)

प्रदीप छाजेड़

तत्व भिन्न निःतत्व है, मन व पवन से न्यार।
नाद विंद अनहद परे, सत्य शब्द निरधार।

संपादकीय

विशेष गहन पुनरीक्षण

बारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भारत का निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तेजी से मजाक में बदलता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मामले को लीजिए, जहां बुजुर्ग बाशिंदों को अपना नामांकन (इनरोलमेंट) फॉर्म जमा करने के बाद भी, दूर जगह जाकर पात्रता सुनवाई में शामिल होना पड़ रहा था, जिस पर मचे हंगामे ने आयोग को घर जाकर सत्यापन का आदेश देने पर मजबूर किया। या फिर, यह तथ्य कि उसे 'अनमैप्ड 'मतदाताओं (वे मतदाता जिनके नामों या माता-पिता के नामों का साल 2002 के एसआईआर से मिलान नहीं हुआ) की सुनवाइयों को सशर्त रूप से रोकना पड़ा। तलबनामे (समन) सॉफ्टवेयर नोटिसों के रूप में थे, लेकिन यह सॉफ्टवेयर बिहार में इस्तेमाल नहीं किया गया। सिविल सेवकों के एक संघ ने शिकायत की कि 'अभी चल रहे एसआईआर में पश्चिम बंगाल में मसौदा सूचियों से मतदाताओं के इस स्व-प्रेरित (सुओ मोटो) सिस्टम-चालित विलोपन ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की वैधानिक भूमिका को दरकिनार किया '। अगर आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एसआईआर करने की हड़बड़ी न की होती तो इस प्रक्रियात्मक अव्यवस्था से बचा जा सकता था। उसके द्वारा सॉफ्टवेयर का तदर्थ (एड हॉक) इस्तेमाल भ्रम और बेचैनी पैदा कर रहा है - आयोग ने अपने दोहराव हटाने वाले (डी-डुप्लीकेशन) सॉफ्टवेयर को बिहार में रद्दी की टोकरी में डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन खबरों के मुताबिक उसने उचित प्रोटोकॉल के बगैर इसे एक अन्य सॉफ्टवेयर के साथ 'अनमैप्ड' मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग जिस तरह काम कर रहा है, उससे यह संदेह पुष्ट होता लगता है कि वह मतदाता सूचियों को अपडेट करने की कवायद का इस्तेमाल दरअसल नागरिकता की जांच की कवायद के रूप में कर रहा है।

आज का विचार

संघर्ष में आदमी अकेला होता है। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति का नया सोपान बनेगा 2026

मनोज कुमार अग्रवाल

भारत 2026 में भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने की राह पर है। इसके पीछे मजबूत आर्थिक वृद्धि, कम मुद्रास्फीति और बैंकिंग सेक्टर का सुदृढ़ प्रदर्शन जैसे कारक हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 में जिस गति से अर्थव्यवस्था ने बढ़त दिखाई, उसे बनाए रखने के लिए सरकार नई सुधार योजनाओं पर काम कर रही है। केंद्र सरकार आगामी बजट में पूंजीगत व्यय और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठा सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि जीवन सुगमता और कारोबार सुगमता को बढ़ाकर भारत को निवेश के लिए और आकर्षक बनाना। इससे शुल्क और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2025 में हर मोर्चे पर सफलता हासिल की और सबसे तेज गति से आगे बढ़ती रही। हाल ही में जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब भारत से आगे सिर्फ जर्मनी, चीन और अमेरिका ही हैं। वहीं,दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाओं ने भारत की जीडीपी की चमकीली तस्वीर दिखाई है। अगर इसी गति से भारत आगे बढ़ता रहा तो अगले ढाई से तीन साल में जर्मनी को पछाड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर लगातार बढ़ी है। 2025-26 की दूसरी तिमाही में यह 8.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। खुदरा मुद्रास्फीति साल के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक की निचली सीमा से दो प्रतिशत से भी कम रही। सरकार ने बताया कि भारत ने 4180 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया है। अनुमान है कि 2030 तक 7300 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। आपको बता दें 2025 में आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत घरेलू मांग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग, कम मुद्रास्फीति और स्थिर निवेश के कारण हुई। सेवा क्षेत्र का विस्तार लगातार बना रहा, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में भी वापसी हुई। कृषि में बेहतर खरीफ उत्पादन और पर्याप्त खाद्यान्न भंडार ने कीमतों को स्थिर रखने में मदद की। इन सभी कारकों ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा। आप को बता दें कि साल 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.2% रही है। यह दिखाता है कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत ने महंगाई पर काबू पाया। वहीं, बेरोजगारी दर भी कम हुई। जीएसटी में छूट देने से लोगों के पास पैसा आया और भारतीय अर्थव्यवस्था ने नया मुकाम हासिल किया। तमाम रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि 2026 में भी भारत जी-20 देशों में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नवंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 0.71% पर आ गई। वहीं, नवंबर में बेरोजगारी दर कम होकर 4.7% रह गई है, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तरहै। देश में ग्रोथ रेट ऊंची है और महंगाई बेहद कम, इसे 'गोल्डिलॉक्सपीरियड' कहा जाता है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.5% और 2026-27 में 6.7% की रफ्तार सेबढ़ेगी। यह वृद्धि घरेलू मांग, कर कटौती और ब्याज दरों में कमी से प्रेरित होगी। मूडीज ने भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक अनुमान लगाया है। एजेंसी का अनुमान है कि 2026 में 6.5% की वृद्धि दर रहेगी। यह वृद्धि घरेलू मांग, निर्यात बाजारों में विविधीकरण और अनुकूल मौद्रिक नीति रुख से समर्थित होगी। मूडजी का अनुमान है कि भारत जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 7.4% ग्रोथ का अनुमान जताया है। एडीबी ने भीभारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपना अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है,जो मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और बढ़ते निवेश के कारण है।

वहीं, विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत की जीडीपी बढ़ोतरी 2026 में 6.5फीसदी हो सकती है। बता दें कि भारत की जीडीपी का कुल वैल्यूएशन अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर (करीब 350 लाख करोड़) हो गया है। जापान को पीछे छोड़ने के बाद अगले 2.5 से 3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगाऔर साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर (655 लाख करोड़) की इकोनॉमी के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई) ने ग्रोथ ट्रेंड को देखते हुए पूरे साल के लिए इसका अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियां होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करने को तैयार है। वहीं सरकार का कहना है कि भारत 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। महंगाई अभी नियंत्रण में है और तय सीमा से नीचे है। बेरोजगारी धीरे-धीरे कम हो रही है और देश के निर्यात में लगातार सुधार हो रहा है। संभव है कि 2026 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साबित होगा और रूपये का अवमूल्यन खत्म हो कर सकारात्मक रुख की ओर बढेगा।

सहज योग संदेश

श्री सद्गुरु देव जी की अनुभव वाणी

मन के विषय तरंग को विवेक युक्ति से मारकर शरीर के रोम रोम में उस व्यापक परब्रह्म का अनुभव साक्षात्कार होगा।

तील मांहि ज्यो तेल है, तुझमें पुरुष पुरान।
सद्गुरु युक्ति निकालिए प्रकटे रूप महान।।

-जारी — महर्षि सदाफल देव जी महाराज

जनवरी की कोख में जन्म लेता नया साल

सुनो दिसंबर, जाओ, रात भर जश्न मनाओ,
यह विदाई है तुम्हारी—
थोड़ी मुस्कान छोड़ जाओ, थोड़ी खामोशी भी
ताकि यादें ठहर सकें।

सुबह जब नई किरण फूटे,
तब आना जनवरी की कोख में
बारह माह का गर्भ बनकर—समय की धड़कनों में
नए स्वप्न बोते हुए।

ले आना नई उम्मीदें, नई आशाएं,
हर थकी आंख के लिए
सपनों का उजाला, हर झुके सिर के लिए
आसमान जितनी हिम्मत।

खुशियों का झुनझुना बजाना, उदास कमरों में
हंसी की खिड़कियां खोल देना,
टूटे हौसलों में
फिर से जान भर जाना, और थमे क़दमों को
चलना सिखा देना।

बीते कल की धूल रास्तों से झाड़ देना, अधूरे पन्नों को
नई स्याही सौंप देना, हर मन में नया विश्वास उगा देना,
कि अँधेरा चाहे जितना हो
सुबह लौटकर आती है।

गल्तियों को अनुभव बना देना,
आँसुओं को सीख में बदल देना,
और हर हार के भीतर एक नई शुरुआत
छुपा देना।

फिर आना... एक साल बनकर,
जीवन के आँगन में नए रंग बिखेर जाना,

हर दिल से कहना— मैं आया हूं, तुम्हारे
लिए, एक और मौका लेकर।

-मयंक मिश्रा

सामयिक

नव वर्ष : नए सपने, नई उम्मीदें

डॉ सत्यवान सौरभ

नया वर्ष केवल कैलेंडर की तारीख बदलने का नाम नहीं है। यह हमारे जीवन में एक ठहराव की तरह आता है—जहाँ हम पीछे मुड़कर देखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और नई संभावनाएँ लेकर आता है। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है और स्वयं से यह प्रश्न करता है कि बीता वर्ष कैसा रहा, मैंने क्या सीखा, क्या खोया और आगे मुझे क्या बनना है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर भागते रहते हैं—लक्ष्यों के पीछे, जिम्मेदारियों के बोझ तले और अपेक्षाओं की दौड़ में। ऐसे में नया वर्ष हमें यह अवसर देता है कि हम थोड़ी देर रुकें, सांस लें और अपने जीवन की दिशा पर पुनर्विचार करें। यह आत्ममंथन ही नए सपनों की नींव बनता है।

बीता वर्ष : सीखों की पाठशाला

हर बीता वर्ष हमारे लिए एक शिक्षक की तरह होता है। उसमें सुख भी होते हैं, दुःख भी; सफलता भी मिलती है और असफलताएँ भी। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि हमने उससे क्या सीखा। कई बार हम बीते साल को केवल घटनाओं के आधार पर आंकते हैं—किसे खोया, क्या पाया—पर सीखों को नजरअंदाज कर देते हैं। बीते वर्ष ने हमें धैर्य सिखाया होगा, किसी ने हमें आत्मनिर्भर बनाया होगा, तो किसी ने रिश्तों की अहमियत समझाई होगी। कुछ अनुभवों ने हमें मजबूत बनाया, तो कुछ ने हमें विनम्र। नया वर्ष तभी सार्थक बनता है जब हम इन सीखों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, न कि केवल पुराने दुखों या शिकायतों को ढोते हुए।

नए सपने : दिखावे नहीं, दिशा हो

नए साल की शुरुआत अक्सर बड़े-बड़े संकल्पों से होती है—यह करूंगा, वह बनूंगा, इतना हासिल करूंगा। लेकिन कुछ ही महीनों में ये संकल्प धुंधले पड़ने लगते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे सपने कई बार दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित होते हैं, न कि हमारे वास्तविक मन से निकले होते हैं। सपने वही सार्थक होते हैं जो हमारे मूल्यों से जुड़े हों। जो हमें भीतर से उत्साहित करें, न कि थका दें। नया वर्ष हमें यह सोचने का मौका देता है कि हमारे सपने दिखावे के हैं या दिशा देने वाले। क्या हम वही बनना चाहते हैं जो समाज चाहता है, या वह जो हमारी आत्मा चाहती है? सपने छोटे भी हो सकते हैं—जैसे खुद को स्वस्थ रखना, परिवार को समय देना, या खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना। हर सपना बड़ा मंच या बड़ी पहचान नहीं मांगता; कई बार सबसे बड़ा सपना होता है—संतुलित और शांत जीवन।

नई उम्मीदें : बाहरी नहीं, आंतरिक

उम्मीदें अक्सर हम दूसरों से जोड़ लेते हैं—कि कोई बदले, परिस्थितियाँ सुधरें, सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन नया वर्ष हमें यह याद दिलाता है कि सबसे मजबूत उम्मीद वह होती है जो अपने भीतर से जन्म लेती है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तब हालात चाहे जैसे हों, हम रास्ता निकाल लेते हैं।

आंतरिक उम्मीद का अर्थ है—यह विश्वास कि मैं बदल सकता/सकती हूँ, मैं सीख सकता/सकती हूँ और मैं बेहतर बन सकता/सकती हूँ। यह उम्मीद हमें निराशा से बाहर निकालती है और असफलता के बाद भी खड़ा होने की ताकत देती है।

खुद से रिश्ताः नए साल की सबसे बड़ी शुरुआत

नए साल में सबसे पहला रिश्ता जिसे सुधारने की ज़रूरत होती है, वह है—खुद से रिश्ता। हम दूसरों की गलतियों को तो तुरंत देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियों से अक्सर बचते रहते हैं। नया वर्ष आत्मस्वीकृति और आत्मसुधार का संतुलन सिखाता है।

खुद से ईमानदारी का मतलब यह नहीं कि हम खुद को कठघरे में खड़ा करें, बल्कि यह कि हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। अपनी सीमाओं को समझें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और खुद के प्रति करुणा रखें। जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब दुनिया से हमारी अपेक्षाएँ भी यथार्थवादी हो जाती हैं।

रिश्तेः मात्रा नहीं, गुणवत्ता

नया वर्ष रिश्तों पर भी पुनर्विचार का समय होता है। आज के समय में संपर्क बहुत हैं, लेकिन संबंध कम। सोशल मीडिया ने हमें जोड़ा तो है, लेकिन दिलों की दूरी भी बढ़ाई है। नया साल यह सोचने का अवसर देता है कि हमारे जीवन में कौन से रिश्ते हमें ऊर्जा देते हैं और कौन से हमें थका देते हैं। हर रिश्ते को निभाना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाना ज़रूरी है। कुछ रिश्तों को समय देना होता है, कुछ को सीमाएँ और कुछ को सम्मानपूर्वक विदा। नए साल में रिश्तों की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी अलमारी की।

सफलता की नई परिभाषा

समाज ने सफलता की एक तय परिभाषा बना दी है—पैसा, पद और प्रतिष्ठा। लेकिन नया वर्ष हमें यह सोचने का अवसर देता है कि क्या यही सफलता है? क्या वह व्यक्ति असफल है जो शांत है, संतुष्ट है और अपने मूल्यों पर खड़ा है? सफलता की नई परिभाषा में मानसिक शांति, आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और संतुलन भी शामिल होना चाहिए। अगर हम दिन के अंत में चैन से सो पाते हैं, खुद पर गर्व महसूस करते हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं करते—तो यह भी सफलता ही है।

असफलता से दोस्ती

नए सपनों के साथ नई असफलताएँ भी आती हैं। लेकिन असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना ज़रूरी है। हर असफलता हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए नहीं है। नया वर्ष हमें यह साहस देता है कि हम फिर से कोशिश करें, बिना खुद को कमतर समझे। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे अक्सर प्रयास ही नहीं करते। और जो प्रयास नहीं करते, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। नया साल जोखिम लेने और सीखते हुए आगे बढ़ने का नाम है।

समाज और जिम्मेदारी

नया वर्ष केवल व्यक्तिगत बदलाव का समय नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी का भी समय है। हम जिस समाज में रहते हैं, उसकी समस्याओं से हम अछूते नहीं रह सकते। छोटे-छोटे प्रयास—जैसे ईमानदारी, संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता—समाज को बेहतर बना सकते हैं।

अगर हर व्यक्ति नए साल में केवल एक अच्छी आदत अपना ले—तो बदलाव अपने आप दिखने लगेगा।

निष्कर्ष : नया साल, नया दृष्टिकोण

नया वर्ष कोई जादुई छड़ी नहीं है जो सब कुछ बदल दे। बदलाव तब आता है जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं। नए सपने, नई उम्मीदें तभी सार्थक हैं जब वे हमें बेहतर इंसान बनाएं—ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा सच्चा। आइए, इस नए वर्ष में हम यह संकल्प लें कि हम परिपूर्ण नहीं, लेकिन ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे। हम सबसे आगे नहीं, लेकिन सही दिशा में चलने का प्रयास करेंगे। और जब साल के अंत में पीछे मुड़कर देखें, तो गर्व से कह सकें—हाँ, मैंने खुद के साथ ईमानदारी की। यही है नूतन वर्ष का असली अर्थ—नए सपने, नई उम्मीदें और एक बेहतर 'मैं'।

अंजेल चकमा पर हमला

देश को कहां ले जाएंगे ये नफ़रती संस्कार?

निर्मल रानी

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गत 9 दिसंबर को कुछ स्थानीय युवकों द्वारा अगरतला (त्रिपुरा) के निवासी 24 वर्षीय अंजेल चकमा नामक एक छात्र पर जानलेवा हमला किया गया। हमले के बाद 17 दिनों तक अस्पताल में इलाजरत रहने के बाद गत 26 दिसंबर को आख़िरकार उसकी मृत्यु हो गई। चकमा, देहरादून स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में एमबीए अंतिम वर्ष के छात्र थे। ख़बरों के अनुसार देहरादून में अंजेल चकमा की मौत एक कथित नस्लीय हमले के कारण हुई। बताया जाता है कि 9 दिसंबर को जब अंजेल और उनके 21 वर्षीय छोटे भाई माइकल चकमा पास के सेलाकुई इलाक़े में किराने का सामान ख़रीदने गए थे उसी समय उनके चेहरों को देखकर हमलावरों ने उन्हें नस्ली गालियां दीं। बताया जाता है कि घटनास्थल पर क़रीब छह लोगों का एक समूह, जो पास में ही पहले से किसी के जन्मदिन का जश्न मना रहा था, ने उन्हें रोक लिया। हमलावरों ने उनपर नस्ली टिप्पणियां करते हुये उनपर 'चिंकी ', 'चीनी' और 'मोमो' जैसी टिप्पणी की। जबकि एक आरोपी ने कहा कि 'ओये चीनी, क्या सूअर का मांस ख़रीदने आए हो ?' माइकल ने इसका विरोध किया, तो एक आरोपी ने उन्हें ब्रेसलेट से सिर पर मारा। अंजेल ने अपने भाई की रक्षा करने की कोशिश की और शांतिपूर्वक कहा, 'हम चीनी नहीं हैं... हम भारतीय हैं। क्या प्रमाण-पत्र दिखाएं कि हम भारतीय हैं?' लेकिन नफ़रती संस्कारों में डूबे गुंडों के इस समूह ने हिंसक रूप से उनपर हमला कर दिया। यज्ञ अवस्थी नामक मुख्य आरोपी ने अंजेल की गर्दन और पीठ पर तेज़ हथियार से वार किया, जिससे वे गिर पड़े। माइकल भी घायल हुए, लेकिन उन्होंने अंजेल को पास के अस्पताल पहुंचाया। अंजेल की हालत गंभीर थी—उनकी गर्दन और स्पाइन में गहरी चोटें थीं—आख़िरकार वे कभी पूर्ण चेतना में वापस नहीं आए और नफ़रत के सौदागरों ने एक होनहार भारतीय छात्र की हत्या कर उसके परिवार को अंधकार में धकेल दिया। निश्चित रूप से इस घटना ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के छात्रों के ख़िलाफ़ उपजी नस्लवाद की समस्या को फिर से उजागर कर दिया है। इस घटना को लेकर त्रिपुरा सहित देश के विभिन्न राज्यों व शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हालाँकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास को लेकर तरह तरह की बातें करते रहते हैं, परन्तु हक़ीक़त यही है कि गत कुछ वर्षों में इसी देव् भूमि में सत्ता संरक्षित धर्म जाति आधारित नफ़रती घटनाओं में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के पुरोला क़स्बे में एक 14 वर्षीय लड़की के अपहरण के बाद 'लव जिहाद' का आरोप लगाकर हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़काये गये। मुस्लिम मकानों व दुकानों पर लक्षित हमले किये गये, कई परिवार शहर छोड़कर भागने को मजबूर हुये। इसी तरह हल्द्वानी में 2024 की बनभूलपुरा में अवैध मदरसे और मस्जिद के विध्वंस पर पथराव, आगज़नी और पेट्रोल बम फेंके जाने की घटना सबसे प्रमुख रही, जहां 6 लोगों की मौतें हुई। 2025 में भी कश्मीरपुर और हल्द्वानी में साम्प्रदायिक तनाव देखा गया। राज्य में दलितों के विरुद्ध भी अनेक घटनायें होती रहती हैं। परन्तु समाज में धर्म जाति व क्षेत्र के नाम पर बढ़ती नफ़रतों के बीच इस राज्य को 'देव् भूमि' के रूप में भी प्रचारित किया जाता है। सवाल यह है कि उत्तराखंड जैसे शांतिप्रिय राज्य सहित देश के अन्य विभिन्न राज्यों में इस तरह के नफ़रत व हिंसा पैदा करने वाले हालात क्या अचानक पैदा हुए हैं

या सत्ता के संरक्षण में इन नफ़रती संस्कारों को पोषित किया जा रहा है? उत्तराखंड की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा दिये गये बयान से यह काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुये कहा कि 'पूर्वोत्तर के लोगों के ख़िलाफ़ ऐसी घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं और समाज को भेदभाव रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए। हम लोगों को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। हमें मिलकर भेदभाव को रोकना होगा। भारत के किसी भी हिस्से के लोगों को हर जगह सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उनकी मृत्यु बेहद दुखद है'। किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि 'देहरादून में एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ, वह एक भयावह घृणा अपराध है'। उन्होंने आगे यह भी कहा कि 'ऐसी नफ़रत रातों रात पैदा नहीं होती। वर्षों से इसे रोज़ाना, ख़ासकर हमारे युवाओं को, ज़हरीली सामग्री और ग़ैर -ज़िम्मेदाराना ख़बरों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी का भी मज़ाक़ नहीं उड़ाया जाना चाहिए। कोई भी घटना देश के लिए दुखद घटना होती है। अगर देश में ऐसी कोई भी घटना होती है तो पूरे समाज को मिलकर उसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए।' वहीं, राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी में कहा कि हम प्रेम और विविधता का देश हैं। हमें ऐसा समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीयों को निशाना बनाए जाने पर अनदेखी करे। हमें यह सोचने और सामना करने की ज़रूरत है कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं ?

अफ़सोस की बात तो यह कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा उत्तराखंड की घटना के बाद व्यक्त किये गये विचार उस समय सामने आये जब उनके अपने पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की नस्लवादी नफ़रती लोगों द्वारा हत्या कर दी गयी? जबकि लगभग एक दशक से देश में जगह जगह अल्पसंख्यकों,दलितों व पिछड़े वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है। लिंचिंग की घटनायें घटित हो रही हैं। जगह जगह उन्मादी भीड़ पुलिस की शह पर वर्ग विशेष के लोगों को निशाना बनाती रही है। जगह जगह उकसाऊ भाषण हो रहे हैं। कहीं हथियार बांटे जा रहे हैं। तो कहीं संवैधानिक पदों पर बैठे लोग स्वयं अपने ज़हरीले बोलों से समाज में हिंसा व नफरत बढ़ा रहे हैं। निःसंदेह गोदी मीडिया भी इस नफ़रती वातावरण को और भी ज़हरीला बना रहा है। ऐसे में रिजिजू की चिंताओं के अनुसार भारत के किसी भी हिस्से के लोगों का स्वयं को हर जगह सुरक्षित महसूस करना कहां संभव हो पा रहा है ? इस समय देश के समक्ष सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि आख़िर देश को कहाँ ले जायेंगे ये नफ़रती संस्कार ?

कहानी में एक मोड़ः क्या वैज्ञानिक डार्क एनर्जी के बारे में गलत हैं?

विजय गर्ग

देश भर में हजारों युवा महिलाओं के पास डिग्री है लेकिन वे बेरोजगार हैं। यह एक गहन संरचनात्मक मुद्दे को दर्शाता हैः साक्षरता और शैक्षणिक योग्यताएं, यद्यपि आवश्यक हैं, लेकिन स्वतः ही रोजगार में परिवर्तित नहीं होतीं। कई स्नातकों में समकालीन उद्योगों द्वारा अपेक्षित व्यावहारिक, डिजिटल और कार्यस्थल कौशल का अभाव होता है।

दो दशकों से अधिक समय से, डार्क एनर्जी ब्रह्माण्ड विज्ञान में सबसे रहस्यमय और आधारभूत अवधारणाओं में से एक रही है। यह समझाने के लिए पेश किया गया कि ब्रह्मांड का विस्तार क्यों तेजी से बढ़ रहा है, डार्क एनर्जी अब ब्रह्मांडीय विकास के आधुनिक सिद्धांतों पर हावी है। लेकिन हाल के शोध और वैकल्पिक विचार इस ब्रह्मांडीय पहेली के पीछे की कुछ धारणाओं को चुनौती दे रहे हैं — अग्रणी वैज्ञानिक पूछते हैंः क्या हम डार्क एनर्जी को गलत समझ रहे हैं? डार्क एनर्जी क्या है?

डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक सैद्धांतिक रूप है जो अंतरिक्ष को भर देता है और ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार को चलाता है। अवलोकनों के अनुसार, ब्रह्माण्ड की ऊर्जा सामग्री का लगभग 70% इस रूप में हो सकता है, तथा शेष भाग डार्क मैटर और साधारण पदार्थ ही हैं। इसका अनुमान पहली बार 1990 के दशक के अंत में दूर से फट रहे तारों (टाइप इआ सुपरनोवा) के अवलोकन से लगाया गया था, जो अपेक्षा से अधिक मंद दिखाई दिए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड समय के साथ तेजी से विस्तार कर रहा था।

मानक ब्रह्मांडीय मॉडल (एलसीडीएम) में, डार्क एनर्जी को एक कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट द्वारा दर्शाया जाता है — एक स्थिर ऊर्जा घनत्व जो अंतरिक्ष में समान रूप से व्याप्त होता है। यह सरल मॉडल कई अवलोकनों पर खरा उतरता है, लेकिन यह नहीं बताता कि डार्क एनर्जी क्या है।

कुछ वैज्ञानिक इस पर पुनर्विचार क्यों कर रहे हैं

1। अवलोकन संबंधी संकेत डार्क एनर्जी समय के साथ बदल सकती है

डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट (डीईएसआई) जैसे बड़े अवलोकन कार्यक्रमों ने लाखों आकाशगंगाओं के विस्तृत 3D मानचित्र तैयार किए हैं, जिससे वैज्ञानिकों को यह अध्ययन करने का अवसर मिला है कि अरबों वर्षों में ब्रह्मांडीय विस्तार किस

प्रकार विकसित हुआ है। कुछ डीईएसआई परिणाम संकेत देते हैं कि डार्क एनर्जी का प्रभाव स्थिर नहीं हो सकता है — यह अतीत में अधिक मजबूत और आज कमजोर हो सकता है। ये विकसित होते संकेत एक सरल ब्रह्मांडीय स्थिरांक के विचार को चुनौती देते हैं और सुझाव देते हैं कि अधिक गतिशील घटना सामने आ सकती है।

यदि समय के साथ डार्क एनर्जी कमजोर हो जाती है, तो ब्रह्मांड का दीर्घकालिक भविष्य अंतहीन त्वरण की पारंपरिक तस्वीर से बहुत अलग हो सकता है - संभावित रूप से एक ब्रह्मांडीय ₹बिग क्रंचर₹ की ओर भी विपरीत दिशा में 2। वैकल्पिक मॉडल जिसमें कोई डार्क एनर्जी नहीं है

कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि डार्क एनर्जी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ सकती। इसके बजाय, देखा गया त्वरण निम्नलिखित के कारण उत्पन्न भ्रम हो सकता है

चिकने ब्रह्मांड के बजाय गांठदार वास्तविक ब्रह्मांड में असमान विस्तार। इस दृष्टिकोण में, ब्रह्मांडीय विस्तार और गुरुत्वाकर्षण प्रभावों में भिन्नताएं उस चीज की नकल कर सकती हैं जिसे हम डार्क एनर्जी के रूप में व्याख्या करते हैं। मौलिक बलों को बदलनाः हाल ही में 2025 के एक सैद्धांतिक अध्ययन ने प्रस्ताव दिया कि मौलिक बल (जैसे गुरुत्वाकर्षण) समय के साथ धीरे-धीरे कमजोर हो सकते हैं। यह परिवर्तन ब्रह्माण्ड को ऐसा दिखा सकता है कि वह गति बढ़ा रहा है — बिना किसी अलग डार्क एनर्जी घटक की आवश्यकता के। विभिन्न ब्रह्मांडीय मॉडल जैसे कि टाइमस्केप परिकल्पना, जो सुझाव देती है कि सुपरनोवा चमक में अंतर वास्तविक त्वरण के बजाय ब्रह्माण्डीय शून्यों और संरचनाओं में समय-माप अंतर को दर्शाता है। इन वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर अभी भी बहस हो रही है और व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन वे दर्शाते हैं कि डार्क एनर्जी की भूमिका उतनी स्थिर नहीं है जितनी एक बार सोचा जाता था। 3। गतिशील डार्क एनर्जी — एक स्थिरांक नहीं

भौतिकविदों ने गतिशील डार्क एनर्जी मॉडल — का प्रस्ताव रखा है जहां समय के साथ डार्क एनर्जी घनत्व बदलता रहता है — जैसेः

क्विंटेसेंस (एक समय-भिन्न क्षेत्र जो पांचवीं शक्ति की तरह कार्य करता है)

क्विंटम परिदृश्य, जहां डार्क एनर्जी ब्रह्मांडीय इतिहास पर व्यवहार को बदल सकती है ये सरल ब्रह्मांडीय स्थिरांक विचार को विस्तारित करते हैं और कुछ विकसित हो रहे अवलोकन संबंधी आंकड़ों के साथ बेहतर ढंग से मेल खा सकते हैं।

ब्रह्माण्ड विज्ञान के लिए इसका क्या अर्थ है

चुनौतियों के बावजूद, डार्क एनर्जी ब्रह्मांडीय त्वरण के लिए सबसे अधिक समर्थित स्पष्टीकरणों में से एक बनी हुई है — लेकिन महत्वपूर्ण चेतावनियों के साथः

त्वरण के साक्ष्य मजबूत हैं, लेकिन उस त्वरण की व्याख्या सक्रिय जांच के अधीन है।

कई अवलोकन परिणाम संकेत देते हैं कि डार्क एनर्जी स्थिर रहने के बजाय समय के साथ विकसित हो सकती है।

वैकल्पिक मॉडल बिना डार्क एनर्जी के कुछ प्रमुख ब्रह्मांडीय विशेषताओं को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अब तक कोई भी सभी अवलोकनों को विश्वसनीय रूप से नहीं समझाता है।

विज्ञान में, किसी मॉडल को शायद ही कभी इसलिए खारिज किया जाता है क्योंकि वह अच्छी तरह से काम करता है - इसे कुछ समान रूप से सफल लेकिन अधिक व्याख्यात्मक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अब तक, डार्क एनर्जी सबसे अच्छा कार्यशील ढांचा बना हुआ है, लेकिन ब्रह्मांडविज्ञानी मानते हैं कि हमारी समझ अधूरी है।

आगे का रास्ता

नए अंतरिक्ष दूरबीनों, अगली पीढ़ी के आकाशगंगा सर्वेक्षणों और ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण — के गहन अध्ययन सहित भविष्य के प्रयोग परीक्षण करेंगे कि क्याः

डार्क एनर्जी एक स्थिरांक, गतिशील क्षेत्र या गहन भौतिकी की गलत व्याख्या है।

ब्रह्मांड हमेशा के लिए विस्तारित होगा, धीमा हो जाएगा, या यहां तक कि पतन में बदल जाएगा।

अगला दशक अंधकारमय ऊर्जा की खोज के बाद से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में सबसे बड़ी क्रांति ला सकता है संक्षेप मेंः डार्क एनर्जी दशकों से ब्रह्माण्ड विज्ञान के लिए केंद्रीय रही है, लेकिन नए शोध से पता चलता है कि कहानी मानक मॉडल की भविष्यवाणी से अधिक जटिल और संभावित रूप से बहुत अलग हो सकती है

डार्क एनर्जी दशकों से ब्रह्माण्ड विज्ञान के लिए केंद्रीय रही है, लेकिन नए शोध से पता चलता है कि कहानी मानक मॉडल की भविष्यवाणी से अधिक जटिल और संभावित रूप से बहुत अलग हो सकती है। वैज्ञानिक अभी तक यह निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि डार्क एनर्जी गलत है, लेकिन वे विकल्पों का सख्ती से परीक्षण कर रहे हैं और अपने मॉडलों को परिष्कृत कर रहे हैं, जिससे ब्रह्मांड और उसके अंतिम भाग्य की गहरी समझ का द्वार खुल रहा है।

गर्ग रिटायर्ड प्रिंसिपल एजुकेशनल स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

नई योजना और रोजगार की चुनौतियां

डॉ विजय गर्ग

भारत तरक्की कर रहा है, आंकड़ों से अर्शशास्त्री यही बताते हैं। निस्संदेह भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा और 2047 में जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब हम पूरी तरह से एक विकसित राष्ट्र होंगे। उस समय हर आदमी यथोचित रोजगार के साथ अच्छा भोजन करेगा, अच्छा पहनेगा और खुशहाली के शिखर होगा। यह है सपना। ऐसा अगर लोग लोग स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के बाद भी सोचते हैं, हैं, तो कारणों की तलाश करनी पड़ेगी। पिछले दिनों कहा गया हम देश से बेरोजगारी मिटा देंगे। बेरोजगारी की भूख अनुकंपा के सस्ते राशन से मिटा दी जाएगी। मगर युवा पीढ़ी जो इस देश की आधी आबादी है, वह काम चाहती है। यह कड़वी सच्चाई है कि बड़ी बड़ी संख्या में युवा आज आज भी बेरोजगार हैं। नए सर्वेक्षणों ने बताया है कि इस कृषि प्रधान देश में ग्रामीण बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बेरोजगारी बहुत का बदला रूप 'बीबी जी राम जी' इस चुनौती का मुकाबला कर पाएगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि गांवों में योजना का नया कलेवर नहीं, काम चाहिए।

बड़ी समस्या है। क्या। क्या मनरेगा का

अब जरूरत है कि देश में नागरिकों को काम के उचित अवसर मिलें। यूपीए सरकार के समय सबसे अच्छी योजना मनरेगा को ही बताया जाता था। यह फरवरी 2006 में लागू हुई थी। इसमें आवेदन करने पर पंद्रह दिन के अंदर रोजगार देना अनिवार्यहोता था। आंकड़े बताते हैं कि इस पर अब तक 11.74 लाख व करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वर्ष 2014 से राजग सरकार के कार्यकाल में भी इस पर 7.8 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हालांकि इसमें केवल सौ दिन का काम दिया जाता है। कई बार तो मजदूरों को औसत पचास दिन ही काम मिला। फिर भी मनरेगा वर्ष 2014 से अब तक आठ करोड़ लोगों को ही लोगों को ही रोजगार दे पाई।।

अब केंद्र सरकार ने संसद में नया ग्रामीण रोजगार विधेयक पारित किया है। है। ग्रामीणों को रोजगार के के लिए 20 साल के बाद योजना को एक नया कलेवर दिया गया है। इसकी शुरुआत नाम बदलने से हुई। इस योजना का नया नाम है- है विकसित भारत जी राम जी जबकि इससे पहले इसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहा जाता था। कुल जमा ये कि नई योजना ने रूप बदला है। पहले सौ दिन काम मिलता था, लेकिन अब 125 दिन काम मिलेगा, लेकिन दिहाड़ी वही रहेगी। पहले इस योजना पर

फीसद पैसा केंद्र सरकार खर्च करती थी। अब इसमें 60 फीसद योगदान केंद्र देगा। जबकि 40 फीसद राज्य सरकारें देंगी। पहले इस योजना में आवेदन करने पर 15 दिन के भीतर काम मिलता था। मगर अब काम न मिलने पर राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। मनरेगा ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए था। फिलहाल 'बीबी जी राम जी' को विकसित भारत का हिस्सा बना कर देखा जा रहा है। नई योजना की डिजिटल निगरानी होगी। ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् बनेंगीं। संचालन समितियां बनेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाली योजनाओं को 'पीएम विकास गतिशक्ति' से जोड़ देंगे। अब सवाल

है कि इस परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? संसद में विधेयक पारित भी हो गया है। इससे पहले इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष की जम कर बहस हुई। सत्तापक्ष का कहना था कि मनरेगा दिशाहीन था और इसमें ऐसा था कि पहले गड्ढे खोदो, फिर उन्हें भर दो। मुख्य उद्देश्य था गरीब परिवार के एक सदस्य को सौ दिन काम देकर मेहनताना देना। अब यह नई योजना दिशाहीन नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार का मत है कि गांवों में परिवर्तन आ गया है। भुखमरी कम हो गई है, ग्रामीण बेरोजगारी इतनी बड़ी चुनौती नहीं रही। मगर सच से कैसे इनकार किया जा सकता है? चुनौती तो अब भी है। सरकार का यह भी कहना है कि ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना बदल रही है। वहां डिजिटल भुगतान पहुंच गया है। बैंक पहुंच गए हैं। बेहतर संपर्क है, लेकिन मनरेगा में फर्जीवाड़ा हो रहा था। योजना की राशि। दुरुपयोग हो रहा था। यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब जैसे राज्यों में इतनी कम दिहाड़ी पर मजदूर काम करने के लिए राजी नहीं। इसलिए वहां फर्जी आंकड़ों से हो रहे हैं। -25 में 1 से भुगतान।

विशेषज्ञ कहते हैं कि वर्ष 2024-25 में इस योजना में 194 करोड़ रुपए का घपला हुआ और केवल 7.6 फीसद ग्रामीण परिवार ही सौ दिन का रोजगार सके, लेकिन अब माहौल बदल जाएगा। फर्जीवाड़ा रुकेगा। अब यह चुस्त-दुरुस्त और नए कलेवर वाली योजना बनेगी, जिस पर बाकायदा काम होगा। श्रम बल को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जाएगा। यह यथार्थवादी योजना होगी। जब गांवों में फसल बिजाई और फसल कटाई का भरपूर आशिक योगदान मिलने की परिस्थितियां पैदा हो हैं, तो यह योजना समांतर रोजगार देना स्थगित कर देगी। बाद में लक्ष्यबद्ध तरीके से कार्यबल का इस्तेमाल किया जाएगा जो ग्रामीण जीवन का कायाकल्प कर देगा। दूसरी ओर विपक्ष के अपने तर्क हैं कि क्या यहाँ नया कलेवर मनरेगा को नहीं दिया जा सकता था? क्या उसे निश्चित उद्देश्यों के साथ लक्ष्यबद्ध नहीं किया जा सकता था। फिर जरूरी महंगाई दर देखते हुए कार्यबल के पारिश्रमिक में वृद्धि कर दी जाती। वृद्धि तो की नहीं, केवल काम 25 दिन बढ़ा दिए। राज्य सरकारें तो पहले ही अपने खाली खजाने का रोना रो रही हैं। उनका यह कहना है कि ग्रामीण विकास कोष से लेकर जीएसटी तक में से उन्हें उनका उचित भुगतान नहीं मिलता। मुआवजा नहीं मिलता। अब उन पर इस इस योजना के योगदान का 40 फीसद भार भी डाल दिया गया है। राज्य सरकारें तो अधिक आर्थिक सहायता की उम्मीद केंद्र से कर रही। थी.. लेकिन यहां एक एक और दायित्व उन पर आ गया कि अगर ग्रामीण विकास को तेजी देनी है, तो आगे बढ़ो और केंद्र सरकार के साथ योगदान करो। यह भी कहा गया कि पंजाब ही नहीं, बल्कि बंगाल इस कोष का भारी दुरुपयोग हुआ। इसलिए नया विधेयक लाया गया

सब कुछ, यह योजना क्या काम करेगी, इसे स्पष्ट किया गया है। यह मूलभूत बुनियादी ढांचा बनाएगी। आजीविका के लिए पूंजी का निर्माण I करेगी और प्रदूषण से निपटने का कार्य करेगी। यह निराशाजनक है कि इस पर गंभीर चर्चा नहीं हुई। इसका नाम बदलने पर ही बहस होती रही। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है! मगर अब तो लगता है कि नाम रखा है। मगर अब तो लगता है कि नाम में ही रखा है। सच तो यही है है। सच तो यही है कि साम, दाम, दंड, भेद के साथ अपना नाम रौशन करने की यह जिद है। बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। सत्ता की यह नई संस्कृति बनती जा रही। जा रही है। ग्रामीण रोजगार संबंधी इस योजना को सार्थक बनाना है, तो उसके लिए आर्थिक आबंटन भी बढ़ना चाहिए। नई योजना में केंद्र सरकार ने आर्थिक आबंटन तो बढ़ाया नहीं, अलबत्ता राज्य सरकारों पर बोझ जरूर डाल दिया गया है। अब जिस प्रकार संवादहीनता गैर-भाजपा सरकारों और केंद्र के बीच चलती है, या जहां 'डबल इंजन सरकारें नहीं हैं, वहां इस नई योजना का भविष्य क्या होगा, यह विचारणीय है। क्या योजना का नाम बदलने भर से सार्थकता साबित होगी?

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

जब कक्षाएं असफल हो जाएं तो पहले स्टाफरूम को देखें

डॉ विजय गर्ग

जैसे-जैसे शैक्षणिक वर्ष समाप्त होता जा रहा है, देश भर के स्कूल अपनी पढ़ाई पूरी करने की एक परिचित अनुष्ठान में लग जाते हैं। वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया जाता है, तस्वीरें चुनी जाती हैं और प्रगति की कहानियां सावधानी से संकलित की जाती हैं। वर्ष के अंत में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य चिंतन और जवाबदेही को दर्शाना है, फिर भी जो चीज अक्सर गायब रहती है, वह है स्टाफरूम संस्कृति की गंभीर जांच, भले ही इसका शिक्षण गुणवत्ता, स्टाफ मनोबल और कक्षाओं की स्थिरता पर सीधा प्रभाव पड़ता हो।

स्टाफरूम को कभी-कभी एक अनौपचारिक स्थान के रूप में माना जाता है, लेकिन व्यवहार में यह स्कूल के भावनात्मक और पेशेवर केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो दैनिक बातचीत को आकार देता है और शिक्षण के तरीके को प्रभावित करता है।

जब कक्षाओं में संघर्ष शुरू होता है, तो स्पष्टीकरण आमतौर पर संस्थान के बाहर ही दिया जाता है। कहा जाता है कि छात्र विचलित हो जाते हैं, माता-पिता को मांग करने वाला बताया जाता है, ध्यान अवधि कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को दोषी ठहराया जाता है, तथा पाठ्यक्रमों को अत्यधिक बताया जाता है। जिसे शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है, वह यह है कि शिक्षण कोई तटस्थ या यांत्रिक गतिविधि नहीं हैः यह गहराई से भावनात्मक और संबंधपरक होती है, जो शिक्षकों के काम करने की परिस्थितियों से आकार लेती है। समय के साथ, स्टाफरूम एक अदृश्य पाठ्यक्रम बन जाता है, जो पदानुक्रम, सहनशक्ति और किसे महत्व दिया

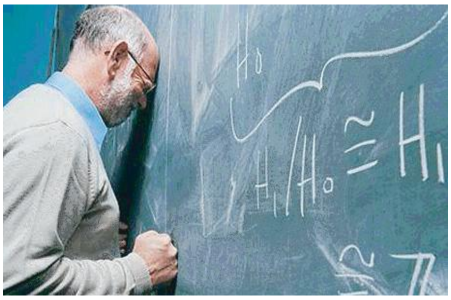

जाता है, इस बारे में अनकहे नियम पारित करता है। जब यह स्थान चयनात्मक मान्यता, प्रदर्शनकारी अनुपालन, दबी हुई असहमति और थकान की शांत स्वीकृति से चिह्नित होता है, तो समस्याएं अचानक प्रकट नहीं होतीं; वे एकत्रित हो जाती हैं। अंतिम सत्र तक, कई शिक्षक न केवल थके हुए होते हैं बल्कि भावनात्मक रूप से भी थक जाते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में शिक्षण सूक्ष्म तरीकों से बदल जाता है। धैर्य कम हो जाता है, प्रयोग जोखिम भरा लगता है, और पाठ संलग्नता के बजाय नियमित रूप से पूरा करने की ओर बढ़ जाते हैं। विद्यार्थियों को जवाब देने के बजाय पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। युवा लोग वयस्कों के बीच असंगति को शीघ्रता से महसूस करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया उदासीनता, वापसी या निष्क्रिय प्रतिरोध हो सकती है। जिसे कक्षा विकार कहा जाता है, वह अक्सर पेशेवर वातावरण का परिणाम होता है, जिसने पहले ही शिक्षकों को सुरक्षा और उद्देश्य की भावना से कमजोर कर दिया है।

इन संस्कृतियों को बनाए रखने या चुनौती देने में नेतृत्व की निर्णायक भूमिका होती है। यह शायद ही कभी नाटकीय होता है। अक्सर यह असहमति के प्रति असहिष्णुता, अस्पष्ट निर्णय लेने, असमान जवाबदेही और मान्यता के रूप में प्रकट होता है जो पदार्थ की अपेक्षा दृश्यता को प्राथमिकता देता है। नियंत्रण को अधिकार के साथ भ्रमित किया जाता है, गति को प्रभावशीलता समझ लिया जाता है। बैठकें समझौते के अनुष्ठान बन जाती हैं, और शिक्षक सीखते हैं कि अनुपालन में निर्णय से कम जोखिम होता है। भय धीरे-धीरे संगठनात्मक सिद्धांत बन जाता है, भले ही यह विश्वास और पहल को कम कर देता है। इसके साथ ही सहकर्मी सहभागिता भी हैः स्टाफ रूम ऐसे स्थानों में बदल सकते हैं जहां गपशप समर्थन की जगह लेती है, सामंजस्य के नाम पर औसत प्रदर्शन का बचाव किया जाता है, और नाजुक संतुलन को बिगाड़ने के लिए मजबूत काम से नाराजगी जताई जाती है।

यदि वर्ष के अंत में चिंतन करना महत्वपूर्ण है, तो उसे इन वास्तविकताओं पर ध्यान देना होगा। चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए ईमानदारी और साहस की आवश्यकता होती है। सतही कल्याण कार्यक्रम या छात्र-केंद्रित पहल, शिक्षकों को थका देने वाले वातावरण की भरपाई नहीं कर सकती। जब स्टाफरूम की संस्कृति में सुधार होता है, तो अन्य परिवर्तन भी होते हैं। शिक्षकों को पुनः आत्मविश्वास मिलता है, सहयोग मजबूत होता है, तथा कक्षाएं अधिक स्थिर हो जाती हैं। अनुशासन प्रतिक्रियात्मक के बजाय निवारक रूप से बढ़ता है, नवाचार साझा महसूस होता है, और सीखने की दिशा पुनः प्राप्त होती है, क्योंकि शिक्षक अब आने वाले वर्ष में स्कूल समुदाय में विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों के लिए उत्तरजीविता मोड में काम नहीं कर रहे हैं।

सेवानिवृत्त प्रधान शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

आत्मसम्मान की रोशनी

डॉ विजय गर्ग

जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभाता है- पुत्र, मित्र, शिक्षक, कर्मचारी, नागरिक। इन सभी पहचानों के बीच एक पहचान ऐसी है जो सबसे स्थायी है- स्वयं की। आत्मसम्मान उसी पहचान का मूल है। यह वह मौन शक्ति है जो व्यक्ति को परिस्थितियों के आगे झुकने नहीं देती, बल्कि उन्हें आकार देने की प्रेरणा देती है।

आत्मसम्मान वह अदृश्य दीपक है, जो भीतर जलता है और अंधकार के समय दिशा दिखाता है। इसक अर्थ है स्वयं को स्वीकारना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और जीवन के प्रति गरिमा का भाव बनाए रखना। यह अहंकार नहीं, बल्कि आत्म- स्वीकार की परिपक्वता है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करता है, जबकि आत्मसम्मान स्वयं को गरिमा से ऊंचा उठाता है। यह उस व्यक्ति की पहचान है जो कहता है कि 'मैं जैसा हूं, वैसा ही पर्याप्त हूं।'

कभी-कभी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं, जो बार - बार हमें चोट पहुंचाते हैं, अपमानित करते हैं, और फिर एक साधारण 'सारी' या 'माफी' कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। वे वही गलती दोहराते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा की तरह माफ करते रहेंगे। पर हर 'सारी' रिश्ते को नहीं जोड़ती। क्षमा तभी अर्थपूर्ण होती है, जब सामने वाला अपनी गलती की गहराई सच में समझे।

आत्मसम्मान का अर्थ कठोर होना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि क्षमा वहीं तक उचित है, जहां हमारी गरिमा सुरक्षित रहे। जब किसी की गलती इतनी गहरी हो कि उसे भूलना खुद के साथ अन्याय लगे, तब दूरी बनाना गुस्सा नहीं, अपनी मानसिक शांति और स्वाभिमान की रक्षा करना होता है। दूसरों को माफ करना अच्छा है, पर खुद को भूल जाना कभी नहीं। इसी तरह, जब कार्यस्थल पर हमारी मेहनत को बार- बार नजरअंदाज किया जाता है, हमारी योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता या हमारा योगदान किसी और के नाम कर दिया जाता है, तो चुप रहकर सब लंबे समय तक सहना विनम्रता नहीं, बल्कि अपने मूल्य को कम आंकना है। वहां अपनी काबिलियत के लिए शांत, पर दृढ़ आवाज उठाना ही सच का पक्ष और स्वाभिमान की रक्षा बन जाता है।

रिश्तों में भी कई बार हम अनजाने में ऐसी आदत पाल लेते हैं कि हर बहस के बाद 'माफी' हम ही बोलते हैं, चाहे गलती सामने वाले की हो। हम सोचते हैं कि इससे रिश्ता बचेगा, पर धीरे-धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। इस चक्र को रोकना, अपनी बात, अपने दर्द और सम्मान को तवज्जो देना दरअसल अपनी कद्र करना है। कुछ स्थितियों में गलत व्यवहार इतना गहरा होता है कि शब्द बेअसर हो जाते हैं। वहां चुप्पी ही सबसे मजबूत जवाब बन जाती है।

जब कोई व्यक्ति हमें सिर्फ तब याद करे, जब उसे हमारी जरूरत हो, काम निकालना हो, सहानुभूति चाहिए हो, या अकेलापन बांटना हो, पर हमारी जरूरत के समय वह हमेशा गायब मिले, तो ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना भी स्वाभिमान का ही हिस्सा है। खुद को हर समय उपलब्ध न कराना, अपनी ऊर्जा और भावनाओं की रक्षा करना, और यह समझना कि हर कोई हमारे दिल तक पहुंचने का अधिकार नहीं रखता, यही आत्मसम्मान की असली शुरुआत है। सच तो यही है कि स्वाभिमान वहीं बचता है, जहां हम खुद को खोने से पहले रुकना और अपनी गरिमा को प्राथमिकता देना सीखते हैं।

आत्मसम्मान केवल दूसरों से व्यवहार का विषय नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति दृष्टिकोण का विषय है। जब कोई व्यक्ति गलती करता है और बिना बहाने के 'हां, मुझसे भूल हुई' कहने की हिम्मत रखता है, वह आत्मसम्मानित होता है। जब कोई अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, चाहे सामने लाभ ही क्यों न हो, वह आत्मसम्मान जी रहा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मसम्मान केवल बड़े निर्णयों में दिखता है, पर सच्चाई यह है कि यह हमारी रोजमर्रा की आदतों में बसता है। जब कोई विद्यार्थी नकल से इनकार करता है, कोई महिला अपने अधिकार के लिए बोलती है, या कोई व्यक्ति अपमानित होकर भी शांत और संयमित रहता है, तो ये सभी आत्मसम्मान के जीवंत उदाहरण हैं।

आज सोशल मीडिया और तुलना की दुनिया में लोग अपनी कीमत 'लाइक' और 'फालोअर्स' से मापने लगे हैं। पर आत्मसम्मान हमें सिखाता है कि पहचान भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है, वही दूसरों को प्रेरणा दे सकता है।

आत्मसम्मान हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। यह चिंता, असुरक्षा और आत्मसंदेह से बचाता है। जब हम खुद को स्वीकारते हैं, तब हम दुनिया की अपेक्षाओं में उलझते नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। यह एक ऐसा मौन कवच है, जो हमें हर असमानता, उपेक्षा और अपमान से बचाता है।

जीवन का सबसे बड़ा संतोष यह नहीं कि दुनिया हमें कितना सम्मान देती है, बल्कि यह है कि हम स्वयं को कितना सम्मान देते हैं। आत्मसम्मान कोई पदक नहीं है, जिसे कोई और दे। यह आत्म-निर्णय है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपनी गरिमा से समझौता नहीं करूंगा। कभी-कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है, जहां चुप रहना आसान होता है, पर स्वयं का सम्मान बचाना कठिन। ऐसे क्षणों में याद रखना चाहिए कि दुनिया की नजरों में हार जाना भी स्वीकार्य है, अगर अपने भीतर हम विजेता हैं। आत्मसम्मान वही रोशनी है जो हमें हर अंधेरे से पार ले जाती है। जब हम खुद का सम्मान करना सीख लेते हैं, तब हमें किसी और से स्वीकृति मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो अपने भीतर की गरिमा को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट

स्कूल के बाहर खड़ी आधी आबादी : जब बेटियाँ बीच रास्ते लौट आती हैं

नववर्ष : आत्ममंथन, आत्मनिर्माण से विजयध्वज तक

नव वर्ष दस्तक देता है चुपचाप,
न कोई शोर, न कोई दावा,
बस पूछता है हमसे इतना—
क्या बदलेगा हम में वक़्त का नज़रिया?
बीते कल को दोष न दें,
वह शिक्षक था, शत्रु नहीं,
हर ठोकर ने गढ़ा हमें,
हर हार बनी नई कहानी।
नया साल कहता है—
तेज़ नहीं, मजबूती सह चलो,
ऊँचा नहीं, सार्थक बनो,
जीतो नहीं, योगदान दो।
जहाँ शब्द नहीं, आचरण बोले,
जहाँ सत्ता नहीं, निश्छल सेवाभाव हो,
जहाँ भीड़ नहीं, विवेक चले,
और हर निर्णय में मानवता की मिसाल हो।
नववर्ष यह भी सिखलाए—
सफलता केवल अर्जित में नहीं,
अर्पण करने में भी होती है,
अहंकार, लालच और भय को।
चलो ऐसे समाज की स्वतः नींव रखें—
जहाँ भूख शर्मिंदा हो जाए,
व न्याय प्रतीक्षा न करे - स्वतः मिले,
और सच को सुरक्षा मिल जाए।
नया वर्ष कोई परिकल्पना नहीं,
यह हमसे ही आकार लेता है,
हम जैसे सोचते, बोलते, करते हैं,
वही तो आने वाला कल स्वयं बनता है।

इस नववर्ष संकल्प लें—
कम बोलें, अधिक करें,
कम चाहें, अधिक दें,
और जो हैं, उसमें ही संतोष रखें।
नववर्ष आपके जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रेम, मानवता, स्पष्टता, साहस और विजय पताका की रोशनी लेकर आए

प्रिय दिसम्बर तुम जा रहे हो..

प्रिय दिसम्बर तुम जा रहे हो..
जाने से पहले, झोली भरकर
सौगातें देकर जाना..
रोशन हो सबका जीवन
अंधियारे लेकर जाना.,,,.!

ग़म न रहें जीवन में किसी के
सौभाग्य, उपहार में दे जाना
दुःख की रातें दूर रहें,
सुख के दिन बरसा जाना.,, !!

रिश्तों के मोती बिखरें न
धागा अटूट बांध जाना
स्वस्थ रहें, सुख चैन रहे,
आशीष दुआएं दे जाना..,, !

हम साल के अंतिम माह मे है
हमने महसूस किया कि हमें
उन सभी लोगों का शुक्रिया
करना है, जिन्होंने हमे मुस्कुराने
कि वजह दी है..
₹आप उनमे से एक हैं₹...!

विदा ले रहे साल के अंतिम दिन
हमारा नमन स्वीकार हों,
हमे क्षमा कीजिये अगर आपके
सम्मान मे जाने अनजाने मे हुई
हमारी भूल को, मन, वचन, कर्म

और वाणी से यदि ठेस पहुंची
हो तो हम हृदय से ₹क्षमा₹
चाहते है..,,, !!

आपका दिन शुभ हो

यह हमारे समर्पित शिक्षकों के मनोबल को कमजोर करने और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर जानबूझकर अविश्वास पैदा करने का एक गंभीर और सुनियोजित प्रयास है। दिल्ली के साथ इस प्रकार का छल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झूठ की राजनीति पर ज़ीरो टॉलरेंस है और इसके लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों को कानून के तहत पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा। **-रेखा गुप्ता**

अब जब राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहरा रहा है, तो उससे टकराने वाली हवाएँ दुनिया भर में यह संदेश लेकर जाएँगी कि हमारी ओर गौर से देखो, हम वही सभ्यता हैं, जिसे मिटाने के लिए न जाने कितने आक्रांता आए। आज उन आक्रांताओं के कहीं अवशेष नहीं बचे हैं, जबकि हमारे ध्वज समंदर पार भी गगन से बातें कर रहे हैं। **-राजनाथ सिंह**

संपादकीय

मजबूत होती अर्थव्यवस्था

दुनिया नए साल यानी 2026 में प्रवेश कर गई है। लोगों को उम्मीद है कि नया साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा बेहतर होगा। भारत भी इसी उम्मीद के साथ भविष्य के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। इसके सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर देश-दुनिया में आए तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत प्रगति कर रहा है। आर्थिक विकास दर लगातार बेहतर हो रही है। जब दुनिया भर में एक और मंदी की आशंका गहरा रही हो,ऐसे में भारत की बढ़ती विकास दर चौकाने वाली है। साथ ही यह इस बात का भी प्रतीक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा पहले तुलना में मजबूत हो रहा है और विकास दर भी बढ़ रही है। विभिन्न वैश्विक आर्थिक संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक, नया साल भारत के लिए और ज्यादा बेहतर आर्थिक संभावनाओं वाला साल होगा। केयर एज रेटिंग के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7 फीसदी के दर से आगे बढ़ सकती है। वहीं एक्सिस बैंक की रिपोर्ट तो दावा करती है कि नए वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था साढ़े सात फीसदी से भी ज्यादा की दर से आगे बढ़ेगी। फिलहाल भारत 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डालर की मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। वैश्विक निवेश फर्म इन्वेस्को का मानना है कि 2026-2027 में भी भारत दुनिया की सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी अपेक्षा की जा रही है कि तमाम वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धाओं के बीच भारत में आर्थिक व वित्तीय सुधार तेजी से जारी रहेंगे। फिलहाल 2025 की आर्थिक प्रगति रिपोर्ट बताती है कि घरेलू मोर्चे पर भारत की मजबूती लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि अमेरिका द्वारा भारी-भरकम 50 फीसदी का टेरिफ थोपने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत मजबूत बनी हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत का घरेलू बाजार और मजबूत होकर 10 फीसदी से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यह वृद्धि दर जारी रही तो 2030 तक भारत का घरेलू बाजार बढ़कर लगभग 237 अरब डालर की उंचाई तक पहुंच जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि 2026 में महंगाई घटने,कर सुधार और व्याज दर में कमी से घरेलू बाजार मजबूत होगा और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी व स्थायित्व के साथ आगे बढेगी। भारतीय रिजर्व बैंक भी दावा कर रहा है कि 2026 में भी महंगाई के स्तर पर पहले ही तरह ही नरमी बनी रहेगी। इसके अलावा बीते साल में जीएसटी की दरों में सुधार की जो पहल हुई थी,उसके परिणाम 2026 में ज्यादा व्यापक होकर सामने आएंगे। उम्मीद यह भी की जा रही है कि मनरेगा में बदलाव करके वीवी जी राम जी, जो नया कानून बनाया गया है,वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला साबित होगा। आगामी 1 अप्रैल से प्रभावी होने जा रहे नए आयकर कानून से भी काफी सकारात्मक उम्मीदें लगाई जा रही हैं।माना जा रहा है कि यह महज कुछ धाराओं में बदलाव ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था में व्यापक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके लागू होने ये मध्य आय वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। उम्मीद की जा रही है कि 2025 में भारत ने ब्रिटेन,ओमान और न्यूजीलैंड के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता किया है और अमेरिका सहित कुछ अन्य देशों के साथ जो बातचीत चल रही है,उसके भी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। भारत के निर्यात में तेजी से वृद्धि होगी और पूंजीगत ढांचे का विकास होगा। इन सबके साथ-साथ नए साल में कई और अच्छी आर्थिक संभावनाएं भी बनती दिखाई पड़ रही हैं। जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 में भारत का शेयर बाजार भी तेजी के साथ रफ्तार पकड़ेगा और दुनिया भर के निवेशक भारत में और भरोसे व उत्साह से निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे।क यानी 2026 भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से पिछले साल की तुलना में ज्यादा बेहतर होगा और इसमें स्थायित्व भी आएगा।

इस साल पांच राज्यों के चुनाव तय करेंगे महागठबंधन की एकता

संजय सक्सेना

> यह साल केवल राज्यों की सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि विपक्षी एकजुटता जमीन पर कितनी मजबूत है और क्या वह सत्तारूढ़ एनडीए को वास्तविक चुनौती दे पाने की स्थिति में है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी इन पांच जगहों पर होने वाले विधानसभा चुनावों को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन पांच राज्यों में कुल ८२४ विधानसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में २९४, तमिलनाडु में २३४, केरल में 140, असम में १२६ और पुडुचेरी में ३० सीटों पर चुनाव होंगे। इन चुनावों का महत्व इसलि

साल 2025 के विदा होते ही भारतीय राजनीति पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। नए साल 2026 की शुरुआत ऐसे दौर से हो रही है, जहां एक के बाद एक चुनाव देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। यह साल केवल राज्यों की सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि विपक्षी एकजुटता जमीन पर कितनी मजबूत है और क्या वह सत्तारूढ़ एनडीए को वास्तविक चुनौती दे पाने की स्थिति में है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी इन पांच जगहों पर होने वाले विधानसभा चुनावों को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन पांच राज्यों में कुल 824 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, केरल में 140, असम में 126 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव होंगे। इन चुनावों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चार राज्यों में मौजूदा सरकारें इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के पास हैं, जबकि असम में भाजपा सत्ता में है और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे में यह मुकाबला एनडीए से ज्यादा विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की मजबूती और उसकी आपसी तालमेल की परीक्षा बन गया है।

राष्ट्रीय राजनीति का सेमीफाइनल

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2011 से सत्ता में हैं और 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीतकर भाजपा को 77 सीटों पर रोक दिया था। हालांकि, भाजपा लगातार दावा करती रही है कि बंगाल में उसका वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत महज डेढ़ फीसदी बढ़ा, जबकि तृणमूल का वोट शेयर करीब तीन फीसदी मजबूत हुआ। 2026 में ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में होंगी, जबकि कांग्रेस और वाम दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते दिखेंगे। भाजपा के सामने चुनौती यह है कि कांग्रेस-वाम के कमजोर होने के बावजूद उसका सीधा लाभ उसे नहीं, बल्कि तृणमूल को मिला है।

दक्षिण भारत में तमिलनाडु का चुनाव सबसे दिलचस्प माना जा रहा है। 2021 में डीएमके ने 234 में से 133 सीटें जीतकर सत्ता संभाली थी और कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एआईएडीएमके 66 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि भाजपा को गठबंधन में रहते हुए 4 सीटें मिली थीं। अब हालात बदल चुके हैं। एआईएडीएमके और भाजपा का गठबंधन टूट चुका है और राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब अभिनेता थलपति विजय ने तमिलागा वेट्टूरी कड़गम के नाम से अपनी पार्टी बना ली। इससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। डीएमके के सामने सत्ता दोहराने की चुनौती है, वहीं एआईएडीएमके खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में है और भाजपा अपने संगठन विस्तार पर जोर दे रही है।

केरल में राजनीतिक परंपरा रही है कि हर पांच साल में सत्ता बदलती है, लेकिन 2021 में पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा ने इस परंपरा को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। एलडीएफ ने 140 में से 99 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ विपक्ष में चला गया था। 2026 का चुनाव पिनराई विजयन के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। अगर वह तीसरी बार सत्ता में लौटते हैं, तो यह केरल ही नहीं, देश की वाम राजनीति के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी ओर कांग्रेस पूरी ताकत से वापसी की कोशिश में है। प्रियंका गांधी केरल से सांसद हैं और केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता राज्य की रणनीति संभाल रहे हैं। भाजपा का लक्ष्य यहां सीटों की संख्या बढ़ाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है।

पूर्वोत्तर में असम का चुनाव भाजपा के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। 2016 से सत्ता में काबिज भाजपा ने 2021 में 126 में से 75 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में पार्टी हैट्रिक की तैयारी में है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 50 सीटों पर सिमट गया था और अब वह अपने लंबे राजनीतिक वनवास को खत्म करने की कोशिश करेगा। असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ तीसरे मोर्चे के रूप में असर डाल सकती है, खासकर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में।

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 2021 में एनआर कांग्रेस और भाजपा गठबंधन ने 30 में से 16 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। एन रंगासामी मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस महज दो सीटों पर सिमट गई थी। 2026 में यहां फिर से एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। छोटे राज्य होने के बावजूद पुडुचेरी का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति में संदेश देने वाला माना जाता है।

विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 2026 में 75 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 7, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 सीटें खाली होंगी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा चुनाव होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, जिन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है।कुल मिलाकर 2026 का साल भारतीय राजनीति के लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है। यह साल बताएगा कि विपक्षी दलों की एकजुटता सिर्फ मंचों और बयानों तक सीमित है या वह चुनावी मैदान में भी असरदार साबित हो सकती है। इन चुनावों के नतीजे न सिर्फ राज्यों की सरकारें तय करेंगे, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की नींव भी यहीं से रखी जाएगी।

समाधान, संकल्प और लोकतांत्रिक नवजागरण का उद्घोष

ललित गर्ग

> २०२६ से शांति, खुशहाली और प्रगति की बहाली की संभावना बनती दिख रही है। बीते वर्ष की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि पुरानी समस्याओं के उत्तर पुराने तरीकों से नहीं मिल सकते। इसलिए २०२६ में हमें बीते बस के सवालों के जवाब नए वक्त, नई सोच और नए विवेक में ढूंढने होंगे। यह वर्ष केवल कैलेंडर का बदलाव नहीं, बल्कि सोच, दृष्टि और प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण का अवसर है। यह वर्ष समाधान, संकल्प और लोकतांत्रिक नवजागरण का उद्घोष बने, इसके लिये हमें तत्पर होना होगा, तैयारी करनी होगी।

नया साल 2026 अनेक आशाओं, अपेक्षाओं, उम्मीदों और संकल्पों के साथ हमारे सामने है। वर्ष 2025 जहाँ वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर इम्तिहान, अस्थिरता और इंतज़ार का साल रहा, वहीं 2026 से शांति, खुशहाली और प्रगति की बहाली की संभावना बनती दिख रही है। बीते वर्ष की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि पुरानी समस्याओं के उत्तर पुराने तरीकों से नहीं मिल सकते। इसलिए 2026 में हमें बीते बस के सवालों के जवाब नए वक्त, नई सोच और नए विवेक में ढूंढने होंगे। यह वर्ष केवल कैलेंडर का बदलाव नहीं, बल्कि सोच, दृष्टि और प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण का अवसर है। यह वर्ष समाधान, संकल्प और लोकतांत्रिक नवजागरण का उद्घोष बने, इसके लिये हमें तत्पर होना होगा, तैयारी करनी होगी।

दुनिया के मोर्चे पर देखें तो रूस-यूक्रेन और इज़राइल-फ़लिस्तीन के युद्धों के अतिरिक्त भी कम-से-कम दस बड़े संघर्ष ऐसे हैं, जहाँ मानवता निरंतर घायल हो रही है। आतंकवाद, नस्ली विद्वेष, धार्मिक कट्टरता और सत्ता-लिप्सा ने इंसानी खून को सस्ता बना दिया है। वर्ष 2025 में यह रक्तपात थमा नहीं, पर नए साल में इन युद्धों, संघर्षों और आतंकवादी हरकतों से मुक्ति की आकांक्षा केवल भावनात्मक कामना नहीं, वैश्विक नैतिकता की अनिवार्यता बननी चाहिए। भारत, जिसने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का संदेश विश्व को दिया है, शांति और संवाद की इस वैश्विक पहल में एक बार फिर नैतिक नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते वर्ष में दुनिया को जता दिये है कि वे वैश्विक नेतृत्व करने एवं दुनिया को उन्नत बनाने की भूमिका निभाने में सक्षम है। भारत की अहिंसक सोच, सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति एवं सकारात्मक मानवीय नजरिया दुनिया के लिये उपयोगी हो सकता है।

भारत के लिए 2026 कई अर्थों में निर्णायक वर्ष है। आंतरिक राजनीतिक चुनौतियाँ हों या वैश्विक दबाव, नए साल में हमें कड़वे और कभी-कभी हिंसक अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद बीते वर्षों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शांति, अहिंसा, सौहार्द और सद्भावना के दीप जलाने का संकल्प दोहराएगा। प्रधानमंत्री का यह कथन विशेष अर्थ रखता है कि जहाँ 2025 सुधारों की बात अर्थात भारत के रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार रहने का वर्ष था, वहीं 2026 से 2047 तक का कालखंड भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की निर्णायक यात्रा है। यह यात्रा केवल आर्थिक आँकड़ों की नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और लोकतांत्रिक सुदृढ़ता की भी है। विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले सुधारों को प्रभावी बनाने के लिये यह अनिवार्य है कि राजनीति की ही भांति नौकरशाही के प्रत्येक स्तर पर सुधार हो। यह ठीक है कि केन्द्र सरकार से जुड़ी उच्च स्तर की नौकरशाही में बीते वर्षों में व्यापक बदलाव हुए है, लेकिन निचले स्तर पर उसका तौर-तरीका जस का तस है। सबसे चिन्ताजनक है कि नौकरशाही का भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कारण अनेक कार्य-योजनाओं का जैसा परिणाम आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है।

हालाँकि, यह स्वीकार करना होगा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक मूल्यों में गिरावट को लेकर जो वातावरण बन रहा है, उसे गंभीरता से लेना आवश्यक है।

कविता

कलम बहुत बोलती है...!

यह कलम भी बहुत बोलती है,
शब्दों से सभी को टटोलती है।
ये राज दिलों के खोल देती है,
अंतस मन को भी टटोलती है!
सबके हृदय को झकझोरती है।

यह कलम भी बहुत बोलती है,
शब्दों से सभी को टटोलती है।
नहीं होता इसका कोई भी कद,
लिखने में ही रहती हरदम रत!
ना होती कोई हद ये है अनहद।

यह कलम भी बहुत बोलती है,
शब्दों से सभी को टटोलती है।
अब कागज की जरूरत नहीं,
स्वरदूत हो गया सबका स्वामी!
बस यही है इसकी बड़ी खामी।

यह कलम भी बहुत बोलती है,
शब्दों से सभी को टटोलती है।
कलम की टंकार गूँज लगातार,
यूँ जब कभी पकड़ती रफ्तार !
झनझनाती सबके दिलों के तार।

-संजय एम. तराणेकर

आपका मत

पानी की शुद्धता की देशव्यापी पड़ताल जरूरी

स्वच्छता और बेहतर प्रशासन के लिए हर पल मुस्तैद रहने वाले इंदौर प्रशासन ने लगातार आधे दर्जन से ज्यादा बार इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर का गौरव दिलवाने हेतु भगीरथी कार्य किये है लेकिन हाल ही में दूषित पेयजल से करीब एक दर्जन लोगों की मौत ने इंदौर की इस उपलब्धि पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है । अधिकांश स्थानों पर पेयजल की पाइप लाइनें जमीन के भीतर दबी होती हैं और जब तक कहीं बड़ा लीकेज न हो, तब तक उनकी निगरानी भी नहीं होती है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण मकानों और बहुमंजिला इमारतों की ड्रेनेज लाइनें भी भूमिगत पाइपों के माध्यम से ही डाली जा रही हैं । कई बार निर्माण एजेंसियां और ठेकेदार लागत बचाने के लिए घटिया गुणवत्ता के पाइप लगाते हैं या नियमों की अनदेखी कर ड्रेनेज लाइनों को गलत ढंग से जोड़ देते हैं ।

परिणामस्वरूप गंदा पानी पेयजल पाइप लाइनों के आसपास जमा होकर उनमें मिल जाता है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा होता है । मध्यप्रदेश सरकार ने इंदौर की घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन को अलर्ट किया है, जो सराहनीय कदम है । **-अरविंद रावल**

लोकसत्य

आप अपना मत व लेख हमें इस ई-मेल भेज सकते है।

loksatyaedit01@gmail.com

Blogger

सरलीकरण से राहतः चक्रव्यूह से मुक्त वसीयत का 'आजादी महोत्सव'

क्रांति कुमार पाठक

> सरल शब्दों में समझें तो 'प्रोबेट' अदालत द्वारा जारी किया गया वह प्रमाणपत्र है, जो कानूनी रूप से यह तस्दीक करता है कि वसीयत पूरी तरह असली है और इसे बनाने वाला व्यक्ति (वसीयतकर्ता) इसे लिखते समय पूरी तरह होश-ओ-हवास और सही मानसिक स्थिति में था।

भारत में अपनी ही संपत्ति को अपनों के नाम छोड़ जाने की प्रक्रिया अक्सर एक कानूनी दुःस्वप्न बन जाती थी। लेकिन संसद ने 'निरसन और संशोधन विधेयक, 2025' के जरिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की बेड़ियां काटकर एक नई सुबह का आगाज किया है। सालों से चली आ रही 'प्रोबेट' की अनिवार्य शर्त को अब इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया है। सरल शब्दों में कहें तो, अब मरने वाले की अंतिम इच्छा यानी उसकी 'वसीयत' को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए अदालतों की लंबी कतारों और भारी-भरकम फीस से मुक्ति मिल गई है।

सरल शब्दों में समझें तो 'प्रोबेट' अदालत द्वारा जारी किया गया वह प्रमाणपत्र है, जो कानूनी रूप से यह तस्दीक करता है कि वसीयत पूरी तरह असली है और इसे बनाने वाला व्यक्ति (वसीयतकर्ता) इसे लिखते समय पूरी तरह होश-ओ-हवास और सही मानसिक स्थिति में था। अब तक हमारा कानून एक अजीब विरोधाभास और 'क्षेत्रीय भेदभाव' का शिकार था। अगर आप मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे पुराने 'प्रेसिडेंसी टाउन्स' में रहते थे, तो वसीयत होने के बावजूद संपत्ति हस्तांतरण

के लिए प्रोबेट लेना अनिवार्य था।

यह प्रक्रिया किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थी; इसमें न केवल सालों का समय बर्बाद होता था, बल्कि संपत्ति की कुल कीमत का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 2 से 5 प्रतिशत तक) भारी-भरकम 'कोर्ट फीस' और वकीलों के खर्च की भेंट चढ़ जाता था। 2025 का यह नया सुधार इसी विसंगति पर प्रहार करता है। अब चाहे आप दिल्ली के दिल में हों, पटना की गलियों में या मुंबई के समंदर किनारे- कानून की नज़र में सब बराबर हैं। सरकार ने इस 'अनिवार्यता' को खत्म कर यह सुनिश्चित किया है कि अब विरासत पाने के लिए आपको अपनी ही जेब खाली नहीं करनी पड़ेगी।

यह ऐतिहासिक बदलाव रातो-रात नहीं आया, बल्कि इसके पीछे न्यायपालिका के दशकों पुराने कानूनी मंथन की गूंज है। इस सुधार की बुनियाद असल में साल 2001 में ही रख दी गई थी, जब 'क्लोरेंस पैस बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। हालांकि उस वक्त अदालत ने धारा 213 की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट संकेत भी दिया कि प्रोबेट की अनिवार्यता केवल कुछ विशेष और सीमित परिस्थितियों के लिए ही तर्कसंगत हो सकती है। इस फैसले ने भविष्य के लिए एक नई बहस छेड़ दी थी - कि क्या एक निर्विवाद वसीयत के लिए भी अदालती मुहर हर हाल में जरूरी होनी चाहिए?

साल 2005 में 'मैरी कोचु बनाम थॉमस' जैसे मामलों में अदालतों ने और भी सख्त रुख अपनाया। केरल हाईकोर्ट और बाद के विभिन्न फैसलों में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि प्रोबेट की अनिवार्यता का नियम अक्सर न्याय दिलाने के बजाय केवल कानूनी पेचीदगियां और बोझ बढ़ाता है। हाल के वर्षों में तो सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह दोहराया कि यदि वसीयत की सत्यता पर कोई संदेह नहीं है, तो वारिसों को जबरन अदालती चक्रव्यूह में घसीटना 'ईज ऑफ लिविंग' (सुगम जीवन) के बुनियादी सिद्धांतों के सरासर खिलाफ है। 2025 के इस नए कानून ने असल में न्यायपालिका की इन्हीं प्रगतिशील टिप्पणियों और वर्षों की कानूनी जद्दोजहद को एक 'वैधानिक कवच' प्रदान कर दिया है। संसद ने अदालतों की उस मंशा को कानून का रूप दे दिया है, जो लंबे समय से आम आदमी को वसीयत के नाम पर होने वाली कानूनी प्रताड़ना से बचाना चाहती थी।

धारा 213 के हटने से वसीयत अब एक बेहद शक्तिशाली दस्तावेज बन गई है। अब उत्तराधिकारी प्रोबेट के बिना भी सीधे संपत्ति का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और बैंक खातों का सेटलमेंट करा सकेंगे। प्रोबेट अब 'अनिवार्य' नहीं है, लेकिन 'अप्रासंगिक' भी नहीं है। भले ही सरकार ने इसे थोपना बंद कर दिया हो, लेकिन इसे बेकार समझना भारी भूल होगी। यदि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की जरा भी आशंका है, तो प्रोबेट आज भी अदालत में सबसे मजबूत 'सुरक्षा कवच' है। विशेषज्ञों के अनुसार, बड़ी संपत्ति या आपसी अनबन की स्थिति में 'स्वैच्छिक प्रोबेट' कराना एक स्मार्ट मूव है- यह भविष्य के महंगे मुकदमों से बचने का एक सबसे सस्ता और पक्का बीमा है।

संपादकीय

राष्ट्रीय नवोन्मेष और विकसित भारत की संकल्पना

पिछले एक दशक में भारत की छवि निश्चित रूप से एक सशक्त देश के रूप में निखरी है। नए वर्ष में इस बदलते भारत के भविष्य के बारे में सोचते हुए हमें देश की समृद्ध प्राचीन सभ्यता और आधुनिक राष्ट्र राज्य की संकल्पना दोनों को ध्यान में रखना होगा। लोक की स्मृति में अभी भी नैतिक और न्यायपूर्ण शासन के लिए राम-राज्य की अमिट छवि कायम है। न केवल साल 1950 में लागू भारत के संविधान की मूल प्रति में मौलिक अधिकारों वाले अध्याय के आरंभ में राम का चित्र अंकित किया गया था बल्कि साल 2025 में अक्टूबर तक 22 करोड़ लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके हैं। साल के अंत तक यह संख्या 50 करोड़ हो सकती है। इसलिए जहाँ वैश्वीकरण के अनुकूल आकांक्षाओं को ध्यान में रखना होगा वहीं नैतिकता, सत्य तथा अहिंसा जैसे मानदंडों की भी चिंता करनी है। राम-राज्य धर्म का राज्य की संकल्पना है जिसमें समता, समानता और सौहार्द के साथ सबका हर तरह से कल्याण मुख्य लक्ष्य है। देश की प्रगति की कथा को देखें तो उसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व मिलते हैं। आज हमें संयत होकर यह विचार करना होगा कि विकसित भारत कैसा होगा ? यह प्रश्न इसलिए भी जरूरी हैं कि भारतीय समाज में अनेक प्रकार की बहुलताएँ हैं जिसे लेकर कुछ विचारक देश की मौलिक एकता को प्रश्नांकित करते हैं। वे भूल जाते हैं कि भारतीय दृष्टि में बहुलता अंतर्निहित मौलिक एकता का ही प्रकटन होती है- एकम्‌ सद्‌ विप्राः बहुधा वदंति। उसी एकता को खोजना पहचानने का उद्देश्य होना चाहिए। यही सात्विक ज्ञान है जैसा गीता में कहा गया है- अविभक्तम्‌ विभक्तेषु यः पश्यति स पश्यति यानी बंटे हुओं में वह तत्व जो अनबंटा रहते हुए सब में मौजद रहता है उसे देखना चाहिए। पूरे प्राणी जगत में निकटता को आधार बना कर विविधताओं का सह अस्तित्व और पारस्परिक संवाद इस भारत की मौलिक सोच रही है। ऐसे में दूसरा या अन्य अनन्य (गहरा दोस्त!) हो जाता है। तब दूसरा या पर हमारे अपने स्व या आत्म का हिस्सा या ह्यअपरह्ल हो जाता है। हम दूसरे का आदर करते हैं और अपरिचित को अतिथि देवता के रूप में पूजते हैं । यह अकारण नहीं है कि परिवार या कुटुंब का रूपक हमारी सोच में केंद्रीय है। सबको शामिल करते हुए वसुधैव कुटुंबकम्‌ के लक्ष्य को अपनाते हुए ही विविधता में समरसता स्थापित हो सकेगी। देश की एकता, देश को अपनाने के भाव और देशप्रेम के लिए भी यह दृष्टि जरूरी है।

भविष्य पर गौर करते हुए ताजे अनुभवों पर ध्यान देना ठीक होगा। बीता वर्ष भारत के लिए चुनौतियों भरा था। अमेरिकी नीति ने भारत के निर्यात, रुपये की कीमत, निवेश तथा भुगतान संतुलन आदि को लेकर मुश्किलें खड़ी कर दीं। राष्ट्रपति ट्रम्प की तथाकथित अमेरिकी हितों को आक्रामक ढंग से आगे धकेलने की नीति ने निश्चित ही व्यापारिक दृष्टि से अहित किया।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
एक्शन इंडिया कार्यालय, अपोजिट एनएस कम्प्यूटर, झंडी रोड़, गीता भवन चौक सोनीपत- 131001

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

वैश्विक अव्यवस्था में भारतीय विवेक की दस्तक

प्रो. आरके जैन

> ब्रिक्स के भीतर एआई सहयोग, कौशल विकास और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साझा मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र को सुदृढ़ कर भविष्य की महामारियों के प्रति सामूहिक तैयारी सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा। ह्लवन अर्थ, वन हेल्थह्ल का विचार इसी व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने का भारत का दृष्टिकोण व्यावहारिक और संतुलित है। इसका उद्देश्य किसी एक मुद्रा के वर्चस्व को चुनौती देना नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार को अधिक लचीला और सुरक्षित बनाना है

नववर्ष 2026 के साथ भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण किया जाना केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन में एक निर्णायक संकेत है। ऐसे समय में जब विश्व युद्ध, ध्रुवीकरण, आर्थिक अनिश्चितता और संस्थागत अविश्वास के दौर से गुजर रहा है, भारत की यह भूमिका वैश्विक दक्षिण के लिए आशा और दिशा–दोनों का स्रोत बनकर उभरती है। यह अध्यक्षता भारत को न केवल अपनी नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर देती है, बल्कि वैश्विक विमर्श को अधिक समावेशी, संतुलित और मानव-केंद्रित बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपती है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालते हुए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि दूरदर्शी और समाधान-उन्मुख है। ब्राजील से प्रतीकात्मक गेवेल प्राप्त करने के साथ भारत ने चार मूल स्तंभों–लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता–पर आधारित एजेंडा सामने रखा है। ये स्तंभ वर्तमान वैश्विक संकटों की जड़ों को संबोधित करते हैं। महामारी, युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं और जलवायु आपात स्थितियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना लचीली प्रणालियों के कोई भी अर्थव्यवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती। भारत इसी अनुभव के आधार पर ब्रिक्स को अधिक सक्षम और अनुकूलनशील मंच के रूप में विकसित करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानवता पहले की सोच इस पूरी अध्यक्षता की वैचारिक रीढ़ है। यह दृष्टिकोण उस पारंपरिक शक्ति-राजनीति से अलग है जिसमें राष्ट्रों के संबंध केवल हितों और प्रभाव के आधार पर तय होते हैं। विस्तारित ब्रिक्स प्लस के दस सदस्य (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया) देश भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत विविध हैं। ऐसे में भारत की भूमिका एक सेतु-निमार्ता की है, जो मतभेदों को टकराव नहीं बल्कि संवाद में बदलने की क्षमता रखता है। वैश्विक दक्षिण की आवाज को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाना भारत की प्राथमिकता रहेगी, ताकि

विकासशील देशों की चिंताएं केवल सुनी ही नहीं जाएँ, बल्कि नीति निर्माण का आधार भी बनें। आज की वैश्विक व्यवस्था व्यापार युद्धों, प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से प्रभावित है। ऐसे माहौल में भारत की संतुलित विदेश नीति विशेष महत्व रखती है। एक ओर वह रूस और चीन के साथ ऊर्जा, व्यापार और डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को आगे बढ़ाता है, तो दूसरी ओर पश्चिमी देशों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को भी बनाए रखता है। यह बहुस्तरीय कूटनीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रमाण है। ब्रिक्स मंच पर इस संतुलन का उपयोग कर भारत यह दिखाना चाहता है कि सहयोग किसी एक ध्रुव के विरोध में नहीं, बल्कि साझा हितों के विस्तार के लिए हो सकता है। एनडीबी (न्यू डेवलपमेंट बैंक) की भूमिका इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, परिवहन और सामाजिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाकर यह बैंक विकासशील देशों को वैकल्पिक वित्तीय सहारा प्रदान करता है। भारत की अध्यक्षता में बैंक को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया जाएगा। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त होगी। यह प्रयास वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में संतुलन लाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा सकता है। जलवायु परिवर्तन आज केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि यह विकास, सुरक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़ा केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान हरित वित्त, स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्राथमिकता देगा। पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा करने की दिशा में भारत की प्रगति उसे नैतिक बढ़त प्रदान करती है। यही कारण है कि भारत जलवायु न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए यह तर्क देता है कि ऐतिहासिक रूप से कम उत्सर्जन करने वाले देशों पर असमान दायित्व नहीं डाला जाना चाहिए। ब्रिक्स मंच इस विमर्श को संस्थागत स्वर देने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। तेजी से विकसित हो रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीकों के संदर्भ में भारत एक संतुलित और नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तकनीक का लाभ सीमित देशों या कॉरपोरेट समूहों तक सिमटने के बजाय समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यह भारत की सोच का मूल है।

ब्रिक्स के भीतर एआई सहयोग, कौशल विकास और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साझा मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र को सुदृढ़ कर भविष्य की महामारियों के प्रति सामूहिक तैयारी सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा। वन अर्थ, वन हेल्थ का विचार इसी व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने का भारत का दृष्टिकोण व्यावहारिक और संतुलित है। इसका उद्देश्य किसी एक मुद्रा के वर्चस्व को चुनौती देना नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार को अधिक लचीला और सुरक्षित बनाना है। भारत यह स्पष्ट करता है कि डी-डॉलराइजेशन कोई वैचारिक अभियान नहीं, बल्कि विकल्पों के विस्तार की प्रक्रिया है। इसके साथ ही आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया जाएगा, ताकि विकासशील देशों को निर्णय प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और वैश्विक शासन अधिक लोकतांत्रिक बन सके। लोगों से लोगों के संपर्क को सशक्त बनाना भारत की अध्यक्षता का मानवीय पक्ष है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान, युवा कार्यक्रम, शैक्षणिक सहयोग, स्टार्टअप नेटवर्क और पर्यटन को बढ़ावा देकर ब्रिक्स को केवल आर्थिक समूह नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक मंच के रूप में विकसित किया जाएगा। नए सदस्य देशों के समुचित एकीकरण के लिए संस्थागत सुधार आवश्यक होंगे, ताकि निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सर्वसम्मति आधारित बन सके। इससे ब्रिक्स की आंतरिक एकता और वैश्विक विश्वसनीयता दोनों मजबूत होंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह अध्यक्षता यह संदेश देती है कि वैश्विक नेतृत्व का अर्थ प्रभुत्व नहीं, बल्कि साझेदारी, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व है। सहयोग, नवाचार और सतत विकास के मूल्यों पर आधारित यह दृष्टिकोण वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को नई आवाज देता है। भारत एक ऐसे जिम्मेदार और दूरदर्शी नेता के रूप में उभरता है, जो न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि भविष्य की अधिक न्यायपूर्ण, संतुलित और मानव-केंद्रित विश्व व्यवस्था की नींव भी रखता है।

नये साल का पुराना एजेंडा, सवाल कीजिए

राकेश अचल

नया साल शुरू हो गया है. इस सदी का एक चौथाई हिस्सा काल के कराल गाल में समा चुका है. इस सदी को हम इक्कीसवीं सदी कहते हैं. इस सदी में नये भारत का एक क्यूट सपना एक क्यूट दिखने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देखा था. हम उस पीढी के लोग हैं जिन्होने आधी बीसवीं सदी देखी है और एक चौथाई 21 वीं सदी देख ली. मै अपने तजुर्बे से कहना चाहता हूँ कि मालिक ! ये इक्कीसवीं सदी है– लेकिन कई बार लगता है कि सोच अब भी उन्नीसवीं में अटकी है.तकनीक(एआई) यानि कृत्रिम बौद्धिकता की और ,दावे अंतरिक्ष के,और हरकतेंह्व बैलगाड़ी वाली.इसीलिए तो सवाल बनता है–ये कौन सी सदी है मालिक !ह्वऔर जवाब हर दिन बदल जाता है. जबाब हर दिन बदलेगा. सत्ताप्रतिष्ठान सवालों का सामना किए बिना ही जबाब देगा. किंतु आप निराश मत होइए. सवाल करना मत छोडिए, प्रश्नाकुलता को हर कीमत पर अक्षुण रखिये.

प्रश्नाकुल समाज ही जीवित समाज होता है. जिस समाज के लोग प्रश्न करना छोड देते हैं या प्रतिकार करना छोड देते हैं, उनका दमन होता है, शोषण होता है. मूकदर्शकों के समाज में शोषण संस्कार और भ्रष्टाचार संस्कृति बन जाती है. दुर्भाग्य से आज का दौर ऐसा ही प्रतिकारहीन और मूकदर्शक समाज है.और इसका खमियाजा पूरा देश भुगत रहा है. हमसे गलती हो गई है. अब इसे सुधारने का समय है.

इक्कीसवीं सदी का ये दौर बीसवीं सदी के दौर से भी गया गुजरा है. बीसवीं सदी में 19 महीने का आपातकाल लगा था. जेलें प्रतिपक्ष के नेताओं से भरीं थीं लेकिन जनता सडकों पर उतरी और अंधियारे छंट गये थे. एक नया सियासी मजहब सबके सामने था. गठबंधन का मजहब. अकबर के दीने इलाही की तरह ज्यादा नहीं चला. लेकिन मरा भी नहीं. आज भी मुल्क मेझ गठबंधन की ही सरकारें चल रहीं हैं. केंद्र में तो गठबंधन के साथ ही बैशाखियों की सरकार चल रही है. नये साल में हम किसी को कोसने नहीं बैठे हैं. हम सब चाहते हैं कि सरकार चाहे जैसी हो, जनादेश की हो या धनादेश की. चुनी हुई हो या खरीदी हुई लेकिन भारत को भारत रहने दे. भारत को हिंदू या मुसलमान मुल्क बनाने की कोशिश न करे. भारतीयों को भारतीय सरकार चाहिए न कि कोई हिंदू या इस्लामिक सरकार.

उम्मीद है कि आप मेरे इस दर्शन से सहमत होंगे. न भी हों तो और भी अच्छा. क्योंकि असहमति और प्रश्नाकुलता ही लोकतंत्र का सौंदर्य है. अलंकार है, आभूषण है. बुरी बात ये है कि पिछले एक दशक में प्रश्नाकुलता की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की जा रही है.उसके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं. नये साल में नयी प्राथमिकताओं की जरूरत है।

विचार

इस साल पांच राज्यों के चुनाव तय करेंगे महागठबंधन की एकता

संजय सक्सेना

साल 2025 के विदा होते ही भारतीय राजनीति पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। नए साल 2026 की शुरूआत ऐसे दौर से हो रही है, जहां एक के बाद एक चुनाव देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। यह साल केवल राज्यों की सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि विपक्षी एकजुटता जमीन पर कितनी मजबूत है और क्या वह सत्तारूढ़ एनडीए को वास्तविक चुनौती दे पाने की स्थिति में है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी इन पांच जगहों पर होने वाले विधानसभा चुनावों को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन पांच राज्यों में कुल 824 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, केरल में 140, असम में 126 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव होंगे। इन चुनावों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चार राज्यों में मौजूदा सरकारें इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के पास हैं, जबकि असम में भाजपा सत्ता में है और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे में यह मुकाबला एनडीए से ज्यादा विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की मजबूती और उसकी आपसी तालमेल की परीक्षा बन गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2011 से सत्ता में हैं और 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीतकर भाजपा को 77 सीटों पर रोक दिया था। हालांकि, भाजपा लगातार दावा करती रही है कि बंगाल में उसका वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत महज डेढ़ फीसदी बढ़ा, जबकि तृणमूल का वोट शेयर करीब तीन फीसदी मजबूत हुआ। 2026 में ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में होंगी, जबकि कांग्रेस और वाम दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते दिखेंगे। भाजपा के सामने चुनौती यह है कि कांग्रेस-वाम के कमजोर होने के बावजूद उसका सीधा लाभ उसे नहीं, बल्कि तृणमूल को मिला है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का चुनाव सबसे दिलचस्प माना जा रहा है। 2021 में डीएमके ने 234 में से 133 सीटें जीतकर सत्ता संभाली थी और कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एआईएडीएमके 66 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि भाजपा को गठबंधन में रहते हुए 4 सीटें मिली थीं। अब हालात बदल चुके हैं। एआईएडीएमके और भाजपा का गठबंधन टूट चुका है और राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब अभिनेता थलपति विजय ने तमिलागा वेट्री कड़गम के नाम से अपनी पार्टी बना ली। इससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।

डीएमके के सामने सत्ता दोहराने की चुनौती है, वहीं एआईएडीएमके खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में है और भाजपा अपने संगठन विस्तार पर जोर दे रही है।

केरल में राजनीतिक परंपरा रही है कि हर पांच साल में सत्ता बदलती है, लेकिन 2021 में पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा ने इस परंपरा को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। एलडीएफ ने 140 में से 99 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ विपक्ष में चला गया था। 2026 का चुनाव पिनराई विजयन के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। अगर वह तीसरी बार सत्ता में लौटते हैं, तो यह केरल ही नहीं, देश की वाम राजनीति के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी ओर कांग्रेस पूरी ताकत से वापसी की कोशिश में है। प्रियंका गांधी केरल से सांसद हैं और केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता राज्य की रणनीति संभाल रहे हैं। भाजपा का लक्ष्य यहां सीटों की संख्या बढ़ाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। पूर्वोत्तर में असम का चुनाव भाजपा के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। 2016 से सत्ता में काबिज भाजपा ने 2021 में 126 में से 75 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में पार्टी हैट्रिक की तैयारी में है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 50 सीटों पर सिमट गया था और अब वह अपने लंबे राजनीतिक वनवास को खत्म करने की कोशिश करेगा। असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ तीसरे मोर्चे के रूप में असर डाल सकती है, खासकर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआई: DELHIN / 2006 / 19302

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन बालाजी हाउस, 244, ब्लॉक- बी, लेन- 3, राकेश भारद्वाज चौक के नजदीक, दिल्ली - 110033 से प्रकाशित एवं मारुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110042 से मुद्रित।
संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी
समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)
मेट्रो संपादक : दीपचंद्र कांडपाल (8447314925)
'एक्शन इंडिया' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक केवल पीआरबी एक्ट के तहत ही उत्तरदायी। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

वैधानिक सूचना
पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

आलेख

2026 की दहलीज परः भारत की आर्थिक कहानी

सुनील कुमार महला

साल 2025 से 2026 में कदम रखना केवल कैलेंडर का पन्ना पलटना भर नहीं है, बल्कि यह आत्ममूल्यांकन और नव-आरंभ का अवसर है। वास्तव में सच तो यह है कि यह समय उन सपनों और लक्ष्यों को फिर से साधने का है, जो बीते वर्ष परिस्थितियों, सीमाओं या संकोच के कारण अधूरे रह गए। साथ ही, यह आने वाली चुनौतियों को पहचानकर उनके लिए स्वयं को मानसिक, बौद्धिक और व्यवहारिक रूप से तैयार करने की प्रेरणा देता है। नया वर्ष हमें अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर आशा, संकल्प और सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। कोई भी साल पूरी तरह आदर्श नहीं होता, और 2025 भी इसका अपवाद नहीं रहा। हालांकि, उससे मिली सीख नए वर्ष में दिशा दिखा सकती है। बीता साल आर्थिक लिहाज से भारी उतार-चढ़ाव से भरा रहा।लंबी तेजी के बाद शेयर बाजार में सुस्ती आई, वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा सत्ता में आने के साथ टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। इन चुनौतियों के बीच भारत ने संतुलन और दृढ़ता का परिचय दिया। ट्रंप के दबाव के बावजूद रूस के साथ संबंधों को प्राथमिकता देकर भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। इसी अवधि में रूस, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ महत्वपूर्ण समझौते भी हुए, जो भारत की कूटनीतिक सक्रियता और आत्मनिर्भर सोच को दर्शाते हैं। जैसा कि पाठक जानते होंगे कि पिछले साल देश के भीतर जीएसटी 2.0 जैसे बड़े सुधार लागू किए गए, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अच्छी खासी मजबूती मिली। इसका असर यह रहा कि दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि 8.2% रही।साल के अंत तक भारत के जापान को पीछे छोड़कर लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान उसकी तेज और निरंतर आर्थिक वृद्धि पर आधारित है। कहना गलत नहीं होगा कि मजबूत घरेलू मांग, बढ़ता मध्यम वर्ग, सरकारी पूंजीगत खर्च, बुनियादी ढांचे में निवेश और जीएसटी जैसे संरचनात्मक सुधारों ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है।

जो बोलते नहीं, वही बहुत कुछ रचते हैं

कृति आरके जैन

जब नववर्ष की चकाचौंध पीछे छूट जाती है और उत्सवों का कोलाहल धीरे-धीरे शांत होता है, तब 2 जनवरी की सुबह एक अलग प्रकार का बोध लेकर आती है। यह वह क्षण है जब समय स्वयं धीमा पड़ जाता है और मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। इसी मौन की पृष्ठभूमि में विश्व अंतमुर्खी दिवस अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है – ऐसा दिवस जो बाहरी शोर के विरुद्ध आंतरिक संतुलन की गरिमा को रेखांकित करता है। यह दिन उन व्यक्तित्वों का सम्मान है जिनकी शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विचार में निवास करती है; जो बोलने से पहले महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया से पहले अर्थ खोजते हैं।

इस दिवस की परिकल्पना 2011 में जर्मन मनोवैज्ञानिक फेलिसिटास हाइने द्वारा की गई थी, ताकि नववर्ष के सामाजिक दबावों के पश्चात अंतमुर्खी व्यक्तियों को आत्मिक विश्राम का अवसर मिल सके। यह केवल विश्राम का दिन नहीं, बल्कि आत्म-पुनसंर्योजन का अवसर है – जहाँ व्यक्ति फिर से अपनी ऊर्जा को भीतर समेटता है। मानव व्यक्तित्व का एक बड़ा वर्ग अंतमुर्खी प्रवृत्ति लिए होता है, किंतु सामाजिक ढाँचे बहिमुर्खी अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं। इसी असंतुलन के कारण अनेक शांत स्वभाव वाले लोग स्वयं को अनदेखा अनुभव करते हैं, जबकि उनका योगदान गहराई और स्थायित्व से परिपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अंतर्मुखिता मस्तिष्क की विशिष्ट सक्रियता से जुड़ी हुई अवस्था है। ऐसे व्यक्तियों का तंत्रिका तंत्र बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए वे सीमित वातावरण में अधिक सहज और संतुलित रहते हैं। डोपामिन जैसे रसायनों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है, जिससे वे आंतरिक शांति और एकांत में मानसिक स्पष्टता अनुभव करते हैं। यही विशेषता उन्हें विचारशील, विश्लेषणात्मक और दूरदर्शी बनाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन का यह कथन कि शांत जीवन रचनात्मक चेतना को पोषित करता है, इसी मानसिक संरचना की पुष्टि करता है। अंतमुर्खी स्वभाव केवल आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति नहीं, बल्कि संबंधों को गहराई देने वाली क्षमता है।

सम्पादकीय

गुरुवार, 1 जनवरी 2026

अब चीन का दावा

गत मई में भारत-पाक के बीच छिड़े सैन्य संघर्ष के दावों में अब चीन का नाम भी जुड़ गया है। बीजिंग में आयोजित कार्यक्रम में चीन विदेश मंत्री वांग यी ने यह दावा करते हुए कहा कि चीन दुनिया के कई संघर्षों को सुलझाने में मदद करता रहा है और उसी कोशिश के चलते ही उसने भारत-पाक के बीच तनाव के दौरान ही मध्यस्थता की थी। इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यह दावा करते रहे हैं कि उनकी टैरिफ की धमकी के चलते ही भारत-पाक युद्ध रोकने पर सहमत हुए थे। जहां तक बात भारत की है, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह चीनी विदेश मंत्री के इस दावे को भी खारिज कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि संघर्ष को रुकवाने में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। भारत के मुताबिक भारी नुकसान होने के बाद पाक के सैन्य अधिकारी ने भारतीय सैन्य अधिकारी से संपर्क किया था। पाक के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिल्ट्री ऑपरेशन्स ने भारतीय डीजीएमओ से बात की और इसके बाद ही दोनों देशों में दस मई से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई। नवंबर में जारी अमे. रिकी रिपोर्ट में भी यह आरोप लगाया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर चीन ने फर्जी अकाउंट के जरिये एआई से बनाई झूठी तस्वीरें फैलाई, जिनका मकसद भारत द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों की छवि को नुकसान पहुंचाना और चीन के अपने जे 35 विमान को बढ़ावा देना था। समझना मुश्किल है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति हों या चीनी विदेश मंत्री इस तरह के दावे कर क्या साबित करना चाहते हैं। वह भी बार-बार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को तो ठीक से याद भी नहीं होगा कि वह कितनी बार अपने देश के बाहर भी जहां भी अवसर मिलता है वह यह दावा करने से भी नहीं चूकते। अब चीन भी शांति का दूत बनकर सामने आने का प्रयास कर रहा है। वैसे देखा जाए तो भारत के लिए भी यह भी एक बड़ा सबक है कि आखिर उसके साथ इस तरह की हरकतें क्यों की जा रही हैं। वह भी तब जब भारत स्पष्ट रूप से साफ कह चुका है कि किसी ने भी भारत-पाक के बीच संघर्ष रुकवाने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसमें कोई दोराय नहीं है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर के चलते जबरदस्त सफलता मिली और उसने पाक के 11 एयरबेसों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि कहीं न कहीं राजनीतिक व कूटनीतिक स्तर पर हमसे चूक हुई है और हम अपनी बात को विश्व स्तर पर सही तरीके से नहीं रख पाए हैं, जिससे अमेरिका व चीन जैसे देशों को भारत के मामलों में बोलने का अवसर मिल गया है और वह बोल भी रहे हैं। अब यह कूटनीति की विफलता ही कहा जाएगा कि भारत पाक के बीच संघर्ष विराम की खबर सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के माध्यम से ही आई थी।

मोदी की चुप्पी परेशान करने वाली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बाद अब चीन दावा कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल हुए सैन्य कार्रवाई में उसकी मध्यस्थता से अचानक ऑपरेशन सिन्दूर रोका गया था, सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर सरकार ने जो कुछ बताया ये दावे उसके विपरीत हैं और इस तरह के दावे देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब देना चाहिए, ट्रम्प पहले ही बार-बार दावे कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर आयात शुल्क का डर दिखाकर कर भारत-पाक के बीच संघर्ष को रुकवाया था और अब चीन भी दावा कर रहा है, इस पर श्री मोदी की चुप्पी परेशान करने वाली है।

-जयराम रमेश, प्रभारी, कांग्रेस संचार विभाग

देश को कहां ले जाएंगे ये नफरती संस्कार

निर्मल रानी

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गत 9 दिसंबर को कुछ स्थानीय युवकों द्वारा अगरतला त्रिपुरा के निवासी 24 वर्षीय एंजेल चकमा नामक एक छात्र पर जानलेवा हमला किया गया। हमले के बाद 17 दिनों तक अस्पताल में इलाजरत रहने के बाद गत 26 दिसम्बर को आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। चकमा, देहरादून स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में एमबीए अंतिम वर्ष के छात्र थे। खबरों के अनुसार देहरादून में एंजेल चकमा की मौत एक कथित नस्लीय हमले के कारण हुई। बताया जाता है कि 9 दिसम्बर को जब एंजेल और उनके 21 वर्षीय छोटे भाई माइकल चकमा पास के सेलाकुई इलाके में किराने का सामान खरीदने गए थे उसी समय उनके चेहरों को देखकर हमलावरों ने उन्हें नस्ली गालियां दीं। बताया जाता है कि घटनास्थल पर करीब छह लोगों का एक समूह, जो पास में ही पहले से किसी के जन्मदिन का जश्न मना रहा था, ने उन्हें रोक लिया। हमलावरों ने उन पर नस्ली टिप्पणियां करते हुए उनपर चिंकी, चीनी और मोमो जैसी टिप्पणी की। जबकि एक आरोपी ने कहा कि ओए चीनी, क्या माल खरीदने आए हो? माइकल ने इसका विरोध किया, तो एक आरोपी ने उन्हें ब्रेसलेट से सिर पर मारा। एंजेल ने अपने भाई की रक्षा करने की कोशिश की और शांतिपूर्वक कहा, हम चीनी नहीं हैं। हम भारतीय हैं। क्या प्रमाण-पत्र दिखाएं कि हम भारतीय हैं, लेकिन नफरती संस्कारों में डूबे गुंडों के इस समूह ने हिंसक रूप से उन पर हमला कर दिया। यज्ञ अवस्थी नामक मुख्य आरोपी ने एंजेल की गर्दन और पीठ पर तेज हथियार से वार किया, जिससे वे गिर पड़े। माइकल भी घायल हुए, लेकिन उन्होंने एंजेल को पास के अस्पताल पहुंचाया। एंजेल की हालत गंभीर थी। उनकी गर्दन और स्पाइन में गहरी चोटें थीं। आखिरकार वे कभी पूर्ण चेतना में वापस नहीं आए और नफरत के सौदागरों ने एक होनहार भारतीय छात्र की हत्या कर उसके परिवार को अंधकार में धकेल दिया। निश्चित रूप से इस घटना ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के छात्रों के खिलाफ उपजी नस्लवाद की समस्या को फिर से उजागर कर दिया है। इस घटना को लेकर त्रिपुरा सहित देश के विभिन्न राज्यों व शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास को लेकर तरह तरह की बातें करते रहते हैं, परन्तु हकीकत यही है कि गत कुछ वर्षों में इसी देव भूमि में सत्ता संरक्षित धर्म जाति आधारित नफरती घटनाओं में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के पुरोला कस्बे में एक 14 वर्षीय लड़की के अपहरण के बाद श्लव जिहादश का आरोप लगाकर हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़काए गए। मुस्लिम मकानों व दुकानों पर लक्षित हमले किए गए, कई परिवार शहर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। इसी तरह हल्द्वानी में 2024 के बनभूलपुरा में अवैध मदरसे और मस्जिद के विध्वंस पर पथराव, आगजनी और पेट्रोल बम फेंके जाने की घटना सबसे प्रमुख रही, जहां 6 लोगों की मौतें हुईं। 2025 में भी काशीपुर और हल्द्वानी में साम्प्रदायिक तनाव देखा गया। राज्य में दलितों के विरुद्ध भी अनेक घटनाएं होती रहती हैं। परन्तु समाज में धर्म जाति व क्षेत्र के नाम पर बढ़ती नफरत के बीच इस राज्य को श्देव भूमिश के रूप में भी प्रचारित किया जाता है।

सवाल यह है कि उत्तराखंड जैसे शांतिप्रिय राज्य सहित देश के अन्य विभिन्न राज्यों में इस तरह के नफरत व हिंसा पैदा करने वाले हालात क्या अचानक पैदा हुए हैं या सत्ता के संरक्षण में इन नफरती संस्कारों को पोषित किया जा रहा है? उत्तराखंड की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा दिए गए बयान से यह काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि श्पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ ऐसी घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं और समाज को भेदभाव रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए। हम लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें मिलकर भेदभाव को रोकना होगा। भारत के किसी भी हिस्से के लोगों को हर जगह सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उनकी मृत्यु बेहद दुखद है। किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि श्देहरादून में एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ, वह एक भयावह घृणा अपराध है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ऐसी नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। वर्षों से इसे रोजाना, खासकर हमारे युवाओं को, जहरीली सामग्री और गैर-जिम्मेदाराना खबरों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। कोई भी घटना देश के लिए दुखद घटना होती है। अगर देश में ऐसी कोई भी घटना होती है तो पूरे समाज को मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। वहीं, राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी में कहा कि हम प्रेम और विविधता का देश हैं। हमें ऐसा समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीयों को निशाना बनाए जाने पर अनदेखी करे। हमें यह सोचने और सामना करने की जरूरत है कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं? अफसोस की बात तो यह कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा उत्तराखंड की घटना के बाद व्यक्त किए गए विचार उस समय सामने आए जब उनके अपने पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की नस्लवादी नफरती लोगों द्वारा हत्या कर दी गई? जबकि लगभग एक दशक से देश में जगह जगह अल्पसंख्यकों, दलितों व पिछड़े वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है। लिंचिंग की घटनाएं घटित हो रही हैं। जगह जगह उन्मादी भीड़ पुलिस की शह पर वर्ग विशेष के लोगों को निशाना बनाती रही है। जगह-जगह उकसाऊ भाषण हो रहे हैं। कहीं हथियार बांटे जा रहे हैं। तो कहीं संवैधानिक पदों पर बैठे लोग स्वयं अपने जहरीले बोलों से समाज में हिंसा व नफरत बढ़ा रहे हैं। निःसंदेह गोदी मीडिया भी इस नफरती वातावरण को और भी जहरीला बना रहा है। ऐसे में रिजिजू की चिंताओं के अनुसार भारत के किसी भी हिस्से के लोगों का स्वयं को हर जगह सुरक्षित महसूस करना कहां संभव हो पा रहा है? इस समय देश के समक्ष सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि आखिर देश को कहां ले जाएंगे ये नफरती संस्कार?

भारत के किसी भी हिस्से के लोगों को हर जगह सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उनकी मृत्यु बेहद दुखद है। किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि श्देहरादून में एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ, वह एक भयावह घृणा अपराध है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ऐसी नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। वर्षों से इसे रोजाना, खासकर हमारे युवाओं को, जहरीली सामग्री और गैर-जिम्मेदाराना खबरों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। कोई भी घटना देश के लिए दुखद घटना होती है। अगर देश में ऐसी कोई भी घटना होती है तो पूरे समाज को मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

मनुष्य की गतिविधियां जीवों पर संकट

शार्क और रे की 24 से 31 प्रजातियों पर विलुप्ति का संकट मंडरा रहा है जबकि शार्क की तीन प्रजातियां संकटग्रस्त श्रेणी में आ गई है। शोधकर्ताओं ने चिंता जताई है कि हिंद महासागर में वर्ष 1970 के बाद शॉर्क और रे की संख्या लगातार कम हो रही है। यहां तक कि अब तक इनकी आबादी में कुल 84.7 फीसदी तक की कमी आ चुकी है। सिमोन फ्रेजर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन से पता लगाया कि हिंद महा. सागर में वर्ष 1970 से अब तक मत्स्याखेट का दबाव 18 गुना बढ़ गया है जिसके कारण निश्चित ही समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ा है और कई जीव विलुप्त हो रहे हैं। अधिक मात्रा में मछली पकड़े जाने से न केवल शार्क बल्कि रे मछलियों पर भी विलुप्ति का खतरा बढ़ गया है।

मानवीय गतिविधियां समस्त जीव-जंतुओं के लिए संकट उत्पन्न कर रही हैं। समुद्री जीवों के शिकार व इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण समुद्र के तापमान में भी वृद्धि हुई है। नतीजतन समुद्री जीवों की कई प्रजातियां समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। वर्ष 2019 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने दो अलग-अलग वातावरण में शार्क की एक प्रजाति की वृद्धि और उनकी शारीरिक स्थिति की तुलना करके पाया था कि बड़े आकार की रीफ शार्क के शिशुओं का विकास कम हो रहा है। शार्क अपने वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में छपे एक शोध से पता चला है कि समुद्री तापमान में होने वाले परिवर्तन के कारण शार्क के बच्चे समय से पहले ही जन्म ले रहे हैं, साथ ही उनमें पोषण की कमी भी देखी गई है। इस कारण से उनका जिंदा रहना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है एवं वे दुबले-पतले बौने रह जाते हैं।

वर्ष 2013 में डलहौजी यूनिवर्सिटी द्वारा किए एक शोध के अनुसार हर साल करीब 10 करोड़ शार्क को मार दिया जाता है। अनुमान है कि यह दुनिया भर में शार्क का करीब 7.9 फीसदी है। वर्ष 2016 में भारत को सबसे अधिक शार्क का शिकार करने वाला देश घोषित किया गया था। शार्क और रे की 24 से 31 प्रजातियों पर विलुप्ति का संकट मंडरा रहा है जबकि शार्क की तीन प्रजातियां संकटग्रस्त श्रेणी में आ गई है। शोधकर्ताओं ने चिंता जताई है कि हिंद महासागर में वर्ष 1970 के बाद शॉर्क और रे की संख्या लगातार कम हो रही है। यहां तक कि अब तक इनकी आबादी में कुल 84.7 फीसदी तक की कमी आ चुकी है। सिमोन फ्रेजर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन से पता लगाया कि हिंद महासागर में वर्ष 1970 से अब तक मत्स्याखेट का दबाव 18 गुना बढ़ गया है जिसके कारण निश्चित ही समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ा है और कई जीव विलुप्त हो रहे हैं। अधिक मात्रा में मछली पकड़े जाने से न केवल शार्क बल्कि रे मछलियों पर भी विलुप्ति का खतरा बढ़ गया है। दरअसल शार्क शिशुओं को प्रजनन करने लायक होने में सालों लग जाते हैं। अपने जीवन काल में यह कुछ ही बच्चों को जन्म दे पाते हैं। ऐसे में अत्यधिक मात्रा में इन्हें पकड़े जाने से स्वाभाविक रूप से इनकी आबादी में गिरावट आ रही है। शार्क की विशेष पहचान उसके हमलावर स्वभाव के कारण है, जो समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि यह शिकारी न हों तो इनके बिना पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही ध्वस्त हो सकता है। बावजूद इसके हमारा ध्यान इनकी सुरक्षा और संरक्षण पर नहीं है। इनके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है। इनके प्रबंधन के लिए आम लोगों को सहयोग करना होगा ताकि समुद्री प्रजातियों और उनके आवासों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके।

साभार
स्रोत फीचर्स

सफलता के लिए शिक्षा ही जरूरी

शिक्षा की जटिलता और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य को सही ढंग से न समझ पाने की वजह से शिक्षा व्यवस्था बेहाल हो गई है। इसकी तस्वीर बदलने के दावे जिस तरह बढ़-चढ़ कर किए जाते रहे, वह शायद केवल विद्यालय में बच्चों के दाखिले, भवनों के रंग-रोगन, मध्यान्ह भोजन आदि तक सिमट कर रह गए हैं। एक ओर देश के स्कूल शिक्षकों की व्यापक कमी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर मौजूदा अध्यापकों की शिक्षण क्षमता भी सवालों के घेरे में है।

आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों का विस्तार तो लगातार होता रहा है, लेकिन शिक्षा के स्तर में अपेक्षित उपलब्धि को लेकर चिंता जाहिर की जाती रही है। दो वर्ष पूर्व सबके लिए शिक्षा विषय पर यूनेस्को ने 12वीं वैश्विक निगरानी रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें शिक्षा की जो तस्वीर उभरती है, वह बताती है कि देश में शिक्षा के प्रति सरकारों का रवैया कितना लाप. रवाही भरा है। इन सभी रिपोर्टों ने विद्यार्थियों के सीखने की गति को लेकर गहन चिंताजनक तथ्य दिए। वंचित तबकों के 90 फीसदी बच्चे अगर चार साल की स्कूली पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बावजूद लगभग निरक्षर हैं, तो हम किस आधार पर अपनी शिक्षा व्यवस्था को संतोषजनक कह सकते हैं और कैसे अपेक्षित उपलब्धि को पा सकते हैं? यह विचारणीय है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई के माहौल से लेकर विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं न मिल पाना, शिक्षकों का अभाव तथा शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में अकादमिक संदर्भ व्यक्तियों का अभाव आदि अनेक वजहों से शैक्षिक गुणवत्ता के स्तर में गिरावट एक बड़ी समस्या बनती गई है। यह बेवजह नहीं है कि समृद्ध राज्यों में भी सामाजिक, आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों के बच्चों और खासकर लड़कियों के बीच सीखने की क्षमता बेहद कमजोर बनी हुई है। दरअसल, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून लागू होने के बाद से सरकारों का जोर स्कूलों में दाखिला बढ़ाने पर रहा है और देश के तमाम इलाकों में इसमें कामयाबी भी दर्ज हुई, लेकिन सिर्फ दाखिलों में इजाफा शैक्षिक तस्वीर में सुधार का मानक नहीं हो सकता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में सीखने के स्तर को लेकर पिछले कुछ दशकों में जो अध्ययन हुए हैं, उन सबके निष्कर्ष यही बताते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था एक तरह से नाम की चल रही है, वहां गुणवत्ता के मानकों की शायद कोई जगह नहीं है। इस स्थिति के लिए कई बार बच्चों की पृष्ठभूमि और उनके परिवार की भूमिका को भी जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जबकि स्कूल में दाखिला लिए किसी भी बच्चे के शैक्षणिक और बौद्धिक विकास के लगभग सभी पहलू आमतौर पर शिक्षक की क्षमता पर निर्भर होते हैं। कुछ समय पहले आरटीई फोरम नामक एक संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि स्कूलों में पेशेवर दक्षता वाले अध्यापकों की निहायत कमी है।

करीब डेढ़ साल पहले पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कराई गई राष्ट्रीय शिक्षक दक्षता जांच में भी यह चिंताजनक तथ्य सामने आया था कि उसमें शामिल हुए 93वें फीसद शिक्षक फेल हो गए। जाहिर है, एक ओर देश के स्कूल शिक्षकों की व्यापक कमी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर मौजूदा अध्यापकों की शिक्षण क्षमता भी सवालों के घेरे में है। आजादी के छह दशक से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद देश में शिक्षा के अधिकार को कानूनी दर्जा मिला। लेकिन इस पर ईमानदारी से अमल करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति किसी भी सरकार में नहीं दिखती।

यूनेस्को द्वारा जारी इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पर्याप्त और प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव के चलते सीखने का यह संकट अगली कई पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाता रहेगा और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव वंचित तबकों के लोगों पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर उप-सहारा अफ्रीकी देशों की स्थिति को देखा जा सकता है, जहां गरीब घरों के पांच में से सिर्फ एक बच्चा प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाता है। युवा आबादी का एक चौथाई हिस्सा एक वाक्य भी ठीक से नहीं पढ़ पाता। तो क्या हमारे देश के नीति-नियंताओं को भविष्य के संकट का अंदाजा नहीं है? क्या केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने या शिक्षा का अधिकार कानून बना देने या नई शिक्षा नीति को बनाए जाने की पैरवी करने से समानता आधारित शिक्षित समाज का सपना पूरा किया जा सकेगा? वहीं दूसरी ओर, परीक्षाओं को पुनः लागू किए जाने को लेकर राज्यों से आवाजें उठने लगी है। परीक्षाएं न होने से शिक्षा का स्तर गिर रहा है, जैसी बातें शिक्षक बिरादरी से लेकर प्रशासनिक हलकों में उठ रही है।

नतीजन तैयार की जा रही नई शिक्षा नीति में इस प्रावधान को शामिल किया गया है। अब पांचवीं कक्षा तक परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी, छठवीं से लेकर पूर्ववत परीक्षाएं होंगी जिससे स्कूलों में परीक्षाएं शुरू करने से शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, लेकिन प्रश्न यह है कि देश में पिछले साठ वर्षों से परीक्षा प्रणाली की प्रक्रिया संचालित होती रही है, तब क्या शिक्षा का स्तर बेहतर माना जाता था? शिक्षा के स्तर का परीक्षाओं से क्या लेना देना? जबसे भारत भर में परीक्षा प्रणाली लागू हुई है, हर साल अधिक. श परीक्षार्थी असफल ही होते चले आ रहे हैं। जब भी इस शोचनीय तथ्य का जिक्र होता है तब कतिपय घिसे-पिटे मुद्दों को दोहरा दिया जाता है, जैसे बच्चे पढ़ते नहीं है, शिक्षक अपने दायित्व को प्रामाणिकतापूर्वक निभाते नहीं है, शालाओं में समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं आदि। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे गलत है। पर वे आंशिक सत्य ही है।

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई के माहौल से लेकर विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं न मिल पाना, शिक्षकों का अभाव तथा शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं में अकादमिक संदर्भ व्यक्तियों का अभाव आदि अनेक वजहों से शैक्षिक गुणवत्ता के स्तर में गिरावट एक बड़ी समस्या बनती गई है। यह बेवजह नहीं है कि समृद्ध राज्यों में भी सामाजिक, आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों के बच्चों और खासकर लड़कियों के बीच सीखने की क्षमता बेहद कमजोर बनी हुई है। दरअसल, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून लागू होने के बाद से सरक. रों का जोर स्कूलों में दाखिला बढ़ाने पर रहा है।

हमारा मन जिस प्रकार विचारों के सहारे आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मानव-चेतना प्रतीकों के सहारे विकसित होती है : सुमित्रानंदन पंत

सामर्थ्यवान भारत

भारत ने वैश्विक पटल पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी उपस्थित दर्ज कराकर, अपने सामर्थ्य का परिचय दिया है। याद हो कि एक समय में दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान 38 प्रतिशत तक था। कालांतर में भारत को उसके 'स्व' से हटा दिया गया, इसलिए वह वैश्विक पटल पर पिछड़ता चला गया। लेकिन, पिछले 10-11 वर्षों में भारत फिर से अपने स्वभाव में लौट रहा है। उसी का परिणाम है कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत अपने सामर्थ्य का परिचय दुनिया को दे रहा है। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत का जापान जैसे विकसित राष्ट्र को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त करना, यह केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि उस संकल्प की सिद्धि है जो भारत को 'विश्वगुरु' और वैश्विक शक्ति केंद्र बनाने की दिशा में लिया गया है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के विकास दर के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भारत न केवल बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली आर्थिक शक्ति है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7.3 ट्रिलियन डॉलर के विराट स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। महत्वपूर्ण यह है कि अगले ढाई से तीन वर्षों में भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

भारत ने वैश्विक पटल पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी उपस्थित दर्ज कराकर, अपने सामर्थ्य का परिचय दिया है। याद हो कि एक समय में दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान 38 प्रतिशत तक था। कालांतर में भारत को उसके 'स्व' से हटा दिया गया, इसलिए वह वैश्विक पटल पर पिछड़ता चला गया। लेकिन, पिछले 10-11 वर्षों में भारत फिर से अपने स्वभाव में लौट रहा है।

बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अर्थ केवल अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में ऊपर जाना नहीं है। इसका सीधा संबंध देश के सामाजिक सुरक्षा विस्तार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। जब देश की तिजोरी में संसाधन बढ़ते हैं, तो जनकल्याणकारी योजनाओं की धार तेज होती है और बुनियादी ढांचे का ऐसा जाल बिछता है जो अंततः गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। आर्थिक सफलता के साथ ही 1 जनवरी 2026 से भारत को मिली ब्रिक्स की अध्यक्षता रणनीतिक रूप से मील का पत्थर है। रूस और चीन जैसे वैश्विक दिग्गजों के साथ ब्रिक्स मंच पर भारत का नेतृत्व करना यह दर्शाता है कि दुनिया अब भारत के बिना अपनी दिशा तय नहीं कर सकती। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया, ओमान और जॉर्डन जैसी यात्राएं यह संकेत देती हैं कि भारत अपनी 'सॉफ्ट पावर' और आर्थिक शक्ति के मेल से क्षेत्रीय संतुलन का नया ध्रुव बन रहा है। भू-राजनीति में 'सौदेबाजी' की शक्ति चार स्तंभों पर टिकी होती है: कच्चा तेल, स्वर्ण भंडार, आर्थिक आकार और खाद्य आत्मनिर्भरता। ब्रिक्स देशों की ताकत इस बात से समझी जा सकती है कि विश्व के 42 प्रतिशत तेल उत्पादन पर इस समूह का नियंत्रण है। भारत इस समूह के माध्यम से डॉलर के वैश्विक एकाधिकार को चुनौती देने और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बहरहाल, भारत आज उस मुकाम पर खड़ा है जहाँ वह अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर बाहरी दुनिया की दशा और दिशा बदल सकता है। जापान को पीछे छोड़ना केवल एक शुरुआत है; लक्ष्य जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व मंच पर शीर्ष पायदान की ओर बढ़ना है। 2026 का यह उदय 'आत्मनिर्भर भारत' से 'सामर्थ्यवान भारत' की ओर बढ़ते कदमों का प्रतिबिंब है।

अमृत कलश

विचारों का प्रवाह

आध्यात्मिक पथ ही वो मार्ग है जहां आपको अपने बारे में जानकारी मिलती है, और पता चलता है कि आप अपने जीवन में बेहतर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। खुद को अच्छा बनाना मतलब कोई बगीचा है जहां पर पौधे हैं फूल हैं। वैसे अपने भीतर भी अच्छे फूल उगाना, उनको रखना, बनाना। जब आप अपने भीतर ही बगीचा बनाते हो। जैसे आप खुद एक माली हैं और खुद माली बनकर उस बगीचे में आपको सुंदर, आकर्षक, मोहक, सुगंधित फूल चाहिए तो आप क्या करेंगे? किस चीज की जरूरत है आपको? सोच कर देखिए आपको किस चीज की जरूरत रहेगी।अगर हमारे पास प्रकाश भी हैं, हमारे पास पानी भी है। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? पता है ना आपको उसके सबसे पहले वो जो बीज है । बीज के लिए एक भूमि की जरूरत है। भूमि मतलब ऐसे भूमि जो उपजाऊ भूमि है। जहां पर वह पौधे उग सकते हैं, वह फूल आ सकते हैं। ऐसी भूमि की जरूरत है। और वह भूमि और कहीं नहीं आपके भीतर ही है।

आपके भीतर जो बंजर जमीन है उसको उपजाऊ बनाने की क्रिया है। उसे अच्छा बनाने की क्रिया है। अभी आप ये मत सोचिए कि फूल आने के बाद आप क्या क्या करेंगे? वो अभी मत सोचिए। अभी ये सोचिए कि जो जमीन है जो भूमि है उसे हम और उपजाऊ बनाएं। यह सोच के साथ हम चलें। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ऐसा नहीं हो कि न्योता आया ही नहीं और आपने खरीददारी शुरू कर दी। ऐसे फूल आए ही नहीं है तो सपने मत देखिए कि क्या क्या होगा । अभी आपका ध्यान जमीन पर रखिए, भूमि पर रखिए और उसे और परिपक्व बनाने की कोशिश करना है। अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करना है। पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है पर आप के लिए आज क्या जरूरत है? हम किस तरह से आगे बढ़े जिससे कि हम उस दिशा की ओर अग्रसर होते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। इसीलिए कक्षा है। जो भागना नहीं चाह रहा है, जो शांति से अपने ऊपर काम करना चाह रहा है, वो आध्यात्मिक सत्य को अनुभव करना चाह रहा है, उसके लिए जगह है। इसके लिए यह परिवर्तन की कक्षा है।

तो हम आज इस एक विचार को, खासतौर पर एक क्रिया को लेकर हम चलेंगे और क्या क्रिया है वो? क्या सोच है, क्या विचार है जिसे हम लेकर चलेंगे तो विचार यह है कि क्या करना है आपको? रोज चलना है। रोज चलने के लिए तैयार हैं आप? अगर भीतर आपको फूल खिलाना है तो रोज चलना भी बहुत जरूरी है। दस मिनट बीस मिनट। जितना आपसे बन पड़ता है। कम से कम 10 मिनट। एक सपाट जमीन हो और उसके ऊपर आपको चलना है बस। रोज दस मिनट। ज्यादा से ज्यादा आपको बीस मिनट चलना हैं रोज। पर ये चलना कैसे है आपको बताता हूं नहीं तो आपको लगेगा बस चलना है। डॉक्टर ने भी कहा है तो चलना है पर वैसे नहीं चलना है। ● दादाश्रीजी

बोध कथा

व्यवहार और तार्किकता

एक तेली अपने कोल्हू के पास सो रहा था, जबकि उसका बैल कोल्हू घसीट रहा था। तभी एक दार्शनिक वहां से गुजरा। उसने तेली को जगाया और पूछा, 'तुमने बैल की आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है?' तेली ने जवाब दिया, 'अगर पट्टी नहीं होगी, तो बैल समझ जाएगा कि वह बस एक ही जगह घूम रहा है और वह चलना बंद कर देगा।' दार्शनिक ने थोड़े सोचकर पूछा, 'लेकिन अभी तो तुम सो रहे थे। अगर बैल चलना बंद कर देगा, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वह रुक गया है?' तेली ने मुस्कुराते हुए कहा, 'इस बैल के गले में घंटी लगी है। जब वह चलता है, घंटी बजती रहती है। जैसे ही घंटी बंद होगी, मैं जान जाऊंगा कि वह रुक गया है और मैं उसे फिर से हांक दूंगा।' दार्शनिक ने पुनः सवाल किया, 'लेकिन यह भी तो संभव है कि वह एक ही जगह खड़ा होकर अपनी गर्दन हिलाकर घंटी बजाता रहे। तब क्या होगा?' तेली थोड़ी झुंझलाकर बोला, 'नहीं, ऐसा नहीं होगा।' दार्शनिक ने हैरानी से पूछा, 'तुम कैसे निश्चित हो सकते हो कि वह ऐसा नहीं करेगा?' तेली ने हंसते हुए कहा, 'यह बैल है, दार्शनिक नहीं।'

खालिस्तान समर्थक संगठन मानवीय चिंता के लिए खड़े न होकर भारत-विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से खड़े किए गए हैं

लंदन के खालिस्तानी समर्थक और बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार

कैलाश चंद्र
सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ स्तंभकार

लंदन की सड़कों पर 'जय बांग्लादेश' के नारे लगाना इसी नैरेटिव हाइजैकिंग का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पीड़ित हिन्दू परिवारों की पीड़ा को दबाकर भारत-विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाना है। यह व्यवहार बताता है कि इनकी राजनीति नैतिकता, करुणा या मानवता पर आधारित नहीं है, बल्कि धन, गठबंधन और भारत-विरोधी सोच पर टिकी हुई है।

आज वैश्विक मंच पर कुछ ऐसे समूह सक्रिय हैं जो स्वयं को मानवाधिकारों का ठेकेदार और उत्पीड़ितों की आवाज बताने में पीछे नहीं रहते। लंदन, टोरंटो और यूरोप के कई शहरों में सक्रिय खालिस्तानी समर्थक इसी श्रेणी में आते हैं। ये लोग भारत में कथित अल्पसंख्यक अत्याचारों के नाम पर प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन यही लोग जब बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य इस्लामी देशों में हिन्दुओं पर हो रहे संगठित अत्याचारों, नरसंहार, बलात्कार और मंदिर विध्वंस की घटनाओं का सामना करते हैं तो उनकी तथाकथित मानवता अचानक मौन धारण कर लेती है।

यह मौन सामान्य नहीं है। यह चयनित संवेदना का परिणाम है, जो किसी नैतिक मूल्य से नहीं उपजा है, यह एक सुनियोजित राजनीतिक एजेंडे से संचालित है। कई बार स्थिति इससे भी आगे बढ़ जाती है, जब बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध के बजाय ये समूह 'जय बांग्लादेश' जैसे नारे लगाते दिखाई देते हैं। यह आचरण स्पष्ट करता है कि इनके लिए मानवाधिकार सार्वभौमिक मूल्य नहीं बल्कि राजनीतिक औजार मात्र है।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि लंदन और पश्चिमी देशों में सक्रिय अधिकांश खालिस्तान समर्थक संगठन मानवीय चिंता के लिए खड़े न होकर भारत-विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से खड़े किए गए हैं। इनमें से अनेक लोग अवैध प्रवासी हैं, कुछ स्थानीय वेलफेयर योजनाओं पर निर्भर हैं और कुछ का संबंध छोटे आपराधिक गिरोहों, ड्रग मनी, हवाला और धन-शोधन नेटवर्क से जुड़ा रहा है। जब आर्थिक आधार ही संदिग्ध और अंधेरे स्रोतों से आता हो, तब विचारधारा और राजनीतिक रुख भी उसी दिशा में ढल जाता है। ऐसे में इनकी राजनीति को 'मानवाधिकार आंदोलन' कहना सत्य का अपमान होगा। यह वस्तुतः फंडिंग आधारित, एजेंडा चालित और भारत-विरोधी राजनीति है।

इस पूरे तंत्र के पीछे गहरा और खतरनाक गठजोड़ काम करता है, जिसे कई सुरक्षा विश्लेषणों में आईएसआई-खालिस्तानी-

इस्लामिस्ट गठजोड़ के रूप में चिन्हित किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 'आईएसआई' लंबे समय से भारत को 'हजार घावों से कमजोर करने' की रणनीति पर काम करती रही है। इसी रणनीति के अंतर्गत खालिस्तानी अलगाववादियों को वित्तीय सहायता, प्रचार संसाधन और अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराए जाते हैं। लंदन और यूरोप में सक्रिय कुछ इस्लामी कट्टरपंथी नेटवर्क और संगठन इन्हें लॉजिस्टिक सहायता देते हैं। इन सभी का साझा उद्देश्य एक ही है- भारत को वैश्विक मंच पर बदनाम करना और उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक एकता पर प्रश्नचिह्न लगाना।

ऐसे गठबंधन के लिए बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचार कोई मुद्दा नहीं बनते क्योंकि वे इनके 'विक्टिम बनाम पर्पट्रेटर' नैरेटिव में फिट नहीं बैठते। इनके वैचारिक ढांचे में मुसलमान सदैव पीड़ित और भारत अथवा हिन्दू समाज सदैव उत्पीड़क के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यदि ये लोग बांग्लादेश में हिन्दू लड़कियों पर हो रहे अत्याचार, परिवारों के कत्लेआम और मंदिर विध्वंस की निंदा करेंगे तो यह पूरा झूठा नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा और इनके इस्लामी सहयोगी उनसे दूरी बना लेंगे।

यही कारण है कि जब बांग्लादेश में हिन्दुओं के गांव जलाए जाते हैं, महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार होता है और सैकड़ों परिवार पलायन को मजबूर होते हैं तब ये तथाकथित मानवाधिकार रक्षक चुप रहते हैं। यह चुप्पी उनकी सच्चाई उजागर करती है। उनके लिए मानवाधिकार नहीं बल्कि राजनीतिक गठबंधन और फंडिंग अधिक महत्वपूर्ण है।

अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों जैसे एसओएएस लंदन, हार्वर्ड और टोरंटो विश्वविद्यालयों में वर्षों से लेफ्ट-इस्लामिस्ट-खालिस्तानी गठजोड़ सक्रिय देखा जा सकता है। इनके सेमिनार, शोधपत्र और अभियानों का केंद्रीय विचार यही होता है कि 'भारत एक दमनकारी राष्ट्र है, मुसलमान हमेशा पीड़ित हैं और खालिस्तानी अलगाववादी उनके स्वाभाविक सहयोगी हैं।' इस वैचारिक पूर्वाग्रह के कारण बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार इनके लिए असुविधाजनक सत्य बन जाते हैं। इसलिए या तो इन घटनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर इन पर बोलने वालों को 'दक्षिणपंथी' और 'नफरत फैलाने वाला' बताकर चुप कराने की कोशिश की जाती है।

लंदन की सड़कों पर 'जय बांग्लादेश' के नारे लगाना इसी नैरेटिव हाइजैकिंग का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पीड़ित हिन्दू परिवारों की पीड़ा को दबाकर भारत-विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाना है। यह व्यवहार बताता है कि इनकी राजनीति नैतिकता, करुणा या मानवता पर आधारित नहीं है, बल्कि धन, गठबंधन और भारत-विरोधी सोच पर टिकी हुई है।

ऐसे में हम सभी को स्पष्ट रूप से समझना होगा कि लंदन और अन्य पश्चिमी देशों में सक्रिय खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियां किसी स्वतःस्फूर्त जनआंदोलन का परिणाम नहीं हैं। यह एक सुनियोजित, फंडेड और राजनीतिक रूप से इंजीनियर किया गया प्रयास है, जिसमें मानवता केवल मुखौटा है। वास्तविक उद्देश्य भारत को बदनाम करना, उसकी सामाजिक एकता को कमजोर करना और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसके विरुद्ध वातावरण बनाना है। अतः इन परिस्थितियों में भारत और विश्व के विवेकशील नागरिकों का दायित्व है कि वे मानवाधिकार के नाम पर चल रहे इस पाखंड को पहचानें और सच्चे पीड़ितों विशेषकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित हिन्दुओं की आवाज को मजबूती से उठाएं।

यह लेखक के निजी विचार है

न्यायाधीश स्वामीनाथन पर महाभियोग की कोशिश भयभीत करने वाली

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के विरुद्ध विपक्ष द्वारा पिछले संसद सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल अभूतपूर्व और अचंभित करने वाली थी। किसी न्यायाधीश को उसके न्यायिक निर्णय या आदेश के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए हमारे माननीय सांसद इस तरह एकजुट हो जाएंगे इसकी कल्पना नहीं थी। हालांकि इसके विरुद्ध 56 पूर्व न्यायाधीश सामने आ गए जिन्होंने खुला पत्र में इसे न्यायालय पर राजनीतिक वैचारिक दबाव बनाने और डराने की कोशिश कहा। वास्तव में तमिलनाडु में आईएनडीआईए सरकार का नेतृत्व करने वाली द्रमुक के आह्वान पर एक साथ 107 सांसदों का लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचकर महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देने की घटना हर दृष्टि से असाधारण थी। अभी तक न्यायाधीशों को उनके आचरण, कदाचार आदि के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा या उसकी कोशिशें हुईं। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा है कि सांसदों के आरोप मान लिए जाएं, तब भी किसी न्यायाधीश को उसके विचारों या फैसलों के आधार पर महाभियोग की धमकी देना न्यायपालिका की आजादी पर हमला है। अगर इस तरह किसी सरकार राजनीतिक दल या दलों के समूह को न्यायाधीश का फैसला स्वीकार नहीं हो और वह महाभियोग प्रस्ताव लाने लगे तो फिर हर न्यायाधीश डरने लगेगा। वास्तव में इस प्रकरण के तीन प्रमुख पहलू है। पहला, न्यायमूर्ति स्वामीनाथन द्वारा दिया गया फैसला और उसकी पृष्ठभूमि। दूसरा, संबंधित विवाद की सच्चाई। और तीसरा महाभियोग प्रस्ताव के पीछे की सोच या विचारधारा।

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने तिरुप्परनकुंद्रम मंदिर पर परंपरागत उत्सव के दीप जलाने का एक आदेश 1 दिसंबर को दिया तथा प्रशासन द्वारा उसका पालन न करने पर तीखे शब्दों में दूसरा आदेश 4 दिसंबर को दिया। न्यायालय ने 4 दिसंबर के आदेश में इसे न्यायपालिका की अवमानना करार देते हुए हर हाल में लागू करने की बात की। द्रमुक सरकार ने इसे सांप्रदायिक निर्णय माना और उनके विरुद्ध राजनीतिक अभियान चल निकला है। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल,तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अरुलमिघु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर से संबंधित पत्थर स्तंभ- दीपथून पर दीपक जलाकर कार्तिगई दीपम त्योहार मनाने की परंपरा है। तमिल महीने कार्तिगई (नवंबर-दिसंबर) में मनाए जाने वाले 'कार्तिगई दीपम' उत्सव के तहत, हमेशा की तरह उच्ची पिल्लैयार मंदिर के मंडपम में दीप जलाने के लिए जब लोग जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। तिथि के अनुसार 3 दिसंबर को दीप जलाया जाना चाहिए था किंतु ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद यह बड़ा मुद्दा बन गया और न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका डाली गई जिसके

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के विरुद्ध विपक्ष द्वारा पिछले संसद सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल अभूतपूर्व और अचंभित करने वाली थी।

तहत यह आदेश आया। मंदिर और पहाड़ी की सुरक्षा में लगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के साथ जब श्रद्धालु दीपक जलाने जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें फिर रोक दिया। तीरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर से 10 किमी दूर है जिस पर यह मंदिर अवस्थित है। सनातन और हिंदू मान्यताओं में यह भगवान मुरूगन या कार्तिकेय के छः निवास स्थानों में से एक है। मुरूगन भक्तों के लिए इसके महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। विवाद का मुख्य कारण पहाड़ी के ऊपरी भाग पर स्थित सिकंदर वधुसाह का दरगाह है। जैसा हम जानते हैं तमिलनाडु वैष्णव और शैव दोनों पंथों का आधार और मुख्य विस्तार भूमि रहा है। वैष्णव परंपरा के कवि और संत 12 अलवरों तथा 63 नयनारों यानी शैश परंपरा के कवियों और संतों में से अधिकांश तमिल क्षेत्र से आए थे। मंदिर समर्थकों की मान्यता है कि यह पूरी पहाड़ी शिवलिंग है जिसके बीच में भगवान मुरूगन का मंदिर है। यह सच है कि जब दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य यहां तक फैला उसके बाद से समस्या शुरू हुई। सिकंदर वधुशाह का दरगाह 17वीं शताब्दी में बना था जबकि मंदिर का उल्लेख छठी शताब्दी तक मिलता है। विजयनगर साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत को पराजित कर मंदिर और वहां की परंपरा को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पुनर्स्थापित किया। बाद में समस्या फिर बढ़ी और अंग्रेजों के काल में इसे लेकर लगातार विवाद होते रहे। न्यायालय के कुछ फैसले भी हैं जिनमें 1920 के एक आदेश का न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने उदाहरण भी दिया है।

पूरे विवाद को निष्पक्षता से देखने के बाद आप अपना निष्कर्ष निकालिए। किंतु मान लीजिए कोई सरकार या पार्टी न्यायाधीश के फैसले से असहमत है तो उसका रास्ता महाभियोग होगा? उच्च न्यायालय की एकल पीठ के विरुद्ध बड़ी पीठ में जाया जा सकता था। आपके लिए उच्चतम न्यायालय का रास्ता खुला है। ऐसा लगता है कि चूंकि तमिलनाडु सरकार को सच मालूम है इसलिए न्यायालय में पुनर्विचार याचिका डालने की जगह ऐसा दबाव बनाओ ताकि आगे इस तरह के फैसले देने से डरे। 56 न्यायाधीशों ने अपने पत्र में लिखा है कि आपातकाल में भी न्यायाधीश राजनीतिक आसहमति के कारण निशाने पर आए थे और तब भी न्यायपालिका ने स्वतंत्रता की रक्षा बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी थी। वस्तुतः महाभियोग न्यायपालिका की ईमानदारी की रक्षा करने के लिए है, न कि जजों पर दबाव डालने या बदला लेने के लिए इस्तेमाल करने। हाल के वर्षों में कई पूर्व मुख्य न्यायाधीशों दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, एसए बोबडे और डीवाई चंद्रचूड़ साथ ही वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भी निशाना बनना पड़ा क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं को उनके फैसले पसंद नहीं आए। महाभियोग और सार्वजनिक आलोचना को दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सेकुलरिज्म के नाम पर सरकार और प्रशासन के लंबे समय से जारी ऐसे रवैयों के विरुद्ध पूरे देश और देश के बाहर हिंदुओं के अंदर गुस्सा और प्रतिक्रिया का भाव चरम तक पहुंचा है जिसकी कई परिणति हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मानने लगे हैं कि सेक्युलरवाद के नाम पर हिंदू और सनातन विरोध तथा मुस्लिमपरस्ती राजनीतिक दलों और सरकारों का चरित्र है। भाजपा के अलावा कोई राजनीतिक दल समर्थन में नहीं आता इसलिए इस गुस्से का लाभ सीधे तौर पर उसे मिलता है। द्रमुक का संकीर्ण एकपक्षीय तमिलवाद व हिंदू धर्म विरोधवाद की अपनी राजनीति है लेकिन कांग्रेस, सपा, तृणमूल आदि का भाजपा विरोध के नाम पर उनके साथ आना आने वाले समय में राजनीतिक रूप से इनके लिए और प्रतिकूल साबित हो सकता है।

नये साल में हम सभी का संकल्प हो

प्रकृति से कम लो, उसे अधिक लौटाओ: सतत जीवन का मूल मंत्र

राज कुमार सिन्हा

प्राकृतिक दुनिया एक अद्भुत आश्चर्य है जो हम सभी को प्रेरित करती है। यह हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और यहां तक कि हमारे अस्तित्व का आधार है। हमारे जंगल, नदियां, समुद्र और मिट्टी हमें भोजन, सांस लेने की हवा और अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी प्रदान करते हैं। इन प्राकृतिक संपत्तियों को अक्सर दुनिया की 'प्राकृतिक पूंजी' कहा जाता है। ये लाभ अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, खेती और वानिकी से लेकर मनोरंजन और पर्यटन तक। विश्व की आर्थिक तरक्की ने पिछले 50 से 70 वर्षों में उत्पादन, व्यापार, और तकनीकी विकास को तेज किया है। लेकिन इस तरक्की की पर्यावरणीय कीमत भारी है। यह कीमत वायु, जल, मिट्टी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में दिखाई देती है। वैश्विक आर्थिक वृद्धि की पृष्ठभूमि देखा जाए तो 1950 से पहले धीमी औद्योगीकरण तक सीमित था।1950 से 2020 के जीडीपी में 10 गुना वृद्धि आया जो बड़े पैमाने पर उद्योग, खनन, तेल-कोयला, शहरीकरण के कारण हुआ है। 2020 से 2025 तक जीडीपी निरंतर बढ़ती है। लेकिन पर्यावरणीय संकट चरम पर पहुंच जाता है। हम ग्रह के संसाधनों को जितनी तेजी से समाप्त कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक तेजी से उपयोग कर रहे हैं। चूंकि प्रकृति मुफ़्त है, हम अक्सर इसे हल्के में लेते हैं और इसका अत्यधिक दोहन करते हैं। हम जंगलों को साफ करते हैं, समुद्रों में जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ते हैं, नदियों को प्रदूषित करते हैं और आद्रभूमि पर निर्माण करते हैं, बिना यह सोचे कि इसका क्या असर होगा। मनुष्य अपनी सुविधाओं और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जंगल काटता है, खनिजों का अत्यधिक दोहन करता है, नदियों को प्रदूषित करता है। यह लालच प्राकृतिक संतुलन को नष्ट कर रहा है। विकास की अंधी दौड़ में हमने उद्योग, शहरीकरण और उपभोग को इतना बढ़ा दिया कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, हवा, पानी, मिट्टी सब प्रदूषित हो गए। लालच ने हमें जंगलों को जलाने, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों पर निर्भर बना दिया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर पिघलना, और अत्यधिक मौसम परिवर्तन जैसी आपदाएं बढ़ रही है। जब हम प्रकृति को केवल 'संसाधन' मानते हैं, तो उसे नष्ट करना आसान लगता है। जब उसे 'मां' मानते हैं, तो उसकी रक्षा स्वाभाविक हो जाती है। अगर हम अपने समाज और अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति के महत्व को समझना शुरू कर दें, तो हम अल्पकालिक लाभ के लिए प्रकृति को नष्ट करने के बजाय, उसके साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के महत्व को समझेंगे।प्रकृति से हमें अपनी आवश्यकतानुसार ही लेना चाहिए और उसे लौटाने का भी प्रयास करना चाहिए।

सामाजिक समरसता और नारी कल्याण के लिये समर्पित जीवन

रमेश शर्मा

प्रसिद्धि स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राधाबाई ने एक ओर स्वतंत्रता संग्राम में अनेक जेल यात्राएँ कीं और दूसरी ओर सामाजिक जागरण विशेषकर वेश्यावृत्ति केलिये विवश की जाने वाली महिलाओं के उत्थान, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक सम्मान की दिशा में अपना जीवन समर्पित कर दिया ।

राधाबाई मूलतः महाराष्ट्र की रहने वालीं थीं। उनका पूरा जीवन छत्तीसगढ़ में बीता। वे पेशे से नर्स थीं लेकिन पूरे परिवेश में डाक्टर राधाबाई के नाम से प्रसिद्ध थीं। वे 1930 से स्वतंत्रता आँदोलन से जुड़ीं और उन्होंने 1942 तक हर 'सत्याग्रह' में भाग लिया एवं जेल गईं।

राधाबाई का जन्म 1875 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। उनकी जन्मतिथि का उल्लेख नहीं मिलता। जब वे मात्र नौ वर्ष की थीं तब 1884 में उनका बाल विवाह हो गया था। पर उनका दाम्पत्य जीवन नहीं चल सका। उनकी पहली विदा होने से पहले ही पति की मृत्यु हो गई। किसी बीमारी में माता पिता की भी मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण पड़ौसिन ने किया। जीवन और आजीविका केलिये परिश्रम आरंभ किया। उनकी माता दाई की पृष्ठभूमि से थीं उन्होंने भी दाई का काम सीख लिया। इसके साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से उपचार भी करने लगीं। राधाबाई गर्भस्थ महिलाओं की छोटी मोटी बीमारियों का उपचार जड़ी बूटियों से कर देतीं थीं। उनके द्वारा कराये गये प्रसव भी सफल होते थे। इसलिये उनकी ख्याति बढ़ी और आसपास डाक्टर राधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। वे 1918 में रायपुर आईं और नगरपालिका में दाई का काम करने लगीं। प्रसव पीड़िताओं के साथ उनका व्यवहार, गुणवत्ता के कारण वे बहुत लोकप्रिय हो गईं। सन 1920 में गाँधीजी पहली बार रायपुर आये। राधाबाई गाँधीजी की सभा सुनने गईं और आँदोलन से जुड़ गईं। तब से राधाबाई ने हर प्रभात फेरी और सभाओं में न केवल भाग लेतीं। इसके साथ प्रभात फेरी के प्रचार कार्य में जुड़ गई। 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने 1942 तक हर सत्याग्रह भाग लिया। अनेक बार जेल गईं। स्वतंत्रता आँदोलन के साथ उन्होंने दो अभियान चलाये एक अस्पृश्यता निवारण का और दूसरा कामगारों की बस्ती में सफाई अभियान । वे सफाई कामगारों की बस्ती में जाती और स्वयं केवल सफाई ही नहीं करतीं थीं अपितु उनके बच्चों को नहलाने और पढ़ाने का काम भी करतीं थीं। उन्होंने उन बस्तियों में ही ऐसे कार्यकर्ता तैयार किये जो सफाई और बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करने लगे । वे केवल रायपुर नगर तक ही सीमित न रहीं। एक टोली बनाकर आसपास भी जातीं। उन्होने धमतरी तहसील के अंतर्गत कंडेल गाँव में एक चरखा केन्द्र भी खोला। चरखा वे स्वयं भी चलातीं और चरखे से खादी तैयार कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करतीं । उन्होने चरखा पर अनेक गीत तैयार किये तथा चरखा चलाने के साथ सब के साथ गीत भी गातीं "मेरे चरखे का टूटे न तार, चरखा चालू रहे।" चरखा सिखाने के लिये उन्होने एक टोली भी तैयार की जिसमें पार्वती बाई, रोहिणी बाई, कृष्ण बाई, सीता बाई, राजकुँवर बाई आदि थीं। ये सभी महिलाएँ 1942 के भारत छोड़ो आँदोलन में जेल भी गईं।

उन दिनों छत्तीसगढ़ में महिलाएँ ब्लाउज नहीं पहनतीं थीं। जबकि महाराष्ट्र विशेषकर नागपुर में पहना जाता था । राधाबाई ने महिलाओं को ब्लाउज पहने के लिये प्रेरित किया । उन्हे अपने समय के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुन्दर लाल की पत्नि की पत्नि श्रीमती बोधनी बाई का साथ मिला और महिला जाग्रति अभियान तेज चलने लगा ।

१ जनवरी 1950 को सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवी डॉ. राधाबाई का निधन हुआ था

उन दिनों छत्तीसगढ़ में एक प्रथा 'किसबिन नाचा' थी। यह एक प्रकार की वेश्यावृत्ति थी राधाबाई ने इस प्रथा के उन्मूलन का काम आरंभ किया। राधाबाई ने इस पृथा के उन्मूलन की शुरुआत 1944 से आरंभ की थी और अपने जीवन की अंतिम श्वाँस तक करती रहीं। वस्तुतः छत्तीसगढ़ के गाँवों और नगरों में एक सामंती प्रथा थी जिसमें नृत्य के लिये जो महिलाएँ आतीं थीं उनका शारीरिक शोषण भी होता था । इसे "किसबिन नाचा" कहा जाता था। "किसबिन नाचा" करने वालों का एक वर्ग ही बन गया था । जैसे राजस्थान और मालवा में कभी बाछड़ा वर्ग हुआ करता था । वैसे ही छत्तीसगढ में यह किसबिन नाचा वर्ग बन गया था । इस वर्ग के लोग अपने ही परिवार की लड़कियों को 'किसबिन नाचा' के काम में लगा देते थे । इस वर्ग की लड़कियाँ भी मानों यही काम अपनी नियति समझती थीं। राधाबाई और उनकी टोली ने इस प्रथा को समाप्त करने का अभियान चलाया । इसकी शुरुआत खरोरा नामक गाँव से हुई । महिलाओं को चरखा चलाने के काम में लगाया और पुरुषों को खेती-बाड़ी के काम में। यह परिवर्तन राधाबाई के कारण ही संभव हुआ । इसके लिये स्वतंत्रता के बाद राधा बाई का सम्मान किया गया । अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित करने वाली राधाबाई का निधन 2 जनवरी,1950 को हुआ । वे अकेली रहतीं थीं। उन्होंने जीवन काल में अपना मकान अनाथालय को देने की बसीयत कर दी थी । उनके निधन के बाद उनकी बसीयत के अनुसार उनका मकान एक अनाथालय को दे दिया गया ।

दैनिक सवेरा टाइम्स

नई दिल्ली, शुक्रवार, 2 जनवरी 2026

'जब भी आप खुद को बहुमत के पक्ष में पाएं, तो रुककर आत्मचिंतन करने का समय आ गया है।' –मार्क ट्वेन

उत्तर भारत में शीत लहर का कहर

नए साल की शुरुआत उत्तरी राज्यों में कड़ाके की सर्दी और कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ हुई। बारिश तो लघुजीवी थी लेकिन बारिश के बाद शीत का कहर और बढ़ गया। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि शीत लहर अभी और कहर ढहाएगी। कोहरे से निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है। इस बार पाला और सूखी ठंड अपना जलवा दिखा रही है। स्पष्ट है कि इसका असर नई बीजी फसलों पर पड़ रहा है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं।

मौसम का मिजाज यूं है कि पहाड़ों और मैदानों के मौसम में इस समय कोई अंतर नहीं रहा। मौसम सर्वेक्षक बताते हैं कि पंजाब के अमृतसर सहित 9 जिले आजकल शिमला से भी ठंडे हैं। पंजाब में सभी सरकारी और निजी स्कूल 7 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। इस समय आलम यह है कि पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, लुधियाना व पटियाला जैसे 9 जिले हिमाचल प्रदेश के शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा और मंडी से भी ठंडे हैं। इस सीजन में यह पहली बार हुआ है कि एक साथ इतने जिलों में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सैल्सियस से कम है। नये साल की पूर्वसंध्या पर हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में और कश्मीर घाटी में बर्फबारी हुई। हिमाचल में आधा फीट तक हिमपात हुआ। बुधवार शाम से हिमपात शुरू हो गया था। रोहतांग दर्रा और शिकुला क्षेत्र पर्यटकों के लिए बंद करना पड़ा। नया वर्ष मनाने के लिए पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ थी और रोहतांग जाते पर्यटकों का बीच रास्ते मढ़ी में बर्फ के ढेलों ने स्वागत किया।ॉ

कश्मीर के उच्च पर्वतीय इलाकों में रुक-रुककर बर्फबारी जारी रही। इस बर्फबारी के बाद बर्फ के ग्लेशियर ही पानी का स्रोत होते हैं लेकिन पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की कुदृष्टि के चलते ये ग्लेशियर समय से पहले पिघलने लगे हैं। नदियों का सहज प्रवाह मारक बाढ़ में बदलने लगा है। इस समय भीषण ठंड के कारण सामान्य जीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। मौसम के बिगड़ने का नतीजा है रेलों का स्थगित होना और विमान उड़ानों का भी प्रभावित होना। 148 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं और यात्रियों को फिर से वही परेशानी सहनी पड़ी है जो इससे पहले इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से पेश आई थी। लोग यातायात साधनों की अनिश्चितता से परेशान नजर आ रहे हैं।

स्पष्ट है कि हवाई जहाज से यात्रा करने वालों का आवेश और आक्रोश हवाई अड्डों पर जाहिर हो रहा है। मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 5 जनवरी तक और राजस्थान में 3 जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा। यात्रियों को यह परामर्श दिया जा रहा है कि अनावश्यक तौर पर इस मौसम में वाहन न चलाएं, यात्रा पर न निकलें। इस घने कोहरे के कारण इन दिनों बहुत सी दुर्घटनाओं और दुखद मौतों की खबरें आ रही हैं। इसका कारण केवल घना कोहरा नहीं बल्कि यात्रियों द्वारा यातायात के नियमों की अवहेलना या बड़ी-बड़ी गाड़ियों को अंधाधुंध गति से चलाना भी है। अमृतसर में न्यूनतम तापमान 6.1 रहा और लुधियाना में 6.8 रिकार्ड किया गया। हरियाणा के अम्बाला में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री चल रहा है। यह अजब बात है कि न्यूनतम तापमान इस मौसम के सामान्य तापमान से तीन डिग्री अधिक है। लेकिन सर्दी कहर की पड़ रही है।

यही हालत पहाड़ों और राजस्थान में भी देखी जा रही है। उच्चतम तापमान तेजी से गिरा है लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। मौसम की ये असाधारण कलाबाजियां बेशक पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है लेकिन लगता है कि सरकार ने इस दुर्भाग्य से लड़ने की केवल घोषणा ही की है। कोई सार्थक कदम इसलिए नहीं उठाए जा रहे क्योंकि समृद्ध देश पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने से इंकार कर रहे हैं और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वे अकेले दम पर्यावरण प्रदूषण से संघर्ष कर सकें।

यह संघर्ष लोगों की सोच में परिवर्तन लाकर भी किया जा सकता है। पराली न जलाकर और उन वाहनों का इस्तेमाल न करके जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं। कहीं पर भी नागरिक प्रतिबद्ध होकर प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए आगे आते दिखाई नहीं दे रहे। इसीलिए आजकल हर मौसम अपने अतिरेक तक चला जाता है। लेकिन मौसम की अनिश्चितता से पिसता तो आम आदमी ही है। इसलिए जितनी जल्दी गुमशुदा मौसमों की तलाश करके इन्हें वापस लाया जा सके तो अच्छा। **–शीतल विज**

नये युग के साथ बदल रही भारत की महिलाएं

आजकल आधुनिकता की पहचान करवाने के लिए अधिकतर हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें करते हैं। हम बड़ी शान से यह कहते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले कमतर नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद यह भी एक अकाट्य सत्य है कि ये सब कहने के बावजूद केवल भारत या तीसरी दुनिया के देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं को कमजोर लिंग माना जाता है और पुरुष वर्चस्व के सामने उन्हें निम्न दिखाने का प्रयास किया जाता है। सत्य सामने है कि चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों या अकादमिक परीक्षाएं, इनमें लड़कियां हमेशा आगे रहती हैं। जो नये समाचार आ रहे हैं, उनसे पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पंजाब की सरहद पर सैन्य टुकड़ियों में महिला सैनिकों ने कमाल का प्रदर्शन किया।

महिला टुकड़ियों ने ड्रोनों की पहचान करके उन्हें नष्ट करने या वापस पाकिस्तान भेजने के लिए मजबूर करने का कौशल दिखाया। बीते वर्ष में महिलाओं को सेना के अग्रिम मोर्चों में शामिल करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा पहले उन्हें अस्थाई कमीशन मिलता था, अब स्थाई कमीशन लेने की इजाजत दे दी गई है। पहले महिलाओं को सेना में उचित प्रोमोशन की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब उन्हें यह इजाजत दे दी गई है। नभसेना में भी चाहे महिला पायलटों की संख्या कम है लेकिन इसकी शुरुआत तो हो ही गई।

दुनियाभर में माना जाता है कि जासूसी के मामले में महिला सैनिकों के मुकाबले पुरुष सैनिक बहुत पीछे रह जाते हैं। यह भी स्पष्ट है कि भारत के गर्व इसरो में महिला वैज्ञानिकों का योगदान पुरुषों से किसी लिहाज से कम नहीं है। इसरो के मंगलयान अभियान, कार्टोसैट, चंद्रयान-2 और 3 अभियानों में महिला वैज्ञानिकों का योगदान अभूतपूर्व है। हम नए वर्ष के अवसर पर महिलाओं का गुणगान नहीं कर रहे बल्कि यही कहना चाहते है कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबर सम्मान दिया जाए, जिसकी वे हकदार हैं। **–शीतल विज**

Email: letter2editor@dainiksaveratimes.net

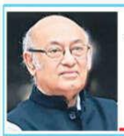

मर्यादाएं

चन्द्र मोहन
संपादकः वीर प्रताप
chander_m@hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

निराशाजनक वर्ष का आशापूर्ण समापन

मुख्य न्यायाधीश का यह कहना कि जजों से भी गलती हो सकती है, न्यायिक नम्रता का सराहनीय प्रदर्शन है

नया साल शुरू हो रहा है। यह अहसास है कि देश कितना बदल गया! यह वह भारत नहीं रहा जिसमें हम जन्मे-पले थे। हमने तो वह समय भी देखा है जब फोन पर बात करने के लिए पहले एक्सचेंज पूछता था, 'नम्बर प्लीज'। फिएट कार लेने के लिए मुख्यमंत्री की चिट चाहिए थी। देश भुखमरी से भी गुजरा था और अमेरिका से सहायता मांगनी पड़ी थी। चीन से मार खाई थी पर बांग्लादेश भी बनवाया था। तब से लेकर अब तक खान-पान, रहन-सहन सब सुधर गया। सर्दी में उत्तर भारत में लगभग हर कोई जैकेट में नजर आता है। भारत एक उभरती ताकत है जो दुनिया मान भी रही है, और कई देश रुकावटें खड़ी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भावलपुर और मुरीदके के आतंकी ठिकानों को तबाह कर हमने वह बदला लिया जो हम मुम्बई पर 26/11 के हमले के बाद नहीं ले सके। आपरेशन सिंदूर हमारे रणनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर रहेगा।

डोनाल्ड ट्रम्प ने हम पर नाजायज टैरिफ लगाया पर हम झेल गए। हमने बता दिया कि हमारी विदेश नीति दिल्ली में तय होगी, न कि वाशिंगटन में या किसी और राजधानी में। हमने आस्ट्रेलिया, ओमान, यूएई, न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) कर लिया है पर कई चरण की बातचीत के बावजूद अमेरिका से नहीं किया क्योंकि उनकी शर्तें मंजूर नहीं है। ट्रम्प को भी समझ आ गई है कि भारत की बांह मरोड़ना आसान नहीं है। उनके ट्रेड रेप्रजेंटेटिव जेमिसन गरीर ने तो माना है कि, 'इंडिया टफ नट टू क्रैक', अर्थात भारत को तोड़ना कठिन है। ट्रम्प ने कोशिश की थी कि उनकी आईटी कम्पनियां भारत न आएं पर असफल रहे क्योंकि 1, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2, भारत का अपना मार्कीट विशाल है और 3, हमारे पास चीन के बाद पढ़े-लिखे लोगों की सबसे अधिक तादाद है।

हाल ही में कई बड़ी आईटी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, एमेजॉन जैसी कम्पनियां यहां 67.5 अरब डॉलर का निवेश करने जा रही हैं। यह ट्रम्प टैरिफ के बावजूद इन कम्पनियों का भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती में विश्वास भी प्रकट करता है। न्यूयार्क टाइम्स ने भारत के बारे लिखा है कि 'यह देश खुद को डेटा और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्लोबल हब के सैंटर में स्थापित कर रहा है'। 2014 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था दोगुनी हो चुकी है। 7-8% की विकास दर बहुत सराहनीय है। अभी बहुत रास्ता तय करना है, पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति पर यह सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। इसलिए हैरानी है कि देश को भविष्य के लिए तैयार करने की जगह पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। बार-बार वे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका आज की चुनौतियों से कोई ताल्लुक नहीं, और जो समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं।

हाल ही में तमिलनाडु में मदुरै के नजदीक थिरूप्परनकुंद्रम मंदिर में दीपक जलाने पर विवाद हो गया है। इसी के पास एक दरगाह है। 100 वर्षों से दीपक दरगाह से दूर जलाया जाता आ रहा है। अब मांग उठी है कि इसे दरगाह के नजदीक पत्थर के दीपक स्तम्भ पर जलाए जाने की इजाजत दी जाए, जो मद्रास हाई कोर्ट ने दे भी दी। इसे तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मैं इस मामले की बहुत जानकारी नहीं रखता पर सवाल तो है कि अचानक यह मामला जिसे प्रदेश से बाहर कोई जानता नहीं था, ज्वलंत कैसे हो गया? मोहन भागवत ने तो कहा था कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, पर संघ परिवार के एक नेता ने तो इसे 'दक्षिण की अयोध्या' बनाने की धमकी दे है। चिंता यह है कि देश में ऐसे विवादों का ढेर है। क्या जहां भी चुनाव होने होंगे वहां ऐसा मसला उठा लिया जाएगा?

पिछला साल यह बहुत विचलित करने वाला संदेश दे गया है कि चुनावी फायदे के लिए पूराने भूले हुए विवादों को रंग-रोगन देकर फिर पेश किया जा रहा है। सांस्कृतिक उद्धार होना चाहिए पर यह लोगों को लड़ा-झगड़ा कर नहीं होना चाहिए। क्रिसमस पर प्रधानमंत्री मोदी ने चर्च जाकर प्रार्थना की। धार्मिक सहिष्णुता और सह अस्तित्व का बढ़िया उदाहरण पेश किया पर इसी क्रिसमस पर बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कुछ लोगों ने कई प्रदेशों में दंगा किया। मोहन भागवत भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं पर इन संगठनों के अराजक कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा? जो संस्कारों की बात करते नहीं थकते उनके संगठनों में कुलदीप सेंगर जैसे रेपिस्ट उच्च पदों तक कैसे पहुंच रहे है?

निश्चित तौर पर यह वह देश नहीं जिसमें हम पले और बड़े हुए थे। दंगे तब भी होते थे पर उन्हें व्यवस्था की मूक सहमति प्राप्त नहीं थी। अब एक वर्ग को प्रभाव दिया जा रहा है कि वह बराबर के नागरिक नहीं है। अगर अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलना है तो यह क्यों देखा जा रहा है कि यह घर हिन्दू का है या मुसलमान का? हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से जायज विचलित है पर हमारे यहां भी तो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। एक नया नफरती भारत उभर रहा है। नफरत राजनीतिक हथियार बनती जा रही है। बरेली में बर्थडे मना रही नर्सिंग छात्राओं पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया और पिटाई कर दी। कैफे के मैनेजर के अनुसार अंदर आते ही उन्होंने पूछा, 'मुसलमान कौन है, और मारपीट शुरू कर दी'। ऐसे तत्व क्यों समझने लगे हैं कि वह समाज के ठेकेदार है और कानून को हाथ में लेने का उन्हें अधिकार है? देहरादून में त्रिपुरा के एंजल चकमा को 'चिंकी' कहकर पीट-पीटकर कुछ युवकों ने मार दिया। वह कहता रहा 'मैं भी इंडियन हूं'। उत्तर पूर्व को क्या संदेश दिया जा रहा है? ऐसी हिंसा सामान्य क्यों हो रही है?

ऐसे हमले चाहे धर्म के आधार पर हो, या जाति या नस्ल के आधार पर हों, देश को कमजोर करते हैं। हमने बांग्लादेश या अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं बनना। ऐसा माहौल क्यों बन गया है कि अतीत की ज्यादतियों को लेकर वर्तमान में हम अपने ही सह-नागरिकों से नफरत करने लगे हैं? अच्छे आर्थिक संकेतक, सैनिक शक्ति, लोकतांत्रिक चुनाव के बावजूद देश में बेचैनी है। जिसे 'आइडिया ऑफ इंडिया' कहा जाता है, उसे बदलने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। 'मनरेगा' का नाम बदल कर 'जी-राम-जी' रखना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। सड़क पर तनाव नजर आ रहा है। यह क्यों समझा जा रहा है कि आगे बढ़ने के लिए पिछले बैर को जीवित रखने की जरूरत है? वर्तमान सरकार अपनी कामयाबियों पर गर्व कर सकती है इसलिए समझ नहीं आता कि पुराने बैर को उछलने से रोकती क्यों नहीं? राष्ट्र भविष्य की तरफ देख कर प्रगति करते है, अतीत के गढ़े मुर्दे उखाड़ कर नही। बहुत सी बुनियादी समस्या, रोजगार, महंगाई, कमजोर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदूषण, स्वच्छ पानी की जरूरत आदि अभी कायम है। रूपया कमजोर हो रहा है। पहलगाम की दर्दनाक घटना और लाल किला के बाहर विस्फोट बताता है कि दुश्मन सक्रिय है लेकिन देश का ध्यान हिंदू-मुसलमान या हिंदू-ईसाई पर लगाया जा रहा है।

चुनाव जीतना ही पर्याप्त नहीं है। आप समाज कैसा बना रहे हो? पिछला साल कई प्रकार की दरारें नंगी कर गया है। धर्म और जाति को लेकर जो इतना तनाव उभर रहा है वह पहले नहीं देखा था। हमें नफरत नहीं सिखाई गई थी, जो आज नियंत्रण से बाहर हो रही है। राजनीति से उपर उठकर देश के दीर्घकालिक हित में फैसले लिए जाने चाहिए। सही कहा गया है कि राजनीतिज्ञ अगले चुनाव के बारे सोचते है, स्टेट्समैन अगली पीढ़ी के बारे। जब अजमेर शरीफ को लेकर कुछ उग्रवादियों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां चादर भेजकर विवाद की हवा निकाल दी। ऐसे और प्रयास चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के पास वह राजनीतिक वजन और लोकप्रियता है जिसे वह देश को सही दिशा देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज अटल जी याद आते हैं जिन्होंने कहा था, 'सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेंगी। मगर यह देश रहना चाहिए।'

2025 में एक और कमजोरी सामने आई। संसद अब बहुत प्रभावी नहीं रही। शशि थरूर ने तो कहा है कि 'संसद के पूरे पतन की सम्भावना बन रही है'। यह तो अतिशयोक्ति लगती है, पर रोज हंगामे होते हैं पर लोगों की जरूरी समस्याओं पर बहस नहीं होती। एक महिला सांसद तो आवारा कुत्ते को संसद ले आई। संसद में ई-सिगरेट पीने की भी शिकायत उठी है। कोविड के बाद प्रदूषण सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पर जिस संसद ने 150 साल पुराने वंदे मातरम पर 10 घंटे बहस की उसके पास प्रदूषण पर बहस करने का समय नहीं था। कैसे 'जन प्रतिनिधि' हैं यह? शायद वह अपने-अपने एयर प्योरिफायर में मुग्ध हैं! पर वर्ष का अंत आशा भी दे गया है। अरावली पहाड़ियों के बारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। अब 100 मीटर से कम पहाड़ियों पर खनन नहीं होगा। उन्नाव के कुख्यात रेप केस में भी कुलदीप सेंगर को मिली जमानत पर रोक लगा दी गई है। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि जजों से भी गलती हो सकती है। यह न्यायिक नम्रता का सराहनीय प्रदर्शन है। यह दो प्रकरण यह सुखद संदेश भी दे गए कि अगर सिविल सोसायटी जोर लगाए तो वह अड़ियल व्यवस्था पर रोक लगा सकती है।

भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को मिली नई बुलंदी

इसरो (इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन) ने वर्ष 2025 का समापन एक और त्रुटिहीन हैवी-लिफ्ट वक्तव्य से किया। श्रीहरिकोटा में 24 दिसम्बर 2025 की सुबह 8:55 का समय था, अंतरिक्ष मलबे से बचने के लिए 1 मिनट की देरी कर दी गई थी, बाहुबली यानी एलवीएम3-एम6 रोकेट तैयार था, अमेरिका की कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 को निम्न पृथ्वी की निचली कक्षा (लो अर्थ ऑर्बिट या एलईओ) में ले जाने के लिए। 15 मिनट बाद सटीक सफलता हासिल हुई, बाहुबली ने 6,100 किलो के उपग्रह को लगभग गोल कक्षा में स्थापित कर दिया और भारत के ह्यूमन-रेटिड लांचर के इतिहास में एक अन्य कामयाब अध्याय जुड़ गया। भारत की धरती से लांच किया गया यह आज तक का सबसे भारी स्पेसक्राफ्ट है। यह एलवीएम3-एम6 की लगातार 9वीं सफलता है-इस मील के पत्थर से गगनयान मानव स्पेसक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए जबरदस्त आत्मविश्वास मिलता है।

ब्लूबर्ड 2 प्रक्षेपण/ विजय कपूर

यह स्पष्ट संकेत है कि भारत वैश्विक एलईओ कम्युनिकेशंस बाजार के कुलीन क्लब में एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में शामिल हो गया है। गौरतलब है कि एलईओ पृथ्वी की सतह से तकरीबन 1600 से 2,000 किमी की ऊंचाई तक का वह क्षेत्र है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आईएसएस और कई उपग्रह जैसे जीपीएस, संचार उपग्रह) परिक्रमा करते हैं, क्योंकि यहां कम ऊर्जा और कम सिग्नल देरी (लेटेंसी) के साथ संचार संभव है, जिससे इमेजिंग और ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी के लिए यह बहुत उपयोगी है।

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सबसे बड़ी कमर्शियल कम्युनिकेशंस सैटेलाइट है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह अंतरिक्ष-आधारित सैलुलर ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी सीधे स्टैंडर्ड मोबाइल स्मार्टफोनों को प्रदान करेगी। एलवीएम3-एम6 मिशन की लिफ्ट-ऑफ श्रीहरिकोटा, आंध्रप्रदेश में सतीश धवन स्पेस सैंटर (एसडीएससी एसएचएआर) के दूसरे लांच पैड से हुई, जो अमेरिका स्थित एएसटी स्पेस मोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को एलईओ में लेकर गया।

यह मिशन पूर्णतः कमर्शियल था। चूंकि यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट भारत की धरती से लांच होने वाला सबसे भारी पेलोड है, इसलिए इसने पिछले माह लांच की गई सीएमएस-03 सैटेलाइट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो बहुत ही कम समय के लिए रहा। यह काबिलेगौर और तारीफ है कि मात्र 52 दिनों में दो एलवीएम3 मिशन लांच किए गए। जैसा कि ऊपर बताया गया, यह एलवीएम3-एम6 मिशन इसरो का लगातार नौवां सफल लांच है अति भरोसेमंद थ्री-स्टेज हैवी लांच व्हीकल का प्रयोग करते हुए और यह तीसरा अवसर है जब एलवीएम3 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स के सहयोग से अंजाम दिया गया। इसरो अब 45 वर्षों में 34 देशों के लिए 434 सैटेलाइट लांच कर चुका है।

एलवीएम3 अपने शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को निरंतरता के साथ प्रदर्शित कर रहा है कि ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट से पहले वह चन्द्रयान-2, चन्द्रयान-3, वनवेब मिशंस, सीएमएस-3 आदि को लांच कर चुका है। ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को लांच करना आसान नहीं था। इसमें जबरदस्त प्रयास और विभिन्न टीमों के बीच करीबी समन्वय की आवश्यकता थी। ऐसा इसरो के प्रमुख वी नारायणन का कहना है। उनके अनुसार यह अनेक कारणों से एकदम अलग उड़ान रही।

लांचर ने 1.5 किमी से कम की कक्षीय सटीकता हासिल की, ब्लूबर्ड को 520 किमी पर रखने का लक्ष्य था और उसे 518.9 किमी पर रखा गया, जोकि भारतीय राकेट का आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। ध्यान रहे कि कक्षीय कट-ऑफ 15 किमी की होती है यानी लक्ष्य से 15 किमी के फासले पर भी सैटेलाइट रख दी जाए तो मिशन कामयाब मान लिया जाता है। यहां तो अंतर लक्ष्य से मात्र 2 किमी से भी कम का था, इसलिए इसे बहुत सफल मिशन कहा जा सकता है। नारायणन के मुताबिक, 'लगातार 9 सफल एलवीएम3 लांच की वजह से गगनयान मिशन में हमारा विश्वास बहुत अधिक बढ़ गया है।' गौरतलब है कि गगनयान मिशन के लिए एलवीएम3 राकेट में 9,500 किलो पेलोड ले जाने की क्षमता की जरूरत है।

अब इसकी क्षमता 8,000 किलो की रेंज में पहुंच गई है। इसका अर्थ है कि यह धीर- धीरे आवश्यक भार क्षमता के निकट पहुंचता जा रहा है। ताजे मिशन के दौरान मोटर्स पर स्टेज वन स्ट्रैप में नये इलैक्ट्रो-मैकेनिकल अक्टुर्स ने भी पेलोड की क्षमता को 100-150 किलो बढ़ाने में मदद की यानी तकनीकी अपग्रेड ने राकेट की क्षमता में इजाफा किया है।

इसरो के वैज्ञानिकों के बढ़ते यकीन की यही मुख्य वजह है, विशेषकर इसलिए भी कि एलवीएम3 का प्रयोग करके इस एजैंसी को निरंतर सफलता हासिल हो रही है। बहरहाल, यह सफल लांच उस समय आया है जब इसरो अगले कुछ माह के दौरान लांच की बढ़ती हुई पाइपलाइन की तरफ देख रहा है, जिनमें गगनयान की मानवरहित टैस्ट फ्लाइट्स और इलैक्ट्रिक सैटेलाइट्स व क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अति विकसित तकनीकी प्रदर्शन भी शामिल हैं। चन्द्रयान 4, जोकि चांद की ओर चौथा मिशन होगा ओर जिसका उद्देश्य चांद के रॉक सैंपल लाना है, भी अच्छी प्रगति देख रहा है।

भारत ने उच्चस्तरीय परिपक्वता के साथ अनेक बार महत्वपूर्ण स्पेस डॉकिंग प्रयोग किए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत इस मिशन के लांच लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एकदम सही दिशा में है। इस बीच एसडीएससी एसएचएआर के निदेशक पद्म कुमार ईएस ने कहा है कि तीसरे लांच पैड के लिए प्रारम्भिक डिजाइन मुकम्मल हो गया है और उनका सैंटर वेंडर्स की पहचान कर रहा है सामान हासिल करने के चरण के लिए। इसरो के चेयरमैन के रूप में नारायणन के समक्ष यह चुनौती है कि वह इस स्पेस एजैंसी को तेजी से बदलते ग्लोबल परिदृश्य में आगे लेकर जाएं और वह लेकर जा भी रहे हैं। नारायणन के कुशल नेतृत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसरो में रहते हुए उन्होंने अनेक प्रमुख मिशन व प्रोजैक्ट्स में अपना योगदान दिया है, जिनमें चंद्रयान सीरीज और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लांच व्हीकल (जीएसएलवी) के लिए सफलतापूर्वक क्रायोजेनिक अपर स्टेज का विकास शामिल हैं।

पाकिस्तान की राह पर बढ़ रहा है बांग्लादेश

बांग्लादेश के हालात दो तरफ इशारा कर रहे हैं और दोनों ही भारत के लिए खतरनाक हैं। एक तरफ बांग्लादेश भारत से दुश्मनी के रास्ते पर जा रहा है तो उसका दूसरा रास्ता उसे बर्बादी की ओर ले जा रहा है। भारत के लिए बांग्लादेश का दुश्मनी के रास्ते पर जाना खतरनाक है तो बांग्लादेश का बर्बाद होना भी बुरी खबर है। पाकिस्तान अपने जन्म के बाद ही भारत का जानी दुश्मन बना बैठा है और अब वो बांग्लादेश को खींचकर उसी रास्ते पर ले जा रहा है। बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और भारत को उम्मीद है कि उसके बाद बांग्लादेश के हालात बेहतर हो सकते हैं। चुनाव से पहले ही बांग्लादेश के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि चुनाव पर ही खतरा नजर आने लगा है।

एक अंदेशा यह भी है कि बांग्लादेश के हालात मोहम्मद यूनुस की ही साजिश है क्योंकि वो चुनाव नहीं करवाना चाहता है। उसे पता है कि अगर चुनाव हुए तो सत्ता उसके हाथ से चली जाएगी। मोहम्मद यूनुस एक गैर-निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा है, कहने को वो सरकार का मुख्य सलाहकार है। ऐसा लगता है कि सत्ता का लालच इतना बढ़ गया है कि उसे देश की बर्बादी नजर नहीं आ रही है। यूनुस ने ही बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को इतना बढ़ावा दिया है कि आज वो सड़क पर उतरकर हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं। एक कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। फिर एक और छात्र नेता की हत्या हो गई है। ऐसा लग रहा है कि इन हत्याओं के पीछे गहरी साजिश है। इन हत्याओं में भारत का हाथ बताकर हिंदुओं पर हमले किये जा रहे हैं। एक हिंदू युवक को हजारों जेहादियों की भीड़ ने लिंचिंग करके मारने के बाद उसके शव को लटकाकर जला दिया। उसके बाद भी दो हिंदुओं की हत्या कर दी गई। ये सिर्फ हत्याएं नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समुदाय पर हमला है, इसलिए इसके खिलाफ बांग्लादेश के हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया है। सवाल यह है कि कट्टरपंथी जेहादियों पर क्या इस प्रदर्शन का कोई असर होगा। ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू आबादी बिखरी हुई है। बिखरी हुई हिंदू आबादी पर जेहादियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार इस तरफ से आंखे बंद किए हुए है। मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया है कि वो प्रदर्शनकारियों को कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने देंगे और देश में सबकी सुरक्षा की जाएगी। उनका ये बयान दबाव में दिया गया है, अन्यथा उनका इन जेहादियों को पूरा समर्थन है। उस्मान हादी के भाई ने उसकी हत्या के लिए मोहम्मद यूनुस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है और कहा है कि ये चुनाव रोकने की साजिश के तहत की गई हत्या है।

सिर-दर्द/ राजेश कुमार पासी

पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच रक्षा समझौते की तैयारी की जा रही है और पाकिस्तान ने बयान दिया है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर आक्रमण किया तो पाकिस्तान उसकी रक्षा करेगा। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान भारत को दो मोर्चों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश के कमजोर होने के बावजूद हम इस कोशिश को हल्के में नहीं ले सकते। आज बेशक बांग्लादेश सैन्य रूप से कमजोर नजर आ रहा है लेकिन कई शक्तियां उसे भारत के खिलाफ तैयार कर रही हैं। बांग्लादेश से ज्यादा बड़ा खतरा उसके घुसपैठिए हैं जो वक्त आने पर भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या दो करोड़ से पांच करोड़ तक हो सकती है जिनसे निपटना हमारे सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होने वाला है। पाकिस्तान की गुप्तचर एजैंसी आईएसआई बांग्लादेश में अपना एजैंडा चलाने में कामयाब हो रही है। जमात-ए-इस्लामी आईएसआई के साथ मिलकर बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा करने की ओर बढ़ रही है। इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि जमात सत्ता पर कब्जा चुनाव में जीतकर नहीं करना चाहती है। जमात अपने कट्टरपंथी समर्थकों की मदद से बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहती है।

ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहती है, जहां शरीयत का राज हो क्योंकि जमात को लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं है। सच तो यह है कि जिस जमात को यूनुस ने बांग्लादेश में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका दिया, अब वही जमात यूनुस को सत्ता से बेदखल कर सकती है। बंगलादेश की राजनीति में सब एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। मोहम्मद यूनुस को जिन छात्रों ने तथाकथित क्रांति करके सत्ता में बिठाया था, वो भी दो धड़ो में बंट गए हैं। शेख हसीना की राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाकर उसे सत्ता की लड़ाई से बाहर कर दिया गया है। खालिदा जिया का देहांत हो चुका है लेकिन उनके बेटे के बांग्लादेश लौटने के बाद से उनकी बांग्लादेश नैशनल पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच गई है। भारत सरकार बांग्लादेश के हालात को बड़ी सतर्कता से देख रही है और बीएनपी के सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है। बीएनपी बेशक एक भारत विरोधी पार्टी मानी जाती है लेकिन उसे पता है कि बांग्लादेश को भारत की कितनी जरूरत है। बीएनपी पहले भी राज कर चुकी है, इसलिए वो एक हद तक ही भारत का विरोध कर सकती है। बांग्लादेश को चलाने के लिए भारत की अहमियत को बीएनपी जानती है। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के अन्य दुश्मन देश इसे समझ रहे हैं, इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि बीएनपी सत्ता में न आ पाए। बांग्लादेश की कट्टरपंथी शक्तियां भी नहीं चाहती हैं कि बीएनपी सत्ता में आए। भारत को उम्मीद थी कि बांग्लादेश की सेना अपने देश को बचाने की कोशिश जरूर करेगी जैसे नेपाल की सेना ने की है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की सेना भी कट्टरपंथियों के कब्जे में जा चुकी है, इसलिए जमात को छूट मिल गई है।

कार्टून कोना

विश्वा मित्र

2025 में भारत की कर संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव

महात्मा गांधी द्वारा 1930 में नमक कर की अवज्ञा ने उजागर किया था कि कैसे दमनकारी कर प्रणाली नागरिक को राज्य से दूर कर सकती है। यह एक चेतावनी थी कि जब कर मनमाने या अत्यधिक होते हैं, तो वे विश्वास और सामाजिक सम्पर्क को कमजोर करते हैं। चार दशक बाद, भारत में एक और चरम स्थिति देखी गई, जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आयकर के स्तर को आश्चर्यजनक रूप से 97.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।

इस परम्परा ने करदाताओं और राज्य के बीच गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। दशकों तक, भय के कारण अनुपालन होता रहा। इसने सक्रिय योगदान देने के बजाय टालमटोल को प्रोत्साहित किया। इसी पृष्ठभूमि में मोदी सरकार के कर सुधार, जो 8 वर्ष पहले आरंभ हुए और 2025 में निर्णायक रूप से आगे बढ़े, अतीत से एक स्पष्ट अंतर का प्रतीक हैं। इस बदलाव में अंतर्निहित लाफर कर्व का तर्क यह है कि कम कर दरें राजस्व सृजन के लिए उप-इष्टतम हैं और कर आधार का विस्तार करती हैं।

जीएसटी से पहले की वास्तविकता: विखंडन, रिसाव और अविश्वास: वैट शासन के दौरान, अप्रत्यक्ष करों की बहुलता ने व्यागपक स्त र पर भ्रम पैदा किया, राज्यों ने 0 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत के एकसमान स्लैब को खत्म करते हुए बार-बार वैट दरों में बदलाव किया। वास्तव में, स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद, राज्यों ने अतिरिक्त शुल्क लगाने के विरुद्ध अपनी 2010 की रिपोर्ट में कैग की सुस्पष्ट सलाह की अनदेखी कर दी, फिर भी प्रवेश कर और स्थानीय अधिभार जारी रहे। इसने भ्रम और विखंडन पैदा किया और प्रत्येक राज्य ने अपने स्वयं के अनुपालन नियमों, दंड और प्रक्रियाओं को लागू किया। इसके गंभीर परिणाम हुए।

कमजोर जांच और असंगत प्रवर्तन ने कर चोरी को प्रोत्साहित किया। हर दो डीलरों में से एक ने कर चोरी करने का प्रयास किया और सिर्फ एक मामले में ही, सात डीलरों को उचित दस्तावेज के बिना 1,026 करोड़ रुपये की छूट दे दी गई।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार (2025): कार्यनीति के रूप में सरलता: वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरुआत ऐतिहासिक थी। इसने भारत को एकल बाजार में समेकित किया, व्यापक करों को समाप्त कर दिया और एक पारदर्शी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की नींव रखी। यद्यपि, दरों और वर्गीकरण में अस्पष्टता के कारण विवाद पैदा हुए और निस्संदेह अनुपालन के साथ-साथ पंजीकरण में भी भारी समस्याएं रहीं। उदाहरण के लिए, वस्त्र क्षेत्र में धुलाई और रंगाई जैसी सेवाओं पर 'जॉब वर्क सर्विसेज' के हिस्से के रूप में 5 प्रतिशत कर लगाया गया था, जबकि ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और रासायनिक उपचार जैसी प्रक्रियाओं पर 18 प्रतिशत का कर लगाया गया था। इससे वर्गीकरण को लेकर गंभीर भ्रम और कर विवाद पैदा हो गए। इन चुनौतियों को स्वीकार

जब्ती करों से लोक केंद्रित सुधार तक

करते हुए मोदी सरकार ने 2025 में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की शुरुआत की, जो जीएसटी के लॉन्च के बाद से सबसे सार्थक सरलीकरण प्रदान करते हैं। इस प्रणाली को दो स्पष्ट स्लैब, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में युक्तिसंगत बनाया गया था। साथ ही, वस्तुओं के वर्गीकरण को भी स्पष्ट किया गया, अनुपालन को सरल बनाया गया और पंजीकरण को सुगम बनाया गया। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने सक्रिय रूप से व्यवसायों और राज्यों की बात सुनी है और राज्यों को कार्यान्वयन में समान भागीदार माना है। जीएसटी दरों में कटौती और आयकर छूट की सीमा में वृद्धि से परिवारों को सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिलेगी। सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 0 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो 18 प्रतिशत से कम है।

अर्थ है कि 20,000 रुपये के बेस प्रीमियम पर पहले 3,600 रुपये जीएसटी (18 प्रतिशत) था, जिससे 23,600 रुपये देय था। छूट के बाद, 20,000 रुपये के भुगतान पर सीधे 3,600 रुपये की बचत है। जीएसटी में सुधार से किराने का सामान और दैनिक आवश्यक वस्तुओं के घरेलू बिलों में 13 प्रतिशत की बचत होगी, जबकि एक छोटी कार का खरीदार लगभग 70,000 रुपये बचा सकता है।

मध्यम वर्ग के लिए कर में महत्वपूर्ण लाभ: भारत की आयकर यात्रा इसके आर्थिक विकास को दर्शाती है। इंदिरा गांधी के युग में कर की दर 97.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी और कर चोरी और अविश्वास की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। दशकों बाद, उदारीकरण के बावजूद, 2014 में राहत मामूली रही; आयकर छूट को 2 लाख रुपये तक सीमित कर दिया गया था, जो शहरीकरण की अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं था।

पिछले दशक में आयकर छूट की सीमा 2014 में 2 लाख रुपये से बढ़कर 2025 में 12 लाख रुपये हो गई है, जो 6 गुना राहत प्रदान करती है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, 75,000 रुपये की मानक कटौती के बाद, प्रभावी शून्य-कर सीमा अब 12.75 लाख रुपये प्रति वर्ष है। नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा जबकि 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को टैक्स के रूप में 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा। नमक कर से लेकर आयकर की जब्ती दरों तक, भारत का इतिहास बताता है कि त्रुटिपूर्ण कर प्रणाली विश्वास और विकास को कमजोर करती है। मोदी सरकार के 2025 के कर सुधार उस अतीत से एक स्पष्ट अंतर का प्रतीक है। 2025 में, भारत में कर प्रणाली अब नियंत्रण का माध्यम नहीं रह गई है। यह एक साझेदारी है, जो यह मानती है कि जब नागरिकों पर भरोसा किया जाता है और प्रणालियां सरल होती हैं, तो अर्थव्यवस्था विकास के साथ मिलकर कदम बढ़ाती है।

(सम्पादकीय डैस्क)

दैनिक सवेरा टाइम्स

सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक शीतल कुमार विज के स्वामित्व में, दैनिक सवेरा न्यूज एंड मीडिया नेटवर्क, एस.-9, इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर से मुद्रित एवं डी.-55, प्रीत विहार, नई दिल्ली से प्रकाशित किया।

DELHIN/2013/53563

पोस्टल रजि. नं. PB-JL-058/25-27

फोन 0181-2370100, 4625005, 4626006, 4629009

समाचार (फैक्स) 0181-2224455

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा उनसे उत्पन्न समस्त विवाद जालंधर न्यायालय के अधीन होंगे।

संपादकीय

नया साल केवल तारीख नहीं

नूतन वर्ष को विश्वभर में नए आरंभ, अवसर और नवीकृत आशाओं के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह वह समय होता है जब लोग पिछले वर्ष पर चिंतन करते हैं। सफलताएं, गलतियां, चुनौतियां और जो जीवन की सीख मिली हैं और अपने आप को मानसिक एवं भावनात्मक रूप से आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं। दरअसल, एक से दूसरे वर्ष में परिवर्तन केवल कैलेंडर की संख्या बदलने जैसा है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक महत्त्व बहुत गहरा होता है। यह लोगों को जीवन में एक प्रकार की समाप्ति का अनुभव कराता है और नए लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर देता है। यही वजह है कि नूतन वर्ष आत्मनिरीक्षण, प्रेरणा और आत्म-सुधार का समय बन जाता है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पेशेवर जीवन में भी इस अवसर को एक महत्त्वपूर्ण मोड़ के रूप में उपयोग कर सकता है।

यह हमें आत्म निरीक्षण की ओर प्रेरित करता है, जो व्यक्तिगत विकास की दिशा में पहला और अहम कदम है। पिछले वर्ष को पीछे मुड़कर देखना यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में क्या सफल रहा और क्या नहीं। यह समय होता है अपनी उपलब्धियों को पहचानने का, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों, और उन प्रयासों की सराहना करने का, जिनका परिणाम हमेशा उम्मीद के अनुसार नहीं आया। आत्म निरीक्षण में असफलताओं और गलतियों को स्वीकार करना भी शामिल है, लेकिन इसके लिए आत्म-आलोचना की आवश्यकता नहीं है। अपने पिछले अनुभवों को समझना लोगों को मूल्यवान सबक सिखाता है, उन्हें मानसिक दृढ़ता विकसित करने में मदद करता है और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह सजग आत्म निरीक्षण एक उद्देश्यपूर्ण और सतत जीवन की नींव रखता है, जो केवल दिनचर्या या संयोग से संचालित न होकर जानबूझ कर चुने गए रास्ते पर आधारित होता है।

यह मौका एक खाली कैनवास की तरह है, जो हमें यह तय करने का अवसर देता है कि हम वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यक्तिगत विकास, करिअर, स्वास्थ्य, रिश्तों और आत्मिक उन्नति जैसे क्षेत्रों में केंद्रित कर सकता है। लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में प्राथमिकताओं को पहचानना, बड़े लक्ष्यों को छोटे और साध्य हिस्सों में बांटना और बाधाओं को पार करने की रणनीति बनाना शामिल है। छोटे-छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से न केवल उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि आत्म-विश्वास और प्रेरणा में भी वृद्धि होती है, क्योंकि हर छोटी सफलता व्यक्ति को संतोष और आत्मविश्वास देती है।

जीवन निरंतर विकास की यात्रा है और प्रत्येक वर्ष बेहतर आदतें अपनाने, हानिकारक व्यवहारों को छोड़ने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का अवसर प्रस्तुत करता है। चाहे वह नया कौशल सीखने के लिए समय समर्पित करना हो, शरीर की सेहत और क्षमता सुधारना, समय का बेहतर प्रबंधन करना या ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास करना हो, नया वर्ष एक स्वाभाविक संकेत है कि व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करे। छोटे और नियमित प्रयास समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदल सकते हैं, जिससे जीवन अधिक संतुलित, पूर्ण और सार्थक बनता है।

मानवीय संबंध भावनात्मक संतुलन और जीवन की खुशी के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। नए साल का जश्न परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ मनाने से अपनापन, कृतज्ञता और साझा खुशी की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा, यह समय पिछले मतभेदों को माफ करने, रंजिश को छोड़ने और संबंधों में सकारात्मकता और सहानुभूति के साथ फिर से शुरुआत करने का भी होता है। मजबूत रिश्ते न केवल भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, बल्कि अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण समाज के निर्माण में भी योगदान करते हैं।

नई योजना और रोजगार की चुनौतियां

अब जरूरत है कि देश में नागरिकों को काम के उचित अवसर मिलें। यूपीए सरकार के समय सबसे अच्छी योजना मनरेगा को ही बताया जाता था। यह फरवरी 2006 में लागू हुई थी। इसमें आवेदन करने पर पंद्रह दिन के अंदर रोजगार देना अनिवार्य होता था। आंकड़े बताते हैं कि इस पर अब तक 11.74 लाख व करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वर्ष 2014 से राजग सरकार के कार्यकाल में भी इस पर 7.8 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हालांकि इसमें केवल सौ दिन का काम दिया जाता है। कई बार तो मजदूरों को औसत पचास दिन ही काम मिला

डॉ विजय गर्ग

भारत तरक्की कर रहा है, आंकड़ों से अर्शशास्त्री यही बताते हैं। निस्संदेह भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा और 2047 में जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब हम पूरी तरह से एक विकसित राष्ट्र होंगे। उस समय हर आदमी यथोचित रोजगार के साथ अच्छा भोजन करेगा, अच्छा पहनेगा और खुशहाली के शिखर होगा। यह है सपना। ऐसा अगर लोग लोग स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के बाद भी सोचते हैं, हैं, तो कारणों की तलाश करनी पड़ेगी। पिछले दिनों कहा गया हम देश से बेरोजगारी मिटा देंगे। बेरोजगारी की भूख अनुकंपा के सस्ते राशन से मिटा दी जाएगी। मगर युवा पीढ़ी जो इस देश की आधी आबादी है, वह काम चाहती है। यह कड़वी सच्चाई है कि बड़ी बड़ी संख्या में युवा आज आज भी बेरोजगार हैं। नए सर्वेक्षणों ने बताया है कि इस कृषि प्रधान देश में ग्रामीण बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बेरोजगारी बहुत का बदला रूप 'बीबी जी राम जी' इस चुनौती का मुकाबला कर पाएगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि गांवों में योजना का नया कलेवर नहीं, काम चाहिए।

बड़ी समस्या है। क्या 7 क्या मनरेगा का

अब जरूरत है कि देश में नागरिकों को काम के उचित अवसर मिलें। यूपीए सरकार के समय सबसे अच्छी योजना मनरेगा को ही बताया जाता था। यह फरवरी 2006 में लागू हुई थी। इसमें आवेदन करने पर पंद्रह दिन के अंदर रोजगार देना अनिवार्य होता था। आंकड़े बताते हैं कि इस पर अब तक 11.74 लाख व करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वर्ष 2014 से राजग सरकार के कार्यकाल में भी इस पर 7.8 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हालांकि इसमें केवल सौ दिन का काम दिया जाता है। कई बार तो मजदूरों को औसत पचास दिन ही काम मिला। फिर भी मनरेगा वर्ष 2014 से अब तक आठ करोड़ लोगों को ही लोगों को ही रोजगार दे पाई।

।अब केंद्र सरकार ने संसद में नया ग्रामीण रोजगार विधेयक पारित किया है। है। ग्रामीणों को रोजगार के के लिए 20 साल के बाद योजना को एक नया कलेवर दिया गया है। इसकी शुरुआत नाम बदलने से हुई। इस योजना का नया नाम है- है विकसित भारत जी राम जी जबकि इससे पहले इसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहा जाता था। कुल जमा ये कि नई योजना ने रूप बदला है। पहले सौ दिन काम मिलता था, लेकिन अब 125 दिन काम मिलेगा, लेकिन दिहाड़ी वही रहेगी। पहले इस योजना पर

फीसद पैसा केंद्र सरकार खर्च करती थी। अब इसमें 60 फीसद योगदान केंद्र देगा। जबकि 40 फीसद राज्य सरकारें देंगी। पहले इस योजना में आवेदन करने पर 15 दिन के भीतर काम मिलता था। मगर अब काम न मिलने पर राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। मनरेगा ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए था। फिलहाल 'बीबी जी राम जी' को विकसित भारत का हिस्सा बना कर देखा जा रहा है। नई योजना की डिजिटल निगरानी होगी। ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् बनेंगीं। संचालन समितियां बनेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाली योजनाओं को 'पीएम विकास गतिशक्ति' से जोड़ देंगे। अब सवाल

है कि इस परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? संसद में विधेयक पारित भी हो गया है। इससे पहले इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष की जम कर बहस हुई। सत्तापक्ष का कहना था कि मनरेगा दिशाहीन था और इसमें ऐसा था कि पहले गड्ढे खोदो, फिर उन्हें भर दो। मुख्य उद्देश्य था गरीब परिवार के

एक सदस्य को सौ दिन काम देकर मेहनताना देना। अब यह नई योजना दिशाहीन नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार का मत है कि गांवों में परिवर्तन आ गया है। भुखमरी कम हो गई है, ग्रामीण बेरोजगारी इतनी बड़ी चुनौती नहीं रही। मगर सच से कैसे इनकार किया जा सकता है? चुनौती तो अब भी है। सरकार का यह भी कहना है कि ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना बदल रही है। वहां डिजिटल भुगतान पहुंच गया है। बैंक पहुंच गए हैं। बेहतर संपर्क है, लेकिन मनरेगा में फर्जीवाड़ा हो रहा था। योजना की राशि । दुरुपयोग हो रहा था। यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब जैसे राज्यों में इतनी कम दिहाड़ी पर मजदूर काम करने के लिए राजी नहीं। इसलिए वहां फर्जी आंकड़ों से हो रहे हैं। -25 में 1 से भुगतान । विशेषज्ञ कहते हैं कि वर्ष 2024-25 में इस योजना में 194 करोड़ रुपए का घपला हुआ और केवल 7.6 फीसद ग्रामीण परिवार ही सौ दिन का रोजगार सके, लेकिन अब माहौल बदल जाएगा। फर्जीवाड़ा रुकेगा। अब यह चुस्त-दुरुस्त और नए कलेवर वाली योजना बनेगी, जिस पर बाकायदा काम होगा। श्रम बल को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जाएगा। यह यथार्थवादी योजना होगी। जब गांवों में फसल बिजाई और फसल कटाई का भरपूर आशिक योगदान मिलने की परिस्थितियां पैदा हो हैं, तो यह योजना समांतर रोजगार देना स्थगित कर देगी। बाद में लक्ष्यबद्ध तरीके से कार्यबल का इस्तेमाल किया जाएगा जो ग्रामीण जीवन का कायाकल्प कर देगा। दूसरी ओर विपक्ष के अपने तर्क हैं कि क्या यहाँ नया कलेवर मनरेगा को नहीं दिया जा सकता था? क्या उसे निश्चित उद्देश्यों के साथ लक्ष्यबद्ध नहीं किया जा सकता था। फिर जरूरी महंगाई दर देखते हुए कार्यबल के पारिश्रमिक में वृद्धि कर दी जाती। वृद्धि तो की नहीं, केवल काम 25 दिन बढ़ा दिए। राज्य सरकारें तो पहले ही अपने खाली खजाने का रोना रो रही हैं। उनका यह कहना है कि ग्रामीण विकास कोष से लेकर जीएसटी तक में से उन्हें उनका उचित भुगतान नहीं मिलता। मुआवजा नहीं मिलता। अब उन पर इस इस योजना के योगदान का 40 फीसद भार भी डाल दिया गया है। राज्य सरकारें तो अधिक आर्थिक सहायता की उम्मीद केंद्र से कर रही। थी. . लेकिन यहां एक एक और दायित्व उन पर आ गया कि अगर ग्रामीण विकास को तेजी देनी है, तो आगे बढ़ो और केंद्र सरकार के साथ योगदान करो। यह भी कहा गया कि पंजाब ही नहीं, बल्कि बंगाल इस कोष का भारी दुरुपयोग हुआ। इसलिए नया विधेयक लाया गया

सब कुछ यह योजना क्या काम करेगी, इसे स्पष्ट किया गया है। यह मूलभूत बुनियादी ढांचा बनाएगी। आजीविका के लिए पूंजी का निर्माण ढ्ढ करेगी और प्रदूषण से निपटने का कार्य करेगी। यह निराशाजनक है कि इस पर गंभीर चर्चा नहीं हुई। इसका नाम बदलने पर ही बहस होती रही। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है! मगर अब तो लगता है कि नाम रखा है। मगर अब तो लगता है कि नाम में ही रखा है। सच तो यही है है। सच तो यही है कि साम, दाम, दंड, भेद के साथ अपना नाम रौशन करने की यह जिद है। बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। सत्ता की यह नई संस्कृति बनती जा रही। जा रही है। ग्रामीण रोजगार संबंधी इस योजना को सार्थक बनाना है, तो उसके लिए आर्थिक आबंटन भी बढ़ना चाहिए। नई योजना में केंद्र सरकार ने आर्थिक आबंटन तो बढ़ाया नहीं, अलबत्ता राज्य सरकारों पर बोझ जरूर डाल दिया गया है। अब जिस प्रकार संवादहीनता गैर-भाजपा सरकारों और केंद्र के बीच चलती है, या जहां 'डबल इंजन सरकारें नहीं हैं, वहां इस नई योजना का भविष्य क्या होगा, यह विचारणीय है। क्या योजना का नाम बदलने भर से सार्थकता साबित होगी ?

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

जब कक्षाएं असफल हो जाएं तो पहले स्टाफरूम को देखें

डॉ विजय गर्ग

जैसे-जैसे शैक्षणिक वर्ष समाप्त होता जा रहा है, देश भर के स्कूल अपनी पढ़ाई पूरी करने की एक परिचित अनुष्ठान में लग जाते हैं। वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया जाता है, तस्वीरें चुनी जाती हैं और प्रगति की कहानियां सावधानी से संकलित की जाती हैं। वर्ष के अंत में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य चिंतन और जवाबदेही को दर्शाना है, फिर भी जो चीज अक्सर गायब रहती है, वह है स्टाफरूम संस्कृति की गंभीर जांच, भले ही इसका शिक्षण गुणवत्ता, स्टाफ मनोबल और कक्षाओं की स्थिरता पर सीधा प्रभाव पड़ता हो।

स्टाफरूम को कभी-कभी एक अनौपचारिक स्थान के रूप में माना जाता है, लेकिन व्यवहार में यह स्कूल के भावनात्मक और पेशेवर केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो दैनिक बातचीत को आकार देता है और शिक्षण के तरीके को प्रभावित करता है।

जब कक्षाओं में संघर्ष शुरू होता है, तो स्पष्टीकरण आमतौर पर संस्थान के बाहर ही दिया जाता है। कहा जाता है कि छात्र विचलित हो जाते हैं, माता-पिता को मांग करने वाला बताया जाता है, ध्यान अवधि कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को दोषी ठहराया जाता है, तथा पाठ्यक्रमों को अत्यधिक बताया जाता है। जिसे शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है, वह यह है कि शिक्षण कोई तटस्थ या यांत्रिक गतिविधि नहीं है: यह गहराई से भावनात्मक और संबंधपरक होती है, जो शिक्षकों के काम करने की परिस्थितियों से आकार लेती है। समय के साथ, स्टाफरूम एक अदृश्य पाठ्यक्रम बन जाता है, जो पदानुक्रम, सहनशक्ति और किसे महत्व दिया जाता है, इस बारे में अनकहे नियम पारित करता है। जब यह स्थान चयनात्मक मान्यता, प्रदर्शनकारी अनुपालन, दबी हुई असहमति और थकान की शांत स्वीकृति से चिह्नित होता है, तो समस्याएं अचानक प्रकट नहीं होतीं; वे एकत्रित हो जाती हैं। अंतिम सत्र तक, कई शिक्षक न केवल थके हुए होते हैं बल्कि भावनात्मक रूप से भी थक जाते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में शिक्षण सूक्ष्म तरीकों से बदल जाता है। धैर्य कम हो जाता है, प्रयोग जोखिम भरा लगता है, और पाठ संलग्नता के बजाय नियमित रूप से पूरा करने की ओर बढ़ जाते हैं। विद्यार्थियों को जवाब देने के बजाय पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। युवा लोग वयस्कों के बीच असंगति को शीघ्रता से महसूस करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया उदासीनता, वापसी या निष्क्रिय प्रतिरोध हो सकती है। जिसे कक्षा विकार कहा जाता है, वह अक्सर पेशेवर वातावरण का परिणाम होता है, जिसने पहले ही शिक्षकों को सुरक्षा और उद्देश्य की भावना से कमजोर कर दिया है।

इन संस्कृतियों को बनाए रखने या चुनौती देने में नेतृत्व की निर्णायक भूमिका होती है। यह शायद ही कभी नाटकीय होता है। अक्सर यह असहमति के प्रति असहिष्णुता, अस्पष्ट निर्णय लेने, असमान जवाबदेही और मान्यता के रूप में प्रकट होता है जो पदार्थ की अपेक्षा दृश्यता को प्राथमिकता देता है। नियंत्रण को अधिकार के साथ भ्रमित किया जाता है, गति को प्रभावशीलता समझ लिया जाता है। बैठकें समझौते के अनुष्ठान बन जाती हैं, और शिक्षक सीखते हैं कि अनुपालन में निर्णय से कम जोखिम होता है। भय धीरे-धीरे संगठनात्मक सिद्धांत बन जाता है, भले ही यह विश्वास और पहल को कम कर देता है। इसके साथ ही सहकर्मी सहभागिता भी है: स्टाफ रूम ऐसे स्थानों में बदल सकते हैं जहां गपशप समर्थन की जगह लेती है, सामंजस्य के नाम पर औसत प्रदर्शन का बचाव किया जाता है, और नाजुक संतुलन को बिगाड़ने के लिए मजबूत काम से नाराजगी जताई जाती है।

यदि वर्ष के अंत में चिंतन करना महत्वपूर्ण है, तो उसे इन वास्तविकताओं पर ध्यान देना होगा। चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए ईमानदारी और साहस की आवश्यकता होती है। सतही कल्याण कार्यक्रम या छात्र-केंद्रित पहल, शिक्षकों को थका देने वाले वातावरण की भरपाई नहीं कर सकती। जब स्टाफरूम की संस्कृति में सुधार होता है, तो अन्य परिवर्तन भी होते हैं। शिक्षकों को पुनः आत्मविश्वास मिलता है, सहयोग मजबूत होता है, तथा कक्षाएं अधिक स्थिर हो जाती हैं। अनुशासन प्रतिक्रियात्मक के बजाय निवारक रूप से बढ़ता है, नवाचार साझा महसूस होता है, और सीखने की दिशा पुनः प्राप्त होती है, क्योंकि शिक्षक अब आने वाले वर्ष में स्कूल समुदाय में विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों के लिए उत्तरजीविता मोड में काम नहीं कर रहे हैं।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधान शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, दो हफ्तों में तीन हत्याएं

ऐसे में वहां की अंतरिम सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है।हालांकि, सरकार का दावा है कि इन घटनाओं को सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की हिंसक घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले दो सप्ताह में वहां तीन हिंदू नागरिकों की हत्या कर दी गई। इससे हिंदू समुदाय के भीतर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं, जब बांग्लादेश में आए दिन विरोध प्रदर्शनों से अराजक स्थिति पैदा हो रही है। सवाल है कि ऐसे हमले अचानक हो रहे हैं या फिर किसी गहरी साजिश के तहत इस तरह की हिंसा का जाल बुना जा रहा है! ऐसे में वहां की अंतरिम सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है।हालांकि, सरकार का दावा है कि इन घटनाओं को सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। अगर यह सही है, तो फिर क्या वजह है कि अल्पसंख्यकों को ही लक्षित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है? कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जाहिर है कि जिस तरह की अराजक स्थिति पैदा हो रही है, उसके लिए शासन एवं प्रशासन ही जवाबदेह हैं।बांग्लादेश में अगस्त 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ था। अंतरिम सरकार बनने के बाद वहां माहौल थोड़ा शांत और स्थिर हुआ था, लेकिन हाल के दिनों में हिंसा फिर से जोर पकड़ने लगी है। खासकर अब हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दो सप्ताह के भीतर तीन हिंदू नागरिकों की हत्या कर दी गई। पहले भालुका इलाके में भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया।इसके कुछ दिन बाद मैमनसिंह जिले में एक हिंदू नागरिक की हत्या कर दी गई। हाल ही में कपड़े के कारखाने में एक हिंदू कर्मी को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में स्थानीय पुलिस का दावा है कि आरोपी ने मजाक में हिंदू व्यक्ति की तरफ बंदूक तानी थी और इस दौरान अचानक गोली चल गई। जबकि घटना के चश्मदीद का कहना है कि आरोपी ने जान-बूझकर गोली चलाई। बयानों के इस विरोधाभास से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।यह बात छिपी नहीं है कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और उनके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। अत्याचार, प्रताड़ना, जबरन धर्मांतरण और हिंसा की वजह से वहां हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद से हिंदू समुदाय के लोगों पर लक्षित हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं। वहां जिस उद्देश्य से अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, वह पूरा होता नजर नहीं आ रहा है।कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की विफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न तो विरोध प्रदर्शन थम रहे हैं और न ही हिंसक गतिविधियों पर अंकुश लग पाया है। इसका असर भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ा है। मगर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां की अंतरिम सरकार भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कूटनीतिक प्रयास तेज करने होंगे, ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पैदा हुए खतरे को कम किया जा सके।

जब कैलेंडर बदले तो नजरिया भी बदले

नूतन वर्ष 2026 का आगमन केवल एक तारीख बदलने की औपचारिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना को झकझोरने वाला एक ऐसा पड़ाव है जहां हमें रुककर पीछे मुड़कर देखना होगा और आगे की राह तय करनी होगी। नववर्ष के आगमन पर हमें रस्मी वादों और खोखले संकल्पों से आगे बढ़कर, जीवन जीने के अपने तौर-तरीकों का एक ईमानदार और कठोर 'ऑडिट' करना होगा

-डॉ. सुरेश कुमार पाण्डेय

समय की रेत हमारी मुट्ठी से जिस तेजी से फिसल रही है, उसका वास्तविक आभास हमें अक्सर तब होता है जब दीवार पर टंगा कैलेंडर बदलने का वक्त आता है और हम एक नए वर्ष की दहलीज पर खड़े होते हैं। नूतन वर्ष 2026 का आगमन केवल एक तारीख बदलने की औपचारिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना को झकझोरने वाला एक ऐसा पड़ाव है जहां हमें रुककर पीछे मुड़कर देखना होगा और आगे की राह तय करनी होगी। नववर्ष के आगमन पर हमें रस्मी वादों और खोखले संकल्पों से आगे बढ़कर, जीवन जीने के अपने तौर-तरीकों का एक ईमानदार और कठोर 'ऑडिट' करना होगा। आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तकनीक के माध्यम से हम पूरी दुनिया से तो 24 घंटे जुड़े हैं, लेकिन खुद से, अपने शरीर के संकेतों से और अपने ही परिवार से पूरी तरह कट गए हैं।नववर्ष 2026 में हमारा सबसे बड़ा संघर्ष किसी बाहरी वायरस, जीवाणु या महामारी से नहीं है, बल्कि हमारी उस जीवनशैली से है, जिसने हमें हाड़-मांस के संवेदनशील इंसान से एक 'मशीन' में तब्दील कर दिया है। इस मशीनीकरण के खिलाफ सबसे पहली और अनिवार्य क्रांति हमारी रसोई और हमारी थाली से शुरू होनी चाहिए। हमें अपने खानपान में 'घर वापसी' करनी होगी। पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण की चकाचौंध में हमारी थाली से पोषण गायब हो गया और केवल स्वाद हावी हो गया। नववर्ष में आइए हम अपनी जड़ों की ओर लौटें और अपनी भारतीय परंपरा में 'मिलेट्स' यानी श्री अन्न (बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो) का जो सम्मानजनक स्थान था, उसे पुनः स्थापित करें। आज के समय में दूषित भोजन से भी ज्यादा खतरनाक वह 'डिजिटल भोजन' है जो हम अनजाने में अपनी आंखों और दिमाग को हर पल खिला रहे हैं। आज का इंसान और विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी, अनिद्रा, गंभीर मानसिक तनाव, एंग्जायटी और डिप्रेशन की जिस अदृश्य महामारी से जूझ रही है, उसका सीधा और गहरा संबंध हमारी हथेलियों में रखे मोबाइल फोन से है। रात का सन्नाटा, जो कभी गहरी नींद, शरीर की मरम्मत और मानसिक शांति के लिए बना था, अब मोबाइल की नीली रोशनी (ब्लू लाइट) और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन की 'टिंग-टिंग' ने छीन लिया है।हम बिस्तर पर लेटने के बाद भी सोने की बजाय, एक के बाद एक 'रील्स' या 'शॉर्ट्स' सरकाते रहते हैं। यह लत हमारे दिमाग में डोपामाइन का ऐसा चक्रव्यूह रचती है जो मस्तिष्क को लगातार उत्तेजित रखता है, जिससे हमें वह गहरी नींद (डीप स्लीप) नहीं मिल पाती, जो हमारे स्वास्थ्य का आधार स्तंभ है। हमें यह कठोर व्रत लेना होगा कि सोने से कम से कम एक घंटा पहले हम इस डिजिटल दुनिया का द्वार बंद कर देंगे और अपने दिमाग को शांत होने का मौका देंगे। अब वक्त आ गया है कि हम 'डिजिटल फास्टिंग' की नई अवधारणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अब मानसिक शांति के लिए तकनीक का त्याग अनिवार्य हो गया है। सप्ताह में कम से कम एक दिन या दिन में कुछ घंटे ऐसे जरूर हों जब हम पूरी तरह 'ऑफलाइन' हों। यह वह समय हो जब हम किसी स्क्रीन को नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों की आंखों में देखकर बात करें, बच्चों के साथ खेलें या बस खामोश बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें। यह डिजिटल डिटॉक्स आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम साबित नहीं होगा और रिश्तों में आई दूरी को पाटने का काम करेगा। हमारी जिम्मेदारियां केवल खुद तक सीमित नहीं हैं।

प्रेरणा

अगर आपके इरादे नेक हों तो चाहे जो हो जाए, आप किसी का साथ नहीं खोते हैं। -निप्से हसल

संपादकीय

भारत में होने जा रही एआई समिट के क्या मायने हैं

एआई इम्पैक्ट पर शिखर वार्ता के चौथे चरण की मेजबानी भारत 15-20 फरवरी के बीच करेगा। इसमें भाग लेने के लिए चीन को भी निमंत्रण भेजा गया है। पहले के तीन चरण यूके, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में हुए थे। भारत की मेजबानी का मतलब है कि यह बैठक ग्लोबल साउथ में पहली बार आयोजित होगी। इन बैठकों का उद्देश्य दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में एआई के खतरों और प्रभावों को लेकर संस्थाओं और नियमों का निर्माण करना और उन पर वैश्विक सर्वसम्मति बनाना है। इस बीच एआई टेक्नोलोजी के प्रणेताओं में से एक सैम आल्टमैन ने एक बार फिर अपने बयानों से चौंकाया है। एआई के भावी खतरे का ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलोजी से सिक्योरिटी के अलावा मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक निर्भरता और बेरोजगारी का संकट बढ़ सकता है। आल्टमैन अपनी कंपनी के लिए एक पद का सृजन कर रहे हैं, जिसे हेड ऑफ प्रिपेयर्डनेस कहा जाएगा। यह एआई के दुष्परिणामों से बचने का खाका तैयार करेगा। एआई के इस्तेमाल के लिए भारत सहित दुनिया का हर देश अपने को तैयार तो कर रहा है लेकिन श्रमिक-बाहुल्य वाले विकासशील देशों में ऐसी तकनीकी को लाने से पहले बारीकी से परखना होगा। एआई से उत्पादन और डिलीवरी लागतें घटेंगी, लेकिन अगर इससे बेरोजगारी बढ़ती है तो उसकी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

जो रिश्ते आपके पास उपलब्ध हों, उनको बचाए रखिए

अत्यधिक व्यस्त लोगों को एक युद्ध प्रतिदिन अपने ही समय से लड़ना पड़ता है। हम जितने व्यस्त होंगे, समय उतना कम पड़ेगा। जो कुछ भी समय आपके पास है और जो समय ईश्वर ने दिया है, उसमें टकराहट होगी। कहते हैं कि समय और जमाना तेजी से बदल रहा है, लेकिन कम या ज्यादा नहीं हो रहा। समय 24 घंटे ही रहेंगे। तो हम जमाने के साथ बदल नहीं पाएंगे। और जो भी 24 घंटे हैं, उनका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे प्रयोग लोग करते हैं, अपनी व्यस्तता के साथ। जब आप समय के साथ दौड़ रहे हों तो उसको व्यस्तता कहेंगे। जब आप समय से आगे दौड़ने की कोशिश करेंगे, उसको अति-व्यस्तता कहेंगे। ऐसे समय एक प्रयोग कर सकते हैं और वो है रिश्तों को थाम लेना। रिश्ते इस दौड़ में आपकी ताकत बनेंगे। क्योंकि जो भी दौड़ेगा, वो थकेगा। और जो भी थकेगा, उसको कोई न कोई सहारा चाहिए। अपनेपन का एहसास बहुत बड़ा सहारा होता है। तो समय का संतुलन बैठाने में रिश्ते बहुत मददगार होंगे।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

दूरदृष्टि • नववर्ष में हमारे देश के लिए एक प्रार्थना

2026 के इस नए साल में हमारा भारत कैसा हो?

आशाएं

राजदीप सरदेसाई
वरिष्ठ पत्रकार
rajdeepsardesai52@gmail.com

'जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो; जहां ज्ञान स्वतंत्र हो; जहां दुनिया संकीर्ण दीवारों से टूटकर टुकड़ों में न बंटी हो स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, मेरे देश को जाग्रत होने दो।' (रबींद्रनाथ ठाकुर)

ये पंक्तियां लिखे जाने के एक सदी से भी अधिक समय बाद भारत के विचार को नई दृष्टि से देखने का समय आ गया है। लिहाजा, इनसे प्रेरित होकर 2026 के भारत के लिए एक प्रार्थना प्रस्तुत है।

एक ऐसा भारत, जो वर्तमान और भविष्य को रियर-व्यू मिरर से देखकर न तय करे। जहां हमारे सांसद इस पर बहस में घंटों न बिताएं कि 1930 के दशक में वंदे मातरम् से किसने कौन-सा अंतरा हटाया था या 1950 के दशक में नेहरू ने क्या किया था, बल्कि इस पर ध्यान केंद्रित करें कि हमारा वर्तमान नेतृत्व एक बेहतर भारत बनाने के लिए आज क्या कर रहा है।

एक ऐसा भारत, जहां वोट जातिगत और धार्मिक विभाजनों को भड़काकर नहीं, बल्कि शासन से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर मांगे जाएं। जहां इतिहास को 'व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी' के पाठ्यक्रम तक सीमित न कर दिया जाए। जहां ध्यान अधिक उपासना-स्थलों के निर्माण पर नहीं, इस पर हो कि कितने गुणवत्तापूर्ण स्कूल और अस्पताल बनाए जा रहे हैं।

एक ऐसा भारत, जहां समुदायों के बीच किसी भी प्रकार के वैमनस्य को केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई के माध्यम से भी अस्वीकार किया जाए। जहां कानून का राज हर नागरिक पर समान रूप से लागू हो। जहां नफरत को इस तरह 'सामान्य' न कर दिया जाए कि समुदायों का 'अन्यीकरण' उनके सामाजिक बहिष्कार का कारण बन जाए।

एक ऐसा भारत, जहां पर्यावरण संरक्षण हर सरकार का मंत्र हो। जहां मुख्यमंत्रीगण एक्यूआई के महत्व को समझें और इसके लिए मिलकर काम करें, ताकि नागरिक स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। जहां पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को बेलगाम खनन और रियल एस्टेट माफियाओं द्वारा नष्ट न किया जाए। जहां जलवायु परिवर्तन केवल सेमिनार कक्षों में बहस का विषय न रह जाए, बल्कि जमीनी कार्रवाई में तब्दील हो।

एक ऐसा भारत, जहां वास्तविक आंतरिक पार्टी-लोकतंत्र हो और असहमति को विद्रोह न माना जाए। जहां ईडी को हथियार बनाकर केवल विपक्ष-शासित राज्यों पर न आजमाया जाए। जहां चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करे। जहां एसआईआर पारदर्शी ढंग से हो और जहां धनबल व संस्थागत-ताकत बराबरी के आदर्श को विकृत न कर दे।

एक ऐसा भारत, जो कश्मीर से केरल तक हर देशवासी को अपनाए। जहां दक्षिण बनाम उत्तर, तमिल बनाम हिंदी जैसे विभाजनों को नकारा जाए। जो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' को नारे से आगे बढ़ाकर वास्तविकता में उतारे। जहां मनुष्य की गरिमा का महत्व जीडीपी से कम न माना जाए। जहां गरीबों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच मिले और समान अवसर हर सरकार का लक्ष्य बने। जहां यह संभव न हो कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएं, जबकि अमीर और प्रभावशाली लोगों की अवैध बसाहटों का बाल भी बांका न हो। जहां हर बड़ी परियोजना चुनिंदा कारोबारियों को न सौंप दी जाए, जबकि अनेक मेहनती उद्यमी 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' की जटिलताओं से जूझते रहें। जहां बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तो उत्सव का विषय हो, लेकिन प्रति व्यक्ति नॉमिनल जीडीपी में 130वें पायदान पर होना भी चिंता का कारण बना रहे।

> **एक ऐसा भारत, जहां नेताओं और नौकरशाहों की ईमानदारी एक मिसाल बन जाए। जहां किसी व्यक्ति का मूल्य उसके ज्ञान से आंका जाए, उसके बैंक-बैलेंस से नहीं। जहां मीडिया की भूमिका एक सजग पहरेदार की हो।**

एक ऐसा भारत, जहां छात्र पेपर लीक और परीक्षा में हेरफेर के शिकार न बनें, जहां परीक्षाएं आपराधिक नेटवर्कों के दबाव में आए बिना पूरी सतर्कता और निष्पक्षता के साथ कराई जाएं, जहां कॉलेजों और विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया योग्यता से संचालित हो, न कि 'सिफारिश' से। जहां कौशल विकास और रोजगार के अवसर साथ-साथ आगे बढ़ें।

एक ऐसा भारत, जहां नेताओं-नौकरशाहों के रूप में ऐसे लोग हों, जिनकी ईमानदारी एक मिसाल बन जाए। जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की संपत्तियों की निगरानी हो। जहां किसी व्यक्ति का मूल्य उसके ज्ञान से आंका जाए, न कि उसके बैंक बैलेंस से। और हां, एक ऐसा भारत, जहां मीडिया की भूमिका एक सजग पहरेदार की हो। जहां सत्ता से असुविधाजनक सवाल पूछना हमारा फर्ज हो। जहां किसी रिपोर्टर का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाए कि वह सच्चाई को उजागर करने का कितना साहस रखता है। स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में, मेरा भारत जाग्रत हो। नववर्ष की शुभकामनाएं! **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

टु द पीपुल• देश में एक-दूसरे से अलग दो तस्वीरें

ईसाइयों पर लगातार बढ़ते हमले कई सवाल उठाते हैं

सौहार्द

डेरेक ओ ब्रायन
राज्यसभा में टीएमसी के नेता
office@derek.in

दृश्य एक : कोलकाता। एक स्त्री नजरें उठाकर देखती हैं तो किसी गीत की धुन को हवा में तेजी से सरक आई ठंडक की चुभन के साथ महसूस करती हैं। इससे पहले कि वे उसे अनुभव कर सकें, वह ओझल हो जाती है। लेकिन वे जानती हैं कि यह खास अहसास 2026 के अंत में फिर लौटेगा। यह वो अनुभूति है, जो पार्क स्ट्रीट (अब मदर टेरेसा सरणी) पर क्रिसमस-थीम वाली रोशनियों के साथ आएगी, पार्कों में बने मंचों पर गूंजते कैरोल्स, फुटपाथों पर बजती धुनों, गिरजाघरों व चैपल्स में। मुख्य सड़क दो रातों के लिए पैदलयात्रियों के लिए खोल दी जाती है। चर्च रोशनी से जगमगा उठते हैं। बहुत कम शहर ऐसे हैं, जो सामुदायिक एकजुटता की इस उत्सवी उमंग की बराबरी कर सकें। कोलकाता में क्रिसमस कोई ऐसा अवसर नहीं है, जो बिना कोई निशान छोड़े चला जाए। यह अपना समय लेता है, ठहरता है और सच्ची खुशियों में भिगो देता है।

कोलकाता क्रिसमस फेस्टिवल अब अपने 15वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। यह 'बोड़ो दिन' की सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाता है। क्रिसमस से नए साल के शुरुआती दिनों तक, यह उत्सव सभी के द्वारा मनाया जाता है। रोशनियां, सजावट, भोजन। कोयर और बैंड उन सभी के लिए प्रस्तुति देते हैं, जो थोड़ी देर रुककर सुनेंगे- और संगीत के साथ मुस्कुराएंगे और झूमेंगे।

दृश्य दो : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान में कहीं। नहीं, यह वो क्रिसमस तो नहीं, जिसे हम जानते हैं। सड़क किनारे सांता क्लॉज की टोपियां बेचकर रोजी-रोटी कमाने वालों को परेशान करना। उन्हें पहनने वालों की पिटाई करना। मॉल्स में लगे क्रिसमस ट्री गिरा देना। नए साल के लिए लगाई गई सजावट को तहस-नहस करना। प्रार्थना में डूबे एक समुदाय को धमकाना।

ये दो तस्वीरें एक-दूसरे से कितनी अलग हैं!

वरिष्ठ जेसुइट पादरी फादर सेड्रिक प्रकाश ने इस स्तम्भकार से कहा : आज भारत में ईसाइयों के साथ जो हो रहा है, वह न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि असंवैधानिक भी है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री यह दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है और क्रिसमस के दिन चर्चों में जाते हैं और दूसरी तरफ क्रिसमस से जुड़े धार्मिक-सामाजिक प्रतीकों पर होने वाले हमलों की निंदा तक नहीं करते। भारत में कैथोलिक बिशपों के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख ने भी एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा : शांतिपूर्ण कैरोल गायकों और चर्चों में एकत्रित श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया है, जिससे कानून का पालन करने वाले नागरिकों में भय और पीड़ा की भावना पैदा हो गई है। ऐसी घटनाएं हमारे संविधान की आत्मा को गहरे आघात पहुंचाती हैं। मैं घृणा और हिंसा के इन कृत्यों की घोर निंदा करता हूं।

बहरहाल, ईसाई समुदाय को केवल 'नकारात्मक कारणों' से ही सुर्खियों में खिंच जाने के जाल में नहीं फंसना चाहिए। सकारात्मक संदेश ही कुंजी है। इस समुदाय ने विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर वर्ष देश भर में ईसाई-संचालित 54,000 शैक्षिक संस्थानों में सात करोड़ छात्र नामांकित होते हैं। इनमें पढ़ने वाले हर चार में से कम से कम तीन छात्र गैर-ईसाई हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई मंत्री ईसाई-संचालित संस्थानों के पूर्व छात्र रहे हैं- जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अतीत में लालकृष्ण आडवाणी भी। वहीं इस समुदाय द्वारा संचालित स्वास्थ्य संस्थान भारत की लगभग दो प्रतिशत आबादी को सेवाएं प्रदान करते हैं। इस कार्य का 80% दूरदराज और चिकित्सकीय रूप से वंचित क्षेत्रों में किया जाता है। महामारी के दौरान, एक हजार से अधिक अस्पतालों में 60,000 इन-पेशेंट बिस्तर उपलब्ध कराए गए। 3,500 से अधिक संस्थानों के साथ कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा गैर-सरकारी स्वास्थ्य नेटवर्क है।

> **किसी अदालत में आपको दोषसिद्धि का ऐसा मामला नहीं मिलेगा, जिसमें जबरन धर्मांतरण कराया गया हो। यह दुष्प्रचार है। देश में हर साल ईसाइयों पर हमलों के 600 मामले दर्ज होते हैं। न्यायपालिका भी मौन रही तो हमारी रक्षा कौन करेगा?**

सर्वोच्च अदालत के एडवोकेट कोलिन गोन्जाल्विस स्पष्ट करते हैं कि किसी भी अदालत में आपको दोषसिद्धि का ऐसा मामला नहीं मिलेगा, जिसमें जबरन किसी का धर्मांतरण कराया हो। यह सब राजनीतिक दुष्प्रचार है। आज देश में हर साल ईसाइयों पर हमलों के 600 मामले दर्ज होते हैं। अगर न्यायपालिका भी मौन साधे रही तो हमारी रक्षा कौन करेगा?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

ब्रांड से सबक | American Airlines | अमेरिकन एयरलाइंस, एविएशन कंपनी

2011 में दिवालिया होने वाली थी, आज 60 से ज्यादा देशों में सेवाएं, शीर्ष एयरलाइंस में शुमार 'अमेरिकन'

2012, अमेरिकन एयरलाइंस (एए) के सीईओ टॉम हर्टन कंपनी को अकेले बचाने की कोशिश कर रहे थे। नवंबर 2011 में कंपनी चैप्टर-11 के तहत खुद को दिवालिया घोषित करने का आवेदन कर चुकी थी। हालांकि हर्टन किसी भी तरह के मर्जर के सख्त खिलाफ थे। तभी यूएस एयरवेज के सीईओ डग पार्कर ने अमेरिकन एयरलाइंस की तीन बड़ी यूनियन के नेताओं के साथ गुप्त बैठक कर 'कंडीशनल लेबर एग्रीमेंट' कर लिया। और इस तरह अमेरिकन एयरलाइंस और यूएस एयरवेज का विलय हुआ, जिससे एक बड़ी एयरलाइन कंपनी बनी।

हालांकि तब हैमलिन ट्रांसपोर्टेशन कंसल्टिंग के अध्यक्ष जॉर्ज हैमलिन ने कहा कि 'लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि सिर्फ बड़ा होना ही सफलता की गारंटी देगा। कई पहलुओं को छोड़ना भी पड़ेगा।' दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी अमेरिकन एयरलाइंस की स्थिति बताती है कि परिस्थितियां बड़े से बड़े साम्राज्य को भी धराशायी कर सकती हैं, लेकिन यदि परिस्थितियों को समय रहते भांप लिया जाए तो खुद को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है, जैसा अमेरिकन एयरलाइंस ने किया। खुद को मर्ज कर कंपनी ने कर्ज घटाए, नई नीतियां बनाई और फिर टॉप एविएशन कंपनियों में शामिल हो गई। आज ब्रांड से सबक में पढ़िए कहानी अमेरिकन एयरलाइंस की।

वर्तमान स्थिति

90,575 हजार करोड़ रुपए का मार्केट कैप

आज यह एयरलाइंस 60 से अधिक देशों में सेवाएं दे रही है। वर्तमान में दुनिया की शीर्ष एयरलाइन कंपनियों में शामिल है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार इससे करीब 20 करोड़ यात्री सालाना यात्रा करते हैं। कंपनी के बेड़े में दिसंबर 2025 तक 1015 मेनलाइन एयरक्राफ्ट हैं, जिससे यह करीब 350 से अधिक डेस्टिनेशन तक उड़ान भरती है। वर्तमान में कंपनी का मार्केट कैप करीब 90,575 करोड़ रुपए है।

सबक क्यों- कंपनी ने दिवालियापन को अंत के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे खुद को रीसेट करने के अवसर की तरह इस्तेमाल किया।

20% के करीब हिस्सेदारी है अमेरिका के एयरलाइन उद्योग में।

1015 विमान हैं आज कंपनी के बेड़े में, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं।

350 से अधिक डेस्टिनेशन तक इसकी उड़ानें पहुंचती हैं।

20 करोड़ से अधिक यात्रियों को दुनियाभर में हर साल सेवा प्रदान कर रही है कंपनी।

1930 में लोगों को लुभाने के लिए अमेरिकन एयरलाइंस ने कुछ इस तरह के पब्लिसिटी फोटोग्राफ जारी किए थे।

यूं संकट में फंसी थी 'एए'

1. **ईंधन के दामों में बढ़ोतरी-** 2000 के दशक में क्रूड ऑइल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे एयरलाइंस का ईंधन पर होने वाला खर्च बढ़ा। लाभ लगातार कम होता चला गया।
2. **भारी कर्ज, नगदी का संकट-** 2011 तक कंपनी पर करीब 3000 करोड़ डॉलर की देनदारी थी, जबकि उसकी संपत्ति की कीमतें लगातार गिर रही थीं।
3. **प्रतिस्पर्धियों का विलय :** 2006 से 2009 के आसपास अमेरिकी एयरलाइन उद्योग में बड़े विलय हुए, जैसे डेल्टा और नॉर्थवेस्ट का विलय। इन विलयों ने बड़ी और बेहतर एयरलाइंस का निर्माण किया, जिनके पास बेहतर नेटवर्क और लागत कम थी।
4. **अधिक श्रम लागत-** 2011 तक अमेरिकन एयरलाइंस एकमात्र ऐसी प्रमुख एयरलाइन कंपनी थी, जिसने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ी कटौती नहीं की। इससे उसकी श्रम लागत बढ़ती गई।

इस तरह की वापसी

1. **यूएस एयरवेज के साथ मर्जर-** अमेरिकन एयरवेज ने 2013-15 के बीच यूएस एयरवेज के साथ खुद को मर्ज कर लिया, जिससे उसका बेड़ा बड़ा हुआ। नेटवर्क और नए मार्गों का हब बना।
2. **बेड़े का आधुनिकीकरण-** कंपनी ने एयरबस A321neos और बोइंग 737 मैक्स जैसे ईंधन किफायती एयरक्राफ्ट अपनाए। इससे खर्च घटा।
3. **लेबर रीस्ट्रक्चरिंग-** दिवालियापन की प्रक्रिया के दौरान कंपनी को अपने पुराने और महंगे लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स को रीस्ट्रक्चर करने की कानूनी ताकत मिली। कंपनी ने कर्मचारियों के साथ नए समझौते किए, जिससे सालाना करोड़ों डॉलर बचे।
4. **कर्ज प्रबंधन और निवेश-** दिवालियापन की प्रक्रिया के बाद कंपनी ने कर्ज को रीस्ट्रक्चर किया। नए निवेशकों और बेहतर वित्तीय साख के साथ कंपनी ने बाजार से कम ब्याज दरों पर पूंजी जुटाई।

अमेरिका की तीन बड़ी एविएशन कंपनियों में से एक है 'एए'

शुरुआत : विमान से डाक ढोने वाली 85 कंपनियों ने रखी थी नींव

1920 के दशक में अमेरिका में छोटे विमानों का उपयोग डाक बांटने के लिए भी किया जाता था। 1930 में ऐसी करीब 85 छोटी कंपनियों ने मिलकर बड़ी होल्डिंग कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा 'द एविएशन कॉर्पोरेशन।' इसने खुद को अमेरिकन एयरवेज के रूप में ब्रांड किया। 1934 में इसकी यात्री सेवा को 'अमेरिकन एयरलाइंस' कर दिया गया। सी.आर. स्मिथ इसके प्रेसिडेंट बने।

गिरावट : ईंधन के ज्यादा दाम, अधिक खर्च से बढ़ा संकट

2008-2009 की मंदी के दौरान ईंधन की कीमतें अत्यधिक बढ़ गईं। कंपनी के बेड़े में कई तरह की मशीनें थीं, जिससे मेंटेनेंस और ट्रेनिंग लागत बढ़ी। खर्च की तुलना में ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाएं घटती गईं। वहीं प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने सस्ती सुविधाएं ग्राहकों को देनी शुरू कीं, जिससे नुकसान बढ़ता गया और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई।

ऐसे पड़ा नाम : अमेरिका में 1934 में पारित 'एयरमेल एक्ट' से होने वाली कानूनी समस्याओं से बचने के लिए इसका नाम 'अमेरिकन एयरलाइंस इंक' किया गया।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : अमेरिकन एयरलाइंस के मुख्य प्रतिद्वंद्वी डेल्टा और यूनाइटेड एयरलाइंस हैं। 'बिग थ्री' में ये तीनों शामिल हैं।

पीपुल भास्कर | थलापति विजय | दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपर स्टार

माता-पिता पर मुकदमा कर चुके, 32 गाने गाए फुटबॉल के भी शौकीन हैं सुपर स्टार विजय

सितंबर 2021, दक्षिण भारत के सुपर स्टार थलापति विजय ने पिता एस. चंद्रशेखर और मां शोभा सहित 11 लोगों के खिलाफ राजनीतिक उद्देश्य के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करने के आरोप में मुकदमा दायर कर दिया था। अपने एक बयान में विजय ने कहा 'मैं अपने प्रशंसकों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे पिता द्वारा शुरू की गई पार्टी में शामिल न हों। यदि कोई भी मेरे नाम, फोटो या मेरे फैन क्लब का दुरुपयोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए करने का प्रयास करता है, तो मैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करूंगा।

विजय की प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके फैंस ने ही उन्हें 'इलैयाथलापति' की उपाधि दी है। इसमें इलैया का अर्थ युवा और थलापति का अर्थ लीडर है। यानी युवाओं का लीडर। विजय तमिल फिल्मों के सर्वाधिक फीस लेने वाले एक्टर हैं।

2024 में आई उनकी फिल्म GOAT (The Greatest of All Time) के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए फीस ली थी। 'जन नायगन' के लिए वे करीब 275 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं। 2017 में आई इनकी फिल्म 'मेर्सल' जापान के चार बड़े शहरों में रिलीज की गई। इसके अलावा चीन में भी इसे बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में तो इसका प्रीमियर भी आयोजित किया गया था। उनकी फिल्में 80 देशों में रिलीज की जा चुकी हैं। विजय को फुटबॉल और क्रिकेट का शौक है।

चर्चा में क्यों- राजनीतिक करियर बनाने के लिए उन्होंने हाल ही में फिल्में छोड़कर पूरी तरह समाजसेवा में आने का निर्णय किया है।

तस्वीर अगस्त 2020 की है, जब विजय ने अभिनेता महेश बाबू के 'ग्रीन चैलेंज' में हिस्सा लेकर पौधे लगाए थे।

थलापति विजय के पिता एस. ए. चंद्रशेखर पहले ही ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल इयक्कम नाम से एक पार्टी बना चुके हैं। हालांकि इस पर दोनों के मतभेद हुए थे।

जन्म : 22 जून 1974, चेन्नई
शिक्षा : 12वीं
परिवार : पत्नी- संगीता सोरनालिंगम, बेटा- जैसन संजय बेटी- दिव्या शाशा।
संपत्ति : करीब 600 करोड़ रुपए
(विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार)

परिवार
तमिल फिल्मों के नामी निर्देशक हैं पिता

विजय का पूरा नाम जोसफ विजय चंद्रशेखर है। इनका जन्म एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। पिता एस.ए चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के जाने-माने निर्देशक हैं जबकि मां शोभा प्लेबैक सिंगर हैं। उनके पिता ने उन्हें 'वेट्री' फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका दिया। बचपन से ही विजय ने तय कर लिया था कि उनका भविष्य सिनेमा में ही है।

विवाह
फिल्में देखकर फैन बनी संगीता से की है शादी

1996 में उनकी एक फिल्म आई 'पूवी उनक्कागा', जो सुपर हिट हुई। खुश होकर लंदन में रहने वाली तमिल प्रशंसक संगीता उनसे मिलने चेन्नई आई। उसने सिर्फ इतना कहा- 'आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए।' विजय और उनके परिवार को संगीता की यह सादगी पसंद आई। बाद में दोनों में दोस्ती हुई और फिर 1999 में दोनों ने शादी कर ली।

करियर
10 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी एक्टिंग

10 साल की उम्र से ही बाल कलाकार के रूप में इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1992 में विजय ने 'नालय तिरुपू' से लीड शुरुआत की और 1996 की 'पूवी उनाक्कगा' से स्थापित कलाकार बन गए। फिल्म 'गिली' ने उन्हें मास हीरो बनाया। विजय अब तक 69 फिल्मों में काम कर चुके हैं। 'जन नायगन' उनकी आखिरी फिल्म है।

रोचक : राजनीति में भी उतरे, टीवीके नामक पार्टी बनाई

खास : 400 क्रू मेंबर्स को बांटी थीं सोने की अंगूठियां

- उनके संगठन विजय पीपुल ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में विजय एजुकेशन अवॉर्ड शुरू किया।
- बिगिल फिल्म की सफलतापूर्वक शूटिंग होने के बाद 400 क्रू मेंबर्स को विजय सोने की अंगूठियां दान कर चुके हैं।
- अब तक 10 से अधिक फिल्मों में उनके पात्र का नाम विजय रखा जा चुका है।

उपलब्धि : फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सूची में शामिल रहे

- फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में कई बार नाम शामिल हो चुका है।
- थलापति विजय एक अच्छे प्लेबैक सिंगर भी हैं। अब तक 32 गाने गा चुके हैं।
- विजय ने 2024 में राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रखा और तमिलगा वेट्री कड़गम (टीवीके) नाम से अपनी पार्टी बनाई।

विवाद : मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया था 1 लाख का जुर्माना

- 2022 में मद्रास हाई कोर्ट ने उन पर रॉल्स रॉयस कार का टैक्स नहीं चुकाने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया था। कार इंग्लैंड से लाई गई थी।
- इनकी फिल्म बिगिल सबसे विवादित फिल्म है। उनकी इस फिल्म के लिए कॉन्सेप्ट चोरी का आरोप लगा था। यह आरोप सहायक निर्देशक केपी सेल्वा के द्वारा लगाया गया था।

दैनिक ट्रिब्यून
स्थापना 15 अगस्त 1978

मेहनतकशों की बेकद्री

गिग-वर्कर्स की मांगों को गंभीरता से लें

बाजार आने-जाने के झंझट से बचा लोगों के घरों में तुरत-फुरत जीवन उपयोगी सामान पहुंचाने वाले गिग-वर्कर्स की जटिल कार्यपरिस्थितियां और पसीने का मोल न मिलना, बेहद चिंता की बात है। अपना व परिवार का पोषण करने वाले ये युवा अकसर सरपट मोटरसाइकिल दौड़ाते और सीढ़ियां चढ़कर ऊंची मंजिलों में दरवाजों तक सामान पहुंचाते देखे जा सकते हैं। बेहद कम मेहनताने, कंपनी मालिकों के दबाव व ग्राहकों की उपेक्षा झेलते गिग वर्कर्स ने नये साल की पूर्व संध्या पर हड़ताल करके अपनी बदहाली को ही उजागर किया है। संवेदनशील कार्य परिस्थितियों और नौकरी की असुरक्षा के चलते गिग-वर्कर्स हड़ताल पर थे। हालांकि, नये साल पर काम के दबाव व पूरी तरह संगठित न होने के कारण इनकी हड़ताल का कुछ ही इलाकों में असर देखा गया। पूरे देश में सामान की आपूर्ति बाधित हुई हो, ऐसा भी कोई समाचार नहीं मिला है। लेकिन गिग-वर्कर्स की विषम कार्य-परिस्थितियों की ओर पूरे देश का ध्यान जरूर गया है। पिछले दिनों आप के राघव चड्ढा और राजद के मनोज कुमार झा जैसे सांसदों ने गिग वर्कर्स के शोषण का मुद्दा संसद में उठाया था। निस्संदेह, देश की गिग अर्थव्यवस्था ने रोजगार सृजन में अपनी क्षमता साबित की है। विडंबना है कि भारत युवाओं को देश का कहा जाता है, लेकिन हम उनकी आकांक्षाओं का रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल, गिग-वर्कर्स की प्रमुख मांग है कि उनके काम का बेहतर भुगतान हो और उनके लिये बेहतर कामकाजी परिस्थितियां बनायी जाएं। उनकी इस हड़ताल ने इन मुद्दों पर देश का ध्यान खींचा है। लेकिन देश के प्रमुख खाद्य वितरण करने वाली कंपनी ने 31 दिसंबर को इस हड़ताल के बावजूद ऑर्डर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। वहीं थके-हारे बाइकर्स अपनी अनगिनत शिकायतें व्यक्त करते रहे। दरअसल, विडंबना यह है कि खूब काम लेने के बावजूद गिग-वर्कर्स को पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी के दायरे से बाहर आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

दरअसल, गिग-वर्कर्स को नई अर्थव्यवस्था में नियोक्ता एक कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने के दायित्व से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन नियोक्ताओं की हायर व फायर की रणनीति के चलते, वे असुरक्षित कार्य परिस्थितियों में काम करने को बाध्य होते हैं। इसके बावजूद वे आज शहरी जीवन व्यवस्था के लिये अभिन्न अंग बन गए हैं। लोगों की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दौड़ते रहते हैं। वे सामान दस मिनट तक दरवाजे पर पहुंचाने के दबाव में हांफते-भागते, मोटरसाइकिल दौड़ाते और सीढ़ियों पर सामान चढ़ाते अकसर नजर आते हैं। आम तौर पर उपभोक्ताओं का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। देरी होने पर इन्हें झिड़का जाता है। सामान में नुक्स निकालकर इन्हें दौड़ाया जाता है। आज भारत में इनकी संख्या सवा करोड़ से अधिक है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इन कामगारों की संख्या दो करोड़ पैंतीस लाख तक हो सकती है। निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि मेहनताने में कटौती, जरा सी चूक पर आर्थिक दंड तथा समय से पहले पहुंचाने के दबाव से गिग-वर्कर्स त्रस्त हैं। मुश्किल परिस्थितियों में काम करते रहने के बावजूद ये कामगार हड़ताल में बड़ी संख्या में भाग नहीं ले पाये। दरअसल, प्लेटफॉर्म अकसर प्रोत्साहन और अतिरिक्त वेतन के जरिये श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन को दबा देते हैं। निश्चित रूप से गिग-वर्कर्स का लगातार 14 घंटे काम करने के बावजूद सात-आठ सौ रुपये कमाना और दुर्घटना बीमा से वंचित रखना, इस व्यवस्था की उन खामियों की ओर भी इशारा करता है, जिन्हें केवल फौरी लालच या प्रोत्साहन से ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे में हालिया श्रम सुधारों का महत्व बढ़ जता है। जिसमें पहली बार, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानून के तरह औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। एग्रीगेटर के टर्नओवर का एक से दो फीसदी सामाजिक सुरक्षा कोष में अनिवार्य योगदान और आधार से जुड़े सार्वभौमिक खाता नंबर को कानूनी मान्यता की दिशा में एक लंबे समय से प्रतीक्षित बदलाव का संकेत देते हैं। हालांकि, कार्यान्वयन ही यह निर्धारित करेगा कि ये सुधार परिवर्तनकारी साबित होते हैं या केवल प्रतीकात्मक रहते हैं।

आज का विचार

यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ेगा।
- जेम्स ऐलन

एकदा

प्रतिभा के चिन्ह

एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से जिज्ञासावश पूछा, 'आपकी खोजपूर्ण दृष्टि को मेरा डील-डौल इतना विशेष क्योंकर लगा था?' चाणक्य ने रहस्यपूर्ण मुखाकृति को सरल करते हुए बताया, 'किशोर चंद्रगुप्त, तुम मुझे शासक का स्वांग रचते हुए ही मिले थे। जंगल में तुम राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। कम वयस में भी तुममें शासक जैसा संतुलन और सूझ-बूझ थी। ऐसी समझ और आत्मविश्वास, मजबूर जीवन जीने वाले में नहीं, बल्कि अपने माहौल को समझने वाले में ही मिल सकता है। तुम बंधकर रहने वाले नहीं, सम्राट बनकर विस्तार पाने वाले हो, चंद्रगुप्त। यह तुमने सिद्ध भी कर दिया है।' चाणक्य की बात सौ प्रतिशत सही थी।

प्रस्तुति : मुग्धा पांडे

40 साल पहले

दैनिक ट्रिब्यून

पंजाब के हालात से केंद्र दुखी

नयी दिल्ली, 1 जनवरी (प्रेट्र)। आज यहां सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में हाल की वृद्धि पर अपनी गंभीर चिंता से राज्य के मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला को अवगत करा दिया है। कल जब बरनाला आंतरिक सुरक्षा राज्यमंत्री अरुण नेहरू से मिले तो नेहरू ने उन्हें बताया कि पंजाब की कानून-व्यवस्था की स्थिति से केंद्र अप्रसन्न है। राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए हुई डेढ़ घंटे की इस बैठक में बरनाला ने प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गये विभिन्न कदमों के बारे में बताया।

कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या

चंडीगढ़ (वार्ता)। आतंकवादियों ने आज रात लुधियाना से पटियाला जा रही एक बस में एक पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी तथा एक अन्य को घायल कर दिया। इसके बाद वे दोनों कांस्टेबलों की स्टेनगनें छीनकर भाग गये। यहां प्राप्त सरकारी सूचना के अनुसार पांच आतंकवादियों ने पेप्सू सड़क परिवहन निगम की बस नंबर पीयूके 7095 में यात्रा करते समय फायरिंग की, जिससे कांस्टेबल प्रेम सिंह मारा गया और दूसरा कांस्टेबल रामलाल घायल हो गया।

अदावत को दोस्ती में बदलने की कूटनीतिक पहल

पुष्परंजन

जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफ़ीकुर रहमान ने भारतीय राजनयिकों के साथ मुलाक़ात की बात मानी है। यह ख़बर जंगल में आग की तरह फैली है। बांग्लादेश स्थित जमात-ए-इस्लामी को भरोसे में लेने की ज़रूरत और भारतीय विदेशमंत्री एस. जयशंकर का पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया के जनाजे में शामिल होना, ये दो घटनायें सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को असहज किये हुए है। मोहम्मद यूनुस चुनाव तक बांग्लादेश में बतौर 'गेस्ट आर्टिस्ट' हैं, बाद के दिनों में वो राष्ट्रपति बनेंगे, या मार्गदर्शक मंडल में शामिल होंगे? यह सवाल अधर में लटका पड़ा है। रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू में, जमात अमीर ने कहा कि जब मैं बीमार था, जैसे दूसरे देशों के राजनयिक मुझसे मिलने आए, वैसे ही दो भारतीय राजनयिक भी कुशल-क्षेम के वास्ते मेरे घर आए थे। मैंने उनसे वैसे ही बात की, जैसे दूसरों से की थी।

जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफ़ीकुर रहमान ने कहा, 'भारतीय राजनयिकों ने अनुरोध किया कि इस दौरे को सार्वजनिक न किया जाए। आगे भी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय हितों से जुड़ी भविष्य की कोई भी बैठक की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी।' जमात प्रमुख शफ़ीकुर रहमान ने पुष्टि की, कि मैंने अपनी बाईपास सर्जरी के बाद सितम्बर, 2025 की शुरुआत में एक भारतीय राजनयिक से मुलाकात की थी। अब सवाल यह है, कि क्या जमात लीडरशिप बीएनपी नेताओं के सम्बन्ध भारत के साथ सॉफ्ट करने में कोई भूमिका निभा रही है? यह भी एक क़िस्म की 'पोलिटिकल बाईपास सर्जरी' है, जिससे मुहम्मद यूनुस के रणनीतिकार अनजान थे।

जमात ने आखिरी बार 2001 और 2006 के बीच बीएनपी के साथ एक जूनियर गठबंधन सहयोगी के रूप में सत्ता संभाली थी, और वह फिर से उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। बाहर से यही दिख रहा था कि भारत विरोधी माहौल बनाने में जमात पाकिस्तान के इशारों पर यह सबकुछ कर रहा था, लेकिन अब वो क्यास कथा पलटती दिख रही है। बांग्लादेश में हिन्दू विरोधी माहौल से देश, और देश से बाहर किस-किस को फायदा मिलता है? इस बारे में डिप्लोमेट तो खुलकर बोलेंगे नहीं, लेकिन यह विश्लेषण का विषय है। बुधवार को, जिस तरह का हुजूम बेग़म ख़ालिदा ज़िया के जनाजे में दिखा, वो इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) एक बार फिर सियासी पारी खेल सकती है। सबका यही अनुमान था कि चुनाव तक बांग्लादेश में जो पार्टियां मैदान में हैं, वो हिन्दुओं को निशाने पर लेते हुए, भारत विरोधी विष वमन करेंगी। लेकिन, किसी ने सोचा नहीं था कि इस बीच बीएनपी की सर्वोच्च नेता ख़ालिदा जिया को सिपुर्द-ए-खाक़ करने की सूरत बन आएगी, और भारतीय विदेशमंत्री शोक और दोस्ती का पैगाम लेकर ढाका जायेंगे।

> विश्लेषकों ने माना है, कि एस. जयशंकर को ढाका भेजने का फैसला कूटनीतिक परिपक्वता का परिचायक है। एस. जयशंकर ढाका जितने समय थे, उन्होंने मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से मिलने की ज़हमत नहीं उठाई।

विश्लेषकों ने माना है, कि एस. जयशंकर को ढाका भेजने का फैसला कूटनीतिक परिपक्वता का परिचायक है। एस. जयशंकर ढाका जितने समय थे, उन्होंने मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से मिलने की ज़हमत नहीं उठाई। इससे साफ़ संदेश जा रहा था, कि भारत सरकार की दिलचस्पी देश के अस्थायी व्यस्थापक में कतई नहीं है।

पीएम मोदी अदावत को दोस्ती में बदलने की कला में माहिर राजनेता हैं। उसका एक और उदाहरण बुधवार को देखने को मिल गया। जून, 2015 में बांग्लादेश यात्रा के दौरान, मोदी ने खालिदा ज़िया से मुलाकात की, जो उस समय विपक्ष की नेता थीं। दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक बताया, मोदी ने बाद में इसे एक 'गर्मजोशी भरी मुलाकात' के रूप में याद किया। उसी मुलाक़ात का हवाला मोदी के पत्र में था, जो उनके बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को अपने विदेशमंत्री के माध्यम से भेजा था।

बांग्लादेश से भारत के सम्बन्ध उतार-चढ़ाव वाले ही रहे हैं। सैन्य शासन के पंद्रह साल की अवधि के दौरान, भारत और बांग्लादेश ने एक-दूसरे को बड़े पैमाने पर सुरक्षा अनिश्चितता की दृष्टि से देखना शुरू किया था। दोनों देशों ने एक-दूसरे के क्षेत्र में विद्रोहियों को गुप्त समर्थन दिया। नई दिल्ली ने बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में शांति वाहिनी का समर्थन किया। इस बीच, ढाका ने भारत के उत्तर-पूर्व में विद्रोहियों को हथियारों की खेप पहुंचाने में मदद की, और उन्हें बांग्लादेशी धरती पर शिविर स्थापित करने की अनुमति दी।

ज़िया की बीएनपी सरकार को भी भारत विरोधी ही माना जाता था। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान और चीन के साथ रक्षा सौदों को बढ़ावा दिया गया, जो भारत के लिए चिंता का विषय था। उन्होंने भारतीय ट्रकों के लिए बांग्लादेश से होकर जाने वाले ट्रांजिट को 'गुलामी' बताया और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए भारत को ट्रांजिट अधिकार देने से इनकार कर दिया। खालिदा जिया पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी समूहों को पनाह देने, और आईएसआई के साथ सांठगांठ के आरोप लगे। बेग़म ज़िया ने 1972 की भारत-बांग्लादेश मैत्री संधि और 1996 की गंगा जल संधि को 'गुलामी की संधि' और 'गुलामी का सौदा' करार दिया था।

सबके बावजूद, शेख हसीना से दोस्ती के पुराने दिन याद करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब वो नई दिल्ली के लिए गले की हड्डी बन चुकी हैं। इस बार अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अर्थात, बांग्लादेश में भारत के लिए अवामी लीग के रूप में कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश की राजनीति में जो विकल्प दिखते हैं, उन्हीं के साथ भारत को संबंध दुरुस्त करने होंगे। डिप्लोमेटिक सूत्र इस बात की पुष्टि करते हैं, कि भारतीय राजनयिकों ने लंदन प्रवास के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान के साथ अनौपचारिक संपर्क बना रखा था। इसलिए एस. जयशंकर का ढाका जाना, आपदा में अवसर जैसा ही था।

बीएनपी नेता तारिक़ रहमान के लन्दन से लौटने के बाद, जितनी तेज़ रफ्तार से सियासी मौसम में बदलाव आया है, उससे मुहम्मद यूनुस की सरपरस्ती वाले छात्र नेता असमंजस में हैं। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने 28 फरवरी, 2025 को नेशनल सिटीजन पार्टी की स्थापना की थी। नाहिद की नेशनल सिटीजन पार्टी सत्ता में आने के सपने देखने लगी थी। संभवतः इनके लिए ही मुहम्मद यूनुस ने दिसंबर के बदले दो माह आगे चुनाव टाल दिया था। कहने को जमात से जुड़ा 'इस्लामी छात्र शिबिर' के नेता अबू शादिक 'कायेम' और बीएनपी के छात्र नेता रकिबुल इस्लाम राकिब भी आंदोलन में परिचित चेहरे थे। एक और छात्र संगठन 'इंकलाब मंच' के सह-संस्थापक शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद, बीएनपी ने इनके घावों पर मरहम लगाना शुरू किया है। ऐसे में लगता नहीं कि छात्र नेता किसी लीड रोल में नमूदार होंगे।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

क्लाइमेट रेजिलियंस

आपदाओं से उबरने की क्षमता में वृद्धि जरूरी

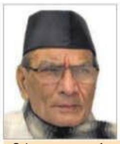

वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

> जलवायु बदलाव के चलते मध्य हिमालय क्षेत्र में मौसमी अतिरेक से आपदाएं बार-बार आ रही हैं। जिससे प्रकृति, बुनियादी ढांचा व मानव जीवन प्रभावित हो रहा है। इससे जल्द उबरने को क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

गर्म होती धरा, उससे उपजते वैश्विक जलवायु बदलाव व आपदाएं आकस्मिक व अतिशय घातक होते जा रहे हैं। कृषि, परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण संरचना जैसे क्षेत्रों में इनका प्रतिगामी असर जैविक व भौतिक दोनों पर पड़ा है। इससे बना-बनाया ध्वस्त भी हो जाता है। फिर से सब कुछ सहेजना मुश्किल होता है। आकस्मिक आपदाओं की निरंतरता के बीच हर क्षेत्र में क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने का मुद्दा केन्द्र में आ गया है।

मध्य हिमालय में जलवायु बदलाव के दो-तीन बड़े असर जाड़ों में भी वनों में आग, बादल विस्फोट, ग्लेशियर टूटने, ग्लेशियर झीलें बनने व ग्लेशियर पीछे खिसकने तथा अपनी मोटाई खोने के रूप में दिखते हैं। हिमस्खलन, भूस्खलन व दावानल की घटनायें बढ़ी हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष भी बढ़े हैं।

सालों से ऐसा हो रहा है कि एक आपदा के बाद संभल नहीं पाते, दूसरी आ जाती है। उत्तराखंड 2025 में भी भारी आपदाग्रस्त रहा। इनसे हुई क्षति की आपूर्ति तो दूर की बात, अभी कहीं-कहीं बीते दशक की आपदाओं में क्षतिग्रस्त कई पुल व सड़कें भी अब तक नहीं बनाई जा सकी हैं। जरूरी है जल्दी से जल्दी सब कुछ सामान्य हो। उत्तराखंड व हिमाचल जैसे राज्यों को क्लाइमेट रेजिलियंस पर काम करने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में देहरादून में बीते 13 व 14 अक्तूबर को 'उत्तराखंड में जलवायु बदलाव रेजिलियंस पर मिलजुल कर कार्यवाही - राष्ट्रीय विचार विमर्श' आयोजित किया गया था। सहमति के बिंदुओं पर आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। क्लाइमेट रेजिलियंस किसी भी प्रणाली व जैविक-अजैविक एकांशों की वह क्षमता है जिससे जलवायु बदलाव प्रेरित अतिवृष्टि,अतिताप, अतिशीत अति बवंडर व समुद्री तूफानों की घटनाओं के आघातों-व्यवधानों से उबरकर वह पहले जैसी भूमिका निर्वहन में सक्षम हो जाता है।

विकास की निरंतरता के लिये खेती, जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली, सड़कों, परिवहन, भवन, पुल, संचार, स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे क्लाइमेट रेजिलियंट होने चाहिये। खेती क्लाइमेट रेजिलियंट होगी तो किसान की आय व खाद्य सुरक्षा में अनिश्चितता कम होगी। सीवरेज व पेयजल व्यवस्था क्लाइमेट रेजिलियंट होंगे तो स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी। ऐसी ही समस्या है सेनिटेशन सततता की। अतिशय बारिश, भूस्खलन, बाढ़ व सूखे जैसी जलवायु आपदायें सेनिटेशन प्रणालियों पर गंभीर असर डाल रही हैं। ऐसे में शौचमुक्त क्षेत्रों में फिर खुले में शौच होना शुरू हो जाता है। आपदाओं में शौचालय प्रणालियों को अबाधित बनाये रखने के लिये यूनीसेफ अपने वाश स्टाफ को जलवायु बदलाव अनुकूलन रणनीति पर प्रशिक्षण दे रहा है।

आजकल ई-गवर्नेंस व ई-बैंकिंग के साथ उद्योग, व्यवसाय, बैंकिंग व प्रशासकीय व्यवस्थाएं जुड़ी हैं तो क्लाइमेट रेजिलियंसी के मानक ये भी हैं कि बाढ़ आदि आपदा में यदि डाटा क्षतिग्रस्त हो जाएं तो उसकी रिकवरी यथाशीघ्र हो जाये।

क्लाइमेट रेजिलियंस आपदा के बाद की स्थिति का विवेचन है। आघात से उबरने में लगने वाले समय का आकलन है। यदि हम प्रोएक्टिव हों तो पूर्व चेतावनियों से आपदाओं के जोखिम कम कर सकते हैं जैसे बाढ़ या चक्रवाती तूफानों में लोगों को तटों से हटा सकते हैं। ग्लेशियर टूटने या उनमें झील बनने की संभावनाओं की मॉनिटरिंग संभव है।

प्रकृति पर भी जलवायु बदलाव से ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी अतिरेकों व अनिश्चितताओं के कुप्रभाव कम नहीं हैं। प्राकृतिक घटकों की रेजिलियंस पर भी फोकस की जरूरत है। प्रकृति की मदद करेंगे तो प्रकृति क्लाइमेट रेजिलियंस पाने में मदद करेगी। किन्तु पूरे विश्व में ही प्राकृतिक संसाधनों की रेजिलियंस में मानवीय कृत्यों से कमी आई है। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बड़े-छोटे बांध बनाकर अथवा सुरंगों में डाल कर उनके फ्लड प्लेनों पर निर्माण व अन्य अतिक्रमण कर उनके बहावों व फैलावों से नदियों को मिलने वाली रेजिलियंस क्षीण की। बेतरतीब कटान से पहाड़ी ढलानों से भूस्खलनों के जोखिम बढ़ाये। ग्लेशियरों की रेजिलियंस खत्म की उनके निकट तक भारी निर्माण व सड़क बनाकर। वहीं वायु मार्ग में भारी ट्रैफिक के प्रदूषण व कम्पन से। वनों की रेजिलियंस खत्म की आग, प्रदूषण, वन कटान से। जमीन की रेजिलियंस कम की ढलान खत्म करके। खेती की रेजिलियंस नष्ट की लैब निर्मित बीजों व रासायनिक खादों से।

क्लाइमेट रेजिलियंस विधिक, पर्यावरणीय व लैंगिक न्याय से भी जुड़ा विषय है क्योंकि जिनकी आपदा लाने में ना के बराबर भूमिका होती है वे भी इसका दंश झेलते हैं। यह अन्याय ही तो है कि उत्तराखंड के ग्रामीणों की गुहारों को नजरअंदाज किया। मसलन-उनके गांवों के नीचे सड़क या टनल बनाने के लिए बारूद विस्फोट न करें, उनके पुल के नीचे अवैध खनन न करें, उनके गांवों के ऊपर से सड़क कटानों का मलबा नीचे न फेंकें, समीपस्थ बांधों व जलाशयों में अत्यधिक पानी न भरें। इन सब कारणों से सुशासन जरूरी है। ताकि आपदा में टूटे पुल, सड़क स्कूल, अस्पतालों को बनने में सालों साल न लगें। क्लाइमेट रेजिलियंस पाने के लिये प्रभावित व्यक्ति या समुदाय की खुद को उबारने व मनोवैज्ञानिक आघातों से बाहर निकलने की मजबूत इच्छाशक्ति भी जरूरी है।

निस्संदेह क्लाइमेट रेजिलियंस पाने व उपाय अपनाने की क्षमता सामाजिक, आर्थिक और टैक्नॉलोजी तक पहुंच की असमानताओं के कारण अलग-अलग हो सकती है।

लेखक पर्यावरण वैज्ञानिक व सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

तिरछी नज़र

नया साल, तीन यार और श्रीमती का तीसरा नेत्र

मुकेश राठौर

> भाभीजी और बच्चे स्वागत को खड़े थे कि अतिथि देवता आए तो तिलक कर ससम्मान गृह प्रवेश करवाएं। वे बाकायदा आए लेकिन तिलक के नाम पर कपाल चुराने लगे। नहाए के बाल, खाए के गाल और पीए के हाल दिख जाते हैं।

गिरधारी हमेशा से नया साल पुराने दोस्तों संग मनाता आया है। त्योहार मनाने का अपना कायदा है। कुछ त्योहार विद फैमिली तो कुछ 'ओनली विद गाइज' सेलिब्रेट करने के लिए बने हैं। अबकी बार गिरधारी ने सपरिवार घर पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मन बनाया था। ऐसा उसकी श्रीमती से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद संभव हो पाया था।

दोस्त किंकर्तव्यविमूढ़ थे। बात कोई खास नहीं मगर जब चार यार मिलते हैं तो सत्संग से लेकर सियासत तक अच्छी-बुरी सब टाइप की बातें होती हैं। नया साल घर से बाहर शुरू हो तो ही अच्छा। जहां सिर्फ यार की यारी निभाते नींद आ जाए। सूरज चाचू की तीसरी, चौथी... किरण कानों में कड़ककर कहे सुबह हो गई मामू और हम कहे ऐसी भी क्या जल्दी है? घर भी कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन की जगह है लल्लू! मगर कहते हैं न 'दोस्ती इम्तेहान लेती है।' बेचारे दोस्त मन और झक मारकर नया साल गिरधारी के घर मनाने पर राजी हो गए।

मित्रों से मंजूरी मिलते ही मिसेज गिरधारी और बच्चे नए साल की तैयारियों में जुट गए। घर सजने लगा गोया पापा के पट्ठे नहीं पुतिन आ रहे हों। खीर-पूड़ी और 'तायों' से नए साल का पेट फोड़ने की कमरकस तैयारी की गई।

आखिरकार इकतीस दिसंबर वाली शाम आ गई। फोन पर बुलावा पाकर तीनों दोस्त फटफटी पर होके सवार खुशी-खुशी चल पड़े। राह में कल्लू ने यकायक गाड़ी रोकी बोला आया। गया तो फिर आया ही नहीं। मंगत बुलाने गया, वह भी नहीं लौटा। मस्तराम के मन में तरह-तरह की कुशंकाएं जन्मने लगीं। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते मगर शाम का भूला घंटों न लौटे तो उसे क्या कहें? मस्तराम भी ढूंढ़ते चला अफसोस वह भी बैठक में समा गया। गिरधारी के फोन आने लगे। भाभीजी और बच्चे स्वागत को खड़े थे कि अतिथि देवता आए तो तिलक कर ससम्मान गृह प्रवेश करवाएं। वे बाकायदा आए लेकिन तिलक के नाम पर कपाल चुराने लगे। नहाए के बाल, खाए के गाल और पीए के हाल दिख जाते हैं। इनके भी दिख गए।

भाभी जी घर से गरीब थीं लेकिन थोड़ा-बहुत अमीर खुसरो को पढ़ रखा था, उन्होंने दोहा दोहराया—खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए/ आया कुत्ता खा गया, अब बैठो तुम ढोल बजाए। पोल खुलने के बाद ढोल बजाना ही शेष रह जाता है। इसलिए लोग पहले ही विदेश जाकर ढोल बजा लेते हैं। तभी दूर ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी, शायद बारह बज गए। दोस्त गिरधारी को साथ लेकर जाना चाहते थे। एक तरफ तीन दोस्त दूसरी तरफ श्रीमती का कुछ-कुछ खुलता तीसरा नेत्र... गिरधारी नेत्र बंद कर घर में सो गया। यह सोचकर कि सुबह कितनी रंगीन होगी!!

आपकी राय

अल्पसंख्यक कौन!

जब देश एक बार फिर जनगणना की दहलीज पर है, यह सवाल केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि न्याय और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा है कि वास्तविक अल्पसंख्यक कौन हैं। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द तो है, पर उसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़ी सुविधाएं अब विशेषाधिकार जैसी दिखने लगी हैं, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। अल्पसंख्यक दर्जा सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए, न कि जनसंख्या के आधार पर।

सुभाष बुड़ावनवाला, रतलाम, म.प्र.

संतुलन और खनन संकट

पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना को नष्ट करना अत्यंत हानिकारक है, और इसके दुष्परिणाम हम आज अनुभव कर रहे हैं। खनन के पर्यावरणीय प्रभावों पर कई प्रश्न उठे हैं। अवैध खनन अक्सर वैध खनन क्षेत्रों में होता है, जिससे समस्या बनी रहती है। अरावली पर्वतमाला, जो प्राचीन पर्वतमालाओं में एक है, रेगिस्तान की रेत को फैलने से रोकती है और क्षेत्र के जलवायु संतुलन तथा भूजल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

पुराने वर्ष का आभार

नव वर्ष को हर्षोल्लास, उत्साह और नए जोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें नए संकल्प, नए इरादे, नए सपने और नई ख्वाहिशें शामिल होती हैं। नव वर्ष की खुशी में हम पुराने वर्ष का शुक्रिया करना भूल जाते हैं। चलिए, इस बार नव वर्ष के आगमन के जोश से पहले, जाते वर्ष को हमारी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए दिल से आभार प्रकट करें और खुशी-खुशी विदा करें।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

कांग्रेस का संकट

कांग्रेस, जो 140 साल पुरानी पार्टी है और स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, आज संकट से जूझ रही है। 2014 की हार के बाद पार्टी उबर नहीं पाई। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में सरकार पर हमले किए, लेकिन बिहार चुनाव में विफल रहे। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर जैसे नेता भी पार्टी में उथल-पुथल पैदा कर रहे हैं। असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए कांग्रेस को संगठन मजबूत कर और समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरना चाहिए।

शामलाल कौशल, रोहतक

संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशनार्थ लेख इस ईमेल पर भेजें :-
dtmagzine@tribunemail.com

कल्पमेधा

जब जिंदगी को अपने दिल के गीत सुनाने का मौका नहीं मिलता, तब वह अपने मन के विचार सुनाने के लिए दार्शनिक पैदा कर देती है।

– खलील जिब्रान

लापरवाही की कीमत

वह अपने आप में विचित्र और अफसोसनाक है कि जिस शहर को पिछले कई वर्षों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिल रहा हो, वहां दूषित पेयजल के सेवन से लोगों के मरने की खबरें आती हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई और करीब दो सौ लोगों को अस्पताल भर्ती होना पड़ा। खबरों के मुताबिक, भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में गंदा पानी मिल गया, जिससे पानी दूषित हो गया। लोगों ने इस पानी का सेवन शायद इसलिए भी कर लिया कि साफ और गंदे पानी में फर्क करना मुश्किल हो गया था। सवाल है कि अगर आम लोग पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति पर निर्भर हों, तो उनके पास गंदा और दूषित पानी पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है। लोगों की मौत के मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने गलती मानते हुए आनन-फानन में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन यह साफ है कि संबंधित महकमों की नींद तभी खुलती है, जब कोई बड़ा नुकसान हो चुका होता है।

यों, देश भर में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, लेकिन ऐसा लगता है कि आम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और इस क्रम में उनकी सेहत के साथ क्या होता है, इसकी परवाह शायद किसी को नहीं है। खबरों के मुताबिक, दूषित पेयजल की मार से प्रभावित इलाके में स्थानीय लोगों ने पिछले डेढ़ वर्ष से इससे होने वाली परेशानी और शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने की बात कही। मगर सरकार के कामकाज की शैली का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पेयजल में दूषित पानी मिलने के बाद जब लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, तब भी अगले कई दिन तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा, पीने के पानी के पाइप लाइन से अलग गंदे पानी के निकासी की लाइन को सुरक्षित मानकों तक दूर रखने की व्यवस्था नहीं की गई, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या यह सिर्फ अक्षम अधिकारियों की अदूरदर्शिता का मामला है या फिर जानबूझ कर की गई अनदेखी का? इस तरह की लापरवाही का इलाज सिर्फ कुछ औपचारिक कदम नहीं हैं, बल्कि इसके लिए सभी स्तर पर सजगता और जिम्मेदारी की जरूरत है।

विडंबना यह है कि सरकार का मकसद प्रचार के लिए किसी शहर की स्वच्छता के तमगे हासिल करना रह गया लगता है। सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में अगर कुछ लोगों को जहरीला पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा, तो इस विरोधाभासी हकीकत की पड़ताल करने की जरूरत है कि ऐसे तमगे जारी किए जाने के पैमाने क्या हैं? पीने का पानी सबसे बुनियादी जरूरत है, जिसके बिना ज्यादा वक्त तक नहीं रहा जा सकता। सरकार देश भर में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना के तहत सबको स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का दावा करती है। मगर इस दावे की हकीकत अक्सर सामने आती रहती है, जब किसी इलाके में भूजल सूख जाने तो कहीं पीने के पानी के लिए लोगों के जद्दोजहद करने की खबरें आती हैं। जहां पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है भी, अगर वहां यह सेहत पर जोखिम से लेकर जानलेवा होने तक के खतरे से बची नहीं है, तो इसे कैसे देखा जाएगा। यह समझना मुश्किल है कि कमियों पर ध्यान देने और पेयजल के पाइप लाइन के सुरक्षित होने की निगरानी नियमित जवाबदेही में शामिल क्यों नहीं होती, ताकि ऐसी त्रासदी से बचा जा सके।

अंधविश्वास की मार

प्रगति के कई सोपान पार करने के बावजूद भारत में अंधविश्वास की जड़ें गहरी हैं। इस देश की यह ऐसी स्याह तस्वीर है, जिसकी आमतौर पर अनदेखी की जाती रही है। आए दिन जादू-टोने के अंधविश्वास में निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है। यों देश के सभी हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान बिहार, झारखंड और असम में हुई ऐसी कई घटनाओं ने व्यापक चिंता पैदा की है। गौरतलब है कि असम के कार्बी आंगलोंग जिले में मंगलवार रात हुई घटना ने एक बार फिर सबको झकझोर दिया है। वहां एक गांव के कुछ लोगों ने जादू-टोना किए जाने के संदेह में घर में घुस कर एक दंपति पर पहले धारदार हथियारों से हमला किया, फिर उनके घर में आग लगा दी। इससे पति-पत्नी की जल कर मौत हो गई। ग्रामीण इलाकों में जादू-टोने या डायन होने का आरोप लगा कर अक्सर महिलाओं को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और कई बार उन्हें मार भी दिया जाता है। हालांकि शहर भी अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हैं। यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है, जो विकास के आधुनिक पैमानों को मुंह चिढ़ाती है, लेकिन इसके निवारण के लिए कभी ईमानदार इच्छाशक्ति नहीं दिखाई गई।

हैरानी की बात यह है कि जिस दौर में देश और दुनिया तकनीक के क्षेत्र में चरम विकास के दौर में है, उसमें महज वहम या अंधविश्वास की वजह से कई लोग अपने परिवार के लोगों के बीमार होने पर डाक्टर से इलाज कराने के बजाय उसे किसी जादू-टोने का नतीजा मानते हैं। विकास के तमाम दावों के बीच यह हकीकत है कि देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार को लेकर सरकारें कभी गंभीर नहीं रहीं। जबकि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का दायित्व संवैधानिक तौर पर भी दर्ज है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के बजाय सरकारें किसी घटना विशेष के संदर्भ में कानून की सीमा में कदम उठाती हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर वैज्ञानिक चेतना निर्माण को लेकर कोई ठोस योजना जमीन पर नहीं दिखती। अलग-अलग राज्यों में इस मसले पर बने कानून हैं, मगर लोगों के भीतर सोच के स्तर पर गहरे तक बैठा अंधविश्वास कानूनों के असर को बेमानी बना देता है।

अरावली के संरक्षण की मुश्किल राह

अरावली कई दशकों से मानवीय दबाव झेल रही है। पत्थर और चूना-पत्थर की निरंतर निकासी ने कई पहाड़ियों को कमजोर कर दिया है। जंगलों का नुकसान हुआ है। आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती गई है।

देवेंद्रराज सुथार

अरावली पर्वत शृंखला एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। इस बार बहस का कारण केवल खनन नहीं, बल्कि वह नई न्यायिक स्थिति है जो सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद बनी है। न्यायालय ने बीते 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगाते हुए यह स्पष्ट किया है कि 21 जनवरी 2026 तक अरावली क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके साथ ही एक नई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है, जो पहले से नियुक्त समिति की रपट तथा न्यायालय की टिप्पणियों का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी। न्यायालय ने यह भी कहा है कि पिछली सिफारिशें और उन पर आधारित उसकी टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी और अगली सुनवाई तक लागू नहीं की जाएंगी। पहली नजर में यह निर्णय सावधानी भरा, संतुलित और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विचारणीय कदम प्रतीत होता है। न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कोई भी व्यवस्था लागू होने से पहले उसका वैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी परीक्षण अवश्य हो।

फिर भी यह सवाल कायम है कि इतनी स्पष्टता के बाद भी अरावली पर विवाद और विरोध क्यों जारी है। इसका उत्तर उस गहरी दूरी में छिपा है जो नीति के इरादों और उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच बनी रहती है। कई लोगों को डर है कि यदि निगरानी और प्रवर्तन कमजोर रहा, तो कोई भी नई व्यवस्था केवल कागजों में सुशोभित होकर रह जाएगी, जबकि जमीन पर पुराने ढर्रे ही चलते रहेंगे।

अरावली कोई साधारण पर्वत शृंखला नहीं है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी उम्र लगभग दो अरब वर्ष आंकी जाती है। दिल्ली से गुजरात तक लगभग 650 किलोमीटर में फैली यह शृंखला उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ रही है। यह थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलाव को रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है और गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाती है। इसकी चट्टानें, वनस्पतियां और घाटियां भूजल को संरक्षित करने में मदद करती हैं। चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का उद्गम भी इसी क्षेत्र से होता है। इसके जंगल अनेक वन्य प्रजातियों को आश्रय देते हैं और जलवायु को स्थिर रखने में योगदान करते हैं। इस दृष्टि से अरावली केवल भूगोल नहीं, बल्कि जीवन तंत्र है, जिसकी क्षति का प्रभाव दूरदराज के क्षेत्रों तक महसूस किया जाता है।

अरावली कई दशकों से मानवीय दबाव झेल रही है। पत्थर, रेत और खनिज की बढ़ती मांग ने इसे खनन का प्रमुख केंद्र बना दिया है। पत्थर और चूना-पत्थर की निरंतर निकासी ने कई पहाड़ियों को कमजोर कर दिया है। जंगलों का नुकसान हुआ है। आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती गई है। भूजल स्तर नीचे गया और ग्रामीण आबादी को पानी के लिए टैंकरों तथा अस्थायी साधनों पर निर्भर होना पड़ा। कई बार नियम बनाए गए, कई बार न्यायालय का सीधा हस्तक्षेप हुआ। मगर इनका पालन हमेशा ठोस रूप में नहीं हो सका।

इसी पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2024 में नए खनन पट्टों और पुराने पट्टों के नवीनीकरण पर रोक लगाई और एक विशेषज्ञ समिति से विस्तृत रपट मांगी। समिति ने इस बात पर बल दिया कि अब तक खनन परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रायः अलग-अलग किया गया, जबकि उनका

संयुक्त प्रभाव पूरे क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर पड़ता रहा है। इसलिए समिति ने संचयी पर्यावरणीय प्रभाव के वैज्ञानिक अध्ययन, सटीक नक्शानवीसी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा और पत्थर क्रशर इकाइयों पर सख्त निगरानी जैसी सिफारिशें कीं।

दिल्ली से गुजरात तक लगभग 650 किलोमीटर में फैली अरावली शृंखला उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ रही है। यह थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलाव को रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है और गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाती है। इसकी चट्टानें, वनस्पतियां और घाटियां भूजल को संरक्षित करने में मदद करती हैं। चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का उद्गम भी इसी क्षेत्र से होता है। इसके जंगल अनेक वन्य प्रजातियों को आश्रय देते हैं और जलवायु को स्थिर रखने में योगदान करते हैं। इस दृष्टि से अरावली केवल भूगोल नहीं, बल्कि जीवन तंत्र है, जिसकी क्षति का प्रभाव दूरदराज के क्षेत्रों तक महसूस किया जाता है।

इसी क्रम में अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा तय करने का प्रश्न उभरा। अलग-अलग राज्यों तथा संस्थानों द्वारा अरावली की पहचान के लिए भिन्न-भिन्न मानदंड अपनाए जाते रहे हैं। इस असंगति के कारण कई क्षेत्रों में यह विवाद बना रहा कि कौन-सा इलाका वास्तव में अरावली का हिस्सा है। इस भ्रम का लाभ उठा कर खनन को वैध ठहराने की कोशिशें भी होती रहीं। इसे समाप्त करने के लिए बनाई गई संयुक्त समिति ने सुझाव दिया कि जो पहाड़ियां सौ मीटर से अधिक ऊंचाई रखती हैं, उन्हें अरावली की परिधि में माना जाए। न्यायालय ने इस मानक को स्वीकार किया, लेकिन यहीं से व्यापक असहमति और विरोध शुरू हुआ।

पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली जैसी अत्यंत पुरानी और घिस कर बनी पर्वतमाला को केवल ऊंचाई के आधार पर परिभाषित करना उसके वास्तविक महत्त्व को कम करके देखना होगा। इस शृंखला की कई पहाड़ियां अपेक्षाकृत नीची अवश्य हैं, परंतु वे वर्षा जल को रोकने, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता बनाए रखने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि केवल सौ मीटर की सीमा लागू कर दी जाए, तो बड़ी संख्या में ऐसी पहाड़ियां अरावली की परिभाषा से बाहर हो सकती हैं और उन पर खनन के लिए कानूनी रास्ते खुल सकते हैं। यही वह मुख्य चिंता है जिसे अब न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और इसी कारण उसने पूर्व सिफारिशों और टिप्पणियों को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है।

सरकार की ओर से यह कहा गया कि आदेशों और प्रक्रियाओं को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जबकि न्यायालय ने साफ किया है कि जब तक नई उच्च स्तरीय समिति स्वतंत्र रूप से पूरी प्रक्रिया की समीक्षा नहीं कर लेती, तब तक न तो सौ मीटर वाली परिभाषा लागू होगी और न ही उससे जुड़े अन्य निर्देश प्रभावी होंगे। इस प्रकार न्यायालय ने संरक्षण तथा नीति निर्माण दोनों को और अधिक वैज्ञानिक तथा पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है। राज्य सरकारों की चिंताएं भी स्वाभाविक हैं। अरावली चार राज्यों में फैली हुई है और हर राज्य की अपनी भूमि नीति, राजस्व संरचना और प्रशासनिक सीमाएं हैं। खनन कई राज्यों के लिए राजस्व का महत्त्वपूर्ण स्रोत रहा है।

इसी संदर्भ में 'अरावली ग्रीन वाल' परियोजना का उल्लेख भी आवश्यक है। इस योजना में अरावली के आसपास बंजर भूमि को पुनर्जीवित कर हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दावा किया गया है कि इससे मरुस्थलीकरण पर रोक लगेगी और स्थानीय पर्यावरण सुदृढ़ होगा। मगर कई स्थानीय समुदायों को आशंका है कि इस योजना से भूमि उपयोग पर नए प्रतिबंध लग सकते हैं और पारंपरिक चराई, खेती और बसावट प्रभावित हो सकती है। इसलिए जो भी हो, स्थानीय समुदायों की सहमति और सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाए। अरावली पर प्रश्न यह भी है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए?

सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय इस दिशा में पुनर्विचार का अवसर है। इससे यह उम्मीद जन्म लेती है कि अरावली की रक्षा पर होने वाली बहस अब अधिक गहराई, वैज्ञानिकता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी। यदि नई समिति निष्पक्षता से सभी पक्षों की बात सुन कर संतुलित सिफारिशें करती है और सरकारें उन्हें ईमानदारी से लागू करती है, तो आज का विवाद कल के विश्वास में बदल सकता है। यदि प्रक्रिया फिर से केवल कागजों में सीमित रह गई और व्यवहार में वही पुरानी कमजोरियां कायम रहीं, तो अरावली की प्राचीन पहाड़ियां एक बार फिर विकास की कीमत चुकाने को मजबूर होंगी। यही आशंका आज की बहस का मूल कारण है और यही वजह है कि सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद असहमति की आवाज थम नहीं रही है।

वक्त का हिसाब

अनिता वर्मा

दुनिया मेरे आगे

अभिनंदन और विदाई- ये सब जीवन यात्रा के अभिन्न अंग है। जनवरी से दिसंबर के महीने के बीच जो भी घटित होता है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, घर-परिवार, देश-विदेश से लेकर सृजन साहित्य तक, वह सब समय के साथ अपनी अवधि के भीतर घटित होकर अपने पद चिह्न मन-मस्तिष्क पर छोड़ जाता है। अमूमन हर बीता वर्ष इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है। हर बार के आकलन में हम गौर करते हैं कि वैश्विक पटल पर कई घटनाक्रम हुए, जो सब कुछ समय के साथ अपना निर्धारित स्थान इस वर्ष में दर्ज करवा कर इस वर्ष में स्थायी हो गए। खेल, साहित्य, शिक्षा और तकनीक में कई उपलब्धियों ने हमें समृद्ध किया और हम सबका गौरव बढ़ाया। व्यक्तिगत संदर्भों में कई मित्र जुड़े, कई बिछड़ गए। यह जीवन का हिस्सा रहा। समय का अभाव कहें या परिस्थितियां, सबके साथ हम चलते रहे। हम सब अपने भीतर झांक सकते हैं कि इस सबके बीच कई बार द्वंद्व रहा, उलझनें रहीं तथा समस्याएं और समाधान साथ-साथ चलते रहे।

समय की धारा में हम सब बहते चले जाते हैं, क्योंकि समय बलवान होता है। समय को हम चाह कर भी पकड़ नहीं पाते। बल्कि यों कहें कि नहीं पकड़ सकते। समय अदृश्य है, पर चलता रहता है अनवरत। यों भी, यह किसी के रोके कभी रुका है क्या? रोकने की कोशिश करने वाले लोग रुक गए, लेकिन समय चलता रहा। हम समय के अभाव का रोना रोते रहते है और समय अपनी निर्धारित सीमा में अपनी चाल चलता रहता है। गांव, शहर, गलियां, व्यक्ति आदि जाने क्या-क्या अपने नवीन संदर्भों के साथ जुड़ते और छूटते चले जाते हैं। हम चुपचाप समय के साथ अपने दिन व्यतीत करते जाते हैं। समय की धारा में हर्ष, विषाद, सम्मान, पुरस्कार, अभिनंदन, सफलताएं, असफलताएं... और भी न जाने क्या हमारे जीवन का हिस्सा बन कर कभी हमें आनंद के सागर में डुबो देते हैं और कभी निराशा हमारा दामन पकड़ कर पीछे खींचती है। मगर हमारा आत्मविश्वास हमें समय के साथ कदमताल मिलाता आगे ले जाता है।

समय की धारा में हम सब बहते चले जाते हैं, क्योंकि समय बलवान होता है। समय को हम चाह कर भी पकड़ नहीं पाते। समय अदृश्य है, पर चलता रहता है अनवरत। रोकने की कोशिश करने वाले रुक गए। हम समय के अभाव का रोना रोते हैं और समय अपनी निर्धारित सीमा में अपनी चाल चलता रहता है।

यही आत्मविश्वास मन के भीतर ऊर्जा, उत्साह, उमंग का संचार करता है। एक नई सुबह रोज बांह पसारे सुंदर मुस्कान के साथ हमारा स्वागत करती है। हम पिछला सब कुछ भूल कर फिर से नए दिन के सूरज के साथ अपने कार्यों में तल्लीनता से संलग्न हो जाते हैं। यही हमें जीवंत बनाए रखता है। बीते वर्ष के दिसंबर ने अब हमसे विदाई ले ली है। जैसे-जैसे हम चिंतन करते हैं इस तरह की विदाई के बारे में, अचानक हम सबके मुंह से निकलता है कि पिछले दिसंबर के बाद भी नया साल आया था और अब फिर यह पूरा हो गया। नया वर्ष अपनी नवीन रूपरेखा, नवीन गतिविधियों उपलब्धियों के साथ दस्तक दे चुका है। पता ही नहीं चला कि बीता वर्ष भी कैसे चुपके से बीत गया। बहुत कुछ नया जुड़ा, बहुत कुछ पुराना पीछे छूट गया। कई सुखद क्षणों में आनंददायी पलों को जिया और कभी मन अनेक बार विपरीत परिस्थितियों में व्याकुल हुआ... आंखें नम हुईं। क्या यही सब फिर से इस वर्ष हमारे जीवन में नहीं दुहराएगा?

दरअसल, ये सब जीवन के अहम हिस्से हैं। इनके सहारे ही जीवन समय के साथ गतिमान रहता है। जीवन चलने का नाम है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा है- 'दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक परदा नीला झीन छिपाए है जिसमें सुख गात।' वक्त के साथ हम सब पिछले बीत चुके महीनों का हिसाब-किताब लगाते हैं। किसी की झोली में खुशियों के दीप जगमगाते हैं, तो किसी के हिस्से में आया दर्द उसे भीतर तक हिला देता है। कभी उम्मीद खिल जाती है, तो कभी भय का साया मंडराने लगता है कि क्या दर्द का सिलसिला कायम रहेगा। फिर भी समय तो समय है, जैसा भी हो बीत ही जाता है। समय सब कुछ भर देता है।

सुख-दुख जीवन के दो पहलू हैं, जिनके साथ हम सबको अपनी-अपनी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। समय किसी के रोकने से नहीं रुकता, जैसे देखते-देखते पिछला वर्ष बीत गया और अब नए वर्ष का सफर शुरू हो चुका है। कितना कुछ पीछे छूट जाता है। हम सब स्मरण करते हैं कि कल की ही तो बात है कि हमने इस वर्ष के स्वागत के लिए पलक-पांवड़े बिछाए थे। अब वह भी चला गया। हम फिर नव ऊर्जा के साथ तैयार हो जाते हैं नववर्ष के स्वागत अभिनंदन के लिए और बीते वर्ष को विदाई देने। यही सृष्टि का नियम भी है।

नूतनता सदैव वंदनीय अभिनंदनीय होती है। जीवन के विविध क्षेत्रों में जहां हमारी उपस्थिति है, वह सब बीते वर्ष के बही खाते में दर्ज हो जाता है। इसके बाद तो कैलेंडर के पन्ने और तिथियां बदल जाती हैं। कभी-कभी ऐसा अहसास होता है कि कितनी तेजी से समय भाग रहा है। एक वर्ष जीवन का और बीत चला अपने पीछे कितने स्मृति-चिह्न छोड़ता हुआ। कितना कुछ रह-रहकर याद आता है लोगों के साथ बिताया गया समय। वे खिलखिलाते चेहरे, वे शहर, वे जगहें, जहां हम घूमने या किसी विशेष कारण से गए, वे यात्राएं, यात्राओं के सहयात्री, यात्राओं के अविस्मरणीय पल..! कुछ भी भूल नहीं पाते, भले ही पुराना साल बीत गया हो। समय की अपनी अवधि और सीमाएं- इन सबके बीच संघर्षशील व्यक्ति गतिमान रहता है।

हवा में जहर

पर्यावरण के प्रति उदासीनता और नियमों की अनदेखी से दिल्ली बुरी तरह प्रदूषित हो गई है। हवा में जहर घुल गया है। कई शहरों में हालत ठीक नहीं है, लेकिन दिल्ली में स्थिति अधिक गंभीर है। कारखानों से नालों में डाली जा रही गंदगी यमुना नदी में मिल रही है। हर बार सर्दियों के मौसम में स्थिति बदतर हो जाती है। पर्यावरण पर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते। यहां चलने वाले वाहनों के कारण भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। वहीं आए दिन हाइवे पर धुंध और धुएं के कारण दुघर्टनाएं हो रही हैं। जिससे जान-माल का नुकसान हो रहा है। फिर इस पर राजनीति क्यों होती है। जनचेतना के साथ शासन-प्रशासन को भी सख्त होने की जरूरत है। पेड़-पौधों और जंगलों को खत्म करने से परेशानी बढ़ गई है। हमने प्रकृति और पर्यावरण से दूरी बना ली है। नतीजा यह कि आने वाली पीढ़ी भी इसका खमियाजा भुगतेगी। हमने पशु-पक्षियों को शहरों से बाहर निकाल दिया और ई-कचरे को अपने घरों में भर लिया है। अभी सिर्फ वाहनों और पराली की बात हो रही है, लेकिन औद्योगिक नीति पर बदलाव नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र मिल कर इस मसले को गंभीरता से सुलझाए।

– हरिहर सिंह चौहान, इंदौर

भेदभाव का दायरा

आए दिन उत्तर-पूर्व के छात्रों को दिल्ली सहित उत्तर भारतीय राज्यों में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन घटनाओं पर आमतौर पर लीपापोती की जाती है। यह खतरनाक है। इसी तरह से उत्तर भारतीयों को पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में भाषाई भेदभाव झेलने पड़ते हैं। अच्छा होगा कि सभी राज्य एक-दूसरे की संस्कृति, साहित्य, इतिहास की जानकारी स्कूली पाठ्यक्रमों में उपलब्ध कराए। इससे किशोरावस्था से सभी के मन-मस्तिष्क में एकता की भावना का बीजारोपण होगा। सिर्फ नारों से एकता नहीं आती है। एकता-अखंडता का संबंध भावनात्मक लगाव से है। इस संबंध को जोड़ने की कड़ी साहित्य है, क्योंकि साहित्य से संकीर्णता का लोप होता है। व्यापकता आती है। व्यक्ति जिन उलझनों से दो-चार होता है। साहित्य में उन उलझनों का व्यापक विश्लेषण ही नहीं मिलता, बल्कि समाधान भी होता है। अधिकतर उलझनों की वजह हम सबकी संकीर्णता होती है।

– मुकेश कुमार मनन, पटना

खुशहाली का संकल्प

नव वर्ष का आगमन उत्साह और उमंग का प्रतीक है। पूरी दुनिया नए सपनों और संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा लेती है। यह केवल तिथि परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत का अवसर है, जहां हम पुरानी कमियों को पीछे छोड़ कर बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। आज जब पूरी दुनिया युद्ध के साए में जी रही है, तब नव वर्ष का यह पर्व हमें शांति की स्थापना के लिए गहन चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। हम पर्यावरण संकट को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें और इसके लिए संकल्प करें , क्योंकि स्वच्छ और संतुलित प्रकृति ही मानवता की सच्ची धरोहर है। नए वर्ष में हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। भारत में शांति स्थापित हो, देश प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, हर नागरिक का जीवन सुखमय बने और सभी के बीच प्रेम और सद्भाव बढ़े। सकारात्मक संकल्प से ही हम एक आदर्श विश्व का निर्माण कर सकते हैं, जहां सब खुशहाल हों और हर चेहरा मुस्कुराता रहे।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

समाज से सवाल

बरेली में अपने जन्मदिन का जश्न मना रही एक छात्रा ने समाज से यह मासूम सवाल किया है कि क्या वह अपना जन्मदिन मना सकती है। वर्तमान समय में यह सवाल सिर्फ एक शहर या एक जन्मदिन पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान समाज की उस दूषित मानसिकता को उजागर करती है जिसमें, निजी जीवन, मित्रता और खुशियों पर भी धर्म का ठप्पा लगाने की जिद हावी होती जा रही है। मित्रता हमेशा विश्वास, संवेदना, साझा अनुभव और आपसी सम्मान से बनती है। जब किसी युवती को अपने दोस्तों को लेकर सफाई देनी पड़े, डर महसूस हो और आरोपों का सामना करना पड़े, तो यह स्थिति कानून-व्यवस्था से अधिक सामाजिक विवेक की विफलता है। इस प्रकार की घटनाएं समाज को सुरक्षा नहीं, बल्कि संदेह और भय की तरफ ले जाती हैं।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

“ जिसके हृदय में मदद करने की भावना हो, उसे आलोचना करने का भी अधिकार है।

–अब्राहिम लिंकन

हिमाचली उत्पादों की टोकरी

पारंपरिक कौशल को नए मुकाम तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिमला में होने जा रहा एमएसएमई फेस्ट, काफी उत्साहित और उम्मीदों भरी जिज्ञासा पैदा कर रहा है। थीम में एक जिला, एक उत्पाद की टोकरी में धरती की अमानत, परंपराओं की थाली और स्वावलंबन की उद्यमशीलता दिखाई देती है। मसलन चंबा रूमाल, कांगड़ा चित्रकला, पारंपरिक कुल्लू शॉल के अलावा नए हिमाचल की पहचान में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, आंवला प्रसंस्करण, स्टील फर्नीचर, पैकेजिंग, मशरूम, पर्यटन का तकनीकी उन्नयन, सीबकथार्न, चुल्ली तेल व कांगड़ा चाय अपनी खूबियों के साथ ई कॉमर्स और देश की मांग में व्यापारिक संबंधों की खेप बन पाएगा। उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए घरेलू, लघु व मध्यम उद्योगों को जाहिर तौर पर इससे प्रेरणा मिलेगी। हिमाचल के उत्पाद, बाजार और नए अंदाज को समझ लें, तो गांव की मिट्टी, नवाचार, स्वरोजगार की दरकार, स्टार्टअप की क्षमता और उद्योगों की विविधता सामने आएगी। मसलन ऊना का कत्था उद्योग का नाता पारंपरिक धंधे के अलावा ग्रामीण आर्थिकी व वन उत्पादों का एक संबल है। दियोटसिद्ध मंदिर के प्रसाद के रूप में बिकने वाला रोट अपनी खासियत और संभावना के साथ एक ऐसा व्यापारिक उत्पाद है, जो प्रदेश की अनूठी विरासत को भविष्य दिखा सकता है। इसी तरह ज्वालामुखी के पेड़े और धूप जैसे उत्पाद बाजार में अलग कतार बना लेते हैं। चंबा की चप्पल और चुख पर मेहनत की जाए, तो व्यापारिक करवटें बदल जाएंगी। इसी तरह हिमाचल के पारंपरिक आभूषणों की बनावट, सजावट तथा लागत को व्यापार के रास्ते उन्नत किया जाए, तो हर जिला से निकलेगा उत्पादों का खजाना। आभूषणों के कुछ बड़े ब्रांड हिमाचल के पारंपरिक गहनों को व्यापारिक रंगत में सजा सकते हैं, तो उद्योग विभाग के दखल से पारंपरिक बाजारों को इनकी नई क्षमता में पेश किया जा सकता है। खुशी की बात यह कि सरकार हर तरह के उत्पादों को संगठित करके बाजार को आवाज दे रही है। इस अभियान का नेतृत्व भले ही उद्योग विभाग कर रहा है, लेकिन ग्रामीण विकास, शहरी विकास तथा कबाइली विकास जैसे विभागों को इनके मूल स्रोतों को जिंदा रखना होगा। हिमाचल के पारंपरिक खान–पान में ही व्यापारिक ऊर्जा नहीं, बल्कि कुछ नुस्खों में शारीरिक हिफाजत के उत्पाद सामने आ सकते हैं। भले ही आगामी तीन से पांच जनवरी तक रिज पर कितने ही उत्पाद अपने–अपने जिला के लिए नाम कमाएंगे, लेकिन कवायद को असली संरक्षण व प्रचार प्रदान करना होगा। वस्तुएं दिखाई जा सकती हैं, लेकिन निर्माण पद्धति की सदियों को बचाने के लिए शिक्षा में इनके प्रति सरोकार चाहिएं। आज की तारीख में पूरा भरमौर नीचे उतर कर कांगड़ा पहुंच गया, किन्नौर ने सोलन–चंडीगढ़ में आशियाना खोज लिया, पांगी–लाहुल ने कुल्लू–मनाली की बहारों में धंधे आजमा लिए, तो पारंपरिक या जिला के उत्पादों को बढ़ावा देने की नीति और वकालत चाहिए। ऐसे सामुदायिक स्कूल व कालेज चाहिए जहां परिवेश के हर उत्पाद की रक्षा हो। उदाहरण के लिए नगरोटा सूरियां के कालेज को स्टेट कालेज ऑफ फिशरीज स्टडी बना कर वहां इससे जुड़ी उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले, तो वहां मत्स्य उद्योग से स्वावलंबन तथा बाजार विकसित होगा। अगर कुल्लू के हस्तशिल्प की संभावना में कालेज को डिजाइनिंग व उत्पादन के अंतरराष्ट्रीय पैमानों का प्रतीक बना दिया जाए, तो यह केवल शॉल–मफलर तक ही नहीं, हिमाचल से फैशन का एक नया चमत्कार होगा। हमारा मानना है कि उद्योगों और पारंपरिक उत्पादों की रूपरेखा में कुछ स्कूल व कालेजों को इनके अभिप्राय से जोड़ते हुए राज्य स्तरीय दर्जा देना चाहिए। बीबीएन क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय इंडस्ट्रियल व प्रबंधन कालेज की शुरुआत करनी चाहिए, जबकि प्रदेश के हर विश्वविद्यालय के लक्ष्यों में केवल स्नातक और स्नातकोत्तर दर्जा नहीं, बल्कि स्वरोजगार के लिए प्रेरित, काबिल और प्रतिबद्ध युवा इस प्रदेश की आत्मनिर्भरता के लिए बाहर आएं।

सरोकार

नव वर्ष, नव संकल्प

नव वर्ष की पहली सुबह जब हिमाचल के पहाड़ों पर हल्की धूप उतरती है, देवदारों के बीच से ठंडी हवा गुजरती है और दूर कहीं मंदिर की घंटी या गांव के घरों से उठती धूप–अगरबत्ती की खुशबू वातावरण को पवित्र कर देती है, तब मन अपने आप ठहर जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं हमें याद दिला रही हो कि एक और वर्ष बीत गया, एक और अवसर हमारे हाथ में है। यह अवसर केवल खुशियां मनाने का नहीं, बल्कि खुद से कुछ सच्चे सवाल पूछने का है। क्या हम पिछले वर्ष बेहतर इनसान बन पाए? क्या हमने अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों, अपने समाज और अपनी धरती के लिए कुछ अच्छा किया? या फिर हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गए, जो समय के साथ तो चलती है, लेकिन दिशा खो देती है। हिमाचल प्रदेश केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है। यह भावनाओं की भूमि है, रिश्तों की धरती है, परंपराओं और संस्कारों की जड़ों से जुड़ा हुआ समाज है। यहां नव वर्ष केवल कैलेंडर बदलने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला क्षण होता है। यही वह समय है, जब हमें अपने भीतर झांककर यह तय करना चाहिए कि आने वाला वर्ष केवल हमारी व्यक्तिगत तरक्की का वर्ष होगा या सामाजिक जिम्मेदारी का भी। आज का हिमाचल तेजी से बदल रहा है। सड़कें बढ़ रही हैं, मोबाइल नेटवर्क हर हाथ में है, दुनिया एक क्लिक पर सिमट आई है। लेकिन इसी तेजी के बीच कहीं न कहीं इनसान पीछे छूटता जा रहा है। सबसे अधिक चिंता तब होती है, जब हम अपने युवाओं की आंखों में सपनों की जगह खालीपन देखते हैं। वही युवा, जो कभी पहाड़ों की तरह मजबूत माने जाते थे, आज नशे और चिट्टे जैसे जहर की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, यह उन घरों की कहानी है, जहां मां की आंखें रात भर जागती हैं और पिता की चुप्पी भीतर ही भीतर टूटती है। चिट्टे और नशे के खिलाफ चली यह जंग केवल परिवारों या समाज की नहीं रह गई है, बल्कि अब यह सरकार और जनता की साझा लड़ाई बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चिट्टामुक्त हिमाचल का जो संकल्प लिया गया है, वह तभी सफल हो सकता है, जब आम नागरिक भी इसे अपना संकल्प बनाए। कानून अपना काम करेगा, पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज चुप रहेगा, तब तक नशे की जड़ें पूरी तरह नहीं उखड़ेंगी। नव वर्ष का यह संकल्प होना चाहिए कि हम नशे के खिलाफ केवल दर्शक नहीं, सहभागी बनें। यदि कहीं गलत होता दिखे तो चुप न रहें, यदि कोई भटक रहा हो तो उसे अकेला न छोड़ें। चिट्टामुक्त हिमाचल का सपना तभी साकार होगा, जब हर मां यह ठान ले कि उसका बच्चा नशे से दूर रहेगा, हर युवा यह तय करे कि वह अपने भविष्य को जहर के हवाले नहीं करेगा और हर नागरिक यह समझे कि नशे के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं, सामाजिक कर्तव्य है। नशा किसी एक व्यक्ति की कमजोरी नहीं होता, यह पूरे समाज की असफलता होती है। जब युवा भटकता है, तो कहीं न कहीं हम सबने उसे अकेला छोड़ा होता है। नव वर्ष का संकल्प यदि सच्चे दिल से लेना है, तो हमें अपने युवाओं को दोष देने से पहले उन्हें समझने का साहस जुटाना होगा। उनसे बात करनी होगी, उन्हें सुनना होगा, उन्हें यह भरोसा देना होगा कि जीवन केवल दबाव और तुलना का नाम नहीं है। खेल, कला, संस्कृति, रोजगार और सकारात्मक सोच यही वे रास्ते हैं, जिनसे हम अपने युवाओं को अंधेरे से बाहर ला सकते हैं।

उमा ठाकुर
स्वतंत्र लेखिका

संपादकीय लेखों पर सुधी पाठकों की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं, भेजें : पाठकों के पत्र, द्वारा संपादक, पोस्ट बॉक्स 14, धर्मशाला–176215
फोन : 01892–264713, 260676
फैक्स : 01892–264700
Email : feature@divyahimachal.com या edit.dshala@divyahimachal.com

कांग्रेस के पतन की जिम्मेवारी किसकी?

कुलदीप चंद अग्निहोत्री
वरिष्ठ स्तंभकार

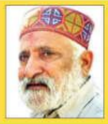

देश की राजनीति जो करवट ले रही है, उसे देखकर मुझे यह आकलन करना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले गांधी परिवार शब्द को स्पष्ट कर देना जरूरी है। दरअसल आज देश की राजनीति में जिस परिवार को गांधी परिवार के नाम से जाना जाता है, वह विस्तृत नेहरु परिवार है जिसे अंग्रेजी में एक्सटेंडेड नेहरु फैमिली कहा जाता है। यह दरअसल पंडित जवाहर लाल नेहरु की बेटी का परिवार है। इसका महात्मा गान्धी या उनके परिवार से कुछ लेना–देना नहीं है। नेहरु जी की बेटी इंदिरा गान्धी के दो बेटे राजीव गान्धी और संजय गान्धी थे। संजय गान्धी के परिवार की चर्चा आजकल विस्तृत नेहरू परिवार में नहीं होती। भारतीय राजनीति में जिसे नेहरु–गान्धी परिवार कह दिया जाता है वह भी दरअसल राजीव गान्धी का ही परिवार है। राजीव गान्धी के परिवार में उनका बेटा राहुल गान्धी और प्रियंका गान्धी हैं। राहुल गान्धी ने न जाने किन कारणों से ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है इसलिए उसका आगे परिवार नहीं है। प्रियंका गान्धी की शादी एक पंजाबी बढेरा परिवार में हुई है जिसे अंग्रेजी में वाड्रा कहा जाता है। इसका कारण शायद उनके पति राबर्ड द्वारा ईसाई मजहब में मतान्तरित हो जाना कहा जाता है। कारण कोई भी हो, कुल मिला कर कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में नेहरू–गान्धी परिवार के नाम पर राबर्ट वाड्रा का परिवार है जिसमें उसकी पत्नी प्रियंका गान्धी वाड्रा और उसके दो बच्चे हैं। उनके बेटे की सगाई किसी अबीवा बेग नामक लड़की से हो गई है, इसलिए अब प्रियंका गान्धी वाड्रा सास बनने की स्थिति में आ गई हैं और सोनिया गान्धी परदादी। यानी इस परिवार में अब दो परिवार हैं।

राहुल गान्धी जो ब्रह्मचारी हैं और राबर्ट वाड्रा जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि देश की जनता वाड्रा परिवार की प्रियंका गान्धी वाड्रा को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है। लेकिन राहुल गान्धी की मां सोनिया गान्धी की लम्बे समय से इच्छा रही है कि परिवार में गद्दी का वारिस राहुल है, बेटी जो पराया धन है, नहीं। इसलिए वो लम्बे समय से राहुल गान्धी को कांग्रेस की कमान इस आशा में दिए हुए हैं कि एक न एक दिन भारत के लोग पुनः सत्ता कांग्रेस को सौंप देंगे, तब राहुल गान्धी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कहा जाता है कि इटली की मानसिक चेतना में भी लड़कों को लड़की के मुकाबले वरीयता दी जाती है। लेकिन सोनिया गान्धी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि समय मुट्ठी में से रेत की तरह निकला जा रहा है लेकिन भारत के लोग तथाकथित नेहरु–गान्धी परिवार को सत्ता सौंप देने की जल्दी में नहीं लगते। इधर वाड्रा परिवार का धैर्य भी चुक रहा है। जो कभी वाड्रा परिवार की बहू थी, वह सास बनने तक पहुंच गई है, लेकिन सत्ता दूर–दूर तक दिखाई नहीं दे रही। कहीं हालत वाड्रा परिवार और राहुल गान्धी में ही रस्साकशी की तो नहीं बन रही? यदि ऐसा होता है तो सोनिया गान्धी किसके साथ खड़ी होंगी? यह प्रश्न भी भारतीय राजनीति में सिर उठाने लगा है। परिवार की इस लड़ाई का लाभ दूसरे राजनीतिक दल उठाने लगे हैं। सबसे पहले भारतीय राजनीति में से अस्त होते जा रहे कम्युनिस्ट समूह। वे राहुल गान्धी और सोनिया गान्धी के इर्द–गिर्द घेरा बांधे रहते हैं। सोनिया गान्धी और राहुल गान्धी का अब विचारधारा या भारतीय दृष्टि से कुछ लेना–देना नहीं हैं। उनको केवल सत्ता चाहिए। कम्युनिस्ट समूह समझ गए हैं कि वे भारत में सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन उन्होंने गान्धी–नेहरु परिवार को किसी तरह समझा दिया है कि वे अपनी विचारक रणनीति से गान्धी नेहरु परिवार को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि राहुल गान्धी अब भारत को लेकर जो कुछ बोलते करते रहते हैं, उसका महात्मा गान्धी और पंडित जवाहर लाल नेहरु से भी कोई संबंध नहीं है। सोनिया गान्धी और कम्युनिस्ट समूहों के अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं। उम्रदराज होती जा रहीं सोनिया गान्धी को भारत में अपने बच्चों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना है और भारत की राजनीति में अप्रासंगिक होते जा रहे कम्युनिस्ट समूहों को किसी तरह अपनी रणनीतिक और वैचारिक प्रासंगिकता बनाई रखनी है। मौका देखकर, इस चक्रव्यूह में फंसे सोनिया गान्धी परिवार के जर्जर होते जा रहे राजनीतिक किले की ईंटें दूसरे क्षेत्रीय दल उठा–उठा कर ले जा रहे हैं। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ममता बैनर्जी, हेमन्त सोरेन, स्टालिन इत्यादि सभी चाहते हैं कि सोनिया गान्धी परिवार, जिसने अभी तक 140 साल पुरानी कांग्रेस पर येन केन प्रकारेण कब्जा किया हुआ है, उनकी पार्टियों की मदद करे और बदले में वे उनकी भी दस–बीस सीटों पर मदद कर देंगे। दरअसल दशकों पहले जब भारत की राजनीति में विभिन्न दलों में तालमेल की शुरुआत हुई थी, तब कांग्रेस इन छोटे–छोटे क्षेत्रीय दलों को कुछ सीटें छोड़ देती थी। अब काल का पूरा चक्र घूम गया है। अब क्षेत्रीय दल कांग्रेस को दस–बीस सीटें छोड़ कर भी उस पर अहसान का भाव जताते हैं। सोनिया परिवार सत्ता के लालच में भारतीय संस्कृति की मुख्य धुरी से ही बाहर होता जा रहा है कि शायद इसी से सत्ता मिल जाए। लेकिन अब लगता है कांग्रेस के भीतर ही यह भाव पनपता जा रहा है कि नेहरु–गान्धी परिवार की सत्ता तक पहुंचने या पहुंचा पाने की क्षमता समाप्त हो गई है या होती जा रही है। उनमें यह भावना भी पनपती जा रही है कि सोनिया परिवार कम्युनिस्ट समूहों के जाल में भारत विरोध की सीमा तक पहुंच रहा है।

दिग्विजय सिंह जैसे खांटी कांग्रेसी को कहना पड़ रहा है कि संगठन की शक्ति से राजनीति चलती है, परिवार की शक्ति से नहीं। इसके लिए उन्हें उदाहरण भी भारतीय जनता पार्टी का ही देना पड़ रहा है। वहां कोई कार्यकर्ता, दिग्विजय सिंह ने नरेन्द्र मोदी का उदाहरण दिया है, संगठन के बल पर प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है। शायद वे यही बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में ये पद सोनिया गान्धी के परिवार तक ही सीमित हैं। हो सकता है अब वे इसे वाड्रा परिवार को हस्तान्तरित करने का निर्णय कर लें। शशि थरूर ने सोनिया परिवार की इच्छा के खिलाफ पार्टी के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ कर इस राज परिवार के चंगुल से कांग्रेस को निकालने की कोशिश की थी लेकिन राज परिवार ने उन्हें अंतिम क्षण तक मतदाता सूची ही नहीं दी थी। राबर्ट वाड्रा ने प्रियंका वाड्रा के प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोंक दिया है और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी को राज परिवार से मुक्त करवाने की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। लेकिन लगता है देश के लोगों को अब महलों की राजनीति के षड्यंत्रों में रुचि नहीं रह गई है, इसलिए पार्टी एक के बाद एक राज्य में सिकुड़ती जा रही है। क्या राज परिवार भारत की विरासत भारतीयों को वापस कर स्वयं ही परे हट जाएगा या फिर इसके लिए भी आम कांग्रेसियों और राजपरिवार में संघर्ष होगा। देश की राजनीति एक नई दिशा की ओर जा रही है। कांग्रेस में उथल–पुथल जैसी स्थिति है।

> दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया है। संगठन के बल पर प्रधानमंत्री पद तक कोई पहुंच सकता है। शायद वे यही बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में ये पद सोनिया गान्धी के परिवार तक ही सीमित हैं। हो सकता है अब वे इसे वाड्रा परिवार को हस्तान्तरित करने का निर्णय कर लें। शशि थरूर ने सोनिया परिवार की इच्छा के खिलाफ पार्टी के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ कर इस राज परिवार के चंगुल से कांग्रेस को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन राज परिवार ने उन्हें अंतिम क्षण तक मतदाता सूची ही नहीं दी थी। राबर्ट वाड्रा ने प्रियंका वाड्रा के प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोंक दिया है और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी को राज परिवार से मुक्त करवाने की रणनीति बनाना शुरू कर दी है...

ईमेल:kuldeepagnihotri@gmail.com

प्रसंगवश

नए साल के सपने–उम्मीदें

नया वर्ष केवल कैलेंडर की तारीख बदलने का नाम नहीं है। यह हमारे जीवन में एक ठहराव की तरह आता है, जहां हम पीछे मुड़कर देखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और नई संभावनाएं लेकर आता है। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है और स्वयं से यह प्रश्न करता है कि बीता वर्ष कैसा रहा, मैंने क्या सीखा, क्या खोया और आगे मुझे क्या बनना है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर भागते रहते हैं– लक्ष्यों के पीछे, जिम्मेदारियों के बोझ तले और अपेक्षाओं की दौड़ में। ऐसे में नया वर्ष हमें यह अवसर देता है कि हम थोड़ी देर रुकें, सांस लें और अपने जीवन की दिशा पर पुनर्विचार करें। यह आत्ममंथन ही नए सपनों की नींव बनता है। बीता वर्ष : सीखों की पाठशाला – हर बीता वर्ष हमारे लिए एक शिक्षक की तरह होता है। उसमें सुख भी होते हैं, दुःख भी। सफलता भी मिलती है और असफलताएं भी। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि हमने उससे क्या सीखा। कई बार हम बीते साल को केवल घटनाओं के आधार पर आंकते हैं, किसे खोया, क्या पाया, पर सीखों को नजरअंदाज कर देते हैं। बीते वर्ष ने हमें धैर्य सिखाया होगा, किसी ने हमें आत्मनिर्भर बनाया होगा, तो किसी ने रिश्तों की अहमियत समझाई होगी। कुछ अनुभवों ने हमें मजबूत बनाया, तो कुछ ने हमें विनम्र। नया वर्ष तभी सार्थक बनता है जब हम इन सीखों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, न कि केवल पुराने दुखों या शिकायतों को ढोते हुए। नए सपने, दिखावे नहीं, दिशा हो : नए साल की शुरुआत अक्सर बड़े–बड़े संकल्पों से होती है, यह करूंगा, वह बनूंगा, इतना हासिल करूंगा। लेकिन कुछ ही महीनों में ये संकल्प धुंधले पड़ने लगते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे सपने कई बार दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित होते हैं, न कि हमारे वास्तविक मन से निकले होते हैं। सपने वही सार्थक होते हैं जो हमारे मूल्यों से जुड़े हों। जो हमें भीतर से उत्साहित करें, न कि थका दें। नया वर्ष हमें यह सोचने का मौका देता है कि हमारे सपने दिखावे के हैं या दिशा देने वाले। क्या हम वही बनना चाहते हैं जो समाज चाहता है, या वह जो हमारी आत्मा चाहती है? सपने छोटे भी हो सकते हैं– जैसे खुद को स्वस्थ रखना, परिवार को समय देना, या खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना। हर सपना बड़ा मंच या बड़ी पहचान नहीं मांगता, कई बार सबसे बड़ा सपना होता है संतुलित और शांत जीवन। नई उम्मीदें– बाहरी नहीं, आंतरिक : उम्मीदें अक्सर हम दूसरों से जोड़ लेते हैं, कि कोई बदले, परिस्थितियां सुधरें, सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन नया वर्ष हमें यह याद दिलाता है कि सबसे मजबूत उम्मीद वह होती है जो अपने भीतर से जन्म लेती है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तब हालात चाहे जैसे हों, हम रास्ता निकाल लेते हैं। आंतरिक उम्मीद का अर्थ है– यह विश्वास कि मैं बदल सकता/सकती हूं, मैं सीख सकता/सकती हूं और मैं बेहतर बन सकता/सकती हूं। यह उम्मीद हमें निराशा से बाहर निकालती है और असफलता के बाद भी खड़ा होने की ताकत देती है। –सत्यवान सौरभ, भिवानी

हिमाचल : खेल

छात्रों की फिटनेस पर सोचें अभिभावक–स्कूल

भूपिंद्र सिंह
अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रशिक्षक

चालीस पार करते ही कई युवा बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। जब इस बात का अध्ययन किया तो पता चलता है कि बचपन से लेकर अठारह वर्ष तक यानी विद्यार्थी जीवन में फिटनेस कार्यक्रम की कमी रही थी। साथ–साथ आजकल अपने आसपास पिछले एक वर्ष में दर्जनों युवाओं ने हृदयघात से दुनिया कोअलविदा कह दिया है। जब किशोर अवस्था में फिटनेस पर काम नहीं होगा तो ऐसे हालात आम देखने को मिलेंगे। जब मन का विकास स्कूल का काम है तो फिर विद्यार्थी के स्वास्थ्य का जिम्मेदार कौन? शिक्षण विषयों के रिपोर्ट कार्ड की तरह स्वास्थ्य के मानकों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रत्येक विद्यार्थी का हर स्कूल में अनिवार्य रूप से हो। क्योंकि भाषा व अन्य शिक्षण विषयों की तरह ही स्वास्थ्य के मूल स्तंभ स्पीड, स्ट्रेंथ, इडोरैंस व लचक आदि का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी उसी उम्र में शुरू करना होता है। शिक्षण विषयों के लिए तो स्कूलों के पास शिक्षक सहित पूरा प्रबंध है, मगर स्वास्थ्य के घटकों को विकसित करके उनका मूल्यांकन करने की कोई भी सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस कॉलम के माध्यम से कई बार इस विषय पर स्कूलों व अभिभावकों को चेताया जा चुका है, मगर कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी देश को इतनी क्षति युद्ध या महामारी से नहीं होती है जितनी तबाही नशे के कारण हो सकती है। आज जब देश के अन्य राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में भी नशा युवा वर्ग पर ही नहीं किशोरों तक चरस, अफीम, स्मैक, नशीली दवाओं तथा दूरसंचार के माध्यमों के दुरुपयोग से शिकंजा कस रहा है। इसलिए सरकार, स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों को इस विषय पर जरूरी कदम जल्दी ही उठा लेने चाहिए।

यदि विद्यार्थी किशोरावस्था में नशे से बच जाता है तो वह फिर युवावस्था आते आते समझदार हो गया होता है। माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विद्याओं में व्यस्त रखने के साथ साथ शारीरिक फिटनेस की तरफ मोड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा की परिभाषा में साफ–साफ लिखा है कि यहां शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से बराबर विद्यार्थियों का विकास करना है, जिससे वह आगे चलकर जीवन को सफलतापूर्वक खुशहाल जी सके। शारीरिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से फिटनेस कार्यक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। खेल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी को नशे से दूर रखा जा सकता है। पड़ोसी राज्य पंजाब एक समय तरक्की में देश का अग्रणी राज्य रहा है। खेलों में उत्कृष्टता उस प्रदेश की तरक्की व खुशहाली का भी पैमाना होती है। पंजाब में हजारों प्रशिक्षक विभिन्न खेलों में खेल प्रशिक्षण के लिए नियुक्त होने के साथ–साथ खेल प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा होना वहां के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख कारण रहा था। बाद में जब पंजाब धीरे–धीरे खेलों से दूर हुआ तो पहले वहां आतंकवाद और फिर आजकल पंजाब नशे का अड्डा बना हुआ है। यही कारण है कि हर क्षेत्र में आज हरियाणा पंजाब से काफी आगे निकल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने एशियाई, राष्ट्रमंडल व ओलंपिक खेलों में पदक विजेता होने पर खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए के नगद ईनाम व सम्मानजनक नौकरी देकर हरियाणा में खेलों के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा का हर किशोर व युवा किसी न किसी खेल के मैदान में नजर आता है। हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की खेलों के लिए अपने पहले कार्यकाल से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड, सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण तथा देश में प्रशिक्षक कैडर डाईंग हो जाने के बाद पहली बार चालीस प्रशिक्षकों की भर्ती जैसे बहुत बड़े खेल सुधार किए। हिमाचल प्रदेश की खेल सुविधाओं का प्रयोग राज्य में स्वास्थ्य व खेलों के लिए बड़े स्तर पर करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश इस समय शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। पिछले कुछ दशकों से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों की फिटनेस में बहुत कमी आई है। इसका प्रमुख कारण है विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम का न होना। रट्टे वाली पढ़ाई की होड़ में हम विद्यार्थियों की फिटनेस को ही भूल गए हैं। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश आबादी गांव में रहती थी। वहां पर सवेरे शाम वर्षों पहले विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ कृषि व अन्य घरेलू कार्यों में सहायता करता था। विद्यालय आने–जाने के लिए कई किलोमीटर दिन में पैदल चलता था। इसलिए उस समय के विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं थी। आज का विद्यार्थी घर के आंगन में बस पर सवार होकर विद्यालय के प्रांगण में उतरता है।

पढ़ाई के नाम पर ज्यादा समय खर्च करने के कारण फिटनेस के लिए कोई समय नहीं बचता है। अधिकांश स्कूलों के पास फिटनेस के लिए न तो आधारभूत ढांचा है और न ही कोई कार्यक्रम है। आज का विद्यार्थी फिटनेस व मनोरंजन के नाम पर दूरसंचार माध्यमों का कमरे में बैठ कर खूब दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात मजाक लगती है। आज के विद्यार्थी के लिए विद्यालय या घर पर आधे घंटे के फिटनेस कार्यक्रम की सख्त जरूरत है। इसमें 15 से 20 मिनट धीरे–धीरे दौड़ना तथा विभिन्न कोणों पर शरीर के जोड़ों की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के बाद शरीर को कूलडाऊन करना होगा। कम से कम बीस मिनटों तक तेज चलने, दौड़ने व शारीरिक क्रियाओं के करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार तेज हो जाता है। उससे हर मसल को उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु मिलने से उसका समुचित विकास होता है। आज के विद्यार्थी को अगर कल का अच्छा नागरिक बनाना है तो हमें स्कूली पाठ्यक्रम के साथ–साथ ही उसके लिए सही फिटनेस कार्यक्रम देना होगा, तभी हम सही अर्थों में अपनी अगली पीढ़ी को संपूर्ण शिक्षित कर सकते हैं जो अपनी आगामी जिंदगी में बिल्कुल स्वस्थ रहकर देश व प्रदेश के लिए साठ वर्ष तक अपने हुनर की सेवाएं दे सकें।

> कम से कम बीस मिनटों तक तेज चलने, दौड़ने व शारीरिक क्रियाओं के करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार तेज हो जाता है। उससे हर मसल को उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु मिलने से उसका समुचित विकास होता है...

ईमेल: bhupindersinghhmr@gmail.com

प्रेरक कहानी

महल में कमी

स्वामी श्रीरामसुखदास जी महाराज

एक राजा था। वह एक संत के पास जाया करता और उनका सत्संग किया करता था। उस राजा ने अपने लिए एक महल बनाया। पहले उसके कई महल थे, पर अब ऐसा महल बनाया, जिसमें आराम की सब चीजें हों और उसमें ज्यादा ठाट–बाट से रहें। राजा ने सन्त से कहा कि महाराज! एक दिन आप चलो, हमारी कुटिया पवित्र हो जाए! सन्त उसको टालते गए। राजा ने बहुत बार कहा तो एक दिन सन्त बोले कि अच्छा भाई, चलो। राजा ने सन्त को महल दिखाना आरम्भ किया कि यह हमारे रहने की जगह है, यह हमारे पंचायती की जगह है, यह भोजन की जगह है, यह शौच–स्नान की जगह है, आदि–आदि। सन्त चुपचाप देखते रहे, कुछ बोले नहीं। अगर वाह–वाह करते हैं तो हिंसा लगती है। कारण कि मकान बनाने में बड़ी हिंसा होती है! बहुत–से जीव मरते हैं। चूहे, सांप, गिलहरी आदि के रहने और चलने–फिरने में आड़ लग जाती है, क्योंकि जितने हिस्से में मकान बना है, उतने हिस्से में वे जा नहीं सकते, स्वतन्त्रता से घूम नहीं सकते। पहले उतने हिस्से में सब जीवों का हक लगता था, पर अब केवल एक का ही हक लगता है। सन्त कुछ बोले नहीं तो राजा ने समझा कि महाराज को मकान पसन्द नहीं आया। राजा लोग चतुर होते हैं। राजा ने पूछ लिया कि महाराज! महल में कमी क्या है? सन्त बोले कि कमी तो इसमें बड़ी भारी है! राजा ने विचार किया कि बड़े–बड़े कुशल कारीगरों ने महल बनाया है। उन्होंने कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी। जहां कमी दिखी, उसको पूरा कर दिया। परन्तु बाबा जी कहते हैं कि कमी है, और वह भी मामूली नहीं है, बड़ी भारी कमी है! राजा को बड़ा आश्चर्य आया और पूछा कि क्या बहुत बड़ी कमी है? सन्त बोले कि हां, बहुत बड़ी कमी है! राजा ने पूछा कि महाराज! क्या कमी है? सन्त बोले कि यह जो दरवाजा रख दिया है न, यह कमी है! राजा बोला कि महाराज! दरवाजे के बिना महल क्या काम आए? सन्त बोले कि तुमने यह महल क्यों बनवाया है? राजा ने कहा कि महाराज! मैंने अपने रहने के लिए बनाया है। सन्त बोले कि राजन, तुमने तो रहने के लिए बनाया है, पर एक दिन लोग उठाकर ले जाएंगे! इससे ज्यादा कमी और क्या होगी, बताओ? बनाया तो है रहने के लिए, पर लोग उठाकर बाहर ले जाएंगे, रहने देंगे नहीं! इसलिए अगर रहना ही हो तो यह दरवाजा नहीं होना चाहिए, बाहर निकलने की जगह नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य है कि यह अपना असली घर नहीं है। एक दिन सब कुछ छोड़कर यहां से जाना पड़ेगा। हमारा असली घर तो वह है, जहां पहुंचने पर फिर लौटकर आना ही न पड़े। भाव यह है कि यह संसार मिथ्या है, जबकि ईश्वर का घर सत्य है। इस संसार में हम मेहमान की तरह हैं, एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा और ईश्वर के घर में शरण लेनी पड़ेगी। यह संसार भौतिक नगरी का प्रतीक है, जबकि ईश्वर का घर आत्मिक नगरी का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य देह में रहकर जितना हो सके, ईश्वर को सुमिरन कर लेना चाहिए। हम जो इस संसार में कमाते हैं, वह साथ नहीं जाएगा। साथ जाने वाली चीज तो ईश्वर का सुमिरन है। इसलिए जितना हो सके, ईश्वर का सुमिरन कर लेना चाहिए। इसी में मोक्ष है। इसी में मनुष्य का कल्याण छिपा है।

पाठकों के पत्र

उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करना जरूरी

विज्ञान ने हमें हर मौसम से बचने के लिए बहुत सी चीजें दी हैं। लेकिन अगर हम इनका सावधानी से प्रयोग न करें तो यह हमारे लिए कभी भी हानिकारक बन सकती हैं और अक्सर खबरें भी पढ़ने और सुनने को मिलती हैं कि इन चीजों के प्रयोग करती बार कोई हादसा हो गया। सर्दियों में गैस गीजर, कोयले की अंगीठी और अन्य गर्मी प्रदान करने वाले उपकरण लोगों की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। सर्दियों के मौसम में नहाने के लिए लोग गैस से चलने वाले गीजर का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके प्रयोग में जरा सी भी असावधानी किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। गैस गीजर को बाथरूम में लगाने के साथ–साथ एक खिड़की जरूर रखें। लोगों को चाहिए कि जहां गैस गीजर लगा हो वहां हवा बाहर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए अर्थात एडजोस्ट फैन बाथरूम में होना चाहिए। –राजेश कुमार चौहान, सुजानपुर टीहरा

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

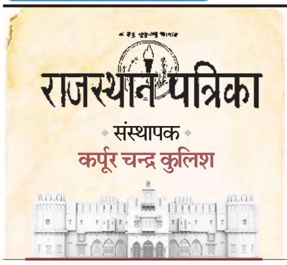

अपराधों में महिलाओं की बढ़ती संलिप्तता चिंताजनक

महिलाओं में शिक्षा का प्रसार और सशक्तीकरण के दावे उस वक्त मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं जब यह तथ्य सामने आता है कि भारतीय जेलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले दुगुनी तेजी से बढ़ रही है। इंस्टीट्यूट फॉर क्राइम एंड जस्टिस पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट का यह खुलासा चिंताजनक है। इसमें कहा गया है कि भारतीय जेलों में महिलाओं की हिस्सेदारी कम होने के बावजूद जेलों में महिला कैदियों की संख्या दो दशक में 162 फीसदी बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार महिला कैदियों के मामले में दुनिया में भारत का स्थान छठा है। चिंता की बात यह भी है कि जेलों में महिलाओं के अनुकूल सुविधाएं नहीं हैं।

बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं का सशक्तीकरण जिस तरह बढ़ा है उसके मुकाबले महिलाएं अपराध से विमुख क्यों नहीं हो रहीं? अपने हकों की लड़ाई में आगे रहने वाली महिलाओं की आखिर आपराधिक प्रवृत्ति क्यों होने लगी है? एक आशंका यह भी सामने आती है कि कहीं खुद के बचाव में पुरुष ही तो महिलाओं को अपराध की दुनिया में धकेलने नहीं लग गए हैं। कई मामलों में जांच के दौरान यह बात सामने आती रही है। खास तौर से मादक पदार्थ और अन्य वस्तुओं की तस्करी में महिलाओं को जोड़ने का दौर बढ़ने लगा है। अमरीका और चीन जैसे विशाल आबादी के देशों से तुलना करें तो हम यह संतोष जरूर कर सकते हैं कि हमारे यहां की जेलों में महिला बंदियों की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है। लेकिन महज चार फीसदी संख्या में महिला बंदी होने के बावजूद आपराधिक मामलों में इनकी भागीदारी का लगातार बढ़ना कई खतरों की ओर संकेत करता है। सबसे बड़ा खतरा तो बच्चों की परवरिश का है, जिसमें बाधा आती है। गौर करें तो इसकी जड़ें सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, पारिवारिक दबावों और लैंगिक पूर्वाग्रहों में हैं, जहां महिलाएं अक्सर गरीबी, घरेलू हिंसा और मानसिक आघात की शिकार होकर अपराध की ओर मुड़ जाती हैं। घरेलू हिंसा से जुड़े मामले जैसे- दहेज हत्या, चोरी, धोखाधड़ी और कभी-कभी हत्या की वारदात तक इनमें शामिल हैं। यह बात सही है कि महिलाओं में आई जागरूकता उन्हें अधिकारों के लिए लड़ने को प्रेरित करती है, लेकिन जब बात आर्थिक असुरक्षा और पारिवारिक दबाव की होती है तो वे अपराध के रास्ते में आसानी से धकेल दी जाती हैं।

उन मामलों में भी सख्ती करने की जरूरत है, जहां खुद के बचाव में पुरुष महिलाओं को मोहरा बनाते हुए चोरी, डकैती व तस्करी जैसे अपराधों को कारित करते हैं। अब चिंता इस बात पर करना जरूरी है कि अपराध की राह पकड़ने वाली महिलाओं के पुनर्वास प्रयासों को गति दी जाए। परामर्श व रोजगार प्रशिक्षण जैसे प्रयासों को गति देने की जरूरत है ताकि जेलों में बंद महिलाएं सजा पूरी होने के बाद पुनः अपराध के दलदल में न फंसे और आत्मनिर्भर होकर अपना सुरक्षित जीवन यापन कर सकें।

संतुलित उदारीकरण: इंडो पैसिफिक में बढ़ेगी भारत की आर्थिक मौजूदगी

भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते ने दिया बड़ा भू-राजनीतिक संकेत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दिसंबर 2025 में सिर्फ नौ महीनों की बातचीत के बाद सम्पन्न हुआ। यह समझौता उस समय सामने आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था विखंडन, सुस्त बहुपक्षीय वार्ताओं और ठप पड़े बड़े व्यापार समझौतों के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में यह संकेत है कि भारत अब अपने 'विकसित भारत 2047' विजन के अनुरूप, सीमित लेकिन उच्च-गुणवत्ता वाले द्विपक्षीय समझौतों को तरजीह दे रहा है। भले ही द्विपक्षीय व्यापार का आकार अभी छोटा है, लेकिन इस समझौते के रणनीतिक, क्षेत्रीय और भू-राजनीतिक प्रभाव कहीं अधिक व्यापक हैं।

के.एस. तोमर
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक
@patrika.com

यह दिखाता है कि भारत विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ सेवाओं, गतिशीलता और विनियामक सहयोग पर आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर रहा है, जबकि डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को सावधानी से सुरक्षित रखा गया है। न्यूजीलैंड के लिए यह समझौता दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजारों में व्यवस्थित प्रवेश का अवसर है, हालांकि घरेलू राजनीतिक असहमति इसके भीतर मौजूद असमानताओं को उजागर करती है। आशाओं के बावजूद कई चुनौतियां मौजूद हैं। सबसे पहली चुनौती टैरिफ असमानता की है। न्यूजीलैंड में औसत शुल्क लगभग 2.3 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह करीब 16 प्रतिशत है। ऐसे में भारतीय निर्यातकों को पहले से ही काफी खुला बाजार मिला हुआ था। यदि निर्यात बढ़ाने के लिए आक्रामक प्रचार और कारोबारी नेटवर्क विकसित नहीं किए गए, तो व्यापार में बढ़ोतरी सीमित ही रह सकती है।

दूसरी चुनौती राजनीतिक है। आव्रजन प्रावधानों और डेयरी क्षेत्र के बाहर रहने पर न्यूजीलैंड में उठ रहा विरोध, संसद में मंजूरी की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकता है। तीसरा, गैर-टैरिफ बाधाएं, मानक पालन और लॉजिस्टिक सीमाएं बड़ी रुकावट हैं। यदि नियामक सहयोग, एसपीएस व्यवस्था और कस्टम सुविधा प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुए, तो टैरिफ में राहत का लाभ व्यावहारिक व्यापार में नहीं बदल पाएगा। अंततः, एफटीए का लाभ उठाने में भारत की क्षमता पहले भी असमान रही है। जब तक संस्थागत सहायता, एमएसएमई में जागरूकता और घरेलू औद्योगिक नीति के साथ तालमेल न हो, तब तक उपयोग दरें सीमित रहती हैं। भारत के लिए इस समझौते का असर सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक-रणनीतिक भी है। यह इंडो-पैसिफिक और ओशियानिया क्षेत्र में भारत की आर्थिक मौजूदगी को गहरा करता है और एक उच्च-आय, ओईसीडी अर्थव्यवस्था के साथ नियम-आधारित साझेदारी को मजबूत बनाता है। इससे यह संदेश जाता है कि भारत अंधाधुंध सुरक्षावादी नीति से हटकर सावधानीपूर्वक उदारीकरण का रास्ता अपना रहा है।

न्यूजीलैंड के लिए स्थिति राजनीतिक तौर पर अधिक संवेदनशील है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इसे विकास के अवसर के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन डेयरी क्षेत्र को बाहर रखने से आलोचना तेज है, क्योंकि यह उसके कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा है। आरोप है कि आव्रजन और सेवाओं में रियायतें देने के बावजूद माल व्यापार में लाभ सीमित हैं। संसद में मंजूरी की परीक्षा कठिन हो सकती है।

भारत के लिए सबसे बड़ा लाभ है- न्यूजीलैंड के बाजार में 100 प्रतिशत निर्यात पर शून्य शुल्क। इससे विशेष रूप से श्रम-प्रधान और विनिर्माण क्षेत्र जैसे वस्त्र, जूते-चप्पल, इंजीनियरिंग सामान, दवाएं, रसायन और प्रोसेस्ड फूड को बढ़त मिल सकती है। सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक बाजार पहुंच, फार्मा और मेडिकल डिवाइस के लिए तेज मंजूरी और वैश्विक मानकों की स्वीकृति, गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करती है। निवेश और सेवाओं में भी नई संभावनाएं खुलती हैं- अगले 15 वर्षों में लगभग 20 बिलियन डॉलर तक निवेश की संभावनाएं बताई गई हैं, जिनसे अवसंरचना, कृषि-प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवाचार और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है। भारत-न्यूजीलैंड एफटीए न तो क्रांतिकारी है और न ही मामूली। असली महत्व रणनीतिक स्थिति, सेवाओं के उदारीकरण और लोगों की आवाजाही में छिपा है। भारत के लिए यह संतुलित उदारीकरण का उदाहरण है, जबकि न्यूजीलैंड के लिए यह उभरती शक्ति के साथ शुरुआती साझेदारी का अवसर है- राजनीतिक जोखिमों के बावजूद। अब असली परीक्षा कार्यान्वयन की है। यदि सरकारें और निजी क्षेत्र मिलकर ठोस कदम उठाएं, तो यह समझौता भविष्य में भारत की पैसिफिक क्षेत्र की व्यापारिक रणनीति का मॉडल बन सकता है।

मिलेट्स: भविष्य के भोजन के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता

स्वास्थ्य ही नहीं, स्वाद और सुविधा का विकल्प भी बन रहा 'श्री अन्न'

श्री अन्न यानी मोटे अनाज को लेकर देश में बीते कुछ वर्षों में जो जागरूकता बढ़ी है, वह केवल एक सरकारी पहल तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे-धीरे एक सामाजिक, आर्थिक और पोषण आंदोलन का रूप ले चुकी है। कभी गरीबों का अनाज कहे जाने वाले बाजरा, ज्वार और रागी आज स्वास्थ्य, पर्यावरण और टिकाऊ खेती के प्रतीक बनते जा रहे हैं। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किए जाने के बाद भारत इस वैश्विक अभियान का नेतृत्वकर्ता बनकर सामने आया है, जिसने देश के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर इस विषय को नई पहचान दी।

बलवंत राज मेहता
वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार
@patrika.com

तथ्यों पर नजर डालें तो भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक देश है और वैश्विक उत्पादन का लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा भारत से आता है। यह आंकड़ा केवल उत्पादन क्षमता नहीं दर्शाता, बल्कि भारत की पारंपरिक कृषि समझ और विविधता की भी कहानी कहता है। देश के भीतर राज्यों की बात करें तो राजस्थान इस दौड़ में सबसे आगे है। कुल मिलेट उत्पादन में लगभग 28 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ राजस्थान शीर्ष पर है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य भी प्रमुख योगदानकर्ता हैं। यह उल्लेखनीय है क्योंकि ये वही क्षेत्र हैं जहां पानी की कमी, सूखा और जलवायु परिवर्तन लंबे समय से खेती के लिए चुनौती बने रहे हैं। ऐसे में श्री अन्न ने कम पानी में टिकाऊ खेती का भरोसेमंद विकल्प प्रस्तुत किया है।

जागरूकता का सबसे स्पष्ट असर शहरी भारत में देखने को मिलता है। बाजरा, ज्वार और रागी अब केवल ग्रामीण रसोई या पारंपरिक भोजन तक सीमित नहीं हैं। मल्टीग्रेन आटा, मिलेट कुकीज, रागी पास्ता, ज्वार फ्लेक्स और रेडी-टू-ईट उत्पाद आज सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध हैं। शहरी उपभोक्ता अब इन्हें केवल स्वास्थ्य कारणों से नहीं, बल्कि स्वाद और सुविधा के विकल्प के रूप में भी अपना रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मिलेट रिसर्च संस्थानों द्वारा विकसित रेडी-टू-ईट उपमा, हलवा और स्नैक्स जैसे उत्पाद यह सिद्ध करते हैं कि श्री अन्न परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बना सकता है। इस बदलाव में स्टार्टअप्स और महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका भी अहम रही है। मिलेट आधारित बेकरी उत्पाद, स्नैक्स, इंस्टेंट मिक्स और पैकेज्ड फूड न केवल बाजार में नए विकल्प लेकर आए हैं, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। इससे श्री अन्न केवल पोषण का विषय नहीं रह गया, बल्कि आजीविका और उद्यमिता से भी जुड़ गया है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो श्री अन्न की संभावनाएं भारत की सीमाओं से कहीं आगे जाती हैं। अफ्रीका और एशिया के कई सूखे और अर्ध-शुष्क देशों के लिए मिलेट्स जलवायु-अनुकूल फसल के रूप में उभर रहे हैं। कम पानी की आवश्यकता, कम रासायनिक इनपुट और अधिक पोषण ये तीनों गुण इसे भविष्य की खाद्य सुरक्षा से जोड़ते हैं। भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर श्री अन्न को स्मार्ट फूड के रूप में प्रस्तुत करने से निर्यात, शोध और वैश्विक सहयोग की नई राहें खुली हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर और कृषि कूटनीति को भी मजबूती देता है। हालांकि, इस सफलता की तस्वीर पूरी तरह उजली नहीं है। किसान स्तर पर अब भी सबसे बड़ी चुनौती बाजार और भरोसे की बनी हुई है। कई क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रभावी खरीद व्यवस्था नहीं है। स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों की कमी के कारण किसान कच्चा माल बेचने तक ही सीमित रह जाते हैं और मूल्यवर्धन का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। सुधार की संभावनाएं स्पष्ट हैं और व्यावहारिक भी। हर प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में छोटे और मध्यम स्तर के मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। स्कूलों के मध्यान्ह भोजन, आंगनवाड़ी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में श्री अन्न का नियमित उपयोग इसके उपभोग को जन-आदत बना सकता है। सबसे जरूरी यह है कि श्री अन्न को फैशन फूड के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

श्री अन्न को लेकर देश में जागरूकता एक मजबूत आधार पर खड़ी हो चुकी है और राजस्थान जैसे राज्यों ने इसे ठोस उत्पादन का सहारा भी दिया है। अब अगली चुनौती इस जागरूकता को स्थायी अवसर में बदलने की है, ताकि यह केवल थाली तक सीमित न रहे, बल्कि किसान की आय बढ़ाए, उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करे और भारत को वैश्विक खाद्य नेतृत्व की भूमिका में और सशक्त बनाए। यही श्री अन्न अभियान की वास्तविक व निर्णायक कसौटी होगी।

बुक इनसाइट

स्वून

बीया मार्टिनेज गैटेल की पुस्तक स्वून अनोखा और विचारोत्तेजक सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन है। यह किताब आम धारणा को चुनौती देती है कि किसी कलाकार या सेलिब्रिटी के प्रति महिलाओं का आकर्षण केवल भावुकता या हल्केपन का प्रतीक है। लेखिका इस आकर्षण को इतिहास, राजनीति और सामाजिक बदलाव से जोड़कर देखती हैं।

भाषा की दृष्टि से यह पुस्तक सहज, प्रवाहपूर्ण और तथ्यात्मक है। हालांकि विषय गंभीर है।

आपकी बात

स्थानीय भाषा में वित्तीय साक्षरता

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर काफी कम है, जिसके कारण ग्रामीण महिलाएं वित्तीय नियोजन, स्मार्ट बचत, ऑनलाइन धोखाधड़ी आदि को नहीं समझ पाती हैं। सूक्ष्म वित्त, वित्तीय नियोजन, घरेलू बजट और बचत के महत्व को समझाने के लिए स्थानीय भाषाओं में सरल और सचित्र शैक्षिक सामग्री तैयार की जानी चाहिए।

- डॉ. प्रेमराज मीना, करौली

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं?' ऑनलाइन भी देखें। https://shorturl.at/RoTyV

समसामयिक विषयों पर पाठकों के विचार आमंत्रित हैं। चुनिंदा विचार प्रकाशित किए जाएंगे।

ईमेल करें: edit@epatrika.com

FORWARD 2026 नए पल लिखेंगे नई कहानियां...

जरा सोचें

विश्वास के साथ पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाएं।

***-मार्टिन लूथर किंग जूनियर**, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता*

ये केवल रुझान नहीं, आने वाले दशक की पटकथा हैं। जो देश, संस्थाएं और समाज इन्हें समय रहते समझ लेंगे, वही भविष्य को आकार देंगे...

दुनिया के मोड़ पर... वे संकेत, जिन्हें इस साल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

दुनिया तेजी से बदल रही है। कहीं शहर बेहद विशाल होते जा रहे हैं, कहीं समुद्र रास्तों की वजह से देश असुरक्षित हो रहे हैं, तो कहीं अंतरिक्ष में नए मोर्चे खुल रहे हैं। गोल्ड युद्धों को लंबा कर रहा है, रेल मार्ग दोस्ती और दुश्मनी दोनों को आकार दे रहे हैं और ग्रहों की चाल तय कर रही है कि हम मंगल की ओर कब उड़ान भर सकते हैं। इन वैश्विक रुझानों की मदद से हम यह समझ सकते हैं कि 2026 और उसके बाद की दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है और हम सब किस तरह इन बदलावों से प्रभावित होने वाले हैं। ये वे जगहें हैं, जहां आज फैसले लिए जा रहे हैं और कल इतिहास लिखा जाएगा।

अमरीका

मध्यावधि चुनावों पर चुनावी क्षेत्र बदलाव का असर

अधिकतर अमीर लोकतंत्रों के विपरीत, अमरीका में कई राज्यों में राजनेता खुद चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तय करते हैं, जिससे वे अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। यह दो तरीकों से होता है, पहला पैकिंग, जिसमें वोटरों को कुछ ही क्षेत्रों में समेट दिया जाता है और दूसरा क्रैकिंग, जिसमें उन्हें कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। दक्षिणी रिपब्लिकन राज्य कुछ डेमोक्रेटिक सीटें खत्म कर सकते हैं, बशर्ते नए चुनावी क्षेत्र नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले बन जाएं।

मंगल पर जाने का अच्छा साल

***पृथ्वी** से मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजने का सबसे अच्छा समय तब है जब पृथ्वी, मंगल की कक्षा में 44 डिग्री पीछे हो। इस समय लॉन्च किया गया यान होमन ट्रांसफर ऑर्बिट का उपयोग करता है। यह ईंधन की दृष्टि से सबसे अच्छा मार्ग है। यह खास सौरमंडल संरेखण हर 26 महीने में केवल एक बार होता है। अगली संभावना 2026 के अंत में है, जब एलन मस्क की स्टारशिप रोबोट यान भेजने की योजना है। यदि यह मौका चूक गया, तो अगली लॉन्च विंडो 2028 के अंत तक नहीं आएगी।*

पिछले ग्रहणों से तुलना 2026 के सूर्यग्रहण

***सभी** सूर्यग्रहण समान नहीं होते। पूर्ण ग्रहण का छायांकन कई बार यह समुद्र में या कम आबादी वाले क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। 2026 में होने वाले दो ग्रहण देखने के लिहाज से इतने अनुकूल नहीं हैं। 17 फरवरी 2026 को पड़ने वाला ग्रहण केवल अंटार्कटिका से दिखाई देगा, जो पहुंचने के लिए बहुत कठिन जगह है। वहीं 12 अगस्त 2026 को पड़ने वाला पूर्ण सूर्यग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तर स्पेन में दिखाई देगा। सबसे लंबा पूर्णता बिंदु (लगभग 2 मिनट) आइसलैंड के पश्चिम में होगा। लेकिन मौसम अधिक अनुकूल स्पेन में होने की संभावना है, इसलिए ग्रहण देखने के शौकीनों के लिए सुरक्षित विकल्प स्पेन होगा।*

सूडान में कैसे पीला धातु बनाए रख रहा संघर्ष

वर्ष 2023 में सूडान में छिड़े गृहयुद्ध के पीछे एक बड़ी वजह सोने पर नियंत्रण की लड़ाई थी। सूडानी सेना (सूडानीज आर्म्ड फोर्स-एसएएफ) और रेपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ), दोनों ही सोने के कारोबार से मिले पैसे से हथियार खरीदते हैं, अपना प्रभाव बढ़ाते हैं और खुद को मजबूत करते हैं। देश में छोटे पैमाने पर सोने का उत्पादन बढ़ा है और तस्करी के जरिए बाहर भेजा गया सोना युद्ध को जारी रखने के लिए लगातार पैसा देता रहता है।

सोने की तस्करी के रास्ते..

एसएएफ मिस्र के जरिए, आरएसएफ दक्षिण सूडान, इथियोपिया और चाड के रास्ते तस्करी करते हैं। ज्यादातर सोना अंत में यूएई में बिकता है। सोने का यह व्यापार क्षेत्रीय राजनीति को उलझाता है और युद्ध को लंबा खींचता है। आर्थिक संकट से जूझ रहा मिस्र, सोने से मिलने वाले लाभ के कारण एसएएफ का मजबूत समर्थक बना रहता है और युद्ध खत्म कराने का दबाव डालने से कतराता है। सूडानी सोने का बड़ा व्यापारिक केंद्र होने के कारण एसएएफ सार्वजनिक रूप से यूएई की आलोचना करने से बचता है क्योंकि उस पर आरएसएफ को हथियार देने के बदले सोना लेने के आरोप लगते रहे हैं (जिन्हें यूएई नकारता है)।

***इसका** नतीजा यह है कि जब तक सोना बहता रहेगा, कई पक्ष सूडान के भीतर और बाहर उससे फायदा उठाते रहेंगे और इसी वजह से शांति की राह लगातार रुकती रहेगी।*

चांद के दक्षिणी ध्रुव की खतरनाक मोहकता

वर्ष 2019 से अब तक भेजे गए 13 चंद्र लैंडर्स में से 5 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है। वर्ष 2026 में लॉन्च होने वाले 4 मिशनों में से 2 (अमरीका का ब्लू मून पाथफाइंडर एम1 और चीन का चेंज-7) भी उसी क्षेत्र की ओर जाएंगे। यानी कुल लैंडर्स का लगभग 40 फीसदी उस इलाके में गए हैं, जबकि वह क्षेत्र चांद की सतह का सिर्फ सात फीसदी है। दक्षिणी ध्रुव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमेशा छाया में रहने वाले गड्ढों में पानी की बर्फ होने की संभावना है, जिसे भविष्य में चांद पर बेस और रॉकेट ईंधन बनाने में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि यह इलाका बेहद जोखिमभरा है। वर्ष 2024 और 2025 में दक्षिणी ध्रुव पर भेजे गए दो अमरीकी लैंडर ऊबड़-खाबड़ जमीन पर गिर गए। यानी जिन गड्ढों में पानी मिल सकता है, वही लैंडिंग को मुश्किल भी बनाते हैं। फिर भी अमरीका और चीन, दोनों अगले कुछ वर्षों में वहां अपने अंतरिक्ष यात्री भेजने की दौड़ में हैं और वर्ष 2026 में यह खोज जारी रहेगी।

ताइवान की भौगोलिक बनावट उसे क्यों असुरक्षित बनाती है

ताइवान के सबसे बड़े बंदरगाह उत्तर और पश्चिम में हैं, जो ताइवान जलसंधि (ताइवान स्ट्रेट) और चीन के तट के पास स्थित हैं। इसी कारण चीन अगर समुद्री नाकाबंदी करे तो ताइवान आसानी से निशाने पर आ सकता है। पूर्वी तट पर मौजूद छोटे बंदरगाहों को बड़ा बनाकर जोखिम नहीं घटाया जा सकता क्योंकि ताइवान का लगभग 70 फीसदी हिस्सा पांच पर्वतमालाओं से ढका है। अगर पूर्वी तट पर एक बड़ा बंदरगाह बना भी लिया जाए, तब भी उसे देश के मुख्य शहरों से जोड़ना बेहद कठिन और महंगा होगा।

चीन की नई सुरक्षा रणनीति

माना जाता है कि शी जिनपिंग 2027 तक अपनी सेना को ताइवान पर कार्रवाई के लिए तैयार रखना चाहते हैं। आशंका है कि यह पूरी तरह से हमला न होकर समुद्री नाकाबंदी अधिक होगा। ऐसी किसी भी कार्रवाई पर ताइवान के सहयोगी देश पलटवार कर सकते हैं। इससे मलक्का जलडमरूमध्य बंद हो सकता है, जहां से चीन को खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई मिलती है। इसी जोखिम को ध्यान में रखते हुए चीन अलग-अलग देशों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर निवेश कर रहा है ताकि ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहे।

म्यांमार

चीन ने गृहयुद्ध के दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखकर अपने हित बचाए हैं, जिनमें 2500 किमी लंबी तेल-गैस पाइपलाइन शामिल है, जो चीन को हिंद महासागर से जोड़ती है। यह पाइपलाइन ऊर्जा के लिए मलक्का के विकल्प देती है, लेकिन चीन की दखलअंदाजी से वहां संघर्ष खत्म होने की संभावना 2026 में कम है।

किर्गिस्तान

उज्बेकिस्तान रेलमार्ग (रूस को बायपास करते हुए) - यह चीन को सीधे यूरोप तक जोड़ सकता है और रूस पर निर्भरता कम करेगा। ट्रंप की व्यापार नीतियों से अमरीका को निर्यात मुश्किल होने पर यह रास्ता यूरोप में सामान भेजने का सहारा बन सकता है। साथ ही, अगर भविष्य में रूस से संबंध बिगड़ें, तो यह एक बीमा पॉलिसी की तरह काम करेगा।

पाक का ग्वादर पोर्ट

पश्चिमी चीन से ग्वादर तक रेल मार्ग चीन के लिए दूसरा रणनीतिक विकल्प है, लेकिन लागत बढ़ने और पाकिस्तान के कर्ज के डर से यह प्रोजेक्ट धीमा और छोटा कर दिया गया है।

दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौनसा है?

अगर कोई एलियन अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखे और सिर्फ उन जगहों को चिह्नित करे, जहां आबादी सबसे ज्यादा है, तो जवाब बिल्कुल साफ दिखाई देगा पर्ल रिवर डेल्टा। यह दक्षिणी चीन के कई शहरों की एक लंबी शृंखला है। अनुमान है कि 2026 के आखिर तक यहां की आबादी लगभग 7 करोड़ 30 लाख तक पहुंच जाएगी।

बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

होशियारपुर, ईएमएस। पंजाब के होशियारपुर में गुरुवार सुबह गढ़शंकर इलाके में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसा बोरहा गांव के जलआपूर्ति कार्यालय के पास हुआ।

अपशिष्ट प्रबंधन कारखाने में भीषण आग

कोझिकोड, ईएमएस। केरल के थामरसेरी इलाके में गुरुवार तड़के अपशिष्ट प्रबंधन कारखाने में भीषण आग लग गई। पुलिस ने बताया कि आग तड़के करीब तीन बजे लगी, जिसने कार्यालय क्षेत्र सहित पूरी इमारत को अपनी चपेट में लेकर नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना में वहां खड़ी एक पिकअप वैन भी जलकर खाक हो गई।

संपादकीय

इजराइल और यूएस की दादागिरी को दुनिया के देशों की चुनौती

वैश्विक व्यापार में स्वदेशी करंसी का महत्व बढ़ा

वर्ष 2026 वैश्विक व्यापार को लेकर एक नई आधार शिला रखने की ओर आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के सैकड़ों मुल्क वैश्विक लेन-देन में डॉलर की एक ध्रुवीय व्यवस्था से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से सैन्य ताकत, आर्थिक प्रतिबंधों और राजनीतिक दबाव के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अपने हितों के अनुसार संचालित कर एक अलग तरीके का दबाव बनाकर आतंक पैदा कर रहे थे। अमेरिका के साथ नाटो के देश भी इसमें शामिल हो जाते थे। अब यही रणनीति उनके लिए चुनौती बनती जा रही है। कई देश इस 'दादागिरी' के खिलाफ खुलकर खड़े होकर वैकल्पिक लेन-देन की व्यवस्था करने लगे हैं। जिसका असर अमेरिका के ऊपर स्पष्ट रूप से पड़ता हुआ दिख रहा है। डॉलर एवं यूरो मुद्रा का लेन-देन दिन-प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। मुद्रा का उपयोग अमेरिका और यूरोपीय समुदाय ने प्रतिबंध के लिए करना शुरू कर दिया था। यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष ने अमेरिका और इजराइल की दोहरी नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। एक ओर लोकतंत्र, मानवाधिकार और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बातें की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिबंध, एसेट फ्रीज और सैन्य हस्तक्षेप कर कई देशों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। रूस के सेंट्रल बैंक के अरबों डॉलर के एसेट्स को फ्रीज करना इसी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। रूस-चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा रूबल और युआन में हो रहा है। वहीं पश्चिम एशिया में ऊर्जा व्यापार के लिए भी डॉलर के विकल्प की तलाश हो रही है। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। इससे अमेरिकी और यूरोपीय देशों के प्रतिबंध के असर और जोखिम को सीमित करने की कोशिश लगभग 40 देशों में शुरू हो गई है। विभिन्न देश अपनी करंसी में व्यापार को महत्व देने लगे हैं। इसका एक बड़ा लाभ यह है, विकासशील देशों पर डॉलर का दबाव कम होता जा रहा है। मुद्रा की अस्थिरता का जोखिम भी कम हो रहा है। इस नई व्यवस्था से विभिन्न देशों को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने और सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों पर भरोसा बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों में चीन का सीआईपीएस रूस का, एसपीएफएस और भारत का यूपीआई का प्रभाव तेजी के साथ वैश्विक व्यापार में बढ़ रहा है। जो अर्थव्यवस्था के बड़े बदलाव का संकेत है। इजराइल-हमास युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र में बार-बार वीटो का इस्तेमाल करने से वैश्विक असंतोष और विभिन्न देशों के बीच में असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। जिसके कारण डॉलर के स्थान पर मिश्रित मुद्राओं में वैश्विक व्यापार की नई शुरुआत हो गई है। ग्लोबल साउथ के देशों में यह धारणा बन चुकी है, कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निष्पक्ष तरीके से अपना काम नहीं कर रही हैं। यही कारण है कि अब कई देश पश्चिमी दबदबे को चुनौती देने के लिए आर्थिक सहयोग और वैश्विक लेन-देन में मिश्रित मुद्राओं के जरिए लेन-देन करने की ओर बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका, यूरोपीय देश और इजराइल की आक्रामक नीतियों ने अनजाने में ही सही एक नई वैश्विक सोच को जन्म दे दिया है। लोकल करंसी में व्यापार का बढ़ता चलन यह दर्शाता है। दुनिया धीरे-धीरे एक अधिक संतुलित और बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। यह बदलाव कितना प्रभावी होगा, यह आने वाला समय तय करेगा। इस परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। वैश्विक व्यापार में डॉलर की पुरानी व्यवस्था अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। दिन प्रतिदिन डॉलर को विभिन्न देशों से चुनौती मिल रही है। अमेरिका की साहूकारी में यह सबसे बड़ा झटका है। डॉलर मुद्रा के रूप में वैश्विक व्यापार होने से अमेरिका को बड़ी कमाई होती थी। अमेरिका की दादागिरी दुनिया के सभी देशों में देखने को मिलती थी, लेकिन जब से रूस और चीन जैसे देशों से चुनौती मिलना शुरू हुई है। विशेष रूप से जब रूस जैसी महाशक्ति की मुद्रा को अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रूस की संपत्ति और मुद्रा को सीज कर प्रतिबंध लगाया, तो उसका भय सारी दुनिया के देशों में फैला। रही सही कसर इजराइल और फिलिस्तीन में गाजा युद्ध के दौरान जो दादागिरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अमेरिका और इजराइल की रही उसने एक नई सोच को जन्म दे दिया है। आज विभिन्न देश आपस में यह तय करने में लगे हैं कि भुगतान किस-किस मुद्रा में कितने प्रतिशत में किया जाएगा। यूपीआई आ जाने के कारण अब वैश्विक व्यापार में लेन-देन यूपीआई के जरिए तुरंत होने लगा है जिसके कारण डॉलर मुद्रा को सारे विश्व से चुनौती मिलना शुरू हो गई है। सभी दुनिया के देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का भंडारण कम करके उसके स्थान पर सोने का भंडारण करना शुरू कर दिया है। जिन देशों के साथ उनके कारोबारी रिश्ते हैं। वह अपनी जरूरत के अनुसार विभिन्न मुद्राओं में भुगतान करके डॉलर से बच रहे हैं। इससे अमेरिका को दोहरा नुकसान हो रहा है। डॉलर में भुगतान होने के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ हो रहा था। वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक में विदेशी मुद्रा में डॉलर को प्राथमिकता मिलने से डॉलर मजबूत होता था। अब डॉलर के स्थान पर सभी देशों के सेंट्रल बैंक सोने को मुद्रा के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण अमेरिका को सारी दुनिया के देशों से एक अलग आर्थिक चुनौती मिलना शुरू हो गई है। अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है। यदि यही स्थिति आगे भी देखने को मिलती रही, तो अमेरिका की दादागिरी जल्द ही खत्म होने वाली है। जिस तरह से सोवियत रूस के हाल हुए थे, वही स्थितियां अब अमेरिका में बनने लगी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तेजना में जिस तरह के निर्णय कर रहे हैं, उसके कारण वैश्विक स्तर पर अमेरिका की साख दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। वहीं अमेरिका के लिए आर्थिक चुनौतियां भी बढ़ती चली जा रही हैं।

\- सनत जैन

राज काज

महाराष्ट्र की राजनीति में अडानी का बोलबाला

महाराष्ट्र की राजनीति में गौतम भाई अडानी कुबेर की भूमिका में है। सभी राजनीतिक दलों को विशेष रूप से शरद पवार और अजीत पवार के साथ उनके जो घनिष्ठ रिश्ते हैं। शरद पवार के आसपास सत्ता बनी रहती है। गौतम भाई अडानी भाजपा के खास हैं। पिछले 10 वर्ष में महाराष्ट्र की राजनीति उन्हीं के आसपास घूम रही है। भले सामने शरद पवार आते हों। पैसे की भूमिका गौतम भाई अडानी ही पूरी करते हैं। अडानी राजनीति की बिसात बिछाते हैं। अजीत पवार को उन्होंने एनसीपी से अलग किया। भाजपा की सरकार में शामिल किया। अब बारामती और पुणे के चुनाव के लिए भाजपा के खिलाफ दोनों को एक साथ लेकर आ गए। यह जादूगरी केवल गौतम अडानी ही कर सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र में इसकी चर्चा हो रही है।

100 करोड़ रुपए देंगे चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है। आंध्र प्रदेश का कोई भी व्यक्ति यदि क्वांटम कंप्यूटिंग में नोबेल पुरस्कार जीतेगा। उसे आंध्र सरकार 100 करोड़ रुपए के पुरस्कार से सम्मानित करेगी। यह बहुत बड़ी रकम है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। चंद्रबाबू नायडू द्वारा 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया जाना, सबको आश्चर्यचकित कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू चाहते तो 200 करोड़ रुपए खर्च करके क्वांटम कंप्यूटिंग का अच्छा रिसर्च केंद्र आंध्रा में बना सकते थे। चंद्रबाबू नायडू की इस घोषणा से विश्व स्तर पर उनकी चर्चा हो रही है। इसे कहते हैं, हर लगे ना फिटकरी-रंग चोखा हो जाए।

विकास के नाम पर जंगलों की सुनियोजित हत्या !

सोनम लववंशी

अखबारों की सुर्खियाँ जब किसी शहर पर बंदरों के 'आतंक' की बात करती हैं या किसी गाँव को हाथियों और भालुओं की दहशत में दिखाती हैं, तब समाज सहज रूप से एक निष्कर्ष पर पहुँच जाता है, कि वन्यजीव समस्या हैं। यह निष्कर्ष सुविधाजनक है, भावनात्मक भी और सत्ता-तंत्र के लिए उपयोगी भी। इसी सुविधा के बीच कहीं अधिक भयावह सच अदृश्य बना रहता है और वह है जंगलों पर संगठित, सुनियोजित और वैध ठहराया गया वह आतंक, जो उद्योग, परियोजना और निवेश के नाम पर फैलाया जा रहा है। यह आतंक शोर नहीं करता, खून नहीं दिखाता, फिर भी इसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। दरअसल ग्लोबल वॉर्मिंग आज केवल वैज्ञानिक शब्द नहीं रह गया है। यह हर सूखते जलस्रोत, हर बढ़ती लू, हर अनियमित बारिश और हर जहरीली हवा में दर्ज हो चुका है। पृथ्वी का तापमान लगातार ऊपर जा रहा है और इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण वही है, जिसे हम विकास का उत्सव कहकर नजरअंदाज करते आए हैं। जंगलों का विनाश इस पूरी प्रक्रिया की धुरी है। जब वृक्ष कटते हैं, तब केवल लकड़ी नहीं हटती, बल्कि कार्बन को रोकने वाली प्राकृतिक ढाल भी खत्म होती है। धरती की त्वचा नंगी होती जाती है और सूरज की तपिश सीधे उसके भीतर उतरने लगती है। भारत जैसे देश में यह अपराध और अधिक गंभीर है, जहाँ जंगल केवल पर्यावरणीय इकाई नहीं, सांस्कृतिक स्मृति, जीवन पद्धति और सामाजिक संतुलन का आधार रहे हैं। इसके बाद भी बीते चार वर्षों में देशभर में 78,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को गैर-वनीय उपयोग

के लिए स्वीकृति दी गई। यह आँकड़ा अपने आप में एक आरोप-पत्र है। मध्य प्रदेश में 17,393 हेक्टेयर, ओडिशा में 11,033 हेक्टेयर, अरुणाचल प्रदेश में 6,561 हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 5,480 हेक्टेयर और छत्तीसगढ़ में 4,092 हेक्टेयर वन क्षेत्र विकास परियोजनाओं के हवाले किया गया। इन संख्याओं के पीछे उजड़े जंगल, विस्थापित आदिवासी, सूखती नदियाँ और टूटता जैव-विविधता का ताना-बाना छिपा है और इसी बीच अरावली पहाड़ी को लेकर गढ़ी गई नई परिभाषा इस पूरे श्रृंखला के अधिकतर हिस्से के विनाश का प्रतीक बन सकती है। गौर करने वाली बात है कि यह पहाड़ियाँ उत्तर भारत के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच रही हैं। रेगिस्तान के फैलाव को रोकना, भूजल को संजोना, प्रदूषण को थामना, ये सभी जिम्मेदारियाँ अरावली सदियों से निभाती आई हैं। खनन, रियल एस्टेट और तथाकथित विकास के नाम पर इन्हें खोखला किया जा रहा है। अरावली को नुकसान पहुँचाने का अर्थ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भविष्य को दाँव पर लगाना है। यह केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि नीति-निर्माण की संवेदनहीनता का प्रमाण है। इसके अलावा वनों को अक्सर पेड़ों की गिनती में समेट दिया जाता है। यह दृष्टि खतरनाक है। जंगल एक जीवित व्यवस्था हैं, जहाँ मिट्टी, पानी, हवा, कीट, पक्षी, जानवर और मनुष्य एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं।

एक पेड़ कटता है तो उसके साथ सैकड़ों जीवन-श्रृंखलाएँ टूटती हैं। पक्षियों के घोंसले उजड़ते हैं, मिट्टी की पकड़ कमजोर होती है, वर्षा का चक्र असंतुलित होता है। यही असंतुलन धीरे-धीरे बाढ़, सूखा और हीटवेव का रूप ले लेता है। वृक्षारोपण के अभियानों को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कैमरों के सामने पौधे लगाए जाते हैं, आँकड़े जारी होते हैं, तस्वीरें वायरल होती हैं। एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान भावनाओं को छूते हैं, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक कठोर है। जब एक ओर प्रतीकात्मक पौधारोपण होता है, दूसरी ओर लाखों पेड़ परियोजनाओं की भेंट चढ़ते हैं। यह संतुलन नहीं, एक छल है। पौधा लगाना तब सार्थक होता है, जब वह जीवित रहकर जंगल बने। संरक्षण के बिना रोपण केवल आत्मसंतोष की कवायद बनकर रह जाता है। विकास की मौजूदा परिभाषा सबसे बड़ा संकट है। सड़क, फैक्ट्री और मॉल को प्रगति का पैमाना मान लिया गया है। हवा, पानी और हरियाली को विकास की राह में बाधा समझा जाने लगा है। दिल्ली इसका सबसे भयावह उदाहरण है, जहाँ सांस लेना स्वास्थ्य जोखिम बन चुका है। तापमान हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ता है, जल संकट स्थायी सच्चाई बन चुका है।

फास्ट फूड की तर्ज पर जिंदगी जीने की नाकाम कोशिश

मनोज कुमार अग्रवाल

आज की नई पीढ़ी सपनों में जी रही है सोशल मीडिया रील ओटीटी पर परोसी जा रही लिव-इन रिलेशनशिप लव अफेयर्स सुसाइड हिंसा की काकटेल यूथ लाइफ पर इस तरह हावी हो रही है कि बिना सोचे समझे जस्ट डिसीजन जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। उस पर मल्टी अफेयर्स विवाह पूर्व और विवाहेत्तर स्वछंद सेक्स रिलेशन युवा जोड़ों के वैवाहिक जीवन को त्रास रहे हैं। एक ओर स्वछंद जीवन जीने की ललक है दूसरे ओर वर्जित संबंधो से बचाव की वर्जना इन दोनों का एक साथ संयोग बनाने की कवायद में बहुत सारे कपल अंकंफर्ट हो रहे हैं और नतीजा कभी मेरठ की मुस्कान के नीले ड्रम तो कभी हनीमून ट्रिप पर राजा रघुवंशी के कत्ल के बतौर सामने आ रहा है। वहीं तमाम समाज और परिवार की परंपराओं को तोड़ कर लव मैरिज कर रहे कपल भी फास्टफूड की तरह लाइफ को जीना चाहते हैं और एक दूसरे को समझने परखने समझौता करने का आत्मविश्वास खो कर पलक झपकते ही सुसाइड जैसे आत्मघाती फैसले ले रहे हैं दरअसल पैरेंट्स के प्रति सम्मान कम हो रहा है बुजुर्गों के पास समय देना पल भर बैठना भी आज के यूथ को बेकार लगता है ऐसे में उसे जीवन बोध से कौन अवगत करा सकता है वह सिर्फ रील देखता है इंस्टा चलाता है फास्ट फूड खाता है और जिंदगी को अपने मुताबिक जीने की ललक में लगातार जिंदगी से दूर होता जा रहा है इस सब जीवन द्वंद को दो दिन में सामने आई दो घटनाओं से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु में शादी के बाद हनीमून से लौटे एक जोड़े ने झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली। पत्नी गानवी की मौत के दो दिन बाद पति सूरज ने नागपुर के एक होटल में फांसी लगा ली। गानवी के परिवार ने सूरज और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सूरज की मां ने भी आत्महत्या का प्रयास किया और उनकी हालत गंभीर है। बेंगलुरु के एक युवक ने अपनी पत्नी की आत्महत्या के दो दिन बाद नागपुर के एक होटल में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक पत्नी के माता-पिता ने सूरज के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया था।पत्नी के आत्महत्या के दो दिन बाद सूरज बेंगलुरु से एक हजार किलोमीटर दूर नागपुर गया, जहां वो अपनी मां के साथ पहुंचा था। उसने कमरे में सीलिंग फैन से लटककर जान दे दी, वहीं उसकी मां ने भी आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस जोड़े ने 29 अक्टूबर को बेंगलुरु में शादी की थी और उसके बाद हनीमून के लिए श्रीलंका गए थे। हालांकि, यह यात्रा छोटी हो गई और एक झगड़े के बाद वे पिछले हफ्ते बेंगलुरु लौट आए। गानवी के परिवार ने दावा किया कि वे लड़की को अपने घर वापस ले आए क्योंकि कथित तौर पर उसे ससुराल वालों से अस्वीकृति और अपमान का सामना करना पड़ा था। मंगलवार को, गानवी ने आत्महत्या की कोशिश की और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। उसकी मौत गुरुवार को हुई।उसकी मौत के बाद, गानवी के परिवार ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें शिवन्ना और उसके परिवार के सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया।

सुविचार

समझदार व्यक्ति इसीलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए या दूसरों से बांटने के लिए कई अच्छी बातें होती हैं, लेकिन एक बेवकूफ व्यक्ति इसीलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ बोलना होता है। -अरस्तु

कविता

विनम्रता का पाठ

एक राजा बहुत अहंकारी था। एक दिन उसके मंत्री ने उसे बताया कि नगर में बुद्ध पधारे हैं, चलकर उनका स्वागत किया जाए। राजा ने कहा, मैं बुद्ध का स्वागत करने क्यों जाऊं? मैं राजा हूं और सभी मुझसे मिलने मेरे महल में आते हैं। बुद्ध को यदि मुझसे मिलना होगा, तो वह स्वयं मेरे महल में आएंगे। राजा की बात सुनकर मंत्री बोला, आप राजा हैं इसलिए सभी आपसे मिलने आते है लेकिन संत पुरुष राजा से भी ऊपर होते है। चूंकि प्रजा के लिए भी वे श्रद्धा के पात्र होते है, इसलिए उनका आदर करके आप प्रजा के भी प्रियपात्र बनेंगे। राजा कुतर्की था। उसने पलटकर कहा, क्या मैं प्रजा का दास हूं कि जो वह करे और चाहे, वही मैं करूं? मैं राजा हूं, इसलिए मैं जो चाहूंगा, वही करूंगा। मंत्री को राजा का व्यवहार उचित नहीं लगा। उसने अपना त्यागपत्र राजा को दे दिया और कहा, मैं आपकी सेवा में नहीं रह सकता। आप में तनिक भी बड़प्पन नहीं है। राजा ने कहा, मैं अपने बड़प्पन के कारण ही बुद्ध के स्वागत हेतु नहीं जा रहा हूं। मंत्री ने कहा, अपने घमंड को बड़प्पन मत समझिए । बुद्ध भी कभी महान सम्राट के पुत्र थे। उन्होंने राय का त्याग कर भिक्षु बनना स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि राय के मुकाबले उनका त्याग अधिक बड़ा है। विनम्रता ही व्यक्ति को बड़ा बनाती है। इसके अभाव में व्यक्ति किसी लायक नहीं रह जाता।

जरा हटके

ड्रैगन सेना की ऐतिहासिक घेराबंदी

ताइपे, ईएमएस। साल 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए नए साल के जश्न के बजाय एक भीषण सैन्य टकराव की आशंका लेकर आया है। जब पूरी दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारी कर रही थी, तब ताइवान की सरहद पर बारूद की गंध और लड़ाकू विमानों की गर्जना ने शांति को भंग कर दिया। बीजिंग से आए एक कड़े सैन्य आदेश के बाद चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान द्वीप को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। ड्रैगन ने इस घेराबंदी में अपने सबसे घातक स्टील्थ फाइटर जेट्स, परमाणु बमवर्षक और विशाल युद्धपोतों को तैनात कर दिया है, जिसे विशेषज्ञ एक खौफनाक जंग की रिहर्सल मान रहे हैं। चीन ने पिछले 24 घंटों के भीतर ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन के 130 से अधिक लड़ाकू विमानों ने ताइवान की हवाई सीमा को चुनौती दी। इस बेड़े में चीन के सबसे आधुनिक जे-20 स्टील्थ फाइटर और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बमवर्षक विमान शामिल थे। आसमान के साथ-साथ समंदर में भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। चीन ने ताइवान की आर्थिक लाइफलाइन माने जाने वाले दो सबसे बड़े बंदरगाहों–कीलुंग और काओशुंग–की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी है। चीनी कोस्ट गार्ड के विशाल जहाज ताइवान के गश्ती जहाजों के अत्यंत करीब पहुंच गए हैं, जिससे किसी भी समय सीधी भिड़ंत का खतरा पैदा हो गया है। चीन की इस आक्रामकता के जवाब में ताइवान ने भी पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं। जैसे ही चीनी विमानों ने सीमा लांघने की कोशिश की, ताइवान के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने सिंचू एयर बेस से हुंकार भरते हुए उड़ान भरी।

फोटो ऑफ द डे

जावा में पारंपरिक नगारोट समारोह में लड़कियां अपने सिर पर फूलों को सजाकर निकलीं। -फोटो-ईएमएस

व्यंग

इक्कीसवीं सदी का कौशल

डॉ. शोभा श्रीवास्तव

दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, जितनी की ज़रूरत नहीं थी। असावधानी में ऐसा हो गया। जैसे कभी-कभी आप असावधानी में उतना खा जाते हैं जितने की ज़रूरत नहीं होती। इतनी तरक्क़ी के बाद कुछ चीजें तो पहले जैसी नहीं ही रहनी थी सो न रहीं। वैसे ही आजकल दुनिया में जवाब देने के तरीक़े भी मॉडर्न हो चले हैं। कामदेव ने जीवन भर कुँआरा रहने की क़सम खाई थी मगर अपने दुश्मन वामदेव के विवाह के जवाब में कामदेव ने भी विवाह कर लिया। मुझे मिले तो मैंने पूछा, भाईसाब आपने जो क़सम खाई थी अविवाहित रहने की वह तो टूट गई। क़सम की क्या बिसात जवाब के सामने। वह भी जब दुश्मन को देना हो। अरे नहीं भाईसाब क़सम तो क़सम होती है। तोड़ी नहीं जाती।

देश में इतनी तरक़्क़ी हो चुकी है कि छोटी-मोटी तोड़-फोड़ का तो पता ही नहीं चलेगा। वह तो तरक़्क़ी का ही पार्ट है, मान लिया जाएगा। आपका क़सम तोड़ना किस तरह पार्ट हुआ? देखिए, जैसा कि दुश्मनों में प्रायः होता है हम दोनों कभी दोस्त थे। साथ रह कर पढ़ाई की। वह भी फ़ेल। मैं भी। ओह! ओह नहीं वाह! हम दोनों साथ नक़ल की कोशिश करते। साथ पकड़े जाते। साथ फ़ेल होते। साथ कुटते-पिटते। इससे हमारी दोस्ती प्रगाढ़ होती गई। आगे चल कर हमने कैरियर बनाने के लिए हाथ-पाँव बहुत मारे मगर इसका नतीजा यह हुआ कि हमसे तंग आ कर घर वालों के हाथ तो कभी पाँव हम पर ही मारे जाने लगे। हम दोनों के घर वालों ने एक दूसरे की संगति को दोष दिया लिहाज़ा उसने मुझसे और मैंने उससे, दूरी बना ली। फिर मुझे अयोग्य मानते हुए, वह स्वयं राजनीति में उतर गया। मगर तरक़्क़ी के पार्ट वाली बात तो रह गई ना! राजनीति का पार्ट तो हुई ना! कैसे? राजनेता ही बताते हैं कि तरक़्क़ी मची है देश में। ओह! मगर दोस्त ने बुरा किया आपके साथ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो क्या बुरा करता, बुरा तो मैंने किया। कैसे? घोर बेकारी के दिनों में हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कभी शादी नहीं करेंगे। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? दरसल उन दिनों हमारी तंगहाली को देख लड़कियाँ हमें घास नहीं डालतीं थीं। उनको जवाब देने के लिए ही हम दो दुखियों ने आपस में वादा किया कि किसी भी लड़की को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे और चिर कुँवारे रहेंगे। अच्छा! फिर क्यों कर ली? मैंने देखा मित्र बहुत छा गया है राजनीति में, बड़ा आदमी हो गया है। उसकी कार में एक सुंदर बनाई गई स्त्री लोड थी। स्त्री पर बहुत सी ज्वेलरी लोड थी। मैं समझ गया मित्र ने वादा तोड़ दिया है। अगले दिन मैंने भी वादा तोड़ दिया और शादी कर ली। मैंने उसे जवाब दे दिया। वाह! बहुत खूब। यह तो कुछ भी नहीं। मैंने उसे आगे भी हर बात का जवाब दिया। कैसे? उसने लग्ज़री में रह कर तोंद बढ़ा ली। बढ़ जाती है अपने आप ही भाईसाब। कोई उस पर मिट्टी थोड़े थोपता है। मगर मैंने थोपी। मिट्टी? नहीं, चर्बी की परत दर परत। बड़ा आसान है। कुछ न करने से, चढ़ जाती है। नहीं नहीं यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिना स्वाद को तवज्जोह दिए ठूँस कर खाओ और घर में अधिक से अधिक ठहर कर किचिन में गाया जा रहा बेसुरा गाना सुनो। तब कहीं कुछ सफलता मिलती है। सेहत के साथ आपने खिलवाड़ क्यों किया, इस ज़रूरी सवाल पर आपका ध्यान नहीं गया। प सवाल को छोड़िए। यह देखिए, मैंने उसकी तोंद का जवाब तोंद से दिया। मैं उनकी इस जवाब देने की कला की क़ायल हूँ।

चिंतन-मनन

मृत्यु की चिंता और चिंतन का महत्व

एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे और उन्हें योगाभ्यास सिखाते थे। वह सत्संग भी करते थे। एक शिष्य चंचल बुद्धि का था। बार-बार गुरु से कहता, आप कहां जंगल में पड़े हैं, चलिए एक बार नगर की सैर करके आते हैं। महात्मा ने कहा, मुझे तो अपनी साधना से अवकाश नहीं है। तुम चले जाओ। शिष्य अकेला ही नगर चला गया। नगर में बाजार की शोभा देखी। मन अति प्रसन्न हुआ। इतने में एक भवन की छत पर निगाह पड़ी। देखा कि एक परम सुंदरी छत पर कपड़े सुखा रही है। बस वह कामदेव के बाण से आहत हो गया। जब शिष्य आश्रम लौटा तो चेले का चेहरा देखकर महात्मा जान गए कि यह बच्चा काम वासना शिकार हो गया है। पूछने पर चेले ने उत्तर दिया - गुरुदेव! हृदय में असहनीय पीड़ा हो रही है। महात्मा बोले, क्या नजर का कांटा हृदय में गड़ गया? चेले ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। चेले से गुरुजी ने उस स्त्री का पता पूछा तो पता चला कि वह नगर के एक सेठ की पत्नी है। महात्मा ने एक पत्र के जरिए सेठ को अपनी पत्नी को लेकर आश्रम में एक रात के लिए आने के लिए कहा। सेठ आया तो उसे अलग बैठाकर महात्मा स्त्री को लेकर शिष्य के पास गए और कहा, यह स्त्री रात भर तेरे पास रहेगी।

स्वास्थ्य

भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का आसान सहारा

नई दिल्ली, ईएमएस। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में काम की जिम्मेदारियों के बीच लोग अपनी सेहत से समझौता करने लगे हैं। न समय पर भोजन, न पर्याप्त नींद और न ही शरीर को जरूरी आराम मिल पाता है। इसका सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ता है और धीरे-धीरे पूरा शरीर कमजोर होने लगता है। पेट से जुड़ी समस्याएं, कमर दर्द, पैरों में थकान और मानसिक तनाव आम हो गया है। ऐसे में अगर कम समय और कम मेहनत में शरीर को स्वस्थ रखना है, तो योग सबसे बेहतर उपाय माना जाता है। योग न सिर्फ शरीर को, बल्कि मन को भी संतुलित रखने में मदद करता है। योगासन में उत्तानपादासन को विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। यह ऐसा आसन है, जो पेट से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में यह योगासन राहत देता है। इसके नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है और पेट व जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यही नहीं, लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए यह आसन कमर और पैरों के दर्द को कम करने में भी उपयोगी माना जाता है। उत्तानपादासन का असर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। यह मन को शांत करने में भी मदद करता है। तनाव और बेचैनी को कम कर यह मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। योग विशेषज्ञों के अनुसार, इस आसन के अभ्यास से हृदय की धड़कन नियंत्रित रहती है और व्यक्ति खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है।

'बैटल ऑफ बेगम्स' का दौर खत्म

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का 30 दिसंबर 2025 सुबह निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थीं। लंबी बीमारी से जूझ रही खालिदा जिया ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती थीं, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। खालिदा जिया की मौत से बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत हो गया है। वे दशकों तक देश की सियासत की धुरी रहीं और अपनी कट्टर प्रतिद्वंद्वी शेख हसीना के साथ उनकी दुश्मनी ने पूरे देश को प्रभावित किया। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के जलपाईगुड़ी जिले में हुआ था, जो आज पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। उनका बचपन का नाम खालिदा खानम 'पुतुल' था। उनका परिवार एक साधारण व्यापारी परिवार से था। 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार पूर्वी बंगाल (आज का बांग्लादेश) के दिनाजपुर जिले में आकर बस गया। खालिदा जिया ने दिनाजपुर की मिशनरी स्कूल और गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। वे खुद को 'सेल्फ-एजुकेटेड' बताती थीं और हाई स्कूल की डिग्री के कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं हैं। साल 1960 में मात्र 15 साल की उम्र में खालिदा की शादी पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन जियाउर रहमान से हो गई। जियाउर रहमान बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के प्रमुख नायक थे। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। शादी के बाद खालिदा जिया एक साधारण गृहिणी बनकर रह गईं। वे दो बेटों तारेक रहमान और आरफ रहमान की परवरिश में व्यस्त रहीं। उस समय उन्हें एक शर्मीली और घरेलू महिला के रूप में जाना जाता था जो राजनीति से दूर रहती थीं। जियाउर रहमान ने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की स्थापना की। वे 1977 से राष्ट्रपति थे और देश को सैन्य शासन से लोकतंत्र की ओर ले जा रहे थे। लेकिन 30 मई 1981 को चटगाँव में एक असफल सैन्य तख्तापलट में जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। इस घटना ने खालिदा जिया की जिंदगी बदल दी। शौहर की मौत के बाद बीएनपी संकट में पड़ गई। कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे में खालिदा जिया ने 1982 में पार्टी की सदस्यता ली और 1984 में बीएनपी की चेयरपर्सन बन गईं। एक गृहिणी से राजनीतिक नेता बनने की उनकी यात्रा प्रेरणादायक थी। 1980 के दशक में बांग्लादेश पर जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद का सैन्य शासन था। खालिदा जिया ने इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र बहाली की लड़ाई का नेतृत्व किया। वे सात दलों के गठबंधन की प्रमुख बनीं और हड़तालों, प्रदर्शनों के जरिए सैन्य तानाशाही का विरोध किया। इस दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और घर में नजरबंद रखा गया लेकिन वे डटी रहीं। 1990 में जन आंदोलन के दबाव से इरशाद को सत्ता छोड़नी पड़ी। लोकतंत्र की बहाली के लिए हुई लंबी लड़ाई में शेख हसीना ने भी मोर्चा थामे रखा। ये वही समय था, जब बांग्लादेश के लिए दोनों बेगमों ने एक पक्ष की तरफ से लड़ाई लड़ी, हालाँकि राजनीतिक वजहों से दोनों हमेशा अलग-अलग खेमों की अगुवाई करती रही। साल 1991 में बांग्लादेश में पहली बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए। बीएनपी ने भारी जीत हासिल की और खालिदा जिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। उनके पहले कार्यकाल (1991-1996) में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। उन्होंने संसदीय व्यवस्था बहाल की, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। अर्थव्यवस्था में सुधार आए और बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत हुआ। साल 1996 में वे चुनाव हार गईं और शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में आई लेकिन 2001 में बीएनपी की वापसी हुई और खालिदा जिया दूसरी बार प्रधानमंत्री बनीं। इस कार्यकाल में भी कई उपलब्धियाँ रहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप और इस्लामी कट्टरपंथी और आतंकवादियों के उभार ने उनकी सरकार को विवादास्पद बना दिया। साल 2006 में सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली और खालिदा जिया पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज किए गए। उन्हें जेल भेजा गया और लंबे समय तक नजरबंद रखा गया। साल 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद खालिदा जिया को नजरबंदी से रिहा किया गया। वे फिर से सक्रिय राजनीति में लौटने की तैयारी कर रही थीं लेकिन स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। अंतिम वर्षों में वे लीवर सिरोसिस, डायबिटीज, गठिया, हृदय और फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित रहीं। 2025 की शुरुआत में लंदन में इलाज के बाद वे वापस ढाका लौटीं लेकिन हालत बिगड़ती गई और अब उनका निधन हो गया। बांग्लादेश की राजनीति को दशकों तक परिभाषित करने वाली शेख हसीना (अवामी लीग) और खालिदा जिया (बीएनपी) की दुश्मनी को दुनिया 'बैटल ऑफ द बेगम्स' कहती है। यह प्रतिद्वंद्विता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और वैचारिक भी थी जो बांग्लादेश को बार-बार अस्थिरता में धकेलती रही। दोनों महिलाओं ने मिलकर 1991 से 2024 तक बांग्लादेश पर बारी-बारी से शासन किया लेकिन उनकी लड़ाई ने हड़तालें, हिंसा और राजनीतिक संकट पैदा किए। प्रतिद्वंद्विता की जड़ें 1970 के दशक में हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिनकी 1975 में हत्या हुई। खालिदा जिया राष्ट्रपति जियाउर रहमान की बीवी थीं, जिनकी 1981 में हत्या हो गई। दोनों एक-दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से हत्या की साजिश का आरोप लगाती रहीं। हसीना कहती थीं कि जियाउर रहमान मुजीब हत्याकांड से जुड़े थे जबकि खालिदा अवामी लीग को अपने शौहर की हत्या का जिम्मेदार ठहराती थीं। लोकतंत्र की बहाली के लिए 1980 के दशक में दोनों महिलाएँ एक साथ दिखीं। उस समय जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद का सैन्य शासन था। खालिदा जिया ने 1984 में बीएनपी की कमान संभाली जबकि शेख हसीना 1981 में अवामी लीग की नेता बनीं। दोनों ने इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र बहाली का आंदोलन चलाया। 1990 में हड़तालों और प्रदर्शनों से इरशाद को सत्ता छोड़नी पड़ी। यह दोनों का एकमात्र साथ था। उसके बाद दुश्मनी शुरू हो गई।

कटाक्ष | सुरेश मिश्र

चुना इंदिरा मैम ने,जीवन मित्र फिरोज
और इधर राजीव ने, इटलीवाला रोज
इटली वाला रोज,बोझ बन गई इसाई
उधर प्रियंका करी वाड्रा संग सगाई
कह सुरेश रेहान अवीवा बेग लुगइया
तो कैसे बाह्मण हो बोलो पप्पू भइया

अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने की ललक है नव वर्ष

वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा अनेक नई पहलें की गई हैं तथा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आरंभ और विस्तार दिया गया है। अब आवश्यकता इसकी है कि सरकार इन योजनाओं को केवल घोषणा तक सीमित न रखे, बल्कि उन्हें प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से उनकी तार्किक परिणति तक पहुंचाए और ठोस, सकारात्मक परिणाम सामने लाए।

नया साल एक नए सवेरे की तरह है, जो हर वर्ष एक बार आता है और अपने साथ नई शुरुआत की संभावनाएं लेकर आता है। समय के साथ वह अपने चरम पर पहुंचता है और फिर धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। यही क्रम एक निरंतर अनुभव है, जिसे इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। यह निरंतरता ही प्रकृति और जीवन का परम सत्य है। नए वर्ष की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति को पिछले साल के निरंतर प्रवाह और अनुभवों से सीख लेकर अच्छे कार्यों से करनी चाहिए। यह समय आत्मचिंतन का होता है, जब हमें अपने अच्छे-बुरे कार्यों का मूल्यांकन कर आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। नए साल की शुरुआत सद्कर्मों, सकारात्मक सोच और स्पष्ट दिशा के साथ करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। नया वर्ष हर व्यक्ति के लिये बीते हुए वर्ष की सफलताओं और उपलब्धियों के साथ-साथ कमियों और गलतियों का मूल्यांकन करने का समय है। यह हमें अपने आप को भावी वर्ष के लिये योजना बनाने, कार्य करने तथा आगामी वर्ष के लिये नये लक्ष्य तय करने का अवसर प्रदान करता है। नये साल की शुरुआत में हर व्यक्ति को भावी वर्ष के लिये नये लक्ष्य बनाने चाहिए और उन्हें पूरा करने की रणनीति बनानी चाहिए। जिससे कि अवसरों को सफलता में बदला जा सके। यदि व्यक्ति अपने जीवन के आरंभ में ही अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, तो सफलता की दिशा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। लक्ष्य हमें अनुशासन, परिश्रम और निरंतर प्रयास की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को नए वर्ष की

शुरुआत में वर्ष भर के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, ताकि आने वाले समय में वह अपने लक्ष्य के लिए किए गए सत्कर्मों और प्रयासों के माध्यम से निरंतर विकास करता हुआ अपने जीवन के चरम और शिखर तक पहुँच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते वर्षों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, साथ-साथ अनेक सफलताएँ भी पायी हैं। इन सफलताओं और उपलब्धियों में मोदी सरकार को अपनी गलतियों और कमियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। बल्कि अपनी गलतियों और कमियों का मूल्यांकन करके भावी वर्ष के लिये रणनीति बनानी चाहिए। जिससे कि गलतियों और कमियों को सुधारकर अवसरों में बदला जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में जिस प्रकार से अनेक चुनौतियों का सामना किया, उसी प्रकार भावी वर्ष में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहा जाए तो साल 2026 में नरेंद्र मोदी को अनेक अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा और आने वाला वर्ष राजनीतिक दृष्टि से भी भाजपा व पीएम मोदी के लिये बेहद अहम है। 2026 में देश के 4 राज्यों- असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश- पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में भाजपा के सामने केवल प्रचार का ही नहीं, बल्कि संगठनात्मक मजबूती और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी की भी चुनौती होगी। इसी क्रम में (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चुनावी तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए वर्ष में मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित, पारदर्शी और अद्यतन बनाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से फर्जी, दोहरे या मृत मतदाताओं के नाम हटाकर वास्तविक और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद को मजबूत करता है। इन पाँच चुनावी क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति अलग-अलग है। असम में पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि पुडुचेरी में गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ है। इन दोनों स्थानों पर सत्ता को बनाए रखना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ भाजपा अपने संगठन का विस्तार कर राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल भाजपा की रणनीति का प्रमुख केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पक्ष मतदान और जागरूक मतदाता पर जोर देना पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है। असम और पश्चिम बंगाल में लंबे समय से यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए कथित रूप से मतदाता सूची में शामिल होकर वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं। यदि ऐसा है, तो यह न केवल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के लिए भी गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। इन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसके तहत मतदाता सूचियों की गहराई से जांच की जा रही है। सरकार का तर्क है कि यह प्रक्रिया विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में आवश्यक है, जहाँ अवैध घुसपैठ की समस्या को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। यह भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि कुछ घुसपैठियों ने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज बनवा लिए हैं, जिसके कारण वे चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में ऐसे मतदाताओं का लाभ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को मिलता है, जबकि असम में इसका प्रभाव विपक्षी दलों की स्थिति को मजबूत करने के रूप में देखा जाता है। सरकार का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य किसी समुदाय या राज्य को निशाना बनाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है, ताकि केवल पात्र और वैध नागरिक ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बनाए रखा जा सकता है। जहाँ तक दो दक्षिणी राज्यों-केरल और तमिलनाडु का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं, बल्कि केवल पाने के अवसर ही हैं। यदि भाजपा इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है, भले ही वह सरकार बनाने की स्थिति में न पहुँचे, तब भी यह पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा प्रदर्शन न केवल संगठनात्मक मजबूती को दर्शाएगा, बल्कि भविष्य में अपनी राजनीतिक संभावनाओं को विस्तार देने की ठोस आधारशिला भी तैयार करेगा। स्पष्ट है कि यदि मोदी सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और प्रभावी संप्रेषण पर ध्यान केंद्रित करती है, तो आगामी चुनावों में भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इन सभी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता और असफलता सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को प्रभावित करेगी।

■ डॉ. ब्रह्मानंद राजपूत

ईरान में जेन जेड क्रांति

शिया मुस्लिम बहुल देश ईरान में 'तानाशाह तेरी कब्र खुदेगी' और 'मुल्लाओं को देश छोड़ना होगा' जैसे नारे लगना हैरत की बात है, क्योंकि कोई सच्चा मुसलमान अयातुल्लाह खुमैनी जैसे मुल्ला शासकों और उनके वतन परस्त हमकदम मुल्लाओं का विरोध क्यों करेगा? खासकर उस अयातुल्लाह खुमैनी का जो पूरी दुनिया में इस्लामिक बादशाहत स्थापित करने का स्वप्नद्रष्टा समझे जाते हैं। बावजूद इसके हाल के ईरान मुल्ला विरोधी आंदोलन में ये नारे आम हो चुके हैं। इसलिए सवाल है कि क्या अयातुल्लाह खुमैनी सरकार ईरान में सुलग रही जेन जेड क्रांति से कुछ सबक लेगी या अपनी शहादत देगी? बताया जाता है कि यह सरकार विरोधी जन-आंदोलन मुख्य रूप से वहां के आर्थिक संकट से उपजे हैं जहां रियाल की कीमत में भारी गिरावट के बाद लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। वहां से मिली खबरों से पता चलता है कि ईरान में चढ़ी 42% से अधिक की महंगाई ने आम जनता को सड़कों पर उतार दिया है। जानकारों का कहना है कि ये जन-प्रदर्शन तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू होकर मशहद, इस्फहान जैसे शहरों में फैल गए हैं, और लोग 'मुल्लाओं को देश छोड़ना होगा' और 'तानाशाह तेरी कब्र खुदेगी' जैसे आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। यह वहां की अयातुल्लाह खुमैनी सरकार के लिए चिंता की बात है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि ईरान की मौजूदा आर्थिक बदहाली के पीछे उस पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध मुख्य वजहें हैं, जो उसके मुख्य उत्पाद तेल निर्यात को प्रभावित कर रहे हैं। यही वजह है कि साल 2022-23 के महसा अमीनी आंदोलन के बाद शुरू हुआ हालिया आंदोलन विगत तीन सालों के बाद प्रारम्भ हुआ सबसे बड़े प्रदर्शन हैं जहां भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरता और सालों की नाकामियों से तंग जनता पुनः सड़क पर चुकी है। वहीं, वैश्विक कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी' ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को और सख्त किया है जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने इसे शासन की आंतरिक कमजोरियों को उजागर करने वाला बताया है, हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेप का कोई स्पष्ट प्रमाण अब तक नहीं मिला है। उधर, इजरायल और अमेरिका के परमाणु ठिकानों पर हमलों ने भी ईरान पर नैतिक दबाव बढ़ाया है। इजरायल जिस तरह से ईरान के सैन्य रणनीतिकारों को ढेर कर देता है, उससे भी सरकार की प्रतिरक्षात्मक कमजोरी जगजाहिर है। फिर भी ईरान के हालिया मुल्ला विरोधी प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें आर्थिक संकट से निजात और सत्ता परिवर्तन से जुड़ी हैं। आंदोलनकारियों ये मांगें तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुए आंदोलन में स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं- पहला, प्रदर्शनकारी "मुल्लाओं को देश छोड़ना होगा" और "तानाशाह की कब्र खुदेगी" जैसे नारों से सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और धार्मिक शासन के खिलाफ खुला विद्रोह जता रहे हैं। दूसरा, वे रियाल की गिरावट, 42% महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त होकर आर्थिक सुधार तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मांग कर रहे हैं। तीसरा, उनकी अतिरिक्त अपेक्षाएं हैं कि जनता इजरायल-अमेरिका के दबाव के बीच परमाणु नीति पर पुनर्विचार करे और महिलाओं पर हिजाब जैसे धार्मिक प्रतिबंधों को समाप्त करने का कार्य करे। यह उनकी सामूहिक अपील है। हालांकि, अनुभव बताता है जिस तरह से धर्म के आधार पर राष्ट्रपति खुमैनी लोगों को नियंत्रित करने की भूल कर रहे हैं, उसके मद्देनजर यह होना स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए कि कोई भी धर्म पारलौकिक समस्याओं का समाधान तो देता है लेकिन इहलौकिक समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को शिक्षा और विकास जैसे सुशासन की जरूरत होती है। समझा जाता है कि जब कोई राजनेता देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और मानवीय संसाधनों का दुरूपयोग अपने धार्मिक महत्वाकांक्षाओं, उसके भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक अवसरवादिता के दृष्टिगत करने लगता है तो वह भीतर ही भीतर खोखला होता जाता है। ऐसा इसलिए कि विरोधी बढ़ जाते हैं जिन्हें काबू में करने के लिए युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी करनी पड़ती है। इसमें खर्च बढ़ने से जनता की सहूलियत में कटौती करनी पड़ती है। इससे महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने से लोगों को भी त्याग करने में कष्ट पहुंचता है। इससे सत्ता विरोधी आक्रोश पनपता है, जिसे विदेशी शक्तियां तूल देती हैं। फिलहाल ईरान, अमेरिका-इजरायल और इनके समर्थक मुस्लिम देशों के षड्यंत्र का सहज शिकार होने के कगार पर पहुंच चुका है। दिलचस्प तो यह है कि जेन जेड पीढ़ी के नेतृत्व में शुरू हुए ये जन-प्रदर्शन 2022 के महसा अमीनी आंदोलन की याद दिलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल के बाद अब ईरान का नेतृत्व भी तथाकथित जेन जेड क्रांति का सहज शिकार होने वाला है। इससे साफ है कि इक्कीसवीं सदी में वैश्विक पटल पर अमेरिकी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए डीप स्टेट प्रोत्साहित जो कथित 'जेन जेड क्रांति' हो रही है, वह विभिन्न एशियाई देशों को अमेरिकी रणनीति के समक्ष घुटने टेकने या अंजाम भुगतने की स्पष्ट नसीहत है। बता दें कि जेन जेड यानी साल 1997-2012 के बीच जन्मे बच्चे अब सोशल मीडिया के जरिए जलवायु परिवर्तन, तानाशाही और अन्याय के खिलाफ सक्रिय हैं, जैसा कि मिस्र की जैस्मीन क्रांति या ईरान के पुराने हिजाब आंदोलनों में दिखा। अब तक कम से कम 8 देशों में ऐसे युवा आंदोलन दर्ज हैं। खासकर साल 2025 में नेपाल, इंडोनेशिया, पेरू और हाल ही में ईरान में भी जेन जेड के बड़े प्रदर्शन देखे गए हैं। इससे पहले अगस्त 2024 में बंगलादेश में भी इनके सफल प्रदर्शन हो चुके हैं और वहां भी शेख हसीना सरकार की बलि चढ़ाई जा चुकी है। घटनाक्रम बताते हैं कि साल 2025 में इनका आंदोलन इंडोनेशिया से शुरुआत होकर पेरू की राजधानी लीमा में राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते के खिलाफ 27 सितंबर को प्रदर्शन हुए। ईरान में दिसंबर 2025 तक तेहरान समेत कई शहरों में जेन जेड ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ विद्रोह किया। वहीं, नेपाल में 8 सितंबर 2025 को शुरू हुए प्रदर्शनों ने संसद और सरकारी भवनों पर हमले किए, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई। यहां भी युवाओं ने सोशल मीडिया बैन हटवाया और नया संविधान की मांग की।

■ कमलेश पांडेय

जब-जब दुनिया डगमगाई

साल 2025 भारतीय राजनीति और वैश्विक कूटनीति के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विजयगाथा के रूप में दर्ज हो गया। यह वर्ष केवल मोदी की चुनावी सफलताओं का नहीं रहा, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच, आर्थिक मजबूती, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के विस्तार का भी साक्षी बना। मोदी ने एक बार फिर यह साबित किया कि उनका नेतृत्व केवल सत्ता संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र को दिशा देने, संकट में निर्णय लेने और दुनिया को भारत की ताकत का अहसास कराने का सामर्थ्य रखता है। 2025 में विभिन्न राज्यों और स्थानीय निकायों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सफलता के पीछे नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति और नेतृत्व की स्पष्ट छाप दिखाई दी। मोदी ने जहां एक ओर सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद को केंद्रीय मुद्दा बनाए रखा, वहीं दूसरी ओर संगठनात्मक मजबूती पर भी विशेष ध्यान दिया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने, लाभार्थी वर्ग से सीधा संवाद स्थापित करने और विपक्ष की कमजोरियों को उजागर करने की उनकी रणनीति ने भाजपा को बढ़त दिलाई। एनडीए के भीतर मतभेदों को साधते हुए मोदी ने सहयोगी दलों को एकजुट रखा और नए सहयोगियों को जोड़कर गठबंधन का विस्तार भी किया। उनका नेतृत्व सहयोगियों में विश्वास पैदा करने वाला रहा, जिससे एनडीए एक मजबूत और अनुशासित राजनीतिक परिवार के रूप में सामने आया। इसके अलावा, साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का रुख पूरी तरह स्पष्ट और सख्त रहा। 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों और उनके ठिकानों पर कार्रवाई कर यह संदेश दे दिया कि भारत अब केवल आतंकी घटना की निंदा तक सीमित नहीं रहेगा। यह कार्रवाई न केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया को यह समझाने में सफल रही कि भारत आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर अडिग है। मोदी के इस साहसिक निर्णय ने देशवासियों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत किया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि एक निर्णायक शक्ति के रूप में और सुदृढ़ हुई। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ और दबावों के बावजूद मोदी ने भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया। रूस के साथ ऐतिहासिक मित्रता को कायम रखते हुए भारत ने ऊर्जा, रक्षा और कूटनीति के क्षेत्रों में संतुलित नीति अपनाई। मोदी का स्पष्ट संदेश रहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी भी बाहरी दबाव को हावी नहीं होने देगा। रूस के साथ संबंधों को मजबूत रखना और साथ ही अमेरिका तथा यूरोप के साथ भी संतुलन बनाए रखना मोदी की बहुपक्षीय कूटनीति का उदाहरण है। इसके अलावा, 2025 में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। वैश्विक मंदी और महंगाई के दौर में भी भारत ने स्थिरता और विकास दोनों को साधा। मोदी सरकार की नीतियों के चलते महंगाई नियंत्रण में रही, ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम बनी रहीं और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की नीतियों ने रोजगार सृजन और विकास को गति दी।

■ नीरज कुमार दुबे

आज का कार्टून

साभार

पर्यावरणीय घटकों को बचाने का संकल्प लें

वर्ष 2026 नव संकल्पों से आरंभ होना चाहिए। वैसे तो जब भी व्यक्ति कुछ सकारात्मक और नया करने की ओर बढ़ जाए, वहीं से नया वर्ष या नए का आरंभ हो जाता है। यदि हमारा जीवन ही खतरे में है तो फिर कैसा उल्लास? कैसा नववर्ष? अंग्रेजी नववर्ष के आरंभ में क्या आज से ही हम पर्यावरणीय घटकों को बचाने का संकल्प ले सकते हैं? क्या आज ही एक पौधा लगाकर हम इस दिशा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं? हमारा यह छोटा सा संकल्प बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। प्रकृति-पर्यावरण भयंकर प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। सांस लेना कठिन है, फिर ऐसे में उल्लास के साथ चिंतन करते हुए संकल्प की ओर बढ़ना ही उचित है। जल, वायु, नदियां, समुद्र, धरती, पहाड़, जंगल, ग्लेशियर, विभिन्न जीव जंतु और वनस्पतियां आदि पर्यावरणीय घटक हैं। ये विभिन्न घटक आज गंभीर प्रदूषण की गिरफ्त में है अथवा अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। परिणामस्वरूप इन घटकों का विकृत होना अथवा असंतुलित होना मानव सहित समूची जीव सृष्टि के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब यह खतरा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। विगत लंबे समय से दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर और बेहद गंभीर श्रेणी में चल रही है। घरों से निकलना मुश्किल है। इससे शारीरिक- मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिकी पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। यूके स्थित भारतवंशी डाक्टरों ने वायु प्रदूषण को कोरोना महामारी के बाद सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बताया है। दिल्ली एनसीआर में सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आयु वर्ग के लोग सिर दर्द,थकान, हृदय रोग, खांसी, बुखार, गले में जलन, आंखों में जलन और सूखापन, त्वचा के रोग व बार-बार संक्रमण जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। प्रदूषण की अधिकता ने हवा को जहरीला बना दिया है। वाहनों, उद्योगों और विद्युत संयंत्रों की धुल, धुआं व घातक रसायन जीवन पर भारी पड़ रहे हैं। सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश के करीब 78 प्रतिशत ताप बिजली संयंत्रों में सल्फर डाइआक्साइड को नियंत्रित करने की प्रणाली नहीं है और प्रदूषण फैलाने में ताप बिजली संयंत्रों की बड़ी जिम्मेदारी है। क्या इन्हें मानकों के अनुरूप संचालित करना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? गंगा, यमुना, हिंडन, काली आदि सैकड़ों नदियां भयंकर प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। महानगरों का अशोधित सीवेज और औद्योगिक कचरा सीधे नदियों में गिर रहा है। विडंबना यह भी है कि विभिन्न प्रदेशों में सीवेज शोधन हेतु एसटीपी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। जितने हैं वे भी समुचित रूप में काम नहीं कर रहे हैं। शासन- प्रशासन की सुस्ती से यह स्थिति और भी चिंताजनक बनती जा रही है। दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि अकेले उत्तर प्रदेश में गंगा व सहायक नदियों में 225 नाले सीधे मिल रहे हैं और लगभग 1100 मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन सीधे नदियों में गिर रहा है। बंगाल के 27 शहरों में कुल 41 एसटीपी हैं जिनमें से अधिकांश मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। पूरे बिहार में केवल 20 एसटीपी के सहारे ही काम चल रहा है। दिल्ली में भी 37 एसटीपी हैं जिनमें से लगभग 16 ही क्षमता के अनुरूप काम कर रहे हैं। दिल्ली सहित देश के विभिन्न महानगरों में छोटे बड़े सैकड़ों नाले सीधे नदियों में गिर रहे हैं। पूरे देश में औद्योगिक अपशिष्ट शोधन प्रणालियों की हालत तो और भी गंभीर है। ध्यान रहे ये सभी नदियां भिन्न-भिन्न रूपों में जीवनदायिनी हैं। क्या पूरे देश में नदियों की बदहाली गंभीर चिंतन का विषय नहीं हैं? वन क्षेत्र धरती के फेफड़े कहे जाते हैं। लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं। प्रत्येक वर्ष करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन उनके संरक्षण-संवर्धन की समुचित योजनाएं नहीं हैं। हाल ही में राज्यों द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी गई एक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि देश के 25 राज्यों में 13 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण है। 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वन क्षेत्र पर अतिक्रमण के बारे में जानकारी नहीं दी है। क्या यह स्थिति गंभीर नहीं है? ताजा अध्ययनों से यह भी सामने आ रहा है कि जल के महत्वपूर्ण स्रोत ग्लेशियर भी प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों में विभिन्न ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर झीलें संवेदनशील बनी हुई हैं।

■ डा.वेदप्रकाश